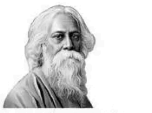

विश्वास ऐसा पक्षी है, जो भोर की आहट पाकर अंधेरे में ही चहचहाने लगता है।

-रवीन्द्रनाथ टैगोर

उम्मीद के 7 मिनट

खुशी की गाइड

खुशी एक अभ्यास और आदत है

डॉ. रितु पाण्डेय शर्मा, reetupost@yahoo.com

धारणा वह अभ्यास है, जिसमें हम अपने विचारों को भटकने से रोककर किसी एक विचार, शब्द या अनुभव पर टिकाए रखते हैं। लेकिन यह तब संभव होता है, जब मन सजग हो। कई बार गलत धारणाओं के कारण जीवन दुःख में बीतता है। नोसीबो प्रभाव उस स्थिति को कहते हैं, जब किसी व्यक्ति की नकारात्मक अपेक्षा या विश्वास पीड़ा, तनाव या बीमारी को बढ़ा देता है। जैसे कोई दवा नुकसान नहीं करती, पर यह सोच लेना कि यह मुझे नुकसान करेगी, शरीर में वैसा ही असर उत्पन्न कर देता है।

• विज्ञान ने सिद्ध किया है कि मन की धारणा शरीर की रासायनिकी को बदल देती है। यही कारण है कि नकारात्मक सोच हमारे स्वास्थ्य, मूड और संबंधों को प्रभावित करती है। इसके विपरीत सकारात्मक धारणा सिखाती है कि सुख केवल दुःख का अभाव नहीं, बल्कि एक सृजनशील अवस्था है, जहां व्यक्ति उद्देश्य, संबंध और आंतरिक संतुलन से जुड़ा रहता है। खुशी कोई संयोग नहीं, बल्कि सजग अभ्यास और आदत है।

• गीता के अनुसार जैसा मन का भाव होगा, वैसा ही जीवन का अनुभव बनेगा। इसीलिए मन को 'मित्र' या 'शत्रु' कहा गया है, यह हमारे ही दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। इसलिए, नोसीबो प्रभाव से मुक्त होकर, सजगता, कृतज्ञता और आत्मविश्वास का अभ्यास करना खुशी का पहला सूत्र है।

▪ 1 मिनट रीड

सकारात्मक संकल्प

उपयोगी विचारों को लिखें

एक शोध के मुताबिक हमारे दिमाग में रोज 12 हजार से लेकर 60 हजार तक विचार आते हैं। विचारों का यह तांता हमारे दिमाग में लगा ही रहता है। इनमें से केवल 10 प्रतिशत विचार ही ऐसे हैं, जिनमें कुछ नयापन होता है और वे हमारे काम के हो सकते हैं- शेष विचार पुराने होते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार अगर हम नएपन वाले विचारों को समय निकालकर लिख लें तो इसके दो फायदे हैं। एक तो विचारों की भीड़ में वो हमसे गुम नहीं होंगे, हम उन्हें भूल नहीं जाएंगे। दो, इससे हमारे विचारों में स्पष्टता आती है और हम निर्णय लेने में समर्थ होते हैं। इस रीति से हम अपने विचारों की समीक्षा भी कर सकते हैं।

सकारात्मक संकल्प लें कि मन में आने वाले असंख्य विचारों में से उपयोगी को लिख लेंगे। ▪ 1 मिनट रीड

दूसरों को स्वीकार करना भी सीखें

जीवन-सूत्र

बीके शिवानी
प्रेरक वक्ता और विचारक

जैसे ही हम किसी के लिए गलत विचार रचते हैं तो अपने लिए भी एक गलत विचार ही रचते हैं। फिर हम एक-दूसरे से दूर होने लगते हैं और तब वो हमारी अच्छी सलाह भी नहीं सुनते। क्योंकि जब उन्होंने हम पर गलत का लेबल लगा दिया तो उन्हें हमारी हर बात गलत ही लगने वाली है।

हमारे विचार अलग हो सकते हैं, संस्कार अलग हो सकते हैं, लेकिन आधार में परस्पर-सम्मान ही होना चाहिए। अनुशासन भले यह कहे कि आपको समय के पहले आना है, लेकिन देरी से आने पर मैं आपकी अवमानना नहीं कर सकती। बच्चे का संस्कार अलग है इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी करे, कुछ भी खाए, कभी भी उठे, कभी भी सोए। एडजस्ट करने का मतलब है उसके संस्कार को समझते हुए, स्वीकारते हुए, उसको अनुशासित करना है। यह हम तभी कर सकेंगे, जब एक-दूसरे के समीप होंगे। लेकिन अगर हमने परस्पर-सम्मान का रिश्ता नहीं बनाया तो यह नहीं होगा।

संस्कार कितना भी भिन्न हो, उसको हमेशा भिन्न ही कहना। दोनों अपने-अपने नजरिए से बिल्कुल सही हैं। हम एक-दूसरे के संस्कार को स्वीकार करते हैं तो एक-दूसरे के संस्कार को बदलने में भी मदद करेंगे। लेकिन दूसरे के संस्कार को बदलने के लिए पहले उनके मौजूदा संस्कार को स्वीकार करना होता है। इसका मतलब है पहले उनको अपने नजदीक लाना पड़ेगा। नकारा तो वो दूर चले जाएंगे।

किसी की झूठ बोलने की आदत हो सकती है, किसी की लेट आने की आदत हो सकती है, किसी को काम समय पर पूरा न करने की आदत हो सकती है। किसी की एक आदत ही लें, ज्यादा लंबी लिस्ट नहीं बनाएं। अब अगला मंत्र अपने मन में यह जपें कि मैं उन्हें इसी रूप में स्वीकार करता हूं या करती हूं। इससे ये संस्कार बाहर ही रह जाएगा, आपके मन को वह मलिन नहीं करेगा।

संस्कार उनका है, व्यवहार उनका है, लेकिन इसके बाद वो आपके मन पर कुछ लेकर नहीं आएगा। उनके संस्कार में इतनी शक्ति नहीं है कि आपके मन को कष्ट दे।

अगर हम हरेक के हरेक संस्कार के लिए इसी तरह से परेशान होते रहे तो हमारा आभामण्डल कैसा हो जाएगा?

आपके पास दो विकल्प हैं- या तो आप मुझे बोलो कि मैं बदलूं, और यह जरूरी नहीं है कि आपके बोलने के बाद मैं बदल जाऊंगी। मैं कह सकती हूं कि मुझे इस तरह से जीने में कुछ गलत लगता नहीं।

या मैं कहूं कि मैं आपके कहने पर क्यों चेंज करूं? या यह कि मैं भी बदलना चाहती हूं, लेकिन मुझसे यह होता नहीं। यानी मैं उस संस्कार के परवश हूं। तो ये सारा कुछ मेरे बारे में है। मेरा संस्कार, मेरे चयन, मेरा उनके अधीन होना, लेकिन आप इसे देख-देख कर अपने मन में हलचलें पैदा क्यों करो?

हमें याद रखना है हम सुबह वाइट सर्कल से निकलेंगे और रात को हमें वाइट सर्कल लेकर ही घर आना है वापस। जैसे अगर हम सुबह सफेद वस्त्र पहनते हैं तो उसे मैला होने से बचाना कठिन है। वाइट सर्कल के साथ भी ऐसा ही है। लेकिन थोड़ा-सा ध्यान रखना होता है। अगर गहरे रंगों की पोशाक पहनी है तो कहीं भी बैठो, कुछ भी खाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सफेद कपड़े वालों को खूब ख्याल रखना होता है।

आप अपना वाइट सर्कल, अपना आध्यात्मिक आभामण्डल लेकर सारा दिन दुनिया में गए, अलग-अलग संस्कार के लोग मिले। लेकिन अगर आप हरेक की मैल पकड़ते गए तो वो संस्कार उनकी मैल न रहकर आपकी हो जाएगी। ▪ 2 मिनट रीड

इस जीवन सूत्र को मोबाइल पर सुनने के लिए QR कोड को स्कैन करें।

संघर्ष की कहानी **अलख पांडे,** फाउंडर (फिजिक्स वाला)

घर बिका, झुग्गियों में रहे, अब भारत के सबसे अमीर टीचर

भारतीय शिक्षा जगत में अलख पांडे (34) काफी मशहूर नाम है। अपने एप फिजिक्स वाला के जरिए प्रतियोगी परीक्षाओं की पढ़ाई को सुलभ और सस्ता बनाने वाले पांडे ने शुरू में कई कठिनाइयां झेलीं। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 में उनकी नेट वर्थ 223% की वृद्धि के साथ शाहरुख खान से भी अधिक हो गई है। यहां तक पहुंचने का उनका सफर आसान नहीं रहा। जानते हैं उनकी संघर्ष से सफलता की कहानी...

प्रयागराज में जन्मे अलख पांडे के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। उनके पिता ठेकेदार थे और मां स्कूल में पढ़ाती थीं। अलख की इच्छा एक्टर बनने की थी। वह जगह-जगह नुक्कड़-नाटक किया करते थे। लेकिन घर की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उन्हें कम उम्र में ही घर की जिम्मेदारी संभालना पड़ी। यही नहीं एक समय ऐसा भी आया, जब घर चलाने और अलख की पढ़ाई के लिए उनके पिता को घर भी बेचना पड़ा। इस दौरान अलख का परिवार किराए की झुग्गी में रहता था।

संघर्ष: आईआईटी में असफल, 125 रुपए प्रति लेक्चर कोचिंग में पढ़ाया

अलख का सपना आईआईटी में जाने का था। लेकिन तीन बार असफल होने के बाद वे पूरी तरह टूट गए। इस बीच उन्होंने कानपुर के हरकोर्ट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग में दाखिला ले लिया। इंजीनियरिंग कोर्स उन्हें पसंद नहीं आया और वे डिप्रेशन में चले गए। एक साल के बाद, वे कॉलेज छोड़कर घर लौट आए। यह फैसला आसान नहीं था। परिवार की उम्मीदें टूट गईं और अलख का खुद पर से भरोसा भी डगमगाया। जेब खर्च के लिए अलख ने प्रयागराज में ही 15 हजार रुपए में कोचिंग पढ़ाना शुरू कर दिया लेकिन उन्हें वहां भी काम छोड़ना पड़ा। इस बीच अलख प्रयागराज में 125 रुपए प्रति लेक्चर के हिसाब से पढ़ाने लगे थे। रिस्पांस अच्छा मिलता देख अलख ने एक छोटे कमरे में खुद ही पढ़ाना शुरू कर दिया था।

शुरुआत: यूट्यूब पर डाले वीडियो, फिर एप भी लॉन्च किया

बेहतर शिक्षा देने के लिए 2016 में अलख ने 'फिजिक्स वाला' नाम से यूट्यूब चैनल शुरू किया। शुरुआत में ज्यादा व्यूज नहीं आते थे। लेकिन अलख दिन-रात लगे रहते थे। उनका पढ़ाने का सरल तरीका युवाओं के बीच धीरे-धीरे लोकप्रिय होने लगा। उनके वीडियोज ने देशभर के लाखों छात्र-छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद की। 2019 में उन्होंने फिजिक्स वाला की वेबसाइट और मोबाइल एप लॉन्च किया, जिससे उनकी पहुंच और बढ़ी।

सफलता : 14 हजार करोड़ की नेटवर्थ, कंपनी भी यूनिकॉर्न में शामिल

2022 में फिजिक्स वाला को 100 मिलियन डॉलर की फंडिंग मिली थी, जिससे इसकी वैल्यूएशन 1.1 बिलियन डॉलर हो गई और कंपनी यूनिकॉर्न में शामिल हो गई। इसके अलावा अलख को 2022 में टाइम्स 40 अंडर 40 की लिस्ट में भी शामिल किया गया था। अलख की नेटवर्थ 14510 करोड़ रुपए है। ▪ 2 मिनट रीड

प्रेरक प्रसंग

सेवाग्राम में सेवा की मूर्ति बने बापू

महात्मा गांधी ने सेवाग्राम का यह नामकरण यों ही नहीं किया था, सच में ही वहां वे सेवा की मूर्ति बन दीन-दुखियों की सेवा किया करते थे। यह प्रेरक प्रसंग इसी भाव को आलोकित करता है।

गांधी जी ने साबरमती के बाद सेवाग्राम में आश्रम बनाया था। यह आश्रम सेगांव में था। गांधी जी के सेगांव पहुंचते ही विदर्भ का यह निर्जन कोना तुरंत ही राष्ट्रीय राजनीति की हलचलों का केंद्र बन गया था।

अगले ही दिन बाबासाहब आम्बेडकर और बालचंद हीराचंद उनसे भेंट करने पहुंचे। फिर नेहरू और पटेल आए। सेगांव में तब डाक-तार व्यवस्था तो क्या, सड़क भी नहीं थी। वायसरॉय ने कहा गांधी जी से बात किए बिना हमारा काम नहीं चल सकता, तब आश्रम में हॉटलाइन लगाई गई। सेगांव में टेलीफोन की घंटियां और गाड़ियों के हॉर्न गूंजने लगे।

एक बार वायसरॉय वहां पहुंचे तो उन्हें सेवाग्राम में खुले में सोने को मजबूर होना पड़ा। समूचे भारत की चिट्ठी-पत्रियों का रुख सेगांव की तरफ हो गया। वर्धा के डाकघर की सक्रियता कई गुना बढ़ गई। लोग चिट्ठी पर केवल 'बापू को मिले' लिखते और पत्र सेवाग्राम पहुंच जाता।

एक बार नेहरू, पटेल और राजेंद्र प्रसाद सेवाग्राम आए। गांधी जी बीमारों की सेवा कर रहे थे। तीनों को प्रतीक्षा करनी पड़ी। पटेल ने कहा, 'बापू अगर आपके पास समय न हो तो हम जाएं?' बापू मुस्कराकर बोले- 'यहां के दीन-दुःखी जन बहुत पीड़ा में हैं।'

मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा...

तब नेहरू जी ने कहा- 'सम्राट कैन्यूट ने समुद्र की लहरों को आदेश दिया था कि रुक जाओ, इससे आगे न बढ़ना। आपका काम भी ऐसा ही है। पर बापू, क्या यह सब आपको ही करना चाहिए? कोई और नहीं है?' बापू बोले- 'बताओ कौन है? गांव जाकर देखो। छह सौ की आबादी में तीन सौ बिस्तरे पर पड़े हैं।' इस समूचे प्रसंग का उल्लेख हरिभाऊ उपाध्याय की पुस्तक 'बापू-कथा' में किया गया है।

▪ 1 मिनट रीड

सीनियर सिटीजन

टेक्नोलॉजी गाइड **अकेले रह रहे बुजुर्गों के लिए** परिवार का हिस्सा बन रही एआई

ये पांच एप और गैजेट्स बनेंगे आपके साथी आपका सुख-दुख बांटेंगे, मनोरंजन भी करेंगे

राजकुमार जैन
एआई एक्सपर्ट

देश में 15 करोड़ आबादी 60 की उम्र पार कर चुकी है। 2050 तक यह 30 करोड़ के पार हो जाएगी। आज लंबी उम्र तो मिल रही है, लेकिन छोटे परिवार, बच्चों का दूसरे शहरों या विदेशों में बस जाना, और तेज रफ्तार लाइफस्टाइल ने बुजुर्गों को अकेला कर दिया है। ऐसे में उनकी जिंदगी आसान कैसे होगी? इसमें एआई बेस्ड एप-गैजेट्स उनके भरोसेमंद साथी बन रहे हैं। जानिए ऐसे पांच एप-गैजेट्स।

रेप्लिका: गाने सुनाएगी, लिखेगी भी

यह एक चैटबॉट एप है। इससे आप हिंदी में बात कर सकते हैं, गाने सुन सकते हैं। स्टोरी-कंटेंट राइटिंग भी कर सकते हैं। 24 घंटे में इसके साथ आप कभी भी बातचीत कर सकते हैं। सुख-दुख के वक्त यह आपके हर सवाल का जवाब देगी।

यहां से डाउनलोड करें: *गूगल प्ले या एपल स्टोर से डाउनलोड करें। फिर अपना अकाउंट बनाएं।*

खर्च: 5800 रुपए सालाना, 1650 रुपए माह।

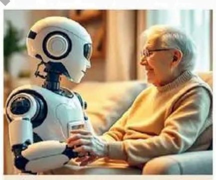

वॉयस असिस्टेंट: आपके काम करेगी

'एलेक्सा, लाइट बंद कर दो।' 'गूगल, मेरे बेटे को कॉल करो।' ये वॉयस असिस्टेंट ऐसे सभी आदेश हिंदी में भी समझ लेते हैं। इसके अलावा अमेजन एलेक्सा व गूगल असिस्टेंट पर आप संगीत भी सुन सकते हैं। हर खबर के बारे में जान सकते हैं।

ऐसे काम करते हैं: *इनके लिए फोन या टाइपिंग की जरूरत नहीं है। सिर्फ आवाज देनी होती है।*

खर्च: 3500 से 20 हजार में ऑनलाइन उपलब्ध।

प्रतिलिपि एफएम: कहानियां सुनें

इसके जरिए एआई आधारित वॉयस इंजन से आप हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, रामचरितमानस, गीता सार जैसी धार्मिक रचनाएं सुन सकते हैं। इसमें पुराने जमाने की कहानियां और किस्से भी उपलब्ध हैं, जिन्हें सुन सकते हैं।

यहां से डाउनलोड करें: *इस एप को गूगल प्ले या एपल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।*

खर्च: फिलहाल इस पर कोई चार्ज नहीं लग रहा।

रोबोट: ये आपसे बातें करते हैं

मित्रा, इलिक्यू, पारो जैसे ह्यूमनॉयड रोबोट इंसानों की तरह आपसे बात करते हैं। गेम्स खेलते हैं। व्यायाम की याद दिलाते हैं। मित्रा तो देश में ही बना है। बाकी विदेशी हैं।

यहां से खरीद सकते: *ये रोबोट ऑनलाइन या बाजार से ले सकते हैं। इनके साथ में उपयोग करने की गाइड भी आती है।*

खर्च: शुरुआती कीमत 15-20 हजार रु. है।

सारेगामा कारवां: 5 हजार गाने सुनें

इस एप की मदद से पुराने दौर के पसंदीदा गाने, अपनी मनपसंद फिल्मों के डायलॉग सुन सकते हैं। इस एप को कारवां डिवाइस से कनेक्ट करना होता है। इसके लिए आपको यह डिवाइस अलग से खरीदनी होगी।

यहां से डाउनलोड करें: *प्ले स्टोर से एप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें 5000 से ज्यादा गाने हैं।*

खर्च: डिवाइस पर 6 हजार रुपए खर्च आएगा।

सप्ताह का स्वास्थ्य मंत्र

आधे घंटे साइकिलिंग संतुलन बेहतर होगा

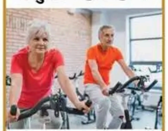

बढ़ती उम्र में इनडोर साइकिलिंग करना आपकी सेहत के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें शरीर को अधिक जोर नहीं लगाना पड़ता। घुटनों, टखनों और कूल्हों पर दबाव कम पड़ता है। वहीं यह शरीर के निचले हिस्से की मांसपेशियों को मजबूत करती है, जिससे बुढ़ापे में चलना-फिरना भी आसान बनता है। इससे शरीर का संतुलन ठीक बना रहता है।

याददाश्त तेज रहती है

अमेरिका की पेंसिलवेनिया यूनिवर्सिटी के अनुसार 30 मिनट इनडोर साइकिलिंग हृदय की क्षमता बढ़ाती है। याददाश्त भी बेहतर होती है। यदि मेडिकल प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर से सलाह लेकर इसे शुरू करें।

आर्थिक साथी **संचय पब्लिक** डिपॉजिट स्कीम

इस स्कीम पर 7% से ज्यादा मिल रहा ब्याज, जरूरत पर लोन की भी सुविधा

अभिलाषा माऊका
बीमा विकास अधिकारी
एलआईसी

वरिष्ठ नागरिकों के लिए एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की संचय पब्लिक डिपॉजिट स्कीम एक सुरक्षित निवेश विकल्प हो सकती है। इसमें 20 हजार से लेकर 20 करोड़ तक निवेश कर सकते हैं। छह अलग-अलग मैच्योरिटी विकल्प मिलते हैं, जिससे सुविधा अनुसार समय अवधि चुन सकते हैं। स्कीम में चक्रवृद्धि ब्याज और बिना चक्रवृद्धि ब्याज दोनों तरह के विकल्प उपलब्ध हैं। साथ ही वक्त से पहले भी पैसा निकाल सकते हैं।

• **75% तक लोन:** वरिष्ठ नागरिकों को 6.95% से लेकर 7.15% तक ब्याज के साथ रिटर्न मिल रहा है। जमा राशि पर 75% तक लोन लेने की सुविधा भी है।

• **निवेश का गणित:** वार्षिक ब्याज के लिए न्यूनतम 20 हजार व मासिक ब्याज के लिए 2 लाख रुपए जमा करना होंगे। इसके बाद हजार और 10 हजार के गुणांक में राशि जमा की जा सकती है।

ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड

पत्नी के निधन से टूटे... जिम से नया जीवन मिला, 83 की उम्र में वृद्धों को दे रहे ट्रेनिंग

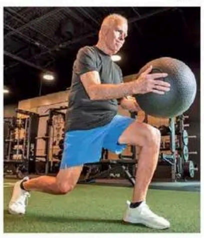

ये हैं अमेरिका के 83 वर्षीय टिम मिनिक। दुनिया के सबसे बुजुर्ग फिटनेस ट्रेनर का खिताब हासिल कर चुके हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज है। वे कहते हैं मैं पत्नी के निधन के बाद भावनात्मक रूप से टूट गया था। नया रास्ता तय करने में कई साल लगे। 65 की उम्र में फिटनेस को जीवनशैली में अपनाना शुरू किया और तब से यह आदत बनी गई।

उम्र का बहाना नहीं, व्यायाम करें

मैं बीमा कंपनी में था। लंबा वक्त डेस्क पर बिताया, लेकिन जिम जाने के बाद डेस्क वर्क, वेट रूम में बदल दिया। अपने आहार में सुधार किया। एक साल में 9% तक फैट घटाया। मेरा अनुभव है हम अक्सर बुढ़ापे में खुद को सीमित कर लेते हैं। ऐसी बातें कहते हैं कि मैं अपनी उम्र की वजह से ऐसा नहीं कर सकता, जबकि मैं इसके उलट हूं, क्योंकि जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है तो व्यायाम सेहत के लिए बहुत जरूरी हो जाता है।

ट्रेनिंग में 90 वर्षीय भी

टिम जिम ट्रेनर होने के साथ बुजुर्गों को व्यायाम भी सिखाते हैं। इसमें 60 से 80-90 वर्ष की आयु के बुजुर्ग भी आते हैं।

मन के रहस्य **मन की प्रकृति ऐसी है कि यदि आप कहते हैं,** 'मुझे यह नहीं चाहिए,' तो आपके मन में वही चलेगा

जैसी स्थिति है वैसी ही समझेंगे तो आप अपना सर्वोत्तम काम कर पाएंगे

सद्गुरु
आध्यात्मिक गुरु और ईशा फाउंडेशन के संस्थापक

दुनिया में बहुत से लोग 'सकारात्मक सोच' के बारे में बात करते रहते हैं। जब आप सकारात्मक सोच कहते हैं, तो एक तरह से आप हकीकत से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। यदि आप दुनिया की नकारात्मक बातों के बारे में नहीं सोचते, तो आप मूर्खों के स्वर्ग में रहेंगे और जीवन इसके लिए आपसे कीमत लेगा। मन की प्रकृति ऐसी है यदि आप कहते हैं, 'मुझे यह नहीं चाहिए,' तो केवल वही आपके मन में चलेगा। यदि आप कहते हैं, 'मुझे नकारात्मक नहीं चाहिए,' तो केवल वही होगा।

यदि सकारात्मक सोच का दृष्टिकोण विकसित करते हैं तो एक स्थिति में अच्छा काम कर सकते हैं

• **सबसे बेहतर करने का सोचिए:** आप सकारात्मक या नकारात्मक की बात ही क्यों कर रहे हैं? हर स्थिति को वैसे ही क्यों न देखें, जैसी वह है। उसे स्वीकार करें और देखें कि आप उसके बारे में सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं? कोई स्थिति न तो सकारात्मक होती है और न ही नकारात्मक। सोच और फिलॉसफी विकसित करने की कोशिश न करें। आप बिना किसी खास सोच या फिलॉसफी के बस जागरूक होकर यहां क्यों नहीं रह सकते?

• **बस आप हमेशा जागरूक होकर रहिए :** अपने रोज के जीवन में सकारात्मक या नकारात्मक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस हमेशा जागरूक रहें। यदि आप जागरूक हैं, तो आप किसी स्थिति को वैसे ही समझेंगे, जैसी वह है, जब आप स्थिति को वैसे ही समझते हैं जैसी वह है,... तो आप अपनी बुद्धिमत्ता और क्षमता के अनुसार सर्वोत्तम काम कर सकते हैं।

• **पूर्वाग्रही सोच से बचिए :** हर स्थिति एक अलग तरह के रिस्पॉन्स की मांग करती है। यदि आप सकारात्मक सोच का दृष्टिकोण विकसित करते हैं, तो वह एक स्थिति में अच्छा काम कर सकता है। लेकिन दूसरी तरह की स्थिति में आप मूर्खतापूर्ण काम करेंगे, क्योंकि आपके पास एक पूर्वाग्रही सोच है कि आपको एक खास तरीके से होना है। यदि आप गलत जगह पर सकारात्मक सोचते रहते हैं, तो आपके साथ सबसे बुरी चीजें हो सकती हैं।

आप अपने ऐसे अनुभव, जो दूसरों के लिए प्रेरणा बनें, srcitizen@dbcorp.in पर भेज सकते हैं। चुनिंदा पत्र प्रकाशित किए जाएंगे।

https://t.me/AllNewsPapersPaid

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। **–वाल्तेयर**

राजस्थान पत्रिका
संस्थापक
कर्पूर चन्द्र कुलिश

सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धि

ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहे भारत के लिए यह बड़ी उपलब्धि कही जाएगी कि वह अब दुनिया का तीसरा सबसे अधिक सौर ऊर्जा पैदा करने वाला देश बन गया है। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रयासों का ही नतीजा है कि अब हमारी सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता 125 गीगावाट पहुंच गई है और सिर्फ अमरीका व चीन ही हमसे आगे हैं। यह उपलब्धि ऐसे दौर में हासिल हुई है जब दुनियाभर में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं जिससे कुल ऊर्जा में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी भी बढ़कर 8.8 फीसदी पहुंच गई है। भारत में तो और भी तेजी से प्रयास हुए हैं, जिससे गत जनवरी से जून के बीच ही सौर ऊर्जा में वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में 25 प्रतिशत ज्यादा हुई है।

कार्बन उत्सर्जन के संकट पर काबू पाने के लिए दुनियाभर में गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा पर न केवल जोर दिया जा रहा है, बल्कि इस दिशा में कहीं ज्यादा और कहीं कम प्रयास भी हुए हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत सदैव पहल करता रहा है। देश में रूफटॉप सौलर पैनल लगाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से शुरू किए गए अभियान ने इन प्रयासों को गति दी है। लेकिन इन प्रयासों के बावजूद देश की कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता में करीब-करीब आधी क्षमता की कोयला और गैस आधारित विद्युत परियोजनाएं हैं। जाहिर है कि अभी इन दोनों पर आधारित बिजली से निर्भरता और कम करने में वक्त लगने वाला है। इसके लिए ज्यादा जरूरत इस बात की है कि आवासीय प्रयोजन से सौर ऊर्जा के अधिकाधिक इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जाए। फिलहाल तो व्यापक क्षमता और सरकार के नीतिगत प्रयासों को बढ़ावा देने के बावजूद घरों में रूफटॉप सोलर का अपेक्षा के अनुरूप विस्तार नहीं हो पा रहा है। कहा जा सकता है कि तकनीक, खर्च, सब्सिडी और मरम्मत आदि को लेकर लोगों की जानकारी अभी सीमित ही है। वहीं इस दिशा में जागरूकता प्रयास भी ज्यादा मजबूती से नहीं हो पाए हैं। इसमें संदेह नहीं कि पिछले सालों में घरेलू उपभोक्ताओं को भी रूफटॉप सोलर लगाने की दिशा में विभिन्न राज्यों के स्तर पर भी प्रयास हुए हैं। इन प्रयासों का ही नतीजा है कि लोगों को यह समझ आने लगा है कि सौर ऊर्जा के इस्तेमाल से न केवल उनके बिजली के बिलों में कमी आएगी, बल्कि पर्यावरण संतुलन की दिशा में भी यह बेहतर कदम होगा। वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एंबर की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2025 की पहली छमाही में सौर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इसी का नतीजा है कि बिजली क्षेत्र से होने वाले कार्बन उत्सर्जन में 24 मिलियन टन की कमी दर्ज की गई है।

जाहिर है, भारत में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व को नया रास्ता दिखाने की अपार क्षमता है। इस क्षेत्र में जिस तेजी से काम कर रहा है, उसमें उम्मीद की जा सकती है कि भारत भविष्य में सौर ऊर्जा में अग्रणी बनकर उभरेगा।

भारतीय न्याय संहिता: भारत एक उत्तरदायी, लोकतांत्रिक और मानवाधिकार-संवेदी प्रणाली की ओर बढ़ रहा है

कानून का नया चेहरा: दंड नहीं, न्याय पर केंद्रित

डॉ. आलोक त्रिपाठी
कुलगुरु, सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय
@patrika.com

भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली का यह कायाकल्प भारत के न्यायिक दर्शन की पुनर्परिभाषा है। यह भारत को एक ऐसे भविष्य की ओर ले जा रहा है, जहां न्याय सिर्फ एक आदर्श नहीं, बल्कि तकनीकी, वैज्ञानिक और मानवीय वास्तविकता होगा।

भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली वर्तमान में एक ऐतिहासिक कायाकल्प के दौर से गुजर रही है। यह केवल कानूनी ढांचे में बदलाव नहीं है, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक ढांचे, नागरिक अधिकारों और तकनीकी प्रगति के समन्वय का एक जीवंत उदाहरण है। एक जुलाई 2025 को देश ने एक नई शुरुआत की, जब भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) को औपचारिक रूप से लागू कर दिया गया। तीनों आधुनिक कानूनों ने लगभग 150 वर्ष पुरानी औपनिवेशिक संहिताओं- भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता व भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली है।

यह परिवर्तन केवल कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली को तकनीक-संचालित, फोरेंसिक-एकीकृत और नागरिक-केंद्रित बनाने की दिशा में एक सशक्त कदम है। नई संहिताएं केवल अपराध की परिभाषा या सजा के निर्धारण तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे इस पूरी प्रक्रिया में वैज्ञानिकता, पारदर्शिता और संवेदनशीलता को लाने का प्रयास करती हैं। भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली की नींव अंग्रेजों ने 19वीं सदी में रखी थी। उस समय के कानून तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप थे, जो औपनिवेशिक शासन की प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित करते थे। आजादी के बाद, यद्यपि समय-समय पर कई संशोधन हुए, परन्तु मूल ढांचा वही बना रहा। परन्तु 21वीं सदी की जटिल चुनौतियों जैसे साइबर अपराध, आतंकवाद, संगठित अपराध, डिजिटल धोखाधड़ी आदि के लिए इस ढांचे में मूलभूत बदलाव की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।

नए कानूनों में, विशेष रूप से भारतीय न्याय संहिता ने अपराधों को फिर से परिभाषित किया है। राजद्रोह और व्याभिचार जैसे उपनिवेशकालीन प्रावधानों को हटाया गया है, जो लंबे समय से विवाद का विषय रहे हैं। इसके स्थान पर राष्ट्रीय सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, महिला सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। यह एक स्पष्ट संकेत है कि भारत अब दमनकारी औपनिवेशिक मानसिकता से निकलकर एक उत्तरदायी, लोकतांत्रिक और मानवाधिकार-संवेदी प्रणाली की ओर बढ़ रहा है।

नए अधिनियमों में तकनीक का जिस तरह से समावेश किया गया है, वह भारत को दुनिया के सबसे उन्नत न्यायिक तंत्रों की पंक्ति में खड़ा कर सकता है। उदाहरण के तौर पर, अब डिजिटल और फोरेंसिक साक्ष्य जैसे डीएनए प्रोफाइलिंग, फिंगरप्रिंट्स, डिजिटल ट्रेस, सीसीटीवी फुटेज, मेटाडेटा और मोबाइल डेटा को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में मान्यता दी गई है। इससे न केवल जांच की सटीकता बढ़ेगी, बल्कि न्याय प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बन सकेगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ई-एफआइआर, जीरो एफआइआर और इलेक्ट्रॉनिक चार्जशीट जैसी व्यवस्थाओं को लागू किया गया है। न्याय प्रक्रिया में फोरेंसिक विज्ञान की भूमिका को पहले कभी इतना महत्त्व नहीं दिया गया था, जितना अब इन नए कानूनों के तहत मिल रहा है। गृह मंत्रालय ने राज्यों के फोरेंसिक ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। अब गंभीर आपराधिक मामलों में आरोप पत्र दाखिल करने से पहले फोरेंसिक जांच अनिवार्य कर दी गई है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि केवल प्रमाण-आधारित, वैज्ञानिक रूप से सत्यापित तथ्यों पर ही आरोप तय हों और निर्दोष व्यक्तियों को झूठे मामलों में फंसाया न जा सके।

डिजिटल युग में जहां एक ओर तकनीक न्याय प्रणाली को सशक्त बना रही है, वहीं दूसरी ओर निजता की चुनौतियां भी सामने हैं। इस सन्दर्भ में 'डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023' को लागू कर यह सुनिश्चित किया गया है कि डिजिटल साक्ष्यों के संग्रहण, विश्लेषण और संरक्षण के दौरान नागरिकों की निजता का उल्लंघन न हो। इसके साथ-साथ गवाह सुरक्षा प्रणाली और डेटा गोपनीयता के उपायों का एक समग्र ढांचा तैयार किया गया है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया केवल तकनीकी रूप से ही नहीं, संवैधानिक रूप से भी मजबूत बन सके। इस पूरे परिवर्तन के केंद्र में नीति निर्माण, शैक्षणिक अनुसंधान और तकनीकी नवाचार का त्रिकोण है। देश के अग्रणी विश्वविद्यालय और शोध संस्थान अब अंतःविषयक अनुसंधान पर बल दे रहे हैं। फोरेंसिक एआइ मॉडल, ड्रोन-आधारित अपराध स्थल पुनर्निर्माण व भविष्यसूचक पुलिसिंग विश्लेषण जैसी उन्नत परियोजनाएं इस बात का प्रमाण हैं कि भारत अब केवल विधायी सुधारों तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यावहारिक नवाचारों की ओर भी गंभीरता से बढ़ रहा है।

भारत की नई न्याय प्रणाली केवल दंड देने वाली नहीं, बल्कि न्याय सुनिश्चित करने वाली बन रही है। इसका उद्देश्य अपराधियों की वैज्ञानिक तरीके से पहचान करना और न्याय प्रक्रिया को नागरिकों के लिए सुलभ, पारदर्शी और संवेदनशील बनाना है। यदि इन कानूनों के प्रति समझ बढ़ाने के लिए अधिकारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाए और तकनीकी अवसंरचना को मजबूत किया जाए तो यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि भारत शीघ्र ही ऐसे देश के रूप में उभरेगा, जहां न्याय प्रणाली न केवल तेज और सटीक होगी, बल्कि मानवीय गरिमा और संवैधानिक मूल्यों की सच्ची संरक्षक भी बनेगी। भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली का यह कायाकल्प भारत के न्यायिक दर्शन की पुनर्परिभाषा है। यह भारत को एक ऐसे भविष्य की ओर ले जा रहा है, जहां न्याय सिर्फ एक आदर्श नहीं, बल्कि तकनीकी, वैज्ञानिक और मानवीय वास्तविकता होगा। भारत आत्मनिर्भर न्याय प्रणाली की दिशा में आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है जो हर नागरिक को विश्वास दिला सके कि न्याय सुलभ है, सुरक्षित है और समयबद्ध है।

नेतृत्व

सहानुभूति से सशक्त होती नेतृत्व क्षमता

यह सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं, विवेक को तीक्ष्ण बनाती है

यदि नेतृत्व की रीढ़ सत्यनिष्ठा है, तो सहानुभूति उसका हृदयस्पंदन है। यह वह शक्ति है, जो नेतृत्वकर्ताओं को विचारों का मार्गदर्शन ही नहीं देती, सभी के हृदय को स्पर्श करने में भी सक्षम बनाती है।

सहानुभूति का अर्थ क्या है?- सहानुभूति का अर्थ अत्यधिक भावुक होना या हर बात में समर्थन देना नहीं है, बल्कि यह वह क्षमता है, जिसमें व्यक्ति यह समझ सके कि दूसरा क्या अनुभव कर रहा है। नेतृत्व करने वाला व्यक्ति केवल कर्मचारियों को नहीं, बल्कि मानवता को देखता है, जिसमें आशाएं, भय, कहानियां व क्षमताएं शामिल हैं।

प्रो. हिमांशु राय
निदेशक
आइआइएम इंदौर
@patrika.com

इससे बनता है विश्वास- जब नेतृत्वकर्ता सहानुभूति अभिव्यक्त करते हैं तो विश्वास स्वयं उत्पन्न होता है। व्यक्तियों को ऐसा लीडर चाहिए, जो उन्हें समझ सके। दूसरों की चुनौतियों को स्वीकार करना और करुणा के साथ प्रतिक्रिया देना, ऐसे माहौल का निर्माण करता है जहां नवाचार, ईमानदारी और सहयोग फलते-फूलते हैं।

यह निर्णय क्षमता को बढ़ाती है- सहानुभूति सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं है, यह विवेक को तीक्ष्ण बनाती है। सहानुभूति नेतृत्वकर्ताओं को प्रदर्शन और कल्याण और उत्पादकता के बीच संतुलन बनाने में मदद करती है।

विविध टीमों को मजबूत बनाती है- आज के कार्यस्थलों में विविधता स्वाभाविक है, पर समावेशन एक चुनाव है और सहानुभूति उसका पुल है। सहानुभूतिपूर्ण लीडर ऐसा वातावरण बनाते हैं, जहां मतभेदों को स्वीकार किया जाता है और प्रत्येक की आवाज सुनी जाती है।

सहानुभूतिपूर्ण नेतृत्वकर्ता कठिन वार्ताओं से नहीं डरते, बल्कि उनमें करुणा के साथ प्रवेश करते हैं। वे लोगों को जिम्मेदारी से बचाते नहीं, बल्कि चुनौती में उनके साथ चलते हैं। यह कमजोरी नहीं अपितु सहानुभूति में नियंत्रित शक्ति है। सहानुभूति नेतृत्व का सहायक अंग नहीं, बल्कि इसकी प्रासंगिकता और मानवीयता का मूल है।

बुक इनसाइट

द जोर्ग: गुलामी के दिनों की कहानी

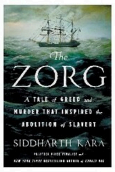

सिद्धार्थ कारा की नई किताब 'द जोर्ग' इतिहास के एक दर्दनाक लेकिन महत्त्वपूर्ण अध्याय को उजागर करती है। यह किताब 19वीं शताब्दी के उस दौर की सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जब गुलामी अपने चरम पर थी और लालच तथा क्रूरता मानवता को शर्मसार कर रही थी।

लेखक ने मूल दस्तावेजों जैसे जहाज के रिकॉर्ड, कानूनी कागजात और समकालीन पत्रों का गहन अध्ययन किया है। इससे कहानी पूरी तरह तथ्य-आधारित लगती है, जो पाठकों को वास्तविक घटनाओं के करीब ले जाती है। कहानी का केंद्र है जोर्ग नामक जहाज, जिस पर दर्जनों अफ्रीकी गुलामों को अमानवीय परिस्थितियों में ले जाया जाता था। यह केवल एक जहाज की कहानी नहीं, बल्कि उस दौर की क्रूर मानसिकता और व्यापारिक लालच का प्रतीक है।

लेखक ने विस्तार से बताया है कि कैसे लालच ने इंसानियत को मार दिया और कैसे एक भयानक हत्या व अत्याचार की घटना ने समाज में दास प्रथा के खिलाफ गुस्से की लहर पैदा की। कारा की लेखनी शोधपूर्ण और असरदार है।

फैक्ट फ्रंट

हनी पॉट एंट: एक अनोखी चींटी

ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी इलाकों में रहने वाली 'हनी पॉट एंट' प्रकृति का एक अनोखा चमत्कार हैं। इनमें से कुछ श्रमिक चींटियां अपने पेट में शहद जैसा मीठा द्रव भरकर जीवित 'स्टोरेज टैंक' बन जाती हैं। यह दृश्य देखने में जितना अजीब लगता है उतना ही यह प्रकृति की बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। ये चींटियां भोजन के अल्प समय में अपने समुदाय की मदद करती हैं, जो 'सामूहिक जिम्मेदारी' का शानदार उदाहरण है। ये खास चींटियां अपने पेट को इतना फुला लेती हैं कि वे हिल तक नहीं सकतीं। जब अन्य चींटियों को भोजन की जरूरत होती है वे इनसे मीठा तरल चूसकर अपनी भूख मिटाती हैं। यह प्रक्रिया इन चींटियों के लिए बलिदान की तरह है क्योंकि वे अपने समुदाय के लिए अपनी गतिशीलता खो देती हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह व्यवस्था रेगिस्तान जैसे कठिन वातावरण में इन चींटियों की जीवित रहने की रणनीति है। इनका पेट इतना लचीला होता है कि वे भारी मात्रा में द्रव स्टोर कर सकता है। ये रासायनिक संकेतों के जरिए अपनी कॉलोनी के साथ संवाद करती हैं।

चिकित्सा | मेडिकल रिसर्च को भी बढ़ावा दिया जाए

डॉक्टरों की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की सेहत खराब

देशभर के सरकारी अस्पतालों की 'सेहत' बिगड़ी हुई है। मरीजों की बढ़ती तादाद और डॉक्टरों के खाली पड़े पद, दोनों मिलकर इस बदहाली के सबसे बड़े कारण बन चुके हैं। शहरों की तुलना में ग्रामीण भारत में हालात कहीं अधिक गंभीर हैं। मेडिकल कॉलेजों की संख्या जरूर बढ़ी है, मगर इसका लाभ आम मरीज तक नहीं पहुंच पा रहा।

डॉ. ईश मुंजाल
सेंट्रल काउंसिल मेंबर, आइएमए, जयपुर ब्रांच
@patrika.com

स्वास्थ्य सेवाओं की नीति या योजना में कमी नहीं है, पर जमीन पर उनका असर दिखाई नहीं देता। सरकारी कोशिशों के बावजूद डॉक्टरों की कमी एक राष्ट्रीय संकट बन चुकी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की भारी कमी हर राज्य में चुनौती बनी हुई है। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण इलाकों में 21,964 विशेषज्ञ डॉक्टरों की आवश्यकता है, जबकि तैनात महज 20% हैं। ऐसे में 80% रिक्तता के साथ स्वास्थ्य सेवाएं कैसे सुधर सकती हैं?

राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्यप्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में सर्जन, फिजीशियन, बाल रोग और स्त्री रोग विशेषज्ञों की भारी कमी है। बड़ा सवाल यह है कि भर्ती क्यों नहीं हो रही? पद खाली क्यों हैं? और जनता इलाज के लिए आखिर करे भी तो क्या? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आइएमए) की 2022 की रिपोर्ट बताती है कि 80% एमबीबीएस स्नातक सरकारी ग्रामीण नौकरी की बजाय निजी क्षेत्र या उच्च शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। इसका मुख्य कारण है- कम वेतन, खराब कार्य-परिस्थिति, पेशेवर विकास के अवसरों की कमी और असुरक्षा का माहौल। सरकारी अस्पतालों में सुधार के बावजूद विशेषज्ञ डॉक्टरों की अनुपलब्धता स्वास्थ्य ढांचे की सबसे बड़ी कमजोरी बनी हुई है। इसे दूर करने के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर भी विचार हुआ, कुछ राज्यों ने प्रयोग किए, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए।

अब वक्त है कि इस दिशा में ठोस और तेज कदम उठाए जाएं। भर्ती प्रक्रिया सरल और समयबद्ध हो, डॉक्टरों की सुरक्षा और वेतन संरचना बेहतर बनाई जाए, और ग्रामीण सेवाओं को प्रोत्साहन मिले। केवल सेमिनार या वर्कशॉप से स्थिति नहीं सुधरेगी- जमीनी स्तर पर बदलाव लाना होगा। कोविड महामारी ने भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर कर दिया था, पर इसके बाद भी कोई बड़ा ढांचागत सुधार नहीं दिखा। रिसर्च और डेवलपमेंट पर कम खर्च हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र को पिछड़ा बना रहा है। अब जरूरी है कि मेडिकल रिसर्च को बढ़ावा दिया जाए, सरकारी अस्पतालों को सशक्त किया जाए और बड़े कॉरपोरेट अस्पताल केवल व्यावसायिक दृष्टिकोण से ऊपर के साथ सामाजिक जिम्मेदारी निभाएं। 'सफेद एप्रन' में भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों को अपने सम्मान को बढ़ाने के लिए सामाजिक कर्तव्यों के प्रति सजग रहना होगा।

सबसे पुराना और आबाद किला विंडसर कैसल

इंग्लैंड के बर्कशायर में स्थित विंडसर कैसल विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा आबाद किला है, जो ब्रिटिश राजशाही की परंपरा का प्रतीक माना जाता है। 11वीं शताब्दी में विलियम द कॉन्करर का बनाया यह किला आज भी राजकीय निवास के रूप में प्रयोग होता है। इसे गॉथिक, जॉर्जियन और विक्टोरियन स्थापत्य शैलियों से संवारा गया है, जिससे यह जीवंत स्थापत्य संग्रहालय बन गया।

हीलिंग | स्वयं से साक्षात्कार यात्रा का कठिन चरण

सच्ची आध्यात्मिकता पलायन नहीं, संलग्नता सिखाती है

आध्यात्मिक जीवन के दो आयाम होते हैं- एक व्यावहारिक और दूसरा अंतर्मुखी। लोग प्रायः इसे शांति, आनंद और मुक्ति का सहज मार्ग मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि यह एक सुखद यात्रा है, जहां दुखों से मुक्ति मिलती है और जीवन हल्का हो जाता है किंतु इस पथ पर धीरे-धीरे निष्ठापूर्वक चलकर समझ आता है कि वास्तविक आध्यात्मिकता न तो आकर्षक है, न सरल। यह साहस, अनुशासन, आत्मपरीक्षण व अपने भीतरी भय, आसक्ति एवं घावों का सामना करने की तैयारी मांगती है।

शिवी दुआ
रेकी एवं थेटा हीलिंग विशेषज्ञ
@patrika.com

यह कठिन है इसलिए नहीं है कि वह दुर्लभ या असंभव है, बल्कि इसलिए कि यह हमारे भ्रमों को तोड़ती है और हमें उस परिवर्तन को स्वीकारने को कहती है, जो जैसा आता है। उसे उसका इच्छुक न होने पर भी वैसा ही मानना पड़ता है।

बहुतों का भ्रम है कि आध्यात्मिकता जीवन के संघर्षों से बच निकलना सिखाती है। बहुत-से लोग चिंता, दुख या अस्थिरता से तुरंत राहत के लिए ध्यान की ओर आकर्षित होते हैं, परंतु सच्ची आध्यात्मिकता पलायन नहीं, संलग्नता सिखाती है। यहां सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार नहीं घटता, बल्कि यह हमें अपने अनुभवों का उत्तरदायित्व लेने और अपनी भावनाओं से साक्षात्कार करने में सहायक बनाती है। यह हमें हमारे भीतर उठने वाले पछतावा, अपराधबोध, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, भय, शोक व अपेक्षाओं जैसे तूफानों से रूबरू कराती है। सच्ची साधना हमें असुविधा के साथ बैठना सिखाती है, उससे भागना नहीं। स्वयं से साक्षात्कार इस यात्रा का सबसे कठिन, लेकिन सबसे रूपांतरकारी चरण होता है। आध्यात्मिक विकास निरंतर ईमानदारी चाहता है। यह हमें अपने मुखौटों और जड़ विश्वासों से परे झांकने को बाध्य करता है और पूछता है-हम कौन हैं और क्यों दुखी हैं? इस प्रक्रिया में हम देख लेते हैं कि जिनसे हम चिपके हैं- पहचान, नियंत्रण और सुरक्षा वे क्षणभंगुर हैं और हमारे दुखों को गहरा व लंबा करने वाले हैं। साधक को अहंकारजन्य इच्छाओं को छोड़कर विनम्रता अपनानी होती है। सच्चा परिवर्तन धीमी जलती हुई अग्नि है, जो धैर्य, अनुशासन और फल की अपेक्षा से रहित निरंतरता की मांग करता है। आध्यात्मिकता कोई कभी-कभार किया गया अभ्यास नहीं है, न ही यह रहस्यमय अनुभवों तक सीमित है। यह तो सजगता और ईमानदारी के साथ प्रतिदिन जीने की कला है।

सच्चा आध्यात्मिक मार्ग यह भी सिखाता है कि हम सब परस्पर जुड़े हैं। जब अहंकार ढीला पड़ता है, तो हम दूसरों को प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि सहयात्री के रूप में देखने लगते हैं। साधक को करुणा और सत्यनिष्ठा से आचरण करना चाहिए- चाहे वह कठिन या गलत समझा जाए। आध्यात्मिकता का अर्थ संबंधों से भागना नहीं, बल्कि उनके माध्यम से स्वयं को पहचानना है। अक्सर हम बाह्य धर्मशीलता को आंतरिक प्रामाणिकता पर वरीयता देते हैं।

आपकी बात

कानून की सख्ती होना जरूरी

रिश्वत लेने वालों के लिए कड़े कानून हों। कानून सख्त होने से सरकारी कर्मचारियों में भय उत्पन्न होगा और वे इस कृत्य से बचेंगे। सिर्फ नियम बनाने से ही नहीं, बल्कि उनका कड़ाई से पालन करने से ही रिश्वततखोरी पर रोक संभव है। **- योगेश स्वामी**, सूरतगढ़

patrika.com पर पढ़ें

पाठकों की अन्य प्रतिक्रियाएं

इसे स्कैन करें

पत्रिकायन का सवाल था, 'लगातार कार्रवाई के बावजूद रिश्वतखोरी के मामले क्यों नहीं रुक पा रहे हैं?' ऑनलाइन भी देखें।
https://shorturl.at/KpPp1

आज का सवाल

युवाओं को नशाखोरी से दूर रखने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

ईमेल करें: edit@epatrika.com

आस्था से अर्थ तक | त्योहार जीवन में संजीवनी का काम करते, इनसे न केवल खरीदारी बढ़ती है, बल्कि रोजगार भी मिलता है

देश की आर्थिक रफ्तार को गति देने में त्योहारों का योगदान

सतीश सिंह
आर्थिक मामलों के जानकार
@patrika.com

भारत के लोग उत्सवधर्मी हैं इसलिए, इसे त्योहारों का देश कहा जाता है। त्योहार जीवन में संजीवनी का काम करते हैं, जो लोगों को हमेशा ऊर्जावान बनाए रखते हैं। दूसरी तरफ त्योहार रोजगार सृजन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाकर देश की आर्थिकी को मजबूत करने का काम भी करते हैं।

हमारे देश में हर साल लाखों-करोड़ों रुपए का कारोबार त्योहारों में किया जाता है। इस साल ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर करीब छह लाख करोड़ रुपए का कारोबार होने का अनुमान है, जिसमें ऑनलाइन पर 1.20 लाख करोड़ रुपए के कारोबार का अनुमान लगाया जा रहा है, जो देश की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.2% है। बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों ने त्योहारों और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में हालिया बदलाव का फायदा उठाना भी शुरू कर दिया है। उन्होंने पहले ही डिस्काउंट ऑफर देने शुरू कर दिए थे। अनुसंधान फर्म 'डेटम इंटेलिजेंस' की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में जीएसटी दरों को आमजन के अनुकूल बनाने से इस साल त्योहारी बिक्री 27% बढ़कर 1.20 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है, क्योंकि टैक्स स्लैब को कम करने से कई जरूरी उत्पादों की कीमत में भारी कमी आई है, जिससे बिक्री में 15% से 20% की बढ़ोतरी होने की आशा है।

नई जीएसटी व्यवस्था में अब सिर्फ 5% और 18% के 2 टैक्स स्लैब रखे गए हैं और कुछ दरों को पूरी तरह से हटा दिया गया है, जिससे ग्राहकों को 10% तक की बचत होने का अनुमान है। नई जीएसटी व्यवस्था में टीवी, एसी, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पर विशेष तौर पर बचत होगी। अनुसंधान फर्म की रिपोर्ट के मुताबिक विगत तीन वर्षों में पहली बार शहरी उपभोक्ताओं के खर्च में वृद्धि देखी गई है। सिर्फ जुलाई महीने में 37.6% उपभोक्ताओं ने अपने गैर-जरूरी खर्च में वृद्धि की है।

त्योहार में कारोबार

4.80 लाख करोड़ रुपए का ऑफलाइन कारोबार होने का अनुमान इस वर्ष त्योहारी सीजन के दौरान।

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) की रिपोर्ट के अनुसार

इस मामले में ग्रामीण और भी आगे हैं। उन्होंने इस मद में अपने खर्च को 54.7% बढ़ाया है, जो विगत 2 वर्षों में सबसे अधिक है। ये आंकड़े यह भी बता रहे हैं कि हाल के महीनों में लोगों की आय में भी वृद्धि हुई है, जिसके कारण लोग बचत भी कर रहे हैं और खर्च भी और इसी वजह से ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई है, जिससे समावेशी विकास को मजबूती मिल रही है।

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने बीते महीने एक सर्वे करवाया था, जिसके अनुसार इस साल सिर्फ रक्षा बंधन, गणेश पूजा, नवरात्रि और दिवाली के दौरान लगभग 4.80 लाख करोड़ रुपए के ऑफलाइन कारोबार होने का अनुमान है। गौरतलब है कि पिछले साल यह आंकड़ा करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए का था। इस तरह, इस साल ऑफलाइन कारोबार में पिछले साल के मुकाबले 27% वृद्धि होने का अनुमान है। हालांकि, इस साल रक्षाबंधन में लोगों के खर्च में पिछले साल के मुकाबले 75 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई है। एक अनुमान के अनुसार त्योहार के दौरान देश के लगभग 70 करोड़ ग्राहक अपनी क्षमता के अनुसार खरीदारी करते हैं। त्योहारों में कई तरह के उत्पादों की मांग और आपूर्ति में उल्लेखनीय इजाफा होता है। उदाहरण के तौर पर दीपावली में जब लोग घर की सफाई, मरम्मत और रंग-रोगन करते हैं तो हार्डवेयर के सामान, पेंट, कलर, आदि की खरीद-फरोख्त बढ़ जाती है। इस समय बड़ी संख्या में विदेशों से पर्यटक हमारे देश आते हैं। इनकी संख्या में पिछले साल के मुकाबले 67% की वृद्धि हुई।

कहा जा सकता है कि भारत में त्योहारों का महत्त्व अतुलनीय है। ये सिर्फ लोगों की आस्था से ही नहीं जुड़े हुए हैं, बल्कि लोगों को रोजगार मुहैया कराने और खर्च और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने का भी काम करते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 18 अंक 203

साझेदारी का निर्माण

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टार्मर की हालिया भारत यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आपसी रिश्तों में हुए हाल में आई गर्मजोशी को आगे बढ़ाना था। इससे पहले गत जुलाई में दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते (सीईटीए) पर हस्ताक्षर हुए थे। स्टार्मर के साथ यूके के कारोबारियों का अब तक का सबसे बड़ा प्रतिनिधिमंडल भारत आया था। ब्रिटिश सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि इस यात्रा के दौरान भारतीय कंपनियों द्वारा ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में करीब 1.3 अरब पाउंड के निवेश का वादा किया गया है। इसमें टीवीएस मोटर्स द्वारा इंगलैंड के उत्तरी हिस्से में विनिर्माण सुविधाओं के विस्तार की योजना भी शामिल है।

टीवीएस मोटर ने 2020 में ब्रिटिश कंपनी नॉर्टन मोटरसाइकल का अधिग्रहण किया था। इस बीच भारत को उम्मीद है कि नई संयुक्त परियोजनाओं की बदौलत उसे उन्नत नवाचार तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी। व्यापार सौदा भी भारतीय कंपनियों के लिए नए बाजार खोल सकता है। इसमें छोटे बाजार भी शामिल हैं। उदाहरण के लिए रत्न एवं आभूषण क्षेत्र जिसके अमेरिकी व्यापार नीतियों से सबसे अधिक प्रभावित होने की आशंका है, उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में वह यूके को अपना निर्यात दोगुना कर सकता है।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने मुंबई में एक फिनटेक सम्मेलन को संबोधित किया। यह इस बात का संकेत है कि दोनों देशों के वित्तीय और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के बीच करीबी रिश्ते देखने को मिल सकते हैं। ब्रिटेन राजकोषीय मोर्चे पर दिक्कतों से जूझ रहा है और उसकी घरेलू अर्थव्यवस्था की लागत भी अधिक है। खासतौर पर बायोटेक और फिनटेक क्षेत्रों के साथ ऐसा है। इन क्षमताओं का प्रतिबिंब उन सहयोग योजनाओं की प्रकृति में दिखाई देता है, जिनका उद्देश्य भारत में जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद द्वारा संचालित संस्थानों तथा भारतीय विज्ञान संस्थान की सुविधाओं को उन्नत करना है। कुछ ऐसी बातें जो अतीत में भारत की प्राथमिकता रही हैं अब उन पर जोर नहीं दिया जा रहा है। उदाहरण के लिए लगता नहीं है कि भारतीयों को वर्क वीजा का मुद्दा बातचीत में दोबारा उभरेगा। इसके पीछे घरेलू राजनीतिक हालात को जिम्मेदार माना जा सकता है। ब्रिटेन पहुंचने वाले भारतीयों की संख्या पहले ही लगातार बढ़ रही है। 2021 से 2024 के बीच 8.50 लाख प्रवासी भारतीय वहां पहुंचे। इसके बजाय भारतीय और ब्रिटिश सरकारों ने अवैध प्रवासियों की वापसी को लेकर करीबी सहयोग पर सहमति जताई है।

हालांकि सीईटीए के उचित क्रियान्वयन को अंजाम देने के लिए अभी भी काफी कुछ करना बाकी है ताकि भारत की सूक्ष्म, लघु और मझोली कंपनियों सहित सभी कंपनियां इससे लाभान्वित हो सकें। पेशेवरों के लिए परस्पर मान्यता वाले समझौतों को अंतिम रूप देना जरूरी है। यह आसान नहीं होगा क्योंकि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं सेवा आधारित हैं। व्यापार में ई-गवर्नेंस और नियामक सहयोग पर किए गए वादों को पूरा करना भी आवश्यक होगा। ऐसा करके व्यापार समझौते का पूरा लाभ उठाया जा सकता है। सुरक्षा के क्षेत्र में भी आगे काम करने की जरूरत है। भारतीय नौसेना और रॉयल नेवी पहले भी संयुक्त अभ्यास कर चुके हैं। परंतु हिंद महासागर के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। खासतौर पर फ्रांस के साथ त्रिपक्षीय प्रारूप में ऐसा किया जा सकता है।

ब्रिटेन ने बहरीन में अपने नौसैनिक अड्डे में निवेश बढ़ाया है तथा उम्मीद की जा रही है कि वे भारतीय नौसेना के सहयोग और समर्थन में समुद्री डकैती रोकने संबंधी निगरानी और अभियानों को और अधिक प्रभावी रूप से अंजाम दे सकेंगे। भारत-यूके साझेदारी भारत के नजरिये से सबसे कम तनावपूर्ण और सबसे अधिक पारदर्शी साझेदारियों में से एक बनी हुई है और इसके आर्थिक और सुरक्षा क्षेत्रों में और अधिक विस्तार की पर्याप्त संभावनाएं मौजूद हैं।

मुख्य न्यायाधीश, आईपीएस, आईएएस और होमबाउंड

शिक्षा, आरक्षण और सरकारी नौकरियों से उम्मीद की जाती है कि ये समता और गरिमा लाएंगे। देश के मुख्य न्यायाधीश की ओर जूता फेंका जाना बताता है कि अभी हम इसे हासिल करने से कोसों दूर हैं।

राष्ट्र की बात
शेखर गुप्ता

पिछले दिनों तीन कारकों के एक साथ आने से जाति और अल्पसंख्यकों से जुड़ी ऐसी समस्याओं का एक मिश्रण हमारे सामने आया है जिन्हें देश संविधान निर्माण के 75 वर्ष बाद भी सुलझा पाने में नाकाम रहा है। जाति की समस्या तो हमारे यहां सदियों से व्याप्त है।

तीन घटनाएं सामने आई हैं: देश के दलित मुख्य न्यायाधीश पर उनकी ही अदालत में जूता फेंका जाना, हरियाणा में एक वरिष्ठ दलित आईपीएस अधिकारी द्वारा आत्महत्या करना और सुसाइड लेटर में वर्षों तक भेदभाव, उत्पीड़न और वर्षों की पीड़ा का जिक्र और तीसरा बॉलीवुड के सबसे प्रमुख और प्रभावशाली दलित फिल्मकार नीरज घेवान की फिल्म 'होमबाउंड' की कामयाबी।

यह फिल्म प्रतिद्वंद्वी सैयारा, पठान, जवान, एनिमल, बाहुबली या कांतारा की तुलना में बड़ी हिट नहीं है। इस फिल्म को लेकर पीआर इंटरव्यू, प्रायोजित समीक्षाएं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल नहीं नजर आया। इसमें बड़े सितारे भी नहीं थे। इसे मनोरंजक भी नहीं कहा जा सकता है। यह फिल्म 100 करोड़ रुपये की ओपनिंग को ध्यान में रखकर नहीं तैयार की गई थी।

इसके बावजूद बहुत धीमी शुरुआत के बाद भी इसने केवल लोगों की आपसी प्रशंसा की बदौलत अपनी पकड़ बनाई। ऐसा करने वालों में ऊपरी श्रेणी के पेशेवर और युवा उद्यमी आदि शामिल थे। कह सकते हैं कि ऐसे लोग जिनकी आय सात या आठ अंकों में है। यानी सामाजिक-आर्थिक प्रभावशाली वर्ग। इसका प्रमाण उन छोटे लेकिन सबसे महंगे मल्टीप्लेक्स हॉल से मिलता है जो महानगरों में पूरी तरह भरे चल रहे हैं। इन सामाजिक चर्चाओं से जो बात सामने आती है, वह यह नहीं है कि फिल्म उबाऊ थी, अतिशयोक्तिपूर्ण थी, बहुत अधिक राजनीतिक थी, या वह सामान्य बात जो हम अक्सर सुनते हैं- 'यह बात एकदम साफ है कि आरक्षण के 75 सालों ने असमानता को समाप्त नहीं किया है।' तो फिर 'हम' और क्या कर सकते हैं? बेहतर होगा कि 'उन्हें' अच्छी शिक्षा और सुविधाएं तथा प्रतिस्पर्धा करने का अवसर दिया जाए। परंतु यह मिशन 'हम' और 'वे' के विभाजन पर ही समाप्त हो जाता है।

इसके विपरीत होमबाउंड देखने वाले दर्शकों में आप तीन युवा और गरीब ग्रामीण भारतीयों के संघर्षों के प्रति समानुभूति को देख सकते हैं। इनमें शिक्षा है, समझ है और आगे बढ़ने की आकांक्षा भी है। दर्शकों ने यह भी स्वीकार किया कि व्यवस्था उन्हें हर बार नाकाम करने के लिए ही बनी थी। तो अब हम क्या करें? संदर्भ के लिए, ये तीन युवा भारत की जनसंख्या के एक-तिहाई से अधिक हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी दलित और मुस्लिम समुदाय।

शिक्षा, आरक्षण और सरकारी नौकरी की मदद से समानता और गरिमा हासिल होनी थी। मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने की घटना दिखाती है कि हम अभी भी इससे कोसों दूर हैं। इससे भी दुखद है हरियाण पुलिस के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) वाई पूरन कुमार की आत्महत्या। उनकी पत्नी और 2001 बैच की आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार भी दलित हैं। उन्होंने राज्य के डीजीपी और जिले के एसपी के विरुद्ध अपने पति के उत्पीड़न की एफआईआर दर्ज कराई है। तो आज हम यहां खड़े हैं। अगर एक मुख्य न्यायाधीश, एक आईपीएस और एक आईएएस अधिकारी की गरिमा सुरक्षित नहीं, उन्हें समानता हासिल नहीं तो यह दिखाता है कि हमारी व्यवस्था में अन्याय और पूर्वग्रह बहुत गहरे तक घर कर चुके हैं और 75 साल का आरक्षण भी इन्हें दूर नहीं कर सका है।

होमबाउंड के तीन युवा मित्र चंदन कुमार (वाल्मीकि), मोहम्मद शोएब अली और सुधा भारती (एक और दलित) जिनकी भूमिका क्रमशः विशाल जेठवा, ईशान खट्टर और जाह्नवी कपूर ने निभाई है, वे पुलिस कॉन्स्टेबल बनने की तैयारी कर रहे हैं। इसे देखते हुए मुझे 1985 में बाबू जगजीवन राम से हुई एक बातचीत याद आई। मंडल आयोग की रिपोर्ट चर्चा का विषय बन गई थी और मैं इंडिया टुडे के लिए उच्चवर्ग की जातियों के पहले आंदोलन को कवर कर रहा था। जगजीवन राम उस समय सत्ता से बाहर थे और उनके पास समय था। उन्होंने आरक्षण को सटीक ढंग से समझाया। उन्होंने एक पुराने दोस्त की बात की जो अनुसूचित जाति (उस समय कोई दलित नहीं कहता था) से आता था। उनका मित्र आगरा का जूतों का कारोबारी था और बड़े पैमाने पर निर्यात करता था। उसका एक बेहतरीन घर था, एक विदेशी कार और लाखों रुपये की जमापूंजी उसके पास थी। इसके बावजूद वह बाबूजी से याचना कर रहा था कि उसके बेटे को उत्तर प्रदेश पुलिस में सहायक पुलिस निरीक्षक (एएसआई) के रूप में नौकरी दे दी जाए। बाबूजी ने उससे पूछा, 'तुम्हारे पास इतनी संपत्ति है, तुम अपने बेटे को एएसआई क्यों बनवाना चाहते हो?' उसने जवाब दिया, 'हम चाहे जितने अमीर हो जाएं, एक ब्राह्मण कभी भी मुझसे या मेरे बेटे से इज्जत से बात नहीं करेगा। लेकिन अगर मेरा बेटा एएसआई बन जाता है तो ब्राह्मणों सहित सभी जूनियर उसे सलाम करेंगे। इस तरह आरक्षण समानता और ताकत देता है।'

होमबाउंड में तस्वीर कुछ अधिक जटिल है क्योंकि चंदन सामान्य श्रेणी में प्रतिस्पर्धा करने पर जोर देता है। वह कहता है कि अगर वह अपनी जाति यानी वाल्मीकि का खुलासा कर देगा तो पुलिस सेवा में भी उसे साफ-सफाई के काम तक सीमित कर दिया जाएगा। सुधा स्नातक की पढ़ाई करके यूपीएससी निकालना चाहती है। शोएब चतुर है और एक कंपनी में चपरासी की नौकरी के बावजूद वह सामान बिकवाने में टाई वाले मैनेजरों तक को पीछे छोड़ देता है। उसका बॉस उसके काम से चकित है और कुछ भी बेच देने की उसकी काबिलियत के चलते उसे बेचू कहकर बुलाता है। वह भी एक टाई वाला मैनेजर बनने की ओर अग्रसर है कि तभी बॉस के घर में एक पार्टी में नशे में धुत कुछ लोग क्रिकेट मैच देखते समय उसे अपमानित करते हैं। वह भी जीत की खुशी मना रहा होता है लेकिन उससे कहा जाता है कि उसका दिल टूट गया होगा क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया।

दलित और मुस्लिम दोनों को उनके पूर्वजों के अतीत के नीचे अलग-अलग ढंग से कुचला जाता है। दलितों को इसलिए क्योंकि उन्होंने पीढ़ीगत अन्याय को झेलना पड़ता है जिसके लिए उनके दमनकारियों को खुद में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। मुस्लिमों को इसलिए क्योंकि वे किसी न किसी तरह अपने मुगल, अफगान, तुर्क पूर्वजों और यहां तक कि जिन्ना द्वारा हिंदुओं पर की गई अतियों की कीमत चुकाते हैं। यही बातें चंदन, शोएब और सुधा के साथ-साथ एक तिहाई भारत की राह का रोड़ा हैं।

मोदी सरकार की कल्याण योजनाएं, प्रत्यक्ष नकदी हस्तांतरण योजनाएं किसी के साथ पहचान के आधार पर भेदभाव नहीं करतीं। सबसे महत्त्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाएं, खासकर- यूपीएससी निष्पक्ष हैं और अच्छी खासी तादाद में मुस्लिम उसमें कामयाबी हासिल करते हैं। मुस्लिम पहले ही शीर्ष राजनीतिक, संवैधानिक या अफसरशाही पदों से बाहर हैं और सरकार के बाहर भी उनके लिए चुनौतियां हैं।

उन्हें अलगाव का सामना करना पड़ता है (शोएब से बार-बार पुलिस जांच के लिए पूछा जाता है, माता-पिता का आधार कार्ड मांगा जाता है) और किराये पर घर मिलने में समस्या आम है। मुस्लिमों से जुड़े कारोबारों पर भी सोचा समझा हमला किया जाता है। उदाहरण के लिए मांस के व्यापार पर त्योहारों के दौरान मनमाने ढंग से हफ्तों और पखवाड़ों तक का प्रतिबंध लगा दिया जाता है, चमड़े के कारोबार, कसाईखाने के साथ ऐसा ही होता है। आपने ध्यान दिया होगा कि कैसे ऐप आधारित डिलिवरी, उबर आदि सेवाओं में बड़ी संख्या में मुस्लिम युवा नजर आते हैं, वे ऐप आधारित मरम्मत या रखरखाव सेवाओं में भी काम करते दिखते हैं। सोशल मीडिया पर पहले ही ऐसा माहौल बना दिया गया है कि मानो वे आपके परिवार के लिए खतरा हों। 'लव जिहाद' और धर्मांतरण या अन्य जघन्य अपराधों के साथ भी उनका नाम जोड़ दिया जाता है।

अच्छी बात यह है कि जैसा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने विज्ञान भवन में गत माह कहा भी था कि भारतीय मुस्लिम अपनी नकारात्मक छवि को बदल रहे हैं। अब वे कितने बच्चे पैदा करते हैं? भागवत ने कहा कि पहले हिंदुओं की जन्म दर में कमी आई और उसके बाद मुस्लिमों की जन्म दर में कमी आ रही है। भारतीय मुस्लिमों ने पाकिस्तान के मुस्लिमों के उलट आधुनिक शिक्षा को अपनाया है, जबकि पाकिस्तानी मानते हैं कि उनका राष्ट्रवाद सर सैयद अहमद खां और अल्लामा इकबाल से प्रेरित है। इसके बावजूद अगर पढ़े-लिखे मुस्लिम अपने ही 'घेटो' में रहने को विवश हों तो यह बहुत दुखद है। इससे विकसित भारत बनाने में मदद नहीं मिलेगी।

यह कोई फिल्म समीक्षा नहीं है। यह जरूर है कि इस वर्ष भारत ने इसे ऑस्कर में अपनी प्रविष्टि के रूप में चुना है। इस फिल्म ने जनसंख्या के उस हिस्से को छुआ है जिसे हम अक्सर उग्र मानते हैं। संयोग से यह वास्तविक जीवन की दो कहानियों से मेल खाती है जिनमें भुक्तभोगी (यह शब्द मैं भारी मन से इस्तेमाल कर रहा हूं) वे हैं जिन्हें भारत एक नागरिक होने के नाते सबसे विशेषाधिकार प्राप्त पदों की पेशकश कर सकता है। मैं आपको भारत के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन की नियुक्ति के दिन ही किए गए उनके अपमान की याद दिलाना चाहूंगा। इस प्रवृत्ति की हम अनदेखी नहीं कर सकते, खासकर तब जब यह हर तीन में से एक भारतीय को प्रभावित करता हो।

ट्रंप टैरिफ के बीच एमएसएमई क्षेत्र को बदलने का शानदार मौका

तुलसी जयकुमार

हाल ही में भारत के प्रमुख निर्यात क्षेत्रों विशेष रूप से कपड़ा, समुद्री खाद्य और रत्न व आभूषण को निशाना बनाने वाले 50 फीसदी 'ट्रंप टैरिफ' (अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप द्वारा घोषित आयात शुल्क) ने देश के कई क्षेत्रों में चिंता पैदा कर दी है। सूरत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) पर वित्तीय दबाव की स्थिति बन रही है, जहां 80 फीसदी हीरा-निर्यात इकाइयां केंद्रित हैं, वहीं दूसरी ओर तिरुपुर में परिधान निर्यातकों को कुल मिलाकर 61 फीसदी से अधिक के शुल्क का सामना करना पड़ रहा है जिससे एक वास्तविक संकट की स्थिति बन रही है। आशंका यह है कि ये आयात शुल्क (टैरिफ) उन क्षेत्रों को प्रभावित कर सकते हैं जो भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात का करीब 25 फीसदी हिस्सा है। यह टैरिफ उन कंपनियों के लिए खतरा है जिनकी मार्जिन और कीमतें तय करने की ताकत सीमित है।

हालांकि, इस तत्कालिक संकट को एमएसएमई तंत्र की व्यापक क्षमता के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। इनकी क्षमता का अभी पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हो सका है। पिछले चार वर्षों में सराहनीय तीन गुना वृद्धि के बावजूद, निर्यात करने वाले एमएसएमई की संख्या पिछले साल मई में महज 1,73,350 थी। हालांकि 7.3 करोड़ एमएसएमई के मजबूत आधार के मुकाबले देखने पर, यह आंकड़ा मात्र 0.23 फीसदी का प्रतिनिधित्व करता है। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो जो उद्यम भारत से लगभग आधे निर्यात (45.79 फीसदी) के लिए उत्पादन कर रहे हैं वे एमएसएमई आधार के चौथाई फीसदी से भी कम हैं।

भारत में एमएसएमई का अधिकांश हिस्सा सूक्ष्म उद्यमों का है और इनमें से कई अनौपचारिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उनके कारोबार का दायरा भी बड़ा नहीं है और न ही जरूरी तकनीक उनके पास है। इसके अलावा उनकी संरचना भी ऐसी नहीं है कि वे अहम क्षेत्रों में वैश्विक वैल्यू श्रृंखला (जीवीसी) की मांग को पूरा कर सकें जिनमें जटिल अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन का पालन करना शामिल है। इसके अलावा आधुनिक इन्वेंट्री प्रबंधन मॉडल जैसे कि 'जस्ट इन टाइम (जेआईटी) और लीन मैन्युफैक्चरिंग' को लागू करने की क्षमता भी होनी चाहिए जिसके लिए डिजिटल तकनीक और भरोसेमंद लॉजिस्टिक्स की जरूरत होती है। साथ ही इंडस्ट्री 4.0 टूल के साथ जुड़ना भी अहम है। भारत के लिए बड़ा अवसर तभी बन पाएगा जब एक व्यापक, निष्क्रिय आधार को एक औपचारिक, जीवीसी के लिए तैयार आपूर्तिकर्ता पूल में बदला जा सके। इस अवसर का फायदा उठाने के लिए, सामान्य कल्याणकारी उपायों से हटकर लक्षित, क्रियान्वयन पर केंद्रित हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इसके अलावा पूंजी तक पहुंच भी सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। इस क्षेत्र को 30 लाख करोड़ रुपये तक के अनुमानित ऋण मांग-आपूर्ति की खाई का सामना करना पड़ता है।

जीवीसी में शामिल होने के लिए नए निवेश की जरूरत है विशेषरूप से तकनीक को बेहतर बनाने के लिए। इनमें नई मशीने खरीदने, प्रमाणन से जुड़े अनुपालन करने और डिजिटल साधन का इस्तेमाल करने के लिए पैसे की जरूरत होगी। सरकार को ऐसे फिनटेक समाधान को बढ़ावा देना चाहिए जो पुराने तरीकों से हटकर जीएसटी/उद्यम डेटा का इस्तेमाल कर आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) से क्रेडिट स्कोरिंग करे। इससे निर्यात के ऑर्डर के लिए कार्यशील पूंजी की जरूरतें पूरी हो सकेंगी। इसके साथ ही क्लस्टर फाइनैंसिंग की व्यवस्था भी मददगार साबित होगी।

इसके अलावा भले ही भारत में लॉजिस्टिक्स की लागत का मौटे तौर पर अनुमान अब सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 7.97 फीसदी है लेकिन अब गहराई में जाना जरूरी है। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग और राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुंसधान परिषद की हाल की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि छोटे उद्योग की लॉजिस्टिक्स लागत उनके उत्पादन का 16.9 फीसदी तक है जबकि बड़े उद्योग के लिए यह लागत 7.6 फीसदी है। इस अंतर के कारण छोटे उद्योग जल्द ही मुकाबले से बाहर हो जाते हैं।

पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय योजना को और तेजी से लागू करना होगा ताकि मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाए जा सकें। इन पार्कों में साझा भंडारगृह की सुविधा होगी और सामान को नजदीक और सुदूर इलाकों तक पहुंचाने का इंतजाम बेहतर होगा। इससे लागत घटेगी और छोटे कारोबारियों पर बोझ कम होगा। एमएसएमई के माल के लिए यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल जरूरी करने से भी मदद मिलेगी।

कुशल कर्मचारियों के बिना कोई भी तकनीक बेकार है। भारत को जल्द से जल्द ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शुरुआत करनी होगी जिनमें जीवीसी से जुड़े जरूरी कौशल की जानकारी दी जाए, जैसे कि गुणवत्ता की जांच करना, डिजिटल परिचालन, मशीनों का रख-रखाव और आपूर्ति श्रृंखला का प्रबंधन। इसके साथ ही, विनिर्माण के क्षेत्र में साझा जांच केंद्र और प्रमाणपत्र देने वाले केंद्र भी खोलने होंगे। इन केंद्रों से छोटे कारोबारों को नियमों का पालन करने का खर्च कम करने में मदद मिलेगी और खरीदारों का भरोसा बढ़ेगा। दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं अपनी आपूर्ति श्रृंखला में विविधता ला रही हैं। टैरिफ और व्यापार में बदलाव से भारत को अपने एमएसएमई क्षेत्र को बदलने का शानदार मौका मिला है। लेकिन, ये मौका ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा। अगर भारत ने अपने 99.76 फीसदी एमएसएमई को सशक्त बनाने के लिए जल्दी और सही कदम नहीं उठाए तो वियतनाम, मेक्सिको या इंडोनेशिया जैसे देश इस मौके को छीन लेंगे। दुनिया का विनिर्माण केंद्र बनने के लिए सिर्फ इरादा नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत, ध्यान और बड़े पैमाने पर काम करना जरूरी है।

(लेखिका एसपीजेआईएमआर के सेंटर फॉर फैमिली बिजनेस ऐंड आंत्रप्रेन्योरशिप की कार्यकारी निदेशक और प्रोफेसर (अर्थशास्त्र) हैं। ये उनके निजी विचार हैं)

आपका पक्ष

त्योहार के समय मिलावटी चीजों से रहें सावधान

पर्व-त्योहार के समय ऐसे कुछ लोग हैं जो अधिक मुनाफा कमाने के लिए खाने-पीने की चीजों में मिलावट करके दूसरों की जान को जोखिम में डाल देते हैं। खाने-पीने की मिलावटी चीजें जहर समान होती है। स्वस्थ भारत के लिए खानपान की चीजों में मिलावट रोकना बहुत जरूरी है। खाद्य पदार्थों में मिलावट इस कारण नहीं रुक रही, क्योंकि अव्वल तो लोग सरकार द्वारा बनाए गए उपभोक्ता संरक्षण के कानून के प्रति जागरूक नहीं हैं। दूसरे, सरकार और प्रशासन मिलावट रोकने के लिए काफी गंभीर नहीं दिखते हैं तथा तीसरा कारक सरकारी तंत्र में फैला भ्रष्टाचार है जिसके कारण खाद्य पदार्थों की जांच समय-समय पर नहीं होती है। सरकार और प्रशासन को भी लोगों की सेहत की सुरक्षा के लिए गंभीरता दिखानी चाहिए। बाजार में बिकने वाली चीजों की समय-समय पर जांच करनी चाहिए। सरकार लोगों को मिलावटी चीजों, घटिया गुणवत्ता और चीजों से बचने के लिए जागरूकता अभियान चलाने और हेल्पलाइन नंबर भी समय-समय जारी करती हैं। लेकिन जब तक लोग किसी वस्तु या खाने-पीने की चीजों की गुणवता पर ध्यान नही देंगे और किसी गड़बड़ी की शिकायत उपभोक्ता न्यायालय में नहीं करेंगे तब तक जागरूकता अभियान कामयाब नहीं हो सकते हैं।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

त्योहारों पर अक्सर नकली मावा से बनी मिठाइयां भी बिकती हैं

राज्य स्तर पर वित्तीय अनुशासन आवश्यक

लेख 'अर्थव्यवस्था में केवल लचीलापन ही काफी नहीं' बहुत सार्थक संवाद करता है। देश की अर्थव्यवस्था में लचीलापन ही कठिन वैश्विक परिस्थितियों और कोरोना महामारी के दौरान में सतत आर्थिक वृद्धि दर को सात प्रतिशत के आसपास स्थापित करने में सफल हुआ है। विश्व भर में विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं और राजनीतिक संरचनाओं में भारी अंतर है, उनकी आवश्यकताओं और भौगोलिक परिस्थितियों में भी बहुत अंतर है। इसलिए भारत का वैश्विक व्यापार सभी देशों के लिए अनुकूलता से सामंजस्य स्थापित करता है। इसका प्रमुख कारण है कि विश्व के कोने-कोने में भारतीय एक प्रभावशाली समुदाय है जो उन देशों के उद्योग व्यापार में भी साझेदार है। इसके साथ ही टेक्नॉलजी भी प्रमुखता से भारत के वैश्विक व्यापार को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। वहीं वित्तीय प्रबंधन और संसाधन जुटाने में राज्य सरकारों में अनुशासन आवश्यक है। राज्य सरकारें जीएसटी एवं अन्य कर संग्रहण और केंद्र के अनुदानों पर निर्भर हैं और राज्य के स्तर पर अतिरिक्त संसाधन जुटाने में कोई सार्थक प्रयास नहीं है। यहां तक कि इतनी विशाल सांस्कृतिक धरोहरों के बावजूद हाल में अयोध्या के अतिरिक्त नए पर्यटन केंद्र सृजित नहीं हुए हैं। गुजरात के अलावा कोई नये उद्योग क्षेत्र और स्पेशल इकॉनमिक जोन (एसईजेड) स्थापित करने के प्रयास भी नहीं दिखाई दे रहे। पूंजीगत खर्च में भी राज्य सरकारों के स्तर पर अनुशासन और निगरानी की आवश्यकता है। राज्य सरकारें भी आर्थिक समृद्धि और अपने विकास दर को देश की आर्थिक वृद्धि के समानांतर बढ़ाएं।

विनोद जौहरी, दिल्ली

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

दिल्ली में रविवार को आयोजित हाफ मैराथन में केन्या के लंबी दूरी के धावक एलेक्स मटाटा और लिलियन कासैट रेंगरुक ने क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग की इलीट दौड़ जीतीं। हाफ मैराथन, ओपन 10के, 'चैंपियंस विद डिसेबिलिटी रन', 'सीनियर सिटीजन रन' और 'ग्रेट दिल्ली रन' सहित विभिन्न श्रेणियों में 40,000 से अधिक धावकों ने दिल्ली की सड़कों पर दौड़ लगाई।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

दैनिक इबादत
सम्पादकीय

सोशल मीडिया बनाम सरकार

विश्व आज डिजिटल क्रांति के दौर से गुजर रहा है। मोबाइल और इंटरनेट अब हर हाथ में है और सोशल मीडिया और आर्टीफिसियल एंटेलीजेंस का प्रयोग मन और मस्तिष्क व दोनों को प्रभावित कर रहा है। सोशल मीडिया युवाओं के लिए जहां विचार साझा करने और सीखने का अवसर देता है, वहीं इसका अंधाधुंध और गलत इस्तेमाल गंभीर खतरा बनता जा रहा है। गलत सूचनाएं, उकसाने वाले संदेश और डिजिटल लत, युवाओं को हिंसा, नैतिक पतन और भ्रमित विचारधाराओं की ओर धकेल रहे हैं। यह खतरा केवल भारत तक सीमित नहीं, बल्कि वैश्विक बन चुका है। दुनिया के कई देशों में सोशल मीडिया का दुरुपयोग और डीपफेक विशेषकर युवाओं द्वारा हिंसा और सत्ता परिवर्तन जैसे गंभीर परिणामों तक पहुँच चुका है।

भारत में भी अग्निपथ योजना, सीएए-एनआरसी और किसान आंदोलन के दौरान सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट और उकसाने वाली सामग्री के कारण कई राज्यों में युवाओं द्वारा हिंसा, पथराव और तोड़फोड़ की घटनाएँ देखी गईं। इसी प्रकार नेपाल में भी सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार विरोधी प्रचार और फर्जी खबरों ने युवाओं को सड़कों पर उतरने और सरकारी संस्थानों के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया है। नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता के दौरान ट्विटर और फेसबुक जैसे मंचों पर फैले अभियानों ने युवाओं को राजनीतिक आंदोलन में उतारने में बड़ी भूमिका निभाई, जिनमें कुछ प्रदर्शन हिंसक भी हो गए। विश्व के अनेक देश ऐसे हैं जिनमें सोशल मीडिया का दुरूपयोग कर युवाओं को भ्रमित कर हिंसक आंदोलनों और अस्थिरता फैलाने के लिए किया गया है। वर्ष 2021 में अमेरिका में हुए कैपिटल हिल हमले के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फैलाए गए झूठे दावों और उकसावों ने हजारों युवाओं को लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रतीक पर हमला करने के लिए प्रेरित किया। जब युवा सोशल मीडिया के दुरुपयोग का शिकार होते हैं, तो उसका असर केवल परिवार और समाज पर नहीं होता, बल्कि लोकतांत्रिक और शासन व्यवस्था पर भी पड़ता है। भारत में भी सोशल मीडिया के कारण कई बार अफवाहें, साम्प्रदायिक तनाव और हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। उदाहरणस्वरूप, मॉब लिंचिंग की घटनाएं, छात्र आंदोलनों में गलत सूचनाओं का फैलाव, और चुनावों के दौरान फेक न्यूज़ का प्रसार, इस डिजिटल खतरे की गंभीरता को दर्शाते हैं। सोशल मीडिया की चुनौती से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कुछ अहम कदम उठा रही हैं। आईटी नियमों (2021) के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जवाबदेह बनाया गया है। उन्हें अवैध या भड़काऊ सामग्री को हटाने के लिए समय-सीमा दी गई है। साइबर क्राइम सेल का विस्तार किया जा रहा है और राज्यों में डिजिटल निगरानी यूनिट्स सक्रिय की जा रही हैं। डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत युवाओं को सोशल मीडिया की सही उपयोगिता और खतरों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। फेक न्यूज़ और डीपफेक जैसी तकनीकों को रोकने हेतु एआई आधारित निगरानी तंत्र विकसित किए जा रहे हैं।

बिहार में रेवड़ी सरकार का बोलबाला

– बाल मुकुन्द ओझा

बिहार में चहुंओर मुफ्त की बारिश हो रही है, जिसे देखकर लगता है चाहे किसी पार्टी की सरकार बने मगर बनेगी तो रेवड़ी सरकार ही। राजनैतिक पार्टियों द्वारा मत हासिल करने के लिए राजकीय कोष से मुफ्त सुविधाएं देने की लगातार घोषणाओं से चुनावी माहौल गरमाने लगा है। चुनाव का सियासी बिगुल बज चुका है। मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन में है। सभी पार्टियों के नेता लोक लुभावन वादों की बौछार कर रहे। आरजेडी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव ने प्रदेश के हर घर में सरकारी नौकरी का वादा कर फ्री बीज का छक्का जड़ दिया है। इसी के साथ आरोप प्रत्यारोप की सियासत शुरू हो गई है। सच तो यह है रेवड़ी संस्कृति के कारण हमारे देश की अनेक राज्य सरकारें लगभग दीवालिया होने की कगार पर हैं। उनका बजट घाटा बढ़ता जा रहा है, लेकिन वे मुफ्तखोरी की सियासत को छोड़ने को तैयार नहीं है। क्योंकि चुनाव जो जीतना है। कहा जाता हैं चुनाव जीतने के लिए सब कुछ जायज है। इस कार्य में कोई भी सियासी पार्टी पीछे नहीं रहती। बिहार में मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की होड़ शुरू हो गई है। बिहार पर पहले से ही 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है, ऊपर से चुनावी सीजन में मुफ्त योजनाओं के लिए बड़े-बड़े वादे किए जा रहे हैं। बिहार में महिलाओं को साधने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत प्रधानमंत्री ने 75 लाख ग्रामीण महिलाओं को पहली किस्त के तौर पर 10,000-10,000 रुपये की राशि ट्रांसफर की। योजना के तहत आगे चलकर प्रत्येक महिला को कुल 2 लाख तक की आर्थिक सहायता मिलेगी। इसे महिलाओं के लिए चुनावी सौगात भी कहा जा रहा है। यानि अभी तो फ्री बीज की यह शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। आरजेडी और इंडिया ब्लॉक का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने दरअसल उन्हीं वादों की नकल की है, जिन्हें विपक्ष ने जनता से करने का दावा किया था। मुख्यमंत्री नीतिश कुमार फ्री बीज की योजनाओं के विरुद्ध रहे है है। उन्होंने दिल्ली चुनाव के दौरान अरविन्द केजरी वाल की मुफ्त बिजली की अवधारणा को 'गलत काम' करार देते हुए कहा था कि यह दीर्घकालिक विकास के लिए हानिकारक है और आज वे खुद ही फ्री बीज के रास्ते पर चल निकले है। नीतीश कुमार ने 2022 में केजरीवाल की मुफ्त बिजली योजना को अव्यवहारिक और गलत बताकर तंज कसा था, आज तीन साल बाद खुद ऐसी ही फ्री बिजली योजना लागू कर अपनी सियासी रणनीति बदल ली है। उनका यह कदम न केवल उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है, बल्कि नीतिगत निर्णयों और सिद्धांतों की राजनीति से किनारा करने की स्थिति को भी बताता है। इसीलिए कहा जाता है हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते है। इससे पूर्व आरजेडी नेता तेजस्वी मुफ्तखोरी की अनेक घोषणाएं की घोषणा कर दी थी। चुनावों के दौरान सियासी पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए तरह तरह के वादे और प्रतिवादे करती है। सरकार बनने के बाद चुनावी वादे पूरा करने में पार्टियों के पसीने छुट जाते है। कई राज्यों की अर्थव्यवस्था तो चौपट तक हो जाती है जिसके कारण सम्बध सरकारों को अपने कर्मचारियों के वेतन आदि चुकाने के लाले पड़ जाते है। राजनैतिक पार्टियों द्वारा मत हासिल करने के लिए राजकीय कोष से मुफ्त सुविधाएं देने का प्रकरण सियासी हलकों में गर्माने लगा है। देश की प्रबुद्ध जमात का मानना है इससे हमारे लोकतंत्र की बुनियाद हिलने लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस प्रकार की योजनाओं की आलोचना की थी। राजनीतिक दलों द्वारा चुनावों के दौरान इस तरह के वादे करने का चलन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक पार्टियां आम लोगों से अधिक से अधिक वायदे करती हैं। इसमें से कुछ वादे मुफ्त में सुविधाएं या अन्य चीजें बांटने को लेकर होती हैं। यह देखा गया है कुछ सालों से देश की चुनावी राजनीति में मुफ्त बिजली-पानी, मुफ्त राशन, महिलाओं को नकद राशि, सस्ते गैस सिलेंडर आदि आदि अनेक तरह की घोषणाओं का चलन बढ़ गया है। विशेषकर चुनाव आते ही वोटर्स को लुभाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कशमीर के चुनाव इसके ज्वलंत उदाहरण है। मुफ्त का मिल जाये तो उसका जी भर उपयोग करना। ये मुफ्त की नहीं है अपितु जनता के खून पसीनें की कमाई है जो राजनीतिक दलों और सरकारों द्वारा दी जा रही है ताकि चुनाव की बेतरणी आसानी से पार की जा सके। देश के प्रधानमंत्री रेवड़ी कल्चर का विरोध कर चुके है मगर चुनावों में उनकी पार्टी भाजपा सहित कांग्रेस और आप सहित सभी पार्टियां रेवड़ी कल्चर में डुबकियां लगा रही है।

(वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर)

न्यायपालिका की गरिमा को बचाने के लिए व्यापक सुधार की जरूरत !

देश की अदालतों में साढे चार करोड़ मुकदमे पेंडिंग है लेकिन एक आतंकी के लिए रात को घर मे अदालत लगाकर आदेश जारी करते हैं एक न्यायाधीश के आवास के कमरे में बोरों में करोड़ों की करेंसी जलती मिलती है लेकिन कानून के हाथ बंधे हुए हैं और उन जज साहब पर कार्यवाही नही होती है। इनमें से अधिकांश के बच्चे विदेशों में पढ़ते है गर्मियों की छुट्टिया मनाने के लिए एक माह अदालत बंद कर देते हैं ये मार्डन राजा हैं।

– मनोज कुमार अग्रवाल

देश के लोकतंत्र के चार स्तम्भों में प्रमुख स्तम्भ न्यायपालिका की गरिमा खतरे में है इस के लिए अकेले बार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते बेंच भी बराबर की जिम्मेवार है। पिछले दिनों इंडिया न्यूज़ के एक ओपिनियन सर्वे में 85 फीसद लोगों ने भारतीय न्याय पालिका में भ्रष्टाचार की बात मानी यह स्थिति बेहतर संकेत नहीं है हाल ही में देश के शीर्ष न्यायमूर्ति को लक्ष्य कर एक 72 वर्षीय गैर अपराधिक प्रवृति और चरित्र वाले वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा जूता उछालना बेहद गंभीर और असामान्य घटना है लेकिन ऐसे हालात क्यों बने? असहमति होना अलग बात है लेकिन इस असहमति के प्रतिकार बतौर इस तरह की अपमान जनक प्रतिक्रिया के मूल में छिपे कारणों को तलशना होगा। देश की न्याय व्यवस्था जिस शुचिता और पारदर्शिता का प्रतिबिंब होनी चाहिए क्या वह परिलक्षित हो रहा है?

दरअसल पिछले कुछ दशकों में न्यायपालिका के स्वरूप में सुधार के स्थान पर गिरावट दृष्टिगत हो रही है लगातार बैंच मामलों के तथ्यों से इतर उपदेशक बतौर अनावश्यक मनमानी टिप्पणी कर रहीं हैं यदि अदालत में कोई अधिवक्ता मामले के तथ्यों से अलग नजीर दे तो उसे यही अदालत और न्यायमूर्ति समय की बर्बादी करार देते हैं जबकि स्वयं केस के तथ्यों की सीमा को पार कर टिप्पणी करते हैं यह दोहरा रवैया बैंच और बार के बीच टकराव पैदा करता है नुपूर शर्मा खजुराहो की प्रतिमा समेत कई मामलों में बेंच ने केस के तथ्यों से बाहर अशोभनीय टिप्पणी कर मर्यादा और गरिमा को तोड़ा है। यहां आपको बता दें कि पीढ़ी दर पीढ़ी कालेजियम से कुछ इने गिने जजों के परिवार के नाती पोते ही जज बनते हैं न्यायपालिका में उच्च पदस्थ होकर मनमानी करते हैं सत्ता और विपक्ष दोनो को खुश रखते हैं और रिटायर्मेंट के बाद का भी सरकारी पदों पर सुविधाभोगी बने रहने का अवार्ड पाते हैं राजनीतिक दल के नेता बनकर चुनाव लड़ते हैं। जिस तरह सत्ता धारी दल लगातार वोटर्स को लुभाने के लिए जातीय क्षेत्रीय संतुलन बनाने में लगे रहते हैं ठीक उसी तरह न्यायपालिका की बेंच सत्ता और विपक्ष के साथ अपना संतुलन बैठा कर चलने के लिए काम करती है। यहां गौरतलब है कि जिनकी नियुक्ति की प्रक्रिया ही पारदर्शिता और ईमानदारी से नही है वह क्या न्याय करेंगे? वह कहीं न कहीं पूर्वाग्रही होंगे। विषय से हट कर अनाप शनाप टिप्पणी करते हैं न्यायमूर्ति बनकर भी अपनी जाति धार्मिक मान्यता से ऊपर नहीं उठते बल्कि अपने कारनामों के बचाव के लिए इनका कवच ओढ़ लेते हैं।

देश की अदालतों में साढे चार करोड़ मुकदमे पेंडिंग है लेकिन एक आतंकी के लिए रात को घर मे अदालत लगाकर आदेश जारी करते हैं एक न्यायाधीश के आवास के कमरे में बोरों में करोड़ों की करेंसी जलती मिलती है लेकिन कानून के हाथ बंधे हुए हैं और उन जज साहब पर कार्यवाही नही होती है। इनमें से अधिकांश के बच्चे विदेशों में पढ़ते है गर्मियों की छुट्टिया मनाने के लिए एक माह अदालत बंद कर देते हैं ये मार्डन राजा हैं जो न्याय के नाम पर इंसाफ़ के नाम पर विवेक की आड़ में मनमानी करते हैं। भगवान के लिए भी अभद्र टिप्पणी कर सकते हैं और इसी का परिणाम है कि आम आदमी का भरोसा अदालत और न्यायपालिका से टूट रहा है। हमारा सुझाव है कि देश में सभी नागरिकों से रायशुमारी करानी चाहिए कि नागरिकों को मौजूदा न्यायपालिका और उसके कर्ता धर्ता अदालत जजों पर कितना विश्वास है? मै दावा करता हूं कि नतीजे बेहद भयावह होंगे और इस समूचे सड़ चुके सिस्टम की पोल खोल देंगे।

इस देश में यदि मीलार्ड अपना काम समयबद्ध और ईमानदारी से करते तो न भ्रष्टाचार होता न अराजकता होती न सांप्रदायिकता होती न तुष्टिकरण होता इस सबका जिम्मेदार यही काले लबादे में सुरक्षित इमारतों में वातानुकूलित भवनों में बैठे आधुनिक मीलार्ड है जो खुद को भगवान से बड़ा मानते हैं और कभी खेत खलिहान किसान गरीब गाँव चौपाल पंचायत ब्लॉक सार्वजनिक वाहन रेल रोडवेज बस से यात्रा सरकारी स्कूल से पढ़ाई सरकारी अस्पताल में इलाज पुलिस चौकी थाने में पुलिस का व्यवहार तहसील आरटीओ में सरकारी काम के भ्रष्टाचार से कभी दूर का भी वास्ता नही पडा होता है ये लोग न आम जनमानस से आते हैं न आम आदमी की परेशानियां समझ सकते हैं क्योंकि इन्होंने उस माहौल को न देखा न भुगता जिस से नब्बे फीसदी आम आदमी रोजाना भुगतता है झेलता है।

ये न्याय की कुर्सी पर बैठ कर कैसे न्याय कर सकते हैं? इस देश के सभी हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीशों के आवास और उनके परिवार की संपत्ति पर एक साथ प्रभावी जांच कराने की जरूरत है सारी ईमानदारी सामने आ जाएगी बोरों में नोट रखने वाले जज साहब से भी बड़े मगरमच्छ सामने आ सकते हैं लेकिन किसी सत्ता में इतना दम नहीं है जो गौमुख से गंगा की सफाई शुरू कर सके लिख तो और भी ज्यादा सकता हूँ लेकिन इस राजनीतिक सामाजिक न्यायिक तंत्र से ज्यादा सुरक्षा की उम्मीद नहीं है और ऐसे माहौल में जहां निठारी कांड के करीब बीस बच्चों के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए गरीब मजदूर परिवार उन्नीस साल तक अदालत के चक्कर काटने के बाद आरोपियों को अदालत द्वारा सबूत के अभाव में बरी करने पर ठगे खड़े रह जाते हैं। जहां एक सौ रुपये की रिश्वत लेने के आरोपी को माथे पर लगा रिश्वत का कलंक हटाने के लिए 47 साल बाद अदालत से न्याय मिलता है लेकिन इस बीच उसकी पत्नी मर जाती है परिवार तबाह हो जाता है। ऐसे एक दो नही हजारों नजीर है जो चीख चीख कर बताते हैं कि न्याय आम आदमी के लिए एक जीवन में हासिल करना टेढ़ी खीर है वास्तव में जज साहब सही कहते हैं एक बारगी भगवान किसी की करुण आर्त पुकार सुन सकते हैं लेकिन अदालत नहीं। लोकतंत्र के चार स्तम्भों में मैं सबसे खराब हालत न्यायपालिका की मानता हूं वकालत के साढे तीन दशक के सफर में मैंने इसे नजदीक से देखा है अनुभव किया है। अभी हमारी न्यायिक प्रणाली में बहुत सुधार की जरूरत है इसमें बहुत पारदर्शिता और बदलाव लाने की जरूरत है।। हमारी न्यायिक व्यवस्था को अधिवक्ता के अप्रिय अपमान जनक व्यवहार से सबक लेकर बदलाव की प्रेरणा लेनी चाहिए।

(यह विचार लेखक के स्वयं के हैं, लेखक अधिवक्ता एवं वरिष्ठ पत्रकार हैं)

शिक्षा, भाषा और संस्कृति देश की समृद्धि का पैमाना

– संजीव ठाकुर

शिक्षा सदैव समाज, संस्कृति और सभ्यताओं के साथ परिवर्तनशील और प्रगतिशील रही है। यह न केवल व्यक्तिगत उन्नति का माध्यम है, बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास की आधारशिला भी है। शिक्षा, ज्ञान, कला, साहित्य और संस्कृति को देश-विदेश की सीमाओं में बाँधना संभव नहीं है। यह असीमित भंडार है, जिसमें आकाशीय ऊँचाइयाँ भी शामिल हैं। न केवल इसकी गहराई को नापा जा सकता है, न ही इसकी ऊँचाई को देखा जा सकता है। शिक्षा और ज्ञान की यह विशालता मानव जीवन में अनंत संभावनाओं के द्वार खोलती है। पूर्वी सभ्यता, विशेषकर भारतीय परंपरा, जहाँ अध्यात्म, वेद, पुराण और योग पर आधारित है, वहाँ पश्चिमी सभ्यता विज्ञान, तकनीकी नवाचार और अनछुई रहस्यमय खोजों पर आधारित है। इन दोनों सभ्यताओं ने अपने-अपने क्षेत्र में मानव जीवन को बदलने वाले अनमोल योगदान दिए हैं। उदाहरण स्वरूप, पश्चिमी विज्ञान ने मानव को चंद्रमा पर पहुँचने का अवसर दिया और आधुनिक तकनीक जैसे हवाई जहाज, इंजन, रेडियो और डिजिटल तकनीक से जीवन को सरल और उन्नत बनाया। वहीं, भारतीय ज्ञान और दर्शन ने योग, आयुर्वेद, ध्यान और जीवन मूल्यों के माध्यम से मानव जीवन में शांति, संतुलन और आत्मसाक्षात्कार की दिशा प्रदान की। इस प्रकार शिक्षा, भाषा और ज्ञान ने पूर्व और पश्चिम के बीच समन्वय स्थापित किया। पश्चिम ने भारतीय दर्शन, आयुर्वेद और योग को अपनाकर अपनी जीवनशैली में संतुलन पाया, और भारत ने पश्चिम के विज्ञान और तकनीकी ज्ञान को अपनाकर विकास की नई ऊँचाइयों को छुआ। शिक्षा और भाषा सदैव अज्ञानता के तमस में प्रकाश की तरह कार्य करती रही है। यह नवजीवन की विकास धारा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और समाज में सतत प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती है। भारतीय संस्कृति और दर्शन में जैन, बौद्ध, नव्य वेदांत और आधुनिक चिंतन ने समाज में नवयुग की कल्पना को साकार किया। वहीं पश्चिम के दार्शनिक और चिंतक जैसे प्लूटो, अरस्तु, सुकरात, कार्ल मार्क्स और लेनिन ने सामाजिक और राजनीतिक विकास के सिद्धांत प्रतिपादित किए, जिन्हें पूरी दुनिया ने अपनाया। इस प्रकार, दोनों सभ्यताओं में ज्ञान और विचारों का आदान-प्रदान निरंतर जारी रहा।

भारतीय समाज में हमेशा सुधार और नवीन युक्तियों को अपनाने की क्षमता रही है। स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता पश्चात राजनीति और समाज में हुए परिवर्तन इसका सजीव उदाहरण हैं। उदाहरण के लिए, गांधीजी ने सत्याग्रह और अहिंसा के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन को साकार किया, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने विज्ञान और तकनीक के माध्यम से आधुनिक भारत की नींव रखी। सुभाष चंद्र बोस और बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्रता संग्राम में नई ऊर्जा और दिशा प्रदान की। इन सबके प्रयासों ने भारत को विश्व पटल पर एक नया स्वरूप और पहचान दी। पाश्चात्य ज्ञान ने हमें अपने आडंबर, अंधविश्वास और रूढ़िवादिता पर विजय पाने में मदद की। उदाहरण के लिए, वास्तु, जन्मकुंडली और अंधविश्वास से जुड़े कई प्रचलित विश्वासों को आधुनिक विज्ञान और शिक्षा के माध्यम से समाज से दूर किया जा सका। यह स्पष्ट करता है कि शिक्षा और ज्ञान समाज में समग्र सुधार और नवप्रवर्तन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। हमारे दैनिक जीवन में भी शिक्षा, भाषा और ज्ञान हमें यह एहसास कराते हैं कि हम अभी भी कितने पीछे हैं और कितनी दूर तक सीखने की आवश्यकता है। ज्ञान का कोई अंतिम स्रोत नहीं होता; यह एक ऐसा समृद्ध भंडार है, जिसमें जितना भी सीखना संभव है, वह निरंतर बढ़ता रहता है। अतः हमें सदैव प्रयासरत रहना चाहिए कि हम पल-पल कुछ नया सीखें-हर व्यक्ति, हर समाज, और हर सभ्यता से। शिक्षा, भाषा और ज्ञान ही हमें समृद्ध, विकसित और परिवर्तनशील बनाते हैं। परिवर्तनशील जीवन ही नई ऊर्जा, आशा और विकास की नींव रखता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो हर मानव, हर समाज और हर राष्ट्र के लिए सीखने, अपनाने और नवाचार करने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। यही कारण है कि शिक्षा और ज्ञान न केवल व्यक्तिगत उन्नति बल्कि समग्र मानवता के विकास के लिए अनिवार्य हैं।

(लेखक, चिंतक, स्तंभकार छत्तीसगढ़)

कविता

अजनबी तन्हाई

कौन सा दर्द
अपने सीने में छुपाए
रखते हो?
मुस्कुराहट के पीछे
कौन सा गम
अपने हृदय में दबाए
रखते हो?
कहते हो तुम
लोगों से अक्सर
कि मुझे कोई गम नहीं ?
फिर इस
तन्हाई के आलम में
किस से गुफ्तगू का
माहौल बनाए रखते हो?
सुना है लोगों से
कि तुम बहुत
बातें करते हो
पर आता है नाम मेरा तो
क्यों अपने लबों पर
खामोशी
और आंखों में
मुस्कुराहट
रखते हो?

डॉ. राजीव डोगरा
(युवा कवि लेखक, हिंदी अध्यापक, गांव जनयानकड़, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश)

मायावती की कुछ वर्षों की निष्क्रियता से भाजपा केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के बदौलत दलित को अपनी तरफ मोड़ने में कुछ कमयाब दिखीं। हालांकि जमीनी सच्चाई यही है इस भीड़ से बसपा और दलित भले खुश हों की बसपा तेजी से उभर रहीं है लेकिन सिर्फ दलित वोट से वह राजनीति में वापसी नहीं कर सकती। क्योंकि मौजूदा वक्त गठबंधन का दौर है और भारतीय जनता पार्टी इसमें सबसे सशक्त दिखाई पड़ती है।

मायावती का नया आगाज क्या होगा अंजाम ?

– प्रभुनाथ शुक्ल

प्रदेश की राजनीति में नए क्षितिज उभर रहे हैं। राज्य विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सत्ता और विपक्ष अपनी-अपनी कमर कसता दिख रहा है। हालांकि अभी चुनाव में वक्त है, लेकिन राजनैतिक दल माहौल बनाना शुरू कर दिया है। भाजपा जहां सत्ता खोना नहीं चाहती वहीं उत्तर प्रदेश का मुख्य विपक्षीय दल समाजवादी पार्टी, पीडीए को साधने में जुटा है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का बेहतर प्रदर्शन रहा था। इस प्रदर्शन ने भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा दिया था। समाजवादी पार्टी अगर यही प्रदर्शन दोहराती है तो विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए जूटे हैं और सत्ता पक्ष के काम का अक्सर विरोध करते दिखते हैं। आजम खान की जेल से रिहाई के बाद अखिलेश यादव खुद रामपुर जाकर उनसे मिले। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा था कि आजम खान समाजवादी पार्टी से नाराज है और वह बसपा में जा सकते हैं। इन सब अटकलें को देखकर अखिलेश यादव को आखिर आजम खान के दरबार में माथा टेकना पड़ा। आजम खान के सियासी शरण में जाना अखिलेश यादव की मजबूरी है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग ही उनका जनाधार है। पिछड़ा वर्ग में भी सभी जातियों को हम शामिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन यादव और मुसलमान अखिलेश के साथ खड़े रहते हैं। आजम खान समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे हैं। समाजवादी पार्टी से अगर आजम खान किनारा करते तो अखिलेश यादव की राजनीतिक पकड़ बेहद कमजोर हो जाती। ऐसी स्थिति में मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए आजम शरणम गच्छामि होना पड़ा। आजम का प्रभाव पश्चिमी यूपी में मजबूत है। यूपी में 2011 जनगणना के अनुसार, मुसलमानों की कुल आबादी तकरीबन 20 फिसदी है। 2025 अनुमान है कि यह आबादी तकरीबन साढ़े चार करोड़ पहुंच जाएगी। सबसे अहम सवाल उठता है कि क्या मुसलमान आजम खान को अपना नेता मानता है। हालांकि यह कहना पूरी तरह से गलत होगा कि यूपी का मुसलमान आजम के साथ पूरी तरह खड़ा है। मुसलमान में कई नेता है और सबके अपने-अपने समर्थक। सिर्फ आजम खान के इशारे पर मुसलमान नहीं खड़ा होगा। हालांकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुसलमानों की अहमियत को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है। इसकी वजह है कि प्रदेश के सभी राजनीतिक दल मुसलमान वोट बैंक साधने के लिए उनके साथ खड़े रहते हैं। हालांकि यह भी सच है मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को भी पड़े पैमाने वोटिंग करता है। भाजपा साल 2017 के चुनाव में पश्चिम के मुस्लिम बहुल इलाकों में भी हुआ अपना परचम लहरा चुकी है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में तकरीबन 55 से 60 सीटों के आसपास मुसलमान का दबदबा है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यहां कल 82 सीटों में 62 पर विजय हासिल किया था। यह चौंकाने वाला आंकड़ा था और राजनीतिक विश्लेषकों को चक्कर में डाल दिया था मुस्लिम सभी सियासी मिथक को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े मिले।

उत्तर प्रदेश की लोकसभा में 80 सीटों में तकरीबन 20 से 22 सीटों पर मुसलमानों का प्रभाव है। इसमें सहारनपुर बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा, संभल और मुजफ्फरनगर एवं रामपुर जैसे संसदीय इलाके शामिल। यही कारण है कि अखिलेश यादव को आजम खान से मिलने रामपुर हवेली जाना पड़ा। समाजवादी पार्टी से अगर मुस्लिम नाराज होता है तो उसके लिए बड़ी चुनौती होगी। सवाल यह भी है कि वह नाराज होकर भी कहाँ जाएगा। लेकिन पूरा मुसलमान सिर्फ समाजवादी पार्टी के साथ है ऐसा कहना भी मुश्किल है। वह मायावती की बहुजन समाज पार्टी और भाजपा के साथ भी खड़ा मिलता है। चुनाव में यह भी ट्रेंड देखा गया है कि मुसलमान परिस्थितियों को देखते हुए अपनी वोटिंग करता है। उत्तर प्रदेश में उधर एक और सियासी घटना ने सपा के लिए नई चुनौती का जन्म दिया है। लखनऊ में काशीराम परिनिर्वाण दिवस पर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती की तरफ से आयोजित रैली से समाजवादी पार्टी की नींद उड़ गई है। उधर दलितों का मसीहा बनने की कोशिश कर रहे चंद्रशेखर आजाद रावण भी उलझन में है। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी कमजोर स्थिति में नहीं। तकरीबन 10 साल बाद मायावती की राजनीति सक्रियता ने उनके सपने पर पानी डाल दिया है। लखनऊ में उमड़ी दलितों की भीड़ ने साबित कर दिया है कि मायावती में दलित पूरी तरह आस्था रखता है। बसपा कैडर बेस पार्टी है बगैर प्रचार के इतनी भारी भीड़ सब की नींद उड़ा दी है। मायावती ने जहां भाजपा की जमकर प्रशंसा किया वहीं अखिलेश यादव पर निशान साधा और उनकी सरकार में किए गए कार्यों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि दलितों के साथ समाजवादी पार्टी सरकार ने दोगली राजनीति की। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मायावती की सक्रियता ने अखिलेश यादव के पीडीएफ फार्मूले को झटका दिया है। मायावती की कुछ वर्षों की निष्क्रियता से भाजपा केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के बदौलत दलित को अपनी तरफ मोड़ने में कुछ कमयाब दिखीं। हालांकि जमीनी सच्चाई यही है इस भीड़ से बसपा और दलित भले खुश हों की बसपा तेजी से उभर रहीं है लेकिन सिर्फ दलित वोट से वह राजनीति में वापसी नहीं कर सकती। क्योंकि मौजूदा वक्त गठबंधन का दौर है और भारतीय जनता पार्टी इसमें सबसे सशक्त दिखाई पड़ती है। केंद्र और राज्य में उसकी सत्ता होने से इसका सीधा लाभ मिल रहा है। छोटे दल भाजपा की सत्ता में सहभागी बनकर मलाई काट रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में यह भी माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की पकड़ कमजोर हो रही थी। माना जा रहा था कि 2027 के चुनाव में भाजपा की राह आसान नहीं होगी। जिसकी वजह से भजपा ने मायावती को री-लांच किया है। क्योंकि मायावती ने इस रैली के दौरान भाजपा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ किया। जबकि अखिलेश यादव पर खूब बरसी। रैली ने समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती बढ़ा दी है और बसपा जितना उत्तर प्रदेश में मजबूत होगी आने वाले 2027 के चुनाव में भाजपा की राह उतनी ही आसान होगी।

(वरिष्ठ पत्रकार, लेखक एवं समीक्षक, ग्राम - हरीपुर, पत्रालय - अभिया जिला - भदोही, (उप्र)

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

संपादकीय

स्वास्थ्य ही असली धन है, सोने-चांदी के टुकड़े नहीं।
-महात्मा गांधी

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की ऐतिहासिक भारत यात्रा में उन्हें जो तवज्जो मिल रही है, उसमें छिपे अर्थों को समझना जरूरी है। दक्षिण एशिया की भू-राजनीति के मद्देनजर इसे अगर भारत की कूटनीतिक जरूरत कहा जाए, तो अतिशयोक्ति नहीं होगा।

कूटनीतिक जरूरत

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की आठ दिवसीय भारत यात्रा काबुल में तालिबान की दोबारा वापसी के बाद उनका इस स्तर पर नई दिल्ली का पहला ही दौरा है, जो सही मायनों में कई बदलावों का संकेत दे रहा है। भारत की विदेश नीति में भी इसे एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा सकता है, क्योंकि नई दिल्ली और तालिबान में बातचीत चल रही है, जबकि भारत ने अब तक तालिबान शासित अफगानिस्तान को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है। भले ही इसकी वजह बदलती भू-राजनीतिक स्थितियां और राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल हो, लेकिन तालिबान की मानवाधिकार और खासकर महिलाओं को लेकर प्रतिगामी नीतियों के चलते भारत के लिए यह राह आसान नहीं होने वाली। उल्लेखनीय है कि 2001 के अमेरिकी हमले के बाद से ही भारत अफगान सरकार को आर्थिक और सैन्य सहायता प्रदान कर तालिबान के खिलाफ मजबूती से खड़ा रहा। लेकिन, 2021 में तालिबान की वापसी के बाद भारत ने काबुल के साथ अपने राजनीतिक और कूटनीतिक रिश्ते खत्म कर दिए। फिर 2025 की शुरुआत में स्थितियों में फिर से बदलाव आया, जब भारतीय विदेश सचिव अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी से दुबई में मिले। अब उन्हीं मुत्ताकी की विदेश मंत्री एस जयशंकर से नई दिल्ली में मुलाकात से द्विपक्षीय रिश्ते परवान चढ़ते नजर आ रहे हैं। इस मुलाकात में भारतीय विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के प्रति भारत की पूर्ण प्रतिबद्धता जताई है, तो मुत्ताकी ने भी भारत को अपना घनिष्ठ मित्र बताते हुए यह आश्वासन दिया है कि अफगानी जमीन का उपयोग भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के लिए नहीं होगा। अफगानिस्तान के बगराम एयर बेस पर कब्जे की अमेरिकी मंशा के विरोध में भारत ने हाल ही में चीन, रूस और पाकिस्तान के साथ खड़े होकर तालिबान को अपना समर्थन दिखाया है। यह भी नहीं भूला जा सकता कि अफगानिस्तान उन देशों में है, जिन्होंने

सबसे पहले पहलगाम आतंकी हमले की सार्वजनिक निंदा की थी। इधर मुत्ताकी भारतीय दौरे पर हैं, उधर अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमा पर संघर्ष छिड़ा हुआ है। इस संदर्भ में देखें, तो यह दौरा और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। पाकिस्तान के लिए भी यह किसी झटके से कम नहीं है, कि जिस तालिबान को कभी उसने सहारा दिया था, आज वही उसके प्रभाव से निकल कर स्वतंत्र निर्णय ले रहा है। पहलगाम आंतकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान जिस तरह से अमेरिका की गोद में बैठना चाह रहा है, और चीन अफगानिस्तान में अपना दखल बढ़ाता जा रहा है, ऐसे में तालिबानी शासन के साथ रिश्ते मजबूत करने को भारत के लिए एक रणनीतिक जरूरत के रूप में भी देखा जा सकता है।

आखिर ये सिरप बाजार में पहुंचते कैसे हैं

भारत के पास ऐसी त्रासदियों को रोकने की क्षमता है, लेकिन नीति-नियंताओं में इच्छाशक्ति का अभाव दिखता है। अगर भारतीय दवा उद्योग के व्यावसायिक हितों की रक्षा प्राथमिकता बनी रही, तो सार्थक सुधारों में रुकावटें आएंगी। यह मामला वैश्विक सुर्खियों में है, जो भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहा है।

छिंदवाड़ा, बैतुल और पंधुरना-ये तीनो मध्य प्रदेश के ग्रामीण जिले हैं, जहां ज्यादातर आदिवासी आबादी रहती है। इन तीनों जिलों में लगभग दो दर्जन बच्चों की मौत हो गई, जिनमें से अधिकतर पांच वर्ष से कम उम्र के थे, जिन्होंने डायथिलीन ग्लाइकॉल (डीईजी) से संदूषित कफ सिरप पिया था। डीईजी का सेवन विशेष रूप से बच्चों में किडनी फेल होने और मृत्यु का कारण बनता है। दवा के रूप में यह जहर मध्य प्रदेश के कई जिलों और राजस्थान में फैल गया, जिससे और भी जानें गईं।

इस मामले में अब तक तीन दूषित कफ सिरप की पहचान की गई है: कोल्ड्रिफ, रेस्पिफ्रेश टीआर और रीलाइफ। तमिलनाडु स्थित श्रीसन फार्मास्युटिकल्स, कोल्ड्रिफ का निर्माण करती थी। रेडनेक्स फार्मास्युटिकल्स और शेप फार्मा की भी दूषित सिरप बनाने वाली कंपनियां है। श्रीसन के मालिक को गिरफ्तार कर उसका विनिर्माण लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में बने डीईजी-दूषित सिरप के कारण दुनिया भर में कम से कम 150 बच्चों की मौत हो चुकी है।

पत्रलेखा चटर्जी
वरिष्ठ पत्रकार

हालिया त्रासदी एक भयावह श्रृंखला में शामिल हो गई है: 2022 में गांबिया, उसी वर्ष उज्बेकिस्तान, 2020 में जम्मू और कश्मीर, 1998 में गुड़गांव, 1986 में मुंबई। हर बार, यही क्रम दोहराया जाता है—दूषित सिरप, मृत बच्चे, जन आक्रोश, और फिर सन्नाटा। गिरफ्तारियां तो होती हैं, लेकिन भारत में दवाओं को दूषित करने के आरोप में किसी को जेल नहीं भेजा गया है।

तमिलनाडु औषधि नियंत्रण विभाग के निरीक्षण में पाया गया कि श्रीसन फार्मास्युटिकल्स ने 364 विनिर्माण नियमों का उल्लंघन किया है, जिनमें से 39 'बहुत गंभीर' और 325 'गंभीर' श्रेणी के हैं। खबरों के मुताबिक, रिपोर्ट में अयोग्य कर्मचारियों, घटिया पानी और उपकरणों, कीट नियंत्रण की कमी, उत्पादन निगरानी प्रक्रियाओं की कमी, और गुणवत्ता आश्वासन या डाटा संग्रह के अभाव का हवाला दिया गया है। सिरप में इस्तेमाल किया गया डीईजी कथित तौर पर बिना बिल के खरीदा गया था, जिससे अवैध स्रोत

का संकेत मिलता है। पुलिस ने उस डॉक्टर को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिसने यह सिरप लिखा था, हालांकि चिकित्सा समूहों का तर्क है कि असली जिम्मेदारी नियामकों की है, न कि चिकित्सकों की। लेकिन सिर्फ गिरफ्तारी से व्यवस्था ठीक नहीं होगी।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने भारत की नियामक खामियों पर गहरी चिंता व्यक्त की है और चेतावनी दी है कि ऐसी दवाएं अनियमित माध्यमों से दूसरे देशों तक पहुंच सकती हैं। भारत का कहना है कि इनमें से किसी भी सिरप का निर्यात नहीं किया गया, लेकिन अतीत को मिटाया नहीं जा सकता। भारत में डीईजी त्रासदियों में मौतों का भूगोल चिंताजनक रूप से एक जैसा है। पीड़ित लगभग हमेशा गरीब, ग्रामीण और बेजुबान होते हैं। ये सिरप सस्ते होने के कारण गरीब लोग खरीदते हैं। निर्माता अक्सर छोटी कंपनियां होती हैं, जिन पर बहुत कम निगरानी होती है, और ये ढीले खरीद मानकों वाले राज्यों में अपना उत्पाद बेचते हैं।

आखिर ये सिरप शहरी भारत के संपन्न इलाकों में क्यों नहीं पहुंचते? जाने-माने जन स्वास्थ्य कार्यकर्ता और *'द ट्रुथ पिल: द मिथ ऑफ ड्रग रेगुलेशन इन इंडिया'* के सह-लेखक दिनेश ठाकुर कहते हैं: 'संपन्न लोग शायद इन उत्पादों को उन दुकानों से खरीदते हैं, जहां छोटी और मध्यम दवा कंपनियों द्वारा बनाए गए कफ सिरप नहीं होते। बड़े शहरों की दवा दुकानों में बड़ी दवा कंपनियों द्वारा बनाए गए कफ सिरप मिलते हैं, जो एक हद तक औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की अनुसूची एम का पालन करती हैं।'

अनुसूची एम भारत में दवा उत्पादों के लिए उत्तम विनिर्माण प्रथाओं (जीएमपी) की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। दिसंबर 2023 में अधिसूचित विनिर्माण नियमों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने और गुणवत्ता नियंत्रण को मजबूत करने के लिए हाल ही में संशोधित करके अद्यतन किया गया है। एक निश्चित आय स्तर से ऊपर के शहरी भारतीय अपनी दवाइयां बेहतर स्टॉक वाली फार्मेसियों से खरीदते हैं, ब्रांडेड विकल्पों की मांग करते हैं, तथा ऐसे स्थानों पर रहते हैं, जहां मीडिया की जांच और नियामक दृश्यता अधिक होती है। संक्षेप में, जो सिरप छिंदवाड़ा में लोगों की जान लेता है, वह दिल्ली के पॉश डिफेंस कॉलोनी या मुंबई के बांद्रा वेस्ट में कभी नहीं पहुंच पाएगा।

इसलिए जहां नियामकीय विफलता स्पष्ट रूप से ऐसी घटिया और खतरनाक दवाओं को बाजार में आने देने के लिए जिम्मेदार है, वहीं यह भारत की दो-स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का भी स्पष्ट संकेत है। एक ओर, भारत में अच्छी गुणवत्ता वाली दवाएं (जिनमें जेनेरिक भी शामिल हैं) जिंदगी बचाती हैं। दूसरी ओर, सस्ते और खतरनाक सिरप बच्चों की जान ले लेते हैं। सुरक्षा अब अधिकार नहीं, विशेषाधिकार बन गया है।

भारत में डीईजी-दूषित सिरप की हालिया त्रासदी में एक प्रमुख नियामकीय खामी केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) और राज्य औषधि नियंत्रण प्राधिकरणों के बीच एक-दूसरे पर दोष मढ़ने और जवाबदेही की कमी है। यह औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के दोहरे नियामक ढांचे से उपजा है, जहां सीडीएससीओ राष्ट्रीय नीति, लाइसेंसिंग और निर्यात को संभालता है, जबकि राज्य प्रवर्तन, निरीक्षण और स्थानीय लाइसेंसिंग का प्रबंधन करते हैं, जिसके चलते असंगत निरीक्षण, विलंबित प्रतिक्रियाएं और एक-दूसरे पर दोष मढ़ा जाता है, जिससे रोकथाम में बाधा आती है।

जैसा कि वैश्विक स्वास्थ्य नीति और जैव नैतिकता विशेषज्ञ डॉ. अनंत भान कहते हैं: 'सभी भारतीय फार्मा कंपनियों को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन नियामक ढांचे में लगातार खामियों का मतलब है कि दवाओं की गुणवत्ता, प्रभावकारिता और सुरक्षा के लिए कठोर परीक्षण और निगरानी नहीं हो रही है। इसके अलावा दवाओं के अतार्किक संयोजनों को भी खत्म करने की जरूरत है।

भारत के पास ऐसी त्रासदियों को रोकने की क्षमता है, लेकिन राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव है। अगर भारतीय दवा उद्योग के व्यावसायिक हितों की रक्षा प्राथमिकता बनी रही, तो सार्थक सुधारों में रुकावटें आएंगी। इस रक्षात्मक रुख ने व्यवस्थागत खामियों को जारी रहने दिया है। विडंबना यह है कि, गांबिया, उज्बेकिस्तान और अब मध्य प्रदेश जैसी त्रासदियों के कारण यह मामला वैश्विक सुर्खियों में है, जो अब भारत की फार्मा प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहा है।

जीवन धारा

सुसान आर. वुल्फ

जो हम सोचते और महसूस करते हैं, उससे कहीं ज्यादा हमारे कार्यों से जीवन में अर्थ आता है। हमें अपने जुनून को पहचानना होगा, उसे मूल्यवान कार्यों से जोड़ना होगा, और फिर उसे जीना होगा।

कुछ ऐसा रचें, जो दूसरों के लिए भी मायने रखे

जीवन में अर्थ की खोज हर व्यक्ति की यात्रा का एक केंद्रीय हिस्सा है। हम सभी अपने जीवन में उद्देश्य, संतुष्टि और गहराई की तलाश करते हैं। जब यह अर्थ अनुपस्थित होता है, तो जीवन में ऊब, नीरसता, अलगाव और उदासीनता जैसे भाव हावी हो जाते हैं। लेकिन जीवन में अर्थ क्या है? क्या यह एक विशिष्ट अवधारणा है, या इसे अन्य लक्ष्यों और विचारों में समाहित किया जा सकता है? जीवन में अर्थ तब उत्पन्न होता है, जब व्यक्ति की व्यक्तिगत रुचि किसी ऐसी चीज से मिलती है, जो वस्तुनिष्ठ रूप से मूल्यवान है। अर्थ तब उत्पन्न होता है जब व्यक्तिपरक आकर्षण वस्तुनिष्ठ आकर्षण से जुड़ता है। अर्थ उन वस्तुओं से प्यार करने से उत्पन्न होता है, जो प्यार के योग्य हैं और उन्हें सकारात्मक तरीके से जोड़ने से। लोग कभी-कभी दूसरों को असाधारण रूप से अर्थपूर्ण जीवन जीते हुए देखते हैं, या उनके जीवन को व्यर्थ मानते हैं, जिसमें अर्थ की कमी है। तीन महत्वपूर्ण तत्व हैं, व्यक्तिपरक आकर्षण, वस्तुनिष्ठ मूल्य, और उत्पादक जुड़ाव। मानव जीवन की गहरी चाहत पूर्णता की ओर होती है। जीवन का अर्थ केवल व्यक्तिगत संतुष्टि या केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि उस संतुलन में है, जहां हमारी व्यक्तिगत रुचियां और जुनून किसी ऐसी चीज से मिलते हैं, जो व्यापक रूप से मूल्यवान हो। केवल यह कहना कि जीवन तब अर्थपूर्ण होता है, जब वह किसी बड़े उद्देश्य में योगदान देता है, अपूर्ण है; क्योंकि यह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की उपेक्षा करता है, जैसे कि व्यक्तिगत संतुष्टि, रिश्तों की गहराई, और छोटे-छोटे दैनिक सुख, जो जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं। अर्थपूर्ण जीवन के लिए जुनून और कार्य का सामंजस्य महत्वपूर्ण है, जहां दोनों मिलकर कुछ ऐसा रचें, जो आपके लिए और दूसरों के लिए भी मायने रखे। यह विचार व्यक्तिगत और सामूहिक कल्याण के बीच एक सेतु बनाता है। जो हम सोचते और महसूस करते हैं, उससे कहीं ज्यादा हमारे कार्यों से जीवन में अर्थ आता है। हमें अपने जुनून को पहचानना होगा, उसे मूल्यवान कार्यों से जोड़ना होगा, और फिर उसे जीना होगा। हमारा दिल, हमारा दिमाग, और हमारा कार्य, तीनों में तालमेल हो, तो एक ऐसा जीवन बनता है, जिसमें आप अपने दिल की सुनते हैं, अपने दिमाग का उपयोग करते हैं, और उन योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं, जिससे गहरी संतुष्टि और सार्थकता मिलती है। हम अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी मूल्यवान बनाएं। जीवन का असली आनंद तब मिलता है, जब हम अपने कार्यों के माध्यम से दुनिया में कुछ सकारात्मक जोड़ते हैं। एक सार्थक जीवन के लिए व्यक्तिपरक अनुभव (सकारात्मक भावनाएं) और वस्तुनिष्ठ मूल्य (जैसे दूसरों की मदद करना), दोनों महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जब आपको व्यक्तिगत खुशी व्यक्तिपरक लक्ष्यों से मिलती है, जो वस्तुनिष्ठ रूप से मूल्यवान हैं, तो जीवन वास्तव में सार्थक बन जाता है। यह तब होता है, जब आप अपने जुनून, मूल्यों और विश्वासों के अनुसार एक उद्देश्यपूर्ण और पूर्ण जीवन जीते हैं।

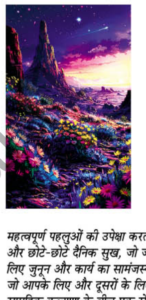

कार्य से प्रेम करना सीखें

सूत्र

हम सबके पास एक ही जीवन है, इसलिए स्वयं को ऐसे कार्यों में समर्पित करें, जो स्वयं के लिए तो बेहतर हों ही, दूसरों के लिए भी मददगार हों। स्वयं के जुनून को पहचानें और उसे ऐसे कार्य में लगाएं, जो आपको आनंद प्रदान करे। कार्य से प्रेम करना सीखें। जीवन का असली आनंद तब मिलता है, जब हम अपने कार्यों के माध्यम से दुनिया में कुछ सकारात्मक जोड़ते हैं।

दूसरा पहलू

आखिर ये अक्ल दाढ़ क्यों आती हैं? इसका जवाब सुदूर अतीत से लेकर कुछ हद तक वर्तमान से जुड़ा है।

किस काम आती है अक्ल दाढ़

अक्ल दाढ़ (विजडम टीथ) हमारे मुंह के सबसे पीछे स्थित दाढ़ों का तीसरा समूह होता है। यह पहली और दूसरी दाढ़ों की तरह दिखती है, लेकिन कभी-कभी थोड़ी छोटी हो सकती है। इसे आम तौर पर अक्ल दाढ़ कहते हैं, क्योंकि यह 32 स्थायी दांतों में से आखिरी होती है, जो 17 से 25 साल की उम्र के बीच निकलती है, जब हम बड़े और समझदार हो जाते हैं। आपको शायद मालूम होगा कि हर किसी के चारों अक्ल दाढ़ नहीं आतीं। अधिकांश लोग अपनी अक्ल दाढ़ निकलवा देते हैं। आखिर ये अक्ल दाढ़ क्यों आती हैं? इसका जवाब सुदूर अतीत से लेकर कुछ हद तक वर्तमान से जुड़ा है। जिस तरह आपके और आपके रिश्तेदारों के बीच कई चीजें मेल खाती हैं, उसी प्रकार मानव जाति भी अपने विस्तृत परिवार यानी बंदर, गोरिल्ला और चिंपैंजी जैसे प्राइमेट्स से कई समनाताएं साझा करते हैं। इन सभी के पास अक्ल दाढ़ होती हैं। कुछ लाख वर्ष पहले, प्रारंभिक मानव पूर्वजों के जबड़े और दांत आज के इन्सानों से बड़े थे।

एरिडेन लेट्रा

आपको शायद मालूम होगा कि हर किसी के चारों अक्ल दाढ़ नहीं आतीं। अधिकांश लोग अपनी अक्ल दाढ़ निकलवा देते हैं।

उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफारेन्सिस नामक एक प्रजाति के जबड़े व दांत अभी के इन्सानों की तुलना में काफी बड़े और मोटे होते थे। वैज्ञानिकों का मानना है प्रारंभिक मानव पूर्वजों को कच्चा मांस और पौधे जैसे सख्त खाना चबाने के लिए मजबूत जबड़े और दांतों की जरूरत थी।

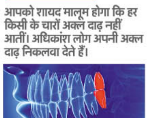

ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफारेन्सिस नामक एक प्रजाति के जबड़े व दांत अभी के इन्सानों की तुलना में काफी बड़े और मोटे होते थे। प्रारंभिक मानव पूर्वजों को सख्त खाना चबाने के लिए मजबूत जबड़े व दांतों की जरूरत थी।

आज का खाना तब के मुकाबले बहुत नरम है। खेती, खाना पकाने और खाने को संग्रहीत करने की तकनीकों की वजह से अब हमें सख्त चीजें चबाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस वजह से, लाखों वर्षों में इन्सानों के जबड़े छोटे व चेहरे सपाट होत गए। वर्षों के सतत बदलाव के बाद हमारे लिए पहले की तरह अब अक्ल दाढ़ महत्वपूर्ण नहीं रही। आजकल करीब 25 प्रतिशत लोगों के अक्ल दाढ़ नहीं आती। वैज्ञानिकों को स्पष्ट रूप से नहीं मालूम कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन इसका संबंध माता-पिता से मिलने वाली जीन से हो सकता है। कुछ वैज्ञानिकों का तर्क है कि आजकल, छोटे जबड़े वाले इन्सानों के लिए अक्ल दाढ़ का न होना फायदेमंद है। कभी-कभी, जगह की कमी के कारण, अक्ल दाढ़ जबड़े की हड्डी के अंदर फंस जाती है। कुछ मामलों में अक्ल दाढ़ आंशिक रूप से ही उभरी होती है। उनमें कभी-कभी दर्द, दांतों में सड़न या मसूड़ों में सूजन हो जाती है, जिससे उन्हें चिकित्सक से निकलवाना पड़ता है। यदि अक्ल दाढ़ मुंह में सही स्थिति में और स्वस्थ हों, तो उन्हें निकलने की आवश्यकता नहीं होती। दिन में कम से कम दो बार ब्रश करने और मुंह की नियमित सफाई करने से आपके दांत स्वस्थ रहेंगे।

आंकड़े

मानसिक स्वास्थ्य

अब लोग मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को स्वीकार कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से ऑस्ट्रेलिया के लोग पीड़ित हैं।

ऑस्ट्रेलिया	43%
अमेरिका	41%
ब्रिटेन	38%
कनाडा	37%
जर्मनी	32%

भारत में मानसिक स्वास्थ्य समस्या के आंकड़े 23 प्रतिशत हैं। | स्रोत : Statista

सुखिया फलवाली का एक भी फल नहीं बिका व घर में अनाज भी नहीं था। निःस्वार्थ दान और कान्हा द्वारा दिए गए गेहूं के केवल चार दानों ने उसकी तकदीर बदल दी।

उदारता का फल मीठा होता है

नन्हा कान्हा माखन-मिश्री के साथ रसीले फलों का शौकीन था। सुखिया फलवाली रोज गोकुल की गलियों में फल बेचती थी। एक दिन वह थकी-हारी कान्हा के दरवाजे पर बैठ गई। उसने उदास होकर कहा, 'सुबह से शाम हो गई, पर एक भी फल नहीं बिका। घर में अनाज भी नहीं है। हे भगवान, मेरी मदद करो!'

कान्हा वहीं पास में खेल रहे थे, सुखिया के पास आए और बोले, 'मैया, मुझे ये मीठे फल खिलाओ, भूख लगी है।' सुखिया ने कहा, 'फल दूंगी, पर तुम्हें इनकी कीमत चुकानी होगी, तुम्हें इन फलों के बदले में मुझे कुछ देना होगा।' कान्हा ने हंसकर कहा, 'हां-हां, अभी लाता हूं!' वह घर गए और अपनी छोटी-छोटी मुट्ठियों में गेहूं के दाने भरकर लौटे। उनकी छोटी मुट्ठी से गेहूं के दाने गिरकर रास्ते में ही बिखर गए और सुखिया तक पहुंचते-पहुंचते केवल चार दाने बचे। कान्हा ने कहा, 'मैया, ये लो कीमत!' सुखिया बोली, 'अरे, बस चार दाने?' कान्हा ने जवाब दिया, 'मैं तो मुट्ठी भर लाया था, पर रास्ते में गिर गए।' सुखिया ने मुस्कराकर कहा, 'कोई बात नहीं, ये सारे फल ले लो।' सुखिया ने कान्हा की भूख मिटाने के लिए सारे फल दे दिए। घर पहुंचकर सुखिया ने देखा कि उसकी टोकरी हीरे-मोतियों से भरी थी। उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया और बोली निःस्वार्थ भाव से किया गया कार्य अप्रत्याशित फल देता है। सुखिया की उदारता ने उसे अपार सुख और समृद्धि दी।

अंतर्यात्रा
संकलित

आज का इतिहास

फिल्म जगत के बहुआयामी कलाकार किशोर कुमार का निधन

रुपहले पर्दे पर चमकने वाले सितारों की बात करें, तो इनमें किशोर कुमार की पहचान सबसे चमकदार सितारों में से एक के तौर पर होती है। शानदार अभिनेता, सुरीले गायक, उम्दा निर्माता-निर्देशक, कुशल पटकथा लेखक और बेहतरीन संगीतकार के तौर पर किशोर को एक संपूर्ण कलाकार कहा जा सकता है। चाहे दर्द भरे गीत हों या रूमानियत से भरे प्रेमगीत, हुल्लड़ वाले जोशीले नगमे हों या संजीदा गाने, उनकी आवाज ने हर तरह के गीतों को यादगार बना दिया। उन्होंने हिंदी के अलावा और भी बहुत सी भाषाओं में गीत गाए। इस महान कलाकार ने 13 अक्टूबर 1987 को इस दुनिया को अलविदा कहा था। 1911 : स्वामी विवेकानंद की शिष्या मार्गरेट एलिज़ाबेथ नोबेल का मात्र 43 वर्ष की आयु में निधन। उन्हें उनके गुरु ने सिस्टर निवेदिता का नाम दिया था। 1999 : अटल बिहारी वाजपेयी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। 2013 : मध्य प्रदेश के दतिया जिले में एक पुल पर भगदड़ मचने से 109 लोगों की मौत। 1943 : इटली ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। 1976 : बोलिविया के दक्षिण में एक बोइंग 707 के दुर्घटनाग्रस्त होकर रिहाइशी इलाके में गिरने से कई लोगों की मौत।

सूचना अधिकार के बीस साल

भारत में आरटीआई कानून लागू हुए दो दशक पूरे हुए हैं, इसलिए इसके प्रभाव और क्रियान्वयन की चुनौतियों पर गौर करना होगा।

मुहम्मद खालिद जीलानी | मुद्दा

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को बीते बारह अक्तूबर को बीस बरस पूरे हो गए। सूचना के अधिकार को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा तथा आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय संधि में मानवाधिकार के रूप में देखा गया है।

भारत में लोक प्रशासन में पारदर्शिता, शुचिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्ट (सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम), 2002 बना, हालांकि इसे कभी अधिसूचित नहीं किया गया। यह लागू भी नहीं हुआ और इसके कमजोर प्रावधानों की आलोचना भी हुई।

वर्ष 2005 में एक व्यापक सूचना का अधिकार

अधिनियम, 2005 बना, जो लागू भी हुआ। भारत के संविधान के अनुच्छेद-19 (1) (ए) के अंतर्गत जो वाक्-स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों को दिया गया है, उसमें सूचना प्राप्त करने का अधिकार अंतर्निहित है। सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है। ये कानून नागरिकों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने, सरकारी गतिविधियों, नीतियों और निर्णयों के बारे में जानकारी लेने, लोक प्राधिकारियों के नियंत्रण में उपलब्ध सूचनाओं तक पहुंच हासिल करने और जन-सामान्य के प्रति नौकरशाही की जवाबदेही, शुचिता व पारदर्शिता का अधिकार देता है। भारत में आरटीआई कानून को लागू हुए दो दशक पूरे हुए हैं, इसलिए इसके प्रभाव और क्रियान्वयन की चुनौतियों पर गौर करना जरूरी होगा। यहां उल्लेखनीय है कि विश्व के 132 देशों ने सूचना के अधिकार को सांविधानिक गारंटी के तौर पर अपनाया या आरटीआई कानून बनाए। इन्हें लागू करने के लिए कानूनी ढांचों की मजबूती पर आधारित सेंटर फॉर लॉ एंड डेमोक्रेसी (सीएलडी) की ग्लोबल आरटीआई रेटिंग में वर्ष 2011 में भारत दूसरे स्थान पर था, लेकिन लगातार गिरावट के बाद 2024 में यह खिसक कर नौवें पायदान पर आ गया। इस गिरावट का कारण भारत के आरटीआई कानून की दूसरी अनुसूची में व्यापक अपवाद होना है, जो सुरक्षा, खुफिया और अन्य निकायों से सूचना तक पहुंच को प्रतिबंधित करते हैं। यह छूट इसलिए दी गई है, ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यक्तिगत गोपनीयता या अन्य महत्वपूर्ण हितों को सुरक्षित रखा जा सके। हालांकि, इन छूटों की व्याख्या करने की गुंजाइश काफी होती है, जिसका उपयोग अक्सर जन सूचना अधिकारियों द्वारा सूचना देने से बचने के लिए किया जाता है। सरकारों की राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव का ही नतीजा है कि इस कानून के अस्तित्व में आने के दो दशक बाद भी सरकारी कार्यालयों में आसानी से सूचना देने की प्रवृत्ति विकसित नहीं हो पाई है, कहीं बड़ी संख्या में आवेदन लंबित हैं, तो कहीं आधी-अधूरी, अपूर्ण और भ्रामक सूचनाएं दी जाती हैं। राज्य सूचना आयोगों में अपीलों की तादाद लगातार बढ़ती रहती है, न तो सूचना देने में तीस दिन की समय-सीमा का पालन किया जाता है और न ही सूचना देने और अपीलों के निस्तारण में देरी का कारण ही बताया जाता है। सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 के जरिये केंद्र और राज्य स्तर पर सूचना आयुक्तों की सेवा शर्तों में संशोधन हुआ, इन संशोधनों से सूचना आयुक्तों की स्वतंत्र कार्यप्रणाली प्रभावित हुई है। इसी तरह वर्ष 2023 में आरटीआई एक्ट की धारा-8 (1)(जे) के संशोधन में सभी व्यक्तिगत जानकारी को प्रकटीकरण से छूट दी गई। ऐसे में, आम लोगों का हथियार बन चुके इस कानून के मूल स्वरूप को बचाए रखना और लोगों में इस कानून के इस्तेमाल की बेहतर समझ बनाना एक बड़ी चुनौती जैसा है। सूचना के अधिकार कानून के अमल में अगर ऐसी ही उदासीनता जारी रही, तो यह कानून निष्प्रभावी हो जाएगा और अभी घपलों-घोटालों, लोक सेवकों के भ्रष्टाचार से सबंधित जो भी जानकारियां छनकर ही सही, मिल रही हैं, वे भी नहीं मिलेंगी।

Special arrangements by Amar Ujala

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेन्ट्स प्रा.लि. के लिए मुद्रक, प्रकाशक समीर माहेश्वरी द्वारा नवभारत प्रेस, नवभारत भवन, प्रेस कॉम्पलेक्स, जी.ई.रोड, रायपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित. प्रधान संपादक : समीर माहेश्वरी, संपादक : राजेश आर. जोशी* (पी.आर.बी. कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिये जिम्मेदार)
■ रायपुर फोन : 0771-4343434, 2535555-66-77, ■ भुवनेश्वर : 0674-2380511/2380518 ■ बिलासपुर : 07752-230591, 407748, 224563 ■ वर्ष 66 ■ अंक 140 (रजि.नं. 13045/59 आरएनआई), पो. रजिस्टर्ड नं. छ.ग./रायपुर संभाग/61/2025-27 ■ भिलाई फोन : (0788) 2294181, 4030655

https://t.me/AllNewsPaperSPai

पायनियर
नई दिल्ली, सोमवार, 13 अक्टूबर 2025

नोबल पुरस्कार

खोज, सृजनात्मकता एवं शांति

1895 में अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत द्वारा स्थापित नोबेल पुरस्कार निस्संदेह इस धरती पर सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं। वर्षों से, यह किसी के काम की सर्वोच्च मान्यता बन गया है। वास्तव में, यह विज्ञान, अर्थशास्त्र, साहित्य और शांति के क्षेत्र में मानवीय उपलब्धियों का जश्न मनाते हुए, सबसे प्रतिष्ठित वैश्विक सम्मान के रूप में विकसित हुआ है। इस वर्ष, चिकित्सा के क्षेत्र में, मैरी ब्रुनको, फ्रेड रामस्डेल और शिमोन सकागुची को परिधीय प्रतिरक्षा सहिष्णुता से संबंधित उनकी महत्वपूर्ण खोजों के लिए सम्मानित किया गया है।

भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जॉन क्लार्क, मिशेल एच. डेवोरेट और जॉन एम. मार्टिनिस को विद्युत परिपथ में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटीकरण को प्रदर्शित करने वाले उनके प्रयोगों के लिए दिया गया है, जबकि रसायन विज्ञान में, सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर याघी को धातु-कार्बनिक ढाँचे (एमओएफ) के विकास के लिए पुरस्कार मिला है। लेकिन जब शांति और साहित्य के लिए नोबेल की बात आती है, तो अलग-अलग दृष्टिकोण होते हैं क्योंकि वे अत्यधिक व्यक्तिपरक होते हैं।

प्रसिद्ध उपन्यासकार वी.एस. नायपॉल को इसे पाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। इस बार, हंगेरियन लेखक लास्जलो क्राज्नाहोरकाई को उनके सम्मोहक और दूरदर्शी कृति के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जो सर्वनाशकारी आतंक के बीच कला की शक्ति की पुष्टि करता है। नोबेल शांति पुरस्कार, जो शायद सबसे अधिक जांचा-परखा गया पुरस्कार है, पिछले कुछ वर्षों में विवादों का विषय रहा है। इस वर्ष, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को शांति समझौतों, विशेष रूप से आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच, को सुगम बनाने में उनकी भूमिका और मध्य पूर्व और यूक्रेन में संघर्षों को समाप्त करने के उनके प्रयासों के लिए नामांकित किया गया था।

हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को यह पुरस्कार नहीं मिला क्योंकि 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला की मुख्य विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया, जो फिलहाल गुप्त रूप से रह रही हैं। मचाडो को लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के उनके कार्यों के लिए वेनेजुएला की आयरन लेडी के रूप में भी जाना जाता है। नोबेल शांति पुरस्कार को लेकर विवाद अक्सर वैश्विक राजनीति की जटिल प्रकृति से उपजा है।

यद्यपि इस पुरस्कार का उद्देश्य शांति के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों या संगठनों को मान्यता प्रदान करना है, चयन प्रक्रिया भू-राजनीतिक विचारों से प्रभावित हो सकती है, जिससे पुरस्कार देने के पीछे के वास्तविक उद्देश्यों पर बहस छिड़ सकती है। वास्तव में, अब तक दो लोगों ने नोबेल पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया है। जीन-पॉल सार्त्र और ले ड्यूक थो ने स्वेच्छा से नोबेल पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया था।

सार्त्र ने 1964 में नोबेल साहित्य पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया था क्योंकि उन्होंने सभी आधिकारिक सम्मानों को अस्वीकार कर दिया था, और थो ने वियतनाम में चल रहे संघर्ष के कारण 1973 के शांति पुरस्कार को अस्वीकार कर दिया था। अमेरिकी विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर को 1973 में शांति पुरस्कार मिला था, लेकिन इसके औचित्य पर अभी भी बहस होती है। अंततः, नोबेल पुरस्कार किसी की उपलब्धि के लिए एक सम्मान मात्र है, लेकिन यह उस व्यक्ति को परिभाषित नहीं करता। दिलचस्प बात यह है कि महात्मा गांधी ने कभी नोबेल शांति पुरस्कार नहीं जीता, लेकिन वे उन सभी लोगों से कहीं ऊपर हैं जिन्होंने इसे जीता है!

गाज़ाः राजनय एवं शांति की मरीचिका

चुनौती लिखित समझौतों में नहीं बल्कि गाजा के ऐतिहासिक आधार में है, जहां वैचारिक तलछट गहरी और प्रतिरोधी है। ट्रम्प और टोनी ब्लेयर के नेतृत्व वाले शांति बोर्ड की देखरेख में एक अस्थायी फि लिस्तीनी तकनीकी समिति को अनिवार्य करके और हमास के विसैन्यीकरण की मांग करके, योजना संघर्ष समाधान के लिए एक रैखिकता की पूर्वकल्पना करती है।

नीलांत इलांगमुआ
लेखक, अंतरराष्ट्रीय मामलों पर टिप्पणीकार हैं।

खैर कुछ हफ़्ते पहले यरुशलम, गाजा और तेल अवीव में बिताए मेरे दिन मूलतः पिछले साल तेहरान में बिताए मेरे दिनों से अलग नहीं थे। वे कट्टर दुश्मन हैं, एक ऐसे संघर्ष में फँसे हुए हैं जिसकी जड़ें जितनी प्राचीन हैं उतनी ही अड़ियल भी, यह संघर्ष बाइबल में वर्णित जमीन और स्मृति पर दावों को लेकर है। ईरानियों और इजराइलियों, दोनों के बीच एक बात समान है।

लोगों के साथ न सिर्फ.पराजित होने वाले विरोधियों जैसा व्यवहार किया जाता है, बल्कि उन्हें गहराई से जड़ें जमाए राष्ट्रीय और धार्मिक अनिवार्यताओं के अस्तित्वगत अवतार के रूप में भी देखा जाता है। जहां ईरानी अपनी स्मृति में सबसे गंभीर आर्थिक तंगी झेल रहे हैं, वहीं इजराइली भी चिंता और तंगहाली का सामना कर रहे हैं, हालाँकि एक सैन्य रूप से मुखर ढांचे के भीतर।

7 अक्टूबर, 2023 को हमास द्वारा किए गए हमलों के बाद, इजराइली जवाबी हमले हुए, जिनकी परिणति एक विनाशकारी चरमोत्कर्ष में हुई जिसने दोनों पक्षों के समुदायों को दुःख, बबार्दी और गहरा आघात पहुंचाया। दो साल बाद भी, इन शत्रुताओं के झटके अभी भी मापे जा रहे हैं, न केवल जान गंवाने वालों के रूप में, बल्कि उन मनोवैज्ञानिक और सामाजिक जख्मों के रूप में भी जो पीढ़ियों को आकार देंगे। जो सामने आ रहा है वह पारंपरिक संघर्ष से ज्यादा दर्द का एक पैलिम्प्सेस्ट है, जहाँ हर विस्फोट नागरिक मानस पर अमिट छाप छोड़ जाता है। अगले अध्यायों की भविष्यवाणी करने का कोई सटीक सूत्र नहीं है, लेकिन निस्संदेह ये महत्वपूर्ण समय हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप इस सप्ताहांत बेन गुरियन हवाई अड्डे पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं, जाहिर तौर पर नेसेट को संबोधित करने के लिए।

ट्रंप की शांति योजना, अपनी महत्वाकांक्षा में दुस्साहसी, शोक और उग्रवाद से ग्रस्त एक क्षेत्र को एक कट्टरपंथ-मुक्त, आर्थिक रूप से पुनर्जीवित और राजनीतिक रूप से स्थिर राजनीति में बदलने का प्रयास करती है।

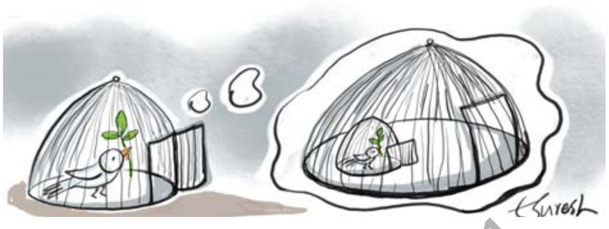

इसके बीस बिंदु एक अर्ध-काल्पनिक दृष्टिकोण को व्यक्त करते हैं: एक आतंक-मुक्त गाजा जिसकी देखरेख टेक्नोक्रेट करेंगे, मानवीय सहायता से भरपूर होगा, अंतर्राष्ट्रीय निगरानी के अधीन होगा, और सशस्त्र संघर्ष को त्यागने के लिए आर्थिक रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा।

फिर भी चुनौती लिखित समझौतों में नहीं बल्कि गाजा के ऐतिहासिक आधार में है, जहां वैचारिक तलछट गहरी और प्रतिरोधी है। ट्रम्प और टोनी ब्लेयर के नेतृत्व वाले शांति बोर्ड की देखरेख में एक अस्थायी फि लिस्तीनी तकनीकी समिति को अनिवार्य करके और हमास के विसैन्यीकरण की मांग करके, योजना संघर्ष समाधान के लिए एक रैखिकता की पूर्वकल्पना करती है जो वास्तविकता शायद ही कभी प्रदान करती है।

यह मानता है कि संरचनात्मक सुधार, सशर्त माफी और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक निवेश शहादत, कारावास और बेदखली की सांस्कृतिक स्मृति को ग्रहण लगा सकते हैं। फिर भी यह रैखिकता क्रमिक संकटों को रणनीतिक लाभ में बदलने की हमास की क्षमता को कम करके आंकती है, जो संगठन की अनुकूलन तीक्ष्णता की एक गहरी गलत व्याख्या को प्रकट करती है।

हमास, अपने वरिष्ठ नेतृत्व के सिर काटने से बच गया है - जिसमें कभी अछूत रहे व्यक्ति भी शामिल हैं इसने शहरी गुरिल्ला हठ, बंधक कूटनीति और वैचारिक भर्ती की हमास की तिपाई रणनीति को नया रूप दिया। 7 अक्टूबर के हमलों का केंद्र रहे सिनवार ने 2004 में संस्थापक शेख अहमद यासीन की हत्या से भी ज्यादा प्रभाव डाला। चल रही शांति वार्ता में, हमास इजराइल से यासीन का शव सौंपने की मांग कर रहा है–यह प्रतीकात्मकता से भरपूर कदम है जो संगठन की क्षति को वैधता और विनाश को स्थायी राजनीतिक मुद्रा में बदलने की क्षमता को उजागर करता है।

केवल समय ही बताएगा कि क्या हमास ने मंडेला की अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस की रणनीतिक कुशाग्रता और सुलहकारी दृष्टिकोण को आत्मसात किया है, या क्या यह मुस्लिम ब्रदरहुड के सिद्धांतवादी अतिवाद और पदानुक्रमिक कठोरता से बंधा हुआ है, जो उग्रवाद और वैचारिक अनम्यता के चक्र को जारी रखता है।

हमास के भीतर आंतरिक बहसें तस्वीर को और जटिल बनाती हैं। खालिद मशाल के इर्द-गिर्द एक व्यावहारिक गुट संयमित व्यवहार की वकालत करता है: पीएलओ में एकीकरण, द्वि-राज्य ढाँचे को मान्यता, पीए सत्ता को हथियार सौंपना, और विशुद्ध रूप से उग्रवादी इकाई के बजाय एक राजनीतिक कर्ता के रूप में पुनः स्थापित होना। इसके विपरीत, खलील अल-हय्या के नेतृत्व वाला कट्टरपंथी गुट इस बात पर जोर देता है कि गाजा पर पूर्ण नियंत्रण और बंधकों पर नियंत्रण के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। यह विभाजन विद्रोही आंदोलनों में एक परिचित तनाव का प्रतीक है: अस्तित्व बनाम अधिकतमवादी दावा। दिलचस्प बात यह है कि कोई यह तर्क दे सकता है कि संगठन को कमजोर करने के बजाय, इस आंतरिक बहस ने हमास की रणनीतिक दक्षता को और निखारा है, जिससे उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयम का प्रदर्शन करने के साथ-साथ घरेलू स्तर पर दमनकारी प्रभुत्व बनाए रखने में मदद मिली है।

इस बीच, गाजा में मानवीय संकट संघर्ष के गहरे होते नैतिक दांव को उजागर करता है, एक ऐसी वास्तविकता जिसका हमास ने अपने अत्याचारों को छिपाने और अत्यधिक परिष्कृत प्रचार तंत्र के माध्यम से वैश्विक सहानुभूति हासिल करने के लिए दोहन किया है।

भर्ती, कट्टरपंथ और सामुदायिक लामबंदी को स्पष्ट अस्तित्वगत शिकायतों द्वारा सुगम बनाया जाता है; पीड़ित होने और प्रतिरोध के आख्यान बचपन से ही गढ़ दिए जाते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आने वाली पीढ़ियाँ सामान्य स्थिति की चाहत के बावजूद उग्रवादी भावना को आत्मसात करती रहें। दूसरे शब्दों में, बाहरी कर्ता जिन संकटों को कम करना चाहते हैं, उन्हें हमास की स्थायी वैचारिक रणनीति में शामिल कर लिया जाता है। स्थिरीकरण और पुनर्निर्माण के महत्वाकांक्षी इरादे वाली ट्रम्प की योजना को इस दोहरी वास्तविकता से जूझना होगाः गाजा मानवीय हताशा का स्थान और परिष्कृत असममित रणनीति का एक अग्निकुंड है। विसैन्यीकरण खंड, तकनीकी निगरानी और आर्थिक प्रोत्साहन एक ऐसे संगठन का सामना करते हैं जो बार-बार पीड़ा और अवसर दोनों को अनुकूलित, संकरित और हथियार बनाता है। गाजा का उभरता हुआ प्रतिमान एक साथ भेद्यता और लचीलेपन का प्रतीक है, जहाँ सैन्य या कूटनीतिक प्रभाव के पारंपरिक आकलन ऐतिहासिक स्मृति, वैचारिक प्रतिबद्धता और संगठनात्मक अनुकूलनशीलता द्वारा लगातार अस्थिर होते रहते हैं।

गाजा, शांत करने योग्य क्षेत्र से ज्यादा असममित शक्ति का एक ऐसा केंद्र है जहाँ ऐतिहासिक शिकायतें, धार्मिक उत्साह और अवसरवादी रणनीतियाँ एक-दूसरे से जुड़ी हैं। ट्रम्प की योजना, अपनी तमाम महत्वाकांक्षाओं के बावजूद, यह मानकर चलती है कि संरचनात्मक और आर्थिक हस्तक्षेप हमास के व्यवहार को आकार देने वाले प्रोत्साहनों को पुनर्संयोजित कर सकते हैं। फिर भी, शांति प्रक्रिया युद्धविराम, कैदियों की अदला-बदली या ढाँचे के पुनर्वास से कहीं बढ़कर है, यह एक ऐसे वातावरण में सामने आती है जहां हर रियायत और हर चाल को ऐतिहासिक स्मृति के चश्मे से देखा जाता है।

हमास एक ऐसी इकाई के रूप में विकसित हुआ है जो एक साथ बातचीत में शामिल होती है और दबाव बनाती है, तकनीकी और मानवीय ढांचों में भाग लेती है, जबकि विषमता के उन साधनों को बरकरार रखती है जो उसके अधिकार को बनाए रखते हैं - एक रणनीतिक परिष्कार जो उस मानवीय पीड़ा से अविभाज्य है जिसका वह शोषण करती है और जिसे वह कायम रखती है।

आश्चर्य की बात नहीं कि स्थानीय लोगों ने इस द्वंद्व को चुपचाप खारिज कर दिया है। फिर भी, कट्टरपंथ, आर्थिक अभाव और क्रूर आतंकवादी रणनीतियाँ, जिन्हें अक्सर हमास और अन्य उग्रवादी समूहों के साथ मिलीभगत करने वाले बाहरी तत्वों द्वारा बढ़ावा दिया जाता है, उनके दैनिक जीवन को नियंत्रित करती रहती हैं। यही वह जगह है जहाँ किसी भी वास्तविक समाधान की तलाश की जानी चाहिए, हालांकि इतिहास बहुत कम आशा देता है।

पर्यावरणीय लचीलापन और समृद्धि का ताना-बाना

भारत, जो दुनिया के सबसे बड़े कपास उत्पादकों में से एक है, इस अवसर के सबसे आगे है। पीढ़ियों से, इस फसल ने लाखों छोटे किसानों का समर्थन किया है और देश भर में ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं और समुदायों को आकार दिया है।

चंद्रकांत कुंभानी
लेखक, स्तम्भकार हैं।

कपास सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, यह एक ऐसा रेशा है जो दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं, पारिस्थितिक तंत्रों और मानव जीवन को एक सूत्र में पिरोता है। हमें गर्म रखने वाले कपड़ों से लेकर इसकी खेती पर निर्भर आजीविका तक, कपास वैश्विक व्यापार और ग्रामीण समृद्धि, दोनों के केंद्र में बना हुआ है।

जैसे-जैसे दुनिया खेती और जीवन जीने के ज्यादा टिकाऊ तरीके खोज रही है, कपास एक सशक्त उदाहरण प्रस्तुत करता है कि कैसे किसान इस बदलाव का नेतृत्व कर सकते हैं, पर्यावरण का संरक्षण करते हुए ज्यादा सुरक्षित और लाभदायक आजीविका का निर्माण करना।

भारत, जो दुनिया के सबसे बड़े कपास उत्पादकों में से एक है, इस अवसर के सबसे आगे है। पीढ़ियों से, इस फसल ने लाखों छोटे किसानों का समर्थन किया है और देश भर में ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं और समुदायों को आकार दिया है। आज, जबकि यह क्षेत्र जलवायु परिवर्तनशीलता, भूजल की कमी और बाजार में उतार-चढ़ाव जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है, पूरे भारत में कपास के खेतों में एक शांत क्रांति हो रही है।

स्थायित्व अब एक विकल्प नहीं, बल्कि एक आवश्यकता और विकास का एक शक्तिशाली माध्यम है। पूरे भारत में, बढ़ती संख्या में किसान ऐसी पद्धतियाँ अपनाने लगे हैं जो कपास को अधिक उत्पादक और अधिक लचीला बनाती हैं। जैविक और पुनर्योजी खेती, फसल चक्र, अंतर-फसल और एकीकृत कीट प्रबंधन के उदाहरण उत्साहजनक परिणाम दिखा रहे हैं–मृदा स्वास्थ्य में सुधार, जल संरक्षण और रासायनिक आदानों पर निर्भरता कम करना।

ये तरीके बंजर भूमि को पुनर्स्थापित कर रहे हैं, उत्पादन लागत कम कर रहे हैं और किसानों को अप्रत्याशित मौसम के पैटर्न के अनुकूल होने में मदद कर रहे हैं। अब चुनौती इन सिद्ध प्रथाओं को छिटपुट सफलताओं से व्यापक रूप से अपनाने की है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जलवायु परिवर्तन के बावजूद कपास की खेती व्यवहार्य बनी रहे। हालाँकि, बदलाव केवल खेत तक ही सीमित नहीं रह सकता। वास्तविक प्रभाव के लिए, किसानों की आवाज मजबूत होनी चाहिए और बाजारों तक उनकी पहुँच अधिक न्यायसंगत होनी चाहिए।

आज, अधिकांश छोटे कपास उत्पादक अभी भी बिचौलियों की लंबी श्रृंखलाओं के माध्यम से बेचते हैं, जिससे उनके पास सौदेबाजी की शक्ति कम होती है और अंतिम मूल्य में उनका हिस्सा बहुत कम होता है।

हालांकि भारत भर में किसान समूहों और उत्पादक संगठनों के उदाहरण उभर रहे हैं, फिर भी वे कपास क्षेत्र का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही दशार्ते हैं। इन मॉडलों का विस्तार यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि किसान अपनी उपज को एकत्रित कर सकें, गुणवत्ता में सुधार कर सकें और जिनरों, कपड़ा इकाइयों और ज़िम्मेदार ब्रांडों के साथ सीधे बातचीत कर सकें।

जब छोटे किसान बेहतर ढंग से संगठित होते हैं और टिकाऊ कपास को महत्व देने वाले बाजारों से जुड़े होते हैं, तो उन्हें न केवल अधिक आय प्राप्त होती है, बल्कि अधिक स्थिरता भी प्राप्त होती है। यदि भारत के कपास किसानों के लिए स्थिरता को वास्तविक आर्थिक सशक्तिकरण में बदलना है, तो बड़े पैमाने पर इन मार्गों का निर्माण आवश्यक है।

इन आर्थिक बदलावों के साथ-साथ हो रहा सामाजिक परिवर्तन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। महिलाएं, जो कृषि कार्यबल का एक बड़ा और अक्सर कम पहचाना जाने वाला हिस्सा हैं, कपास की सफलता में आवश्यक योगदानकर्ता के रूप में तेजी से स्वीकार की जा रही हैं।

जब महिला किसानों को प्रशिक्षण, तकनीक और वित्तीय संसाधनों तक समान पहुंच प्राप्त होती है, तो पूरे समुदाय को लाभ होता है। महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करना और समानता को बढ़ावा देने वाले किसान सहकारी समितियों और उत्पादक संगठनों का समर्थन करना ऐसी व्यवस्थाएँ बनाने में मदद करता है जहाँ ज्ञान, अवसर और लाभ अधिक समान रूप से साझा किए जाते हैं।

बेशक, चुनौतियाँ बनी हुई हैं। जलवायु तनाव, मृदा उर्वरता और श्रम असमानताएँ कृषक समुदायों की सहनशीलता की परीक्षा ले रही हैं। फिर भी, इनमें से कई समस्याओं के समाधान पहले से ही मौजूद हैं; अब जरूरत है पैमाने की। जल संरक्षण और कुशल उपयोग को बढ़ावा देने, मृदा स्वास्थ्य को बहाल करने और कार्य स्थितियों में सुधार लाने वाली सिद्ध पद्धतियों को स्थायी बदलाव लाने के लिए अधिक से अधिक किसानों तक पहुँचाना होगा। यहीं पर सहयोग महत्वपूर्ण हो जाता है। नागरिक समाज संगठनों, कॉर्पोरेट्स, सरकारी एजेंसियों और परोपकारी लोगों, सभी की किसानों की शिक्षा, जागरूकता और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका है।

उत्साहजनक रूप से, सहयोग का यह बढ़ता हुआ पारिस्थितिकी तंत्र दशार्ता है कि कपास का भविष्य वास्तव में टिकाऊ हो सकता है, एक ऐसा भविष्य जहाँ उत्पादकता, पर्यावरण संतुलन और मानव कल्याण साथ-साथ आगे बढ़ें। जब कपास की खेती, प्रसंस्करण और मूल्यांकन में स्थिरता केंद्रीय हो जाती है, तो यह न केवल फसल की रक्षा करती है, बल्कि उन लाखों परिवारों की भी रक्षा करती है जिनका जीवन इससे जुड़ा हुआ है। कपास की कहानी हमेशा से ही मानवीय रही है।

यह उन हाथों की कहानी है जो बोते हैं, चुनते हैं, कातते हैं और बुनते हैं, आजीविका को बनाए रखते हैं और भविष्य का निर्माण करते हैं। स्थायित्व को अपनाकर, भारत यह प्रदर्शित कर सकता है कि कैसे पारंपरिक कृषि पद्धतियाँ और समकालीन दृष्टिकोण मिलकर समुदायों और पर्यावरण, दोनों की रक्षा कर सकते हैं। इसमें जोखिम बहुत अधिक है, लेकिन क्षमता भी उतनी ही है।

कपास दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला प्राकृतिक रेशा बना हुआ है, और आज लिए जाने वाले निर्णय - खेत से लेकर कपड़े तक - यह तय करेंगे कि क्या यह लाखों किसानों और उनके समुदायों की आजीविका का आधार बना रहेगा।

भारत कपास को सतत विकास का एक आदर्श बनाने में अग्रणी भूमिका निभा सकता है, यह दिखाते हुए कि कैसे एक पारंपरिक फसल पर्यावरणीय स्वास्थ्य और ग्रामीण परिवारों के लिए अधिक स्थिर, समान आजीविका, दोनों को सुरक्षित कर सकती है।

आप की बात

यह तर्क कदापि उचित नहीं

टीन शेड में चलने वाले स्कूलों के अच्छे एवं बेहतर परिणाम आते हैं,यह दिल्ली सरकार के तर्क की दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ी आलोचना की है। अदालत का कहना है कि अगर अच्छे परिणाम टिन शेड वाले स्कूल ही दे सकते हैं तो क्या अब बाकी सभी स्कूलों को टीन शेड में परिवर्तित कर दिया जाए। कह सकते हैं कि एक तरह से यह दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग की आलोचना ही हम कह सकते हैं। हमारा यहां यही कहना है कि टिन शेड में चलने वाले स्कूलों की अपनी कई समस्याएं भी हो सकती है जिसमें बिजली,पानी जैसी बुनियादी असुविधाओं के अलावा छत से पानी टपकने की भी समस्याए आम रह सकती है। तब अगर वही स्कूल किसी मजबूत सिमेंटेंट बिल्डिंग में चल रहा है एवं कई मंजिला भी है तो वह हर तरह से पूरी तरह से सुरक्षित एवं व्यवस्थित भी कहा जा सकता है। टिन शेड वाले स्कूल कभी भी निजि स्कूलों का सामना भी नहीं कर सकते हैं। फिर आजकल तो पीएम राइज एवं सीएम राइज स्कूल काफी बनाए जा रहे हैं, तब यह कहना कि टिन शेड के स्कूल हर तरह से बेहतर है हम इस तर्क को उचित नहीं कह सकते हैं। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों को चाहिए कि वे नवागंतुक नये बच्चों के लिए आज अच्छे एवं बेहतर स्कूलों की नींव अवश्य डालें।

– **मनमोहन राजावत**, शाजापुर

तालिबान की सही सोच

अगस्त 2021 जब अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन हुआ तब यह आशंका थी कि वहां की तालिबान सरकार पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के लिए समस्याएं पैदा कर सकती है लेकिन भारत ने धैर्यपूर्ण और लचीलापन दिखाते हुए अपना संयत व्यवहार बनाए रखा तथा संकट के समय उसका भरपूर साथ भी दिया। वहां के तालिबान शासन ने भी समझदारी दिखाते हुए व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया तथा भारत के महत्व को समझा दोनो देशो के संबंध आर्थिक एवं सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं । अफगानियो के लिए भारत में अनुकूल व्यवसायिक वातावरण है ।इसका प्रमाण हे कि चालु वित्तीय वर्ष में अफगानिस्तान और भारत के बीच व्यापार 763 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जिसमें अफगानिस्तान का निर्यात 541 मिलियन डॉलर और भारत से आयात 222 मिलियन डॉलर है। पिछले कई दशको से अशांत रहे अफगानिस्तान के लिए यह बहुत बड़ा आर्थिक एवं व्यवसायिक संबल है।वहीं अफगानिस्तान में लिथियम, नियोडिमियम, लैंथेनम और सेरियम जैसी दुलर्भ धातु के अलावा लौह अयस्क, तांबा और एल्यूमीनियम के भी प्रचुर भंडार हे। भारत की इसी व्यवहारिकता एवं लचीलेपन के कारण अफगानिस्तान ने भारतीय कंपनियों को अपने खनन क्षेत्र में निवेश के लिए आमंत्रित किया है ।

– **विमलेश पगारिया**, बदनावर, म.प्र.

आई लव यू कहना यौन उत्पीड़न नहीं

आज के समय में समाज में यौन उत्पीड़न को लेकर जागरूकता बढ़ी है, जो एक सकारात्मक कदम है। परंतु इसके साथ-साथ यह भी जरूरी है कि हम उसके सही अर्थ और सीमाओं को समझें। केवल किसी महिला से ह्यआई लव यूह्ण कहना अपने आप में यौन उत्पीड़न नहीं माना जा सकता। यह वाक्य प्रेम, स्नेह या भावनाओं की अभिव्यक्ति हो सकती है, जिसका आशय व्यक्ति की नीयत पर निर्भर करता है। यदि किसी ने यह शब्द ईमानदारी, सम्मान और मयार्दा के साथ कहा है, बिना किसी दबाव, धमकी या शारीरिक/मानसिक उत्पीड़न के, तो इसे अपराध नहीं माना जा सकता। यह बातें कोर्ट में भी साबित हो चुकी हैं। लेकिन जब यही शब्द बार-बार, बिना अनुमति या अपमानजनक ढंग से कहा जाए, या इसके साथ कोई अनुचित व्यवहार जोड़ा जाए, तो यह यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आ सकता है। कानून की दृष्टि में किसी भी तरह का यौन उत्पीड़न तभी माना जाता है जब किसी महिला की गरिमा, निजता या सुरक्षा पर आंच आती हो। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि भावनाओं की अभिव्यक्ति तथा उत्पीड़न दोनों में स्पष्ट अंतर है। समाज में परस्पर सम्मान और समझ का माहौल बनाए रखना ही सही रिश्तों और सुरक्षित वातावरण की नींव है।

– **संदीप कुमार**, मधुपुर, झारखंड

जातिवाद का जहर

भारत की सामाजिक संरचना में जातिवाद एक सामाजिक जहर बन चुका है इसका जीता जागता उदाहरण हरियाणा के अनुसूचित जाति के आईपीएस अधिकारी वाई पुरन कुमार के द्वारा अपने आवास पर गोली मारकर की गई आत्महत्या है। पूर्व आईएएस अधिकारी ने मृत्यु से पहले 8 पन्नों का एक नोट लिखा था जिसमें उन्होंने उच्च अधिकारियों के द्वारा जातिय एवं मानसिक उत्पीड़न, ट्रांसफर पोस्टिंग में भेदभाव और सार्वजनिक स्थान पर बेज्जती करने संबंधी जानकारी विस्तार से दी गई है। इस संदर्भ मे अधिकारियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के अलावा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण एक्ट 1989 के तहत भी प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज की गई है।इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने यह सोचने को मजबूर कर दिया है कि यदि आईपीएस /आईपीएस भी जातिय भेदभाव, उत्पीड़न अत्याचार के शिकार हो सकते हैं तो देश में दबे कुचले समाज के लोगों को जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं उनका क्या हश्र होता होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पूर्व आईपीएस के परिवार से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की और दोषियों को बक्शा ने जाने का आश्वासन भी दिया है।

– **वी के जाटव**, नई दिल्ली

पाठकगण अपने विचार **responsemail.hindipioneer@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

मजबूत रक्षा संबंधों में बंधते भारत-ब्रिटेन

डॉ. मनन द्विवेदी
एसिस्टेंट प्रोफेसर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन
manannanny@gmail.com

ब्रिटेन के साथ हाल में हुए मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के बाद अब रक्षा और प्रौद्योगिकी सहयोग को नयी ऊर्जा मिल रही है. भारत-ब्रिटेन के रक्षा संबंध ऐसे समय में नये दौर में प्रवेश कर रहे हैं, जब भारत विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और सुरक्षा समझौते को वरीयता दे रहा है. ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता जहां अमेरिकी टैरिफ से उपजे दबाव की कमोबेश भरपाई करेगा, वहीं यह कदम ज्यादा से ज्यादा देशों के साथ संबंध मजबूत करने की भारत की नीति का भी परिचायक है.

ब्रिटेन के साथ हुआ रक्षा समझौता ऐसे समय में भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जब अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते पहले जैसे नहीं रह गये हैं. ब्रिटेन के साथ हाल में हुए मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के बाद अब रक्षा और प्रौद्योगिकी सहयोग को नयी ऊर्जा मिल रही है. हाल ही में भारत यात्रा पर आये ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के साथ मुंबई में बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और ब्रिटेन स्वाभाविक साझेदार हैं और दोनों देशों के बीच साझेदारी वैश्विक स्थिरता एवं आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण आधार बन रही है. प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत-ब्रिटेन संबंधों का आधार लोकतंत्र, स्वतंत्रता और कानून के शासन जैसे मूल्यों में साझा विश्वास है. उनका कहना था कि यह महज एक व्यापारिक समझौता नहीं है, बल्कि विश्व की दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच साझा उन्नति, साझा समृद्धि तथा साझा जनता का मार्गदर्शक खाका है. बाजार पहुंच के साथ यह समझौता दोनों राष्ट्रों के लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमइ) को सशक्त बनाएगा तथा लाखों युवाओं के समक्ष नयी रोजगार संभावनाओं के दरवाजे भी खोलेगा.

भारत-ब्रिटेन के रक्षा संबंध ऐसे समय में नये दौर में प्रवेश कर रहे हैं, जब भारत विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और सुरक्षा समझौते को वरीयता दे रहा है. स्वाभाविक है कि अमेरिका जैसी सुरक्षा साझेदारी का हमारा रोडमैप दूसरे देशों के साथ भी ऐसे ही समझौते करने को प्रेरित करता है. बेशक ब्रिटेन आज पहले जैसी मजबूत स्थिति में नहीं रह गया है, लेकिन स्टार्मर पिछले करीब एक साल से ब्रिटेन के रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने की पुरजोर कोशिश में जुटे हुए हैं, जिससे आर्थिक विकास को गति दी जा सके. स्टार्मर ने नाटो लक्ष्यों के अनुरूप खर्च बढ़ाने का वादा किया है. साथ ही, निर्यात बढ़ाने पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है. इसके तहत पिछले दिनों ब्रिटेन ने नॉर्वे के साथ 13.5 अरब डॉलर का फ्रिगेट अनुबंध किया था. कीर स्टार्मर के नेतृत्व में ब्रिटेन ने यह समझा है कि नयी दिल्ली के साथ रक्षा समझौता दोनों देशों के बीच के रणनीतिक रिश्ते को मजबूत करेगा. ब्रिटिश सत्ता प्रतिष्ठान का आधिकारिक पोर्टल बता रहा है कि 'भारत के साथ 350 मिलियन पाउंड के रक्षा समझौते के तहत भारतीय सेना को ब्रिटिश मिसाइलों की आपूर्ति की जायेगी और इससे ब्रिटेन में सैकड़ों रोजगार को मदद मिलेगी. भारत-ब्रिटेन रक्षा-उद्योग सहयोग ने नयी ऊंचाइयां छुई हैं, जिसके तहत ब्रिटेन भारतीय नौसैनिक जहाजों के लिए बिजली से चलने वाले इंजन देगा. कीर स्टार्मर ने मुंबई में दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत के साथ 350 मिलियन पाउंड के सौदे से उत्तरी आयरलैंड में रोजगार के सैकड़ों अवसर सृजित होंगे और बदले में ब्रिटेन अपने महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार भारत को एयर डिफेंस मिसाइलों और लांचरों की आपूर्ति करेगा.'

रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले जारी रखने के इस दौर में ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे देशों व पूर्व औपनिवेशिक शासकों पर यूक्रेन को हथियारों तथा तकनीकों से मदद करने की बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है, क्योंकि वे संसाधनों से संपन्न हैं और यूक्रेन की मदद करने में सक्षम भी हैं. यह ज्ञात तथ्य है कि यूक्रेन इतने समय से रूस के खिलाफ जंग में बना हुआ है, तो इसकी एक वजह ब्रिटिश मार्टलेट मिसाइलें हैं. ब्रिटेन वही मिसाइलें भारत को देने जा रहा है. आसमान और जमीन पर मार करने में समान रूप से सक्षम और बेहद हल्की इस मिसाइल को थेल्स एयर डिफेंस की तरफ से विकसित किया गया है. इसका नाम ऐतिहासिक मार्टलेट नामक पक्षी के नाम पर रखा गया है, जो कभी घोंसला नहीं बनाता. समझौते में भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षकों को रॉयल एयरफोर्स के साथ जोड़ने के लिए एक अलग पहल की भी घोषणा की गयी है, जिसके तहत भारतीय उड़ान प्रशिक्षकों को यूके रॉयल एयर फोर्स प्रशिक्षण से जोड़ा जायेगा. भारत-ब्रिटेन के बीच नयी रणनीतिक साझेदारी के पीछे का एक विचार यह है कि वैश्विक परिदृश्य बदल रहा है. दुनिया की रणनीतिक धुरी पश्चिम एशिया से खिसक कर अब एशिया-प्रशांत की तरफ आ रही है. इस रक्षा समझौते का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य दोतरफा सुरक्षा व्यवस्था में उपेक्षित पड़े व्यावसायिक क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाना है. इसी आपसी सहयोग के तहत ब्रिटिश जहाज एचएमएस प्रिंस ऑफ वेल्स को हिंद महासागर और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सक्रिय है. दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच गहरी साझेदारी और सहयोग की स्थिति भी बनी है.

स्टार्मर अपने साथ 125 व्यापारिक नेताओं का प्रतिनिधिमंडल लेकर आये थे. यही बताता है कि ब्रिटेन को आज भारत जैसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था के साथ मजबूत व्यापारिक रिश्ते बनाना कितना आवश्यक है. दोनों देशों के बीच आर्थिक निवेश और सहयोग की दिशा में भी सहमति बनी है. ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने मुंबई को अपना गंतव्य दरअसल चुना ही इसलिए था कि आर्थिक मामले में बड़े समझौते तक पहुंचा जाए. इसके तहत कुल 64 भारतीय कंपनियों ने ब्रिटेन में 1.3 अरब पाउंड का निवेश करने की प्रतिबद्धता जतायी है, जिससे वहां लगभग 7,000 नये रोजगार सृजित होने की उम्मीद है. भारतीय कंपनियों ने खासकर इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और दूसरे उद्योगों में निवेश करने का फैसला किया है. उदाहरण के लिए, टीवीएस मोटर ने मोटरसाइकिल का विस्तार करने और इलेक्ट्रिक वाहन विकसित करने के लिए सोलीहुल में 250 मिलियन पाउंड के निवेश की योजना बनायी है. ऐसे ही, हीरो मोटर्स ने अगले पांच साल में ई-मोबिलिटी, ई-साइकिल और एयरोस्पेस क्षेत्रों में 100 मिलियन पाउंड के निवेश की योजना बनायी है.

मुथूट फाइनेंस यूके लिमिटेड ने 100 मिलियन पाउंड के निवेश के साथ अपने शाखा नेटवर्क के विस्तार करने का लक्ष्य रखा है. सेमीकंडक्टर और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए भी भारतीय कंपनी ने निवेश की इच्छा जतायी है, जिससे ब्रिटेन में रोजगार पैदा होने की उम्मीद है. व्यापार और उद्योग के अलावा दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान-प्रदान पर भी सहमति जताई है. यह समझौता हमारे मजबूत प्रशिक्षण और शिक्षा संबंधों को सुगम बनाएगा. इसके अंतर्गत उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ब्रिटेन के लंकास्टर और सरे विश्वविद्यालयों को भारत में अपने परिसर खोलने की मंजूरी मिल गयी है. ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता जहां अमेरिकी टैरिफ से उपजे दबाव की कमोबेश भरपाई करेगा, वहीं यह कदम ज्यादा से ज्यादा देशों के साथ संबंध मजबूत करने की भारत की नीति का भी परिचायक है.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

कृषि विकास की दिशा में

दीपावली से पहले प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी के पूसा परिसर में 35,440 करोड़ रुपये की दो महत्वपूर्ण कृषि योजनाओं, पीएम धन-धान्य कृषि योजना और दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन, का शुभारंभ किया, जिनसे कृषि क्षेत्र में बेहतर बदलाव की उम्मीद है. प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा की सरकार ने विगत ग्यारह वर्षों में किसानों के हित में बीज से बाजार तक कई सुधार किये हैं, जिसका लाभ किसानों और अर्थव्यवस्था को मिल रहा है. बीते ग्यारह साल में कृषि निर्यात दोगुना हुआ है, खाद्यान्न उत्पादन 900 लाख टन बढ़ा है, तो फल-सब्जियों के उत्पादन में 640 टन की वृद्धि हुई है. जीएसटी दरों में बदलाव से भी किसानों को लाभ मिला है, क्योंकि ट्रैक्टर जैसी कृषि मशीनरी की कीमत घटी है. प्रधानमंत्री ने घरेलू और वैश्विक मांग पूरी करने के लिए किसानों से उत्पादन बढ़ाने की अपील करते हुए कहा कि हमें उन फसलों का उत्पादन बढ़ाने पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिनसे वैश्विक कृषि बाजार में अपना वर्चस्व स्थापित किया जा सके. उनका कहना था कि 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में किसानों की बड़ी भूमिका है. कुल 24,000 करोड़ रुपये की पीएम धन-धान्य कृषि योजना का उद्देश्य आकांक्षी जिला कार्यक्रम मॉडल के आधार पर कमतर प्रदर्शन वाले 100 कृषि जिलों का कायाकल्प करना है. देश के कई जिले ऐसे हैं, जहां प्रति हेक्टेयर उत्पादन बहुत कम है. सरकार ने ऐसे ही सौ पिछड़े जिलों को चुना है, जहां ग्यारह सरकारी विभागों की कुल छत्तीस योजनाएं मिलकर काम करेंगी. यह योजना फसल की उत्पादकता बढ़ाने, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने, सिंचाई और भंडारण सुविधाओं में सुधार करने, चयनित जिलों में ऋण पहुंच बढ़ाने और किसानों को नयी कृषि तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने पर केंद्रित होगी. जबकि 11,440 करोड़ रुपये की दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का उद्देश्य दलहन की खेती का दायरा 35 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाना है, ताकि दालों के आयात पर निर्भरता घटाई जा सके. दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की घोषणा 2025-26 के केंद्रीय बजट में की गयी थी. सरकार ने वर्ष 2030-31 तक देश को दाल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा है. दरअसल गेहूं और चावल में आत्मनिर्भर होने के बावजूद भारत अब भी दालों के आयात पर निर्भर है. इन दोनों योजनाओं से न केवल कुल कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, बल्कि कम उत्पादकता वाले, पिछड़े और सिंचाई सुविधाओं से वंचित जिलों को विशेष लाभ मिलेगा.

प्रधानमंत्री ने हाल ही में पीएम धन-धान्य कृषि योजना दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया. इन योजनाओं से कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ कम उत्पादकता वाले, पिछड़े और सिंचाई सुविधाओं से वंचित जिलों को विशेष लाभ मिलेगा.

स्वदेशी मैसेजिंग एप अरट्टै की बढ़ती लोकप्रियता

डॉ. मुकुल श्रीवास्तव
प्रोफेसर, लखनऊ विश्वविद्यालय
sri.mukul@gmail.com

अरट्टै के पास जोहो की तकनीकी क्षमता, भारत केंद्रित सर्विस और प्रमोटर्स का समर्थन तो है, पर प्रयोगकर्ताओं को प्लेटफॉर्म बदलने के लिए ठोस कारण देना, लोगों की निजता की गारंटी देना और लगातार नवाचार ही अरट्टै जैसे एप के भविष्य का निर्धारण करेगा.

पिछले दिनों देश के डिजिटल मैसेजिंग इकोसिस्टम में एक ऐसा बवंडर मचा, जिसने सारी दुनिया में मशहूर हो चुके व्हाट्सएप के नीति नियंताओं के माथे पर पसीने की बूंदें ला दीं. यह है भारत का देसी मैसेजिंग एप 'अरट्टै'. प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 'स्वदेशी तकनीक' अपनाने की अपीलों तथा मंत्रियों व उद्योगपतियों के अभियान की वजह से इस महीने के शुरुआती तीन दिनों में अरट्टै 75 लाख डाउनलोड के आंकड़े तक पहुंच गया, जहां रोजाना साइन-अप्स 3,000 से बढ़कर 3,50,000 तक जा पहुंचे. वर्तमान में अरट्टै के 10 लाख से अधिक मासिक सक्रिय प्रयोगकर्ता हैं, जबकि व्हाट्सएप के भारत में मासिक सक्रिय प्रयोगकर्ताओं की संख्या 53.58 करोड़ से अधिक है. ऐसी घटनाएं भी कुछ लोगों ने फेसबुक पर साझा कीं, जब उन्होंने अरट्टै की खूबियां गिनाते हुए पोस्ट लिखी, तो उनका अकाउंट कुछ घंटों के लिए सस्पेंड कर दिया गया. हालांकि इस तथ्य की पुष्टि नहीं हो पायी, फिर भी अरट्टै ने एक चुनौती तो पेश कर ही दी है.

'अरट्टै' को समझने से पहले जोहो को समझना जरूरी है. यह कोई नया स्टार्टअप नहीं, बल्कि एक स्थापित भारतीय टेक्नोलॉजी दिग्गज कंपनी है, जो दुनियाभर में कारोबार करती है. जोहो का इकोसिस्टम सिर्फ एक एप तक सीमित नहीं है. यह जोहो मेल (ई-मेल सेवा), जोहो राइटर (डॉक्यूमेंट), जोहो शीट (स्प्रेडशीट) और जोहो शो (प्रेजेंटेशन) जैसे दर्जनों सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का एक मजबूत सूट प्रदान करता है. इसे हम गूगल सूट जैसा भी समझ सकते हैं, पर कंपनी की प्रसिद्धि उसकी गोपनीयता-केंद्रित और विज्ञापन-मुक्त नीतियों पर बनी है. जहां गूगल और मेटा (फेसबुक) जैसी टेक कंपनियां प्रयोगकर्ताओं के आंकड़ों और उनको दिखाये जाने वाले विज्ञापनों पर केंद्रित हैं, वहीं जोहो प्रयोगकर्ताओं के डाटा का ऐसा इस्तेमाल नहीं कर रही. इसी दुनिया का नया सदस्य है 'अरट्टै', जिसका तमिल में अर्थ है 'गपशप'. यह एप उन सभी बुनियादी फीचर्स के साथ है, जिनकी एक मैसेजिंग एप से उम्मीद की जाती हैं-यानी टेक्स्ट मैसेज, वॉयस व वीडियो कॉल, 1,000 सदस्यों तक के ग्रुप चैट और मल्टीमीडिया शेयरिंग. भारत की एप इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है, जबकि चीन राजस्व व उपभोग के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बना हुआ है. वहीं अमेरिकी कंपनियां एप निर्माण के मामले में शायद सबसे ज्यादा इनोवेटिव (नवोन्मेषी) हैं. भारत प्रति माह एप इंस्टॉल करने व उसका प्रयोग करने के मामले में अव्वल है. भारतीय एप परिदृश्य का नेतृत्व टेलीकॉम दिग्गज एयरटेल और जिओ करते हैं, यद्यपि स्ट्रीमिंग कंपनियां, जैसे नोवी डिजिटल, जिओ सावन और पेटीएम, फोन पे और फ्लिप्कार्ट जैसी ई-कॉमर्स साइट्स ने खुद को वैश्विक परिदृश्य पर भी स्थापित किया है. फोर्टी टू मैटर्स डॉट कॉम के अनुसार, गूगल प्ले स्टोर पर अक्तूबर तक कुल 20,83,249 एप्स उपलब्ध हैं, जिनमें भारतीय एप्स की संख्या 89,083 बनी हुई है, जो कुल एप्स का करीब 4.3 फीसदी है. कुल एप पब्लिशर्स की संख्या 6,11,857 है, जिनमें 15,541 भारतीय एप पब्लिशर्स हैं-यह सभी पब्लिशर्स का करीब 2.5 फीसदी है.

देश में उपभोक्ताओं की उपलब्धता के हिसाब से भारतीय एप की संख्या अब भी बहुत कम है. एप बाजार में भारत के पिछड़े होने का एक बड़ा कारण कोडिंग की पढ़ाई देर से शुरू होना भी है. हालांकि नयी शिक्षा नीति, 2020 ने इस अंतर को पाटने की कोशिश की है, पर इसका परिणाम 2030 के बाद दिखेगा. ऐसे में 'अरट्टै' व्हाट्सएप को कितनी कड़ी टक्कर दे पायेगा, यह कहना अभी मुश्किल है. व्हाट्सएप का एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन हर मैसेज, कॉल, फोटो और वीडियो को इतना सुरक्षित बनाता है कि कोई तीसरा इन्हें पढ़ या सुन नहीं सकता. वहीं अरट्टै में यह सुरक्षा सिर्फ वॉयस और वीडियो कॉल तक सीमित है, टेक्स्ट मैसेज के लिए नहीं, यानी जिनके लिए डिजिटल गोपनीयता सबसे जरूरी है, उन लोगों का भरोसा 'अरट्टै' को अभी जीतना होगा. दूसरे, मैसेजिंग एप्स की सबसे बड़ी ताकत होता है उनका यूजर नेटवर्क.

हर कोई व्हाट्सएप पर है, ऐसे में कोई यूजर उस एप पर जाने का जोखिम क्यों उठाये, जहां उसके दोस्त-परिवार, रिश्तेदार कोई है ही नहीं? करोड़ों भारतीय व्हाट्सएप के डिजाइन और फीचर्स के इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि उन्हें किसी नये प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए राजी करना बहुत मुश्किल काम है. एक बार जो डिजिटल आदतें बन जाती हैं, तो उनको बदलना बेहद जटिल है. जैसे कू व हाइक जैसे स्वदेशी एप्स को शुरुआती उत्साह, सरकारी समर्थन और ट्विटर विवादों के चलते खूब डाउनलोड तो मिले, पर टिकाऊ सफलता हासिल नहीं हो सकी. अरट्टै के पास जोहो की तकनीकी क्षमता, भारत केंद्रित सर्विस और प्रमोटर्स का समर्थन तो है, पर प्रयोगकर्ताओं को प्लेटफॉर्म बदलने के लिए ठोस कारण देना, लोगों की निजता की गारंटी देना और लगातार नवाचार ही अरट्टै जैसे एप के भविष्य का निर्धारण करेगा.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

देश दुनिया

हरित ऊर्जा महाशक्ति बनने के लिए तिब्बत की बलि चढ़ा रहा चीन

जब हम वैश्विक स्तर पर स्वच्छ और हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने की बात करते हैं, तो चीन सबसे आगे खड़ा दिखाई देता है. चीन ने अकेले 2024 में अन्य सभी देशों की तुलना में कहीं अधिक सौर पैनल और पवन टर्बाइन स्थापित किये. वह इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण और प्रसंस्करण में भी अग्रणी है, जो जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है. यह देश लिथियम और तांबे जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादन में भी दुनिया में अग्रणी है, और इसके लिए पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील तिब्बत में बड़े पैमाने पर उत्खनन हो रहे हैं. दुनिया की कुछ सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजनाएं भी वर्तमान में तिब्बत की नदियों पर बन रही हैं, जो सीधे तौर पर चीन के हरित और स्वच्छ ऊर्जा की प्रगति से जुड़ी हैं. पर इन प्रभावशाली प्रगति के पीछे एक कहानी छुपी है, जिसकी गहन निगरानी की आवश्यकता है. दुर्लभ मृदा धातुओं और महत्वपूर्ण खनिजों सहित प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध क्षेत्र तिब्बत, चीन की संसाधन रणनीति का केंद्र बिंदु बन गया है. बीते दशक से चीन ने तिब्बती क्षेत्रों में अन्वेषण तेज किया है. भले ही चीन की हरित ऊर्जा की दिशा में प्रगति की विश्व स्तर पर सराहना हो रही है, पर इसके कार्यान्वयन से तिब्बत में गंभीर नैतिक और पारिस्थितिक प्रश्न उठ रहे हैं. प्रमुख वैज्ञानिक रिपोर्टों ने संकेत दिया है कि तिब्बत का तापमान वैश्विक औसत से दोगुने से भी अधिक दर से बढ़ रहा है, जिससे यह दुनिया के सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील क्षेत्रों में से एक बन गया है. यदि दुनिया को सचमुच एक टिकाऊ भविष्य की ओर बढ़ना है, तो हरित ऊर्जा पर्यावरण विनाश या मूल निवासियों की आवाज को दबाने के मूल्य पर प्राप्त नहीं करना चाहिए. वास्तविक परिवर्तन के लिए पर्यावरण संरक्षण, सार्थक सामुदायिक जुड़ाव सुनिश्चित करना होगा और मानवाधिकारों की रक्षा करनी होगी. तिब्बती लोगों को भी अपनी मातृभूमि की पारिस्थितिकी और सतत विकास का संरक्षक बनना होगा.

-धोंधुप वांग्मो

बोधि वृक्ष

ईश्वर प्रेम का रंग

दिल में समर्पण का भाव आते ही भक्त जान जाता है कि अब तीर्थ करने, कहीं जाने की जरूरत नहीं रह गयी. अब मेरा दिल ही तीर्थ हो चुका है. जब अविद्या और अज्ञान मन से दूर हो गये, तो बाहर जाकर किस गंगा में डुबकी लगाऊं? जो ज्ञान की गंगा दिल में बह रही है, उसी में सुस्नात होकर पवित्र हो गया हूं. कबीर कहते हैं, 'कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लाग्यो हरि फिरे कहत कबीर कबीर.' मन की यह निर्मलता तभी आती है, जब हम संपूर्णता से समर्पण कर पाते हैं. याद रहे, समर्पण करते समय ईश्वर को केवल अपने पाप ही चढ़ाने से काम नहीं बनेगा. समर्पण पूर्णरूप से तभी होता है, जब हम अपने पुण्य भी चढ़ाते हैं. अपने पाप-पुण्य, गुण-अवगुण, सब कुछ चढ़ाकर निर्भार, बोझरहित हो जायें. फिर जो हो सो हो. वेद की ऋचाएं गाती हैं कि प्रभु मेरे ही मन के मूल में हैं. परम चेतन, आनंदघन मेरे ही भीतर विराजमान हैं. लेकिन जब शिव स्वरूप, आनंद स्वरूप परमात्मा मेरे ही भीतर मौजूद हैं, तो मेरा मन तरसता क्यों है? मेरा मन दुखी क्यों है? मेरा मन अशांत क्यों है? मुझको तो आनंद से झूमते रहना चाहिए. मेरा गीत तो कभी बंद ही नहीं होना चाहिए. हम ऐसे राजा हैं, जो भिखारी का जीवन जी रहे हैं. हमारा जो परमपिता है, उस परमात्मा की उपलब्धियों और शक्तियों के आगे तो कोई भी नहीं टिकता. जिस मनुष्य को यह बात समझ आ जाये, उसके जीवन में फिर एक अजीब-सी बेपरवाही आ जाती है. इसी को तो 'मलंग' कहते हैं. मलंग को किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से दोस्ती नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं. वह अपने भीतर बैठे परमात्मा के साथ ही सब प्यार-प्रेम कर लेता है. जब कोई परमात्मा के प्रेम में रंग जाता है, तो जीवन मलंग हो जाता है. तो फिर हर हाल में, हर रूप में, हर स्वरूप में, खुशी में, गम में, सुख में, दुख में, मान में, अपमान में, हर चीज में उसी के रंग को देखता है. जीवन के इन सप्तरंगों को देख जीवन को उन रंगों से भरपूर भर लेता है. पर यह तभी संभव होगा, जब भीतर प्रेम का रंग चढ़ जाये.

-आनंदमूर्ति गुरु मां

प्रबंध सूत्र

शांति और मौन सर्वोत्तम तपस्या

आलोक पुराणिक
स्तंभकार
puranika@gmail.com

ज्यादा बोलना बहुत बेइज्जती देता है. डोनाल्ड ट्रंप अनगिनत बार अपने लिए नोबल शांति पुरस्कार की मांग कर रहे थे. उन्हें यह पुरस्कार नहीं मिला. ट्रंप अब मजाक का पात्र बन गये हैं. नोबल शांति पुरस्कार पर ट्रंप बहुत बयानबाजी न करते, तो उनकी छवि एक जिम्मेदार नेता की बनी रहती. जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए लोग अक्सर अपनी योजनाओं को जोर-शोर से प्रचारित करते हैं, पर अनुभव हमें सिखाता है कि वास्तविक विजय मौन और गुप्त तैयारी में छिपी होती है.

चुपके से तैयारी का अर्थ है अपनी योजनाओं को गोपनीय रखना और पूर्ण एकाग्रता के साथ कार्य करना. जब हम अपनी महत्वाकांक्षाओं को सार्वजनिक नहीं करते, तो बाहरी आलोचना, ईर्ष्या और बाधाओं से बचते हैं. संस्कृत में एक प्रसिद्ध सूक्ति है- 'मौनं सर्वार्थ साधनम', जिसका अर्थ है कि मौन सभी उद्देश्यों को सिद्ध करने का साधन है. ट्रंप यदि अपनी कूटनीतिक उपलब्धियों को जोर-शोर से प्रचारित करने के बजाय चुपचाप रहते, तो शायद उनकी छवि अधिक प्रभावशाली होती.

आज के सोशल मीडिया युग में लोग अपनी हर छोटी-बड़ी बात साझा करते हैं, पर प्राचीन ज्ञान हमें सिखाता है कि अत्यधिक बोलना हानिकारक हो सकता है. संस्कृत उक्ति है, 'संपूर्ण कुंभो न करोति शब्दं, अर्द्धोघटो घोषमुपैति नूनम. विद्वान कुलीनो न करोति गर्वं, गुणैर्विहीना बहु जल्पयन्ति', अर्थात जिस प्रकार आधा भरा हुआ घड़ा अधिक आवाज करता है, परंतु पूरा भरा हुआ घड़ा जरा भी आवाज नहीं करता, उसी प्रकार विद्वान अपनी विद्वत्ता पर घमंड नहीं करते, जबकि गुणविहीन लोग स्वयं को गुणी सिद्ध करने में लगे रहते हैं. गरिमायुक्त मौन सम्मान दिलाता है. फिजूल की वाचालता बेइज्जत ही करती है. वॉरेन बफेट या एलन मस्क जैसे सफल व्यक्तित्व अपनी बड़ी रणनीतियों को लागू करने से पहले मौन रहते हैं. वे चुपके से तैयारी करते हैं, बाजार का अध्ययन करते हैं, फिर सफलता प्राप्त करते हैं. यदि ट्रंप ने भी अपनी उपलब्धियों को प्रचारित करने के बजाय चुपचाप प्रस्तुत किया होता, तो शायद परिणाम भिन्न होता.

एक अन्य संस्कृत उद्धरण है - 'शमः परमं तपः', जिसका अर्थ है कि शांति और मौन सर्वोत्तम तपस्या है. यह उद्धरण 'महाभारत' से लिया गया है, जो मौन को आत्मसंयम और तप का सर्वोच्च रूप बताता है. ट्रंप की तरह जोर-शोर से मांग करने से असफलता का सामना करना पड़ सकता है. शांति की तपस्या बहुत मुश्किल है अब. हर किसी को अपनी उपलब्धियों का प्रचार करना है. सबको सब बताना है, बल्कि वह भी बताना है, जो हासिल नहीं किया है. इससे मजाक बनता है, जैसे अभी ट्रंप का बन रहा है.

आपके पत्र

अभ्यर्थियों की परेशानी समझे सरकार

कहते हैं, समय सबसे मूल्यवान होता है, परंतु राज्य में न तो प्रतियोगी परीक्षाएं समय पर हो रही हैं, न ही उनका परिणाम निर्धारित कैलेंडर के अनुसार आ रहा है. साल-दर-साल बीत जाते हैं, पर परिणाम का कोई संकेत नहीं मिला. इससे अभ्यर्थियों की मेहनत और समय, दोनों व्यर्थ चले जाते हैं. सरकार से आग्रह है कि वह तय समय-सारणी के अनुसार परीक्षाएं आयोजित करे, ताकि युवाओं का समय और विश्वास दोनों बचा रहे. ऐसा होने पर ही राज्य का विकास होगा, अन्यथा यहां का युवा अंधकार में भटकता रहेगा.

दिव्या राजन, रांची

ऐतिहासिक हवाई अड्डा है चकुलिया

झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित चकुलिया हवाई अड्डे का निर्माण 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा कराया गया था. द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसने सैन्य हवाई क्षेत्र के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी. इसे बी-29 लिबरेटर विमानों के संचालन के लिए डिजाइन किया गया था, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से इस हवाई अड्डे का उपयोग बंद हो गया. सरकार से आग्रह है कि वह चकुलिया हवाई अड्डे का संचालन फिर से प्रारंभ करे, ताकि यहां के लोगों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मिले.

सीमा निखत, चकुलिया

पोस्ट करें : प्रभात खबर, 15 पी, इंडस्ट्रियल एरिया, कोकर, रांची 834001 ■ **फैक्स करें :** 0651-2544006 ■ **मेल करें :** eletter@prabhatkhabar.in पर ■ ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है.

CCI NG 3.7 Product: NBTMumbaiBS PubDate: 13-10-2025 Zone: Mumbai Edition: 1 Page: NBTMEDIT User: sandeep.hande Time: 10-12-2025 22:38 Color:

> अंतरराष्ट्रीय व्यापार का विस्तार और और उसमें तेज वृद्धि की वजह से अलग-अलग देश मिलकर एक बड़े समुदाय का हिस्सा बने हैं।
> *– जॉन स्टुअर्ट मिल, राजनीतिक अर्थशास्त्री*

नया टकराव

चीन और अमेरिका एक नए ट्रेड वॉर के मुहाने पर खड़े हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स पर चीन अपना नियंत्रण कड़ा करना चाहता है और इसी बात से नाराज डॉनल्ड ट्रंप ने उस पर 100% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। दोनों महाशक्तियों के बीच की इस खींचतान का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा।

चीन का एकाधिकार । किचन से लेकर युद्ध के मैदान तक, आज इस्तेमाल होने वाली हर आधुनिक मशीन रेयर अर्थ बिना अधूरी है और फिलहाल इस पर चीन का कब्जा है। वैश्विक जरूरतों की 90% सप्लाई चीन से होती है और इसमें भी 60% वह खुद प्रोड्यूस करता है, जबकि बाकी मिनरल्स उसके यहां रिफाइन होते हैं। इसी एकाधिकार की बदौलत इस साल अप्रैल में भी उसने ट्रंप की टैरिफ नीतियों को चुनौती दी थी।

ट्रंप-शी फिर भिड़े

टूटता समझौता । अमेरिकी टैरिफ के विरोध में चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स के निर्यात पर कड़ाई की, तो पूरी दुनिया के ऑटोमेटिव और डिफेंस सेक्टर पर संकट आ गया था। तब दोनों देश एक समझौते पर पहुंचे थे, जिसके तहत अमेरिका ने टैरिफ कम किया और चीन ने नियंत्रण, लेकिन अब वह समझौता टूटता लग रहा है।

कूटनीतिक हथियार । चीन के लिए रेयर अर्थ की सप्लाई का इस्तेमाल कूटनीतिक हथियार के तौर पर करना नया नहीं है। उसके नए नियम, लाइसेंस प्रक्रिया को कठोर बनाना, ऐसे ही कदम हैं। और इनका सबसे ज्यादा असर अमेरिकी डिफेंस सेक्टर पर पड़ने की आशंका है। ट्रंप की तरफ से आई तीखी प्रतिक्रिया की वजह यह भी है। हालांकि चीन जिस तरह रेयर अर्थ पर अपने एकाधिकार को हथियार बना रहा, वैसा ही कुछ अमेरिका ने भी किया था, जब उसने पेइचिंग को कुछ महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर और चिप डिजाइन तकनीक बेचने पर रोक लगा दी थी।

समाधान की उम्मीद । ट्रंप ने चीन पर एक नवंबर से नए टैरिफ लगाने की धमकी दी है। यही वक्त है, जब एशिया-पैसिफिक इकॉनमिक कोऑपरेशन से इतर ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच मुलाकात होनी है। दोनों देशों के बीच ट्रेड डील पर भी बातचीत जारी है, तो उम्मीद की जा सकती है कि उस मुलाकात में ताजा संकट का कोई हल निकल जाए।

दूसरों के लिए सबक । इस टकराव ने फिर साबित कर दिया है कि ग्लोबल सप्लाई चेन किस तरह चुनिंदा ताकतों पर निर्भर है। चीन और अमेरिका, दोनों ही अपने व्यापारिक प्रभाव का इस्तेमाल अपनी नीतियों को थोपने में कर रहे हैं। रेयर अर्थ और चिप मेकिंग में भारत समेत दूसरे देश कोशिश कर रहे हैं, जिसमें और मेहनत व निवेश की जरूरत है।

नश्तर

स्वप्न में गधा

ऑफिस की छुट्टी हुई। बाइक निकालकर सड़क पर आया। एक दोस्त ने रोक लिया। दुखड़ा कहने लगा- यार, सिर्फ कहने को आठ घंटे की नौकरी है। घर जाकर भी काम करना ही पड़ता है। पास खड़े दूसरे दोस्त ने गाल फुलाते हुए कहा कि अपन तो सिंगल हैं, 18 घंटे तक भी खुशी-खुशी काम कर सकते हैं। ठीक इसी वक्त, पता नहीं कैसे पर ढेचूं-ढेचूं की आवाज सुनाई देने लगी। सड़क पर मलबा उठाने के काम में लगे गधे अचानक चिल्लाने लगे। सब हंस पड़े।

सौरभ श्रीवास्तव

बात यहीं खत्म नहीं हुई। उस रात गधा सपने में आया। कहने लगा तुम लोग तो मनुष्य हो, थोड़ी मनुष्यता दिखाओ। मनुष्य और जानवरों की सहजीविता के इतिहास में हमारी विशेषता यह है कि हम ज्यादा देर तक बिना थके और सोचे-समझे काम कर सकते हैं। तुम इस क्षेत्र में भी हमसे मुकाबला करने लगे। आलम यह है कि कोई गधा ज्यादा काम करने लगता है तो साथ वाले गधे कहते हैं कि क्या इंसानों की तरह जुटे हो।

गधे को बीच में रोकते हुए मैंने कहा, हम सुकून से आठ घंटे काम करना चाहते हैं, पर तभी कुछ लोग आ जाते हैं और खुद को कॉम्पिटेंट साबित करने के फेर में 18-18 घंटे तक काम करने के ऑफर देने लगते हैं। मालिक ऐसा ऑफर क्यों नहीं लपकेगा। मुकाबले में बने रहने के लिए हमें भी ज्यादा काम करना पड़ता है। गलती उनकी भी नहीं है। वे ऐसे महानायकों, दिव्य पुरुषों से प्रेरणा ले रहे हैं जो काम करना बंद ही नहीं कर रहे हैं। बताओ हम क्या करें? वह मुस्कुराते हुए बोला- मैं तो गधा हूं।

मुझे उदास देखकर गधे से रहा नहीं गया। बोला, एक बार मालिक मुझे किसी लेखक के घर ले गया था। घर संकरी गली में था तो किताबें मुख्य सड़क तक ढोनी थीं। वहां कुछ लोग बात कर रहे थे कि काम के घंटे आठ से ज्यादा नहीं होने चाहिए, साम्यवाद आना चाहिए... उनकी बातें तो ठीक थीं। गधे की यह बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। आज की तारीख में साम्यवाद..तुम गधे ही रहोगे। अचानक अलार्म बजने लगा और

एकदा

संकलन : **दीनदयाल मुरारका**

शास्त्री की सादगी

पंडित निष्कामेश्वर मिश्र लाल वाराणसी के हरिश्चंद्र महाविद्यालय में लाल बहादुर शास्त्री के गणित के अध्यापक थे। उनके पुत्र राधाकृष्ण मिश्र एक बार दिल्ली गए। शास्त्री जी उस समय दिल्ली में ही रहते थे और वाणिज्य मंत्रालय का कामकाज देख रहे थे। राधाकृष्ण मिश्र ने अपने संस्मरण में लिखा है कि जब वह दिल्ली में शास्त्री जी के घर पर रुके हुए थे, उनका बेटा सुनील उनके पास आया और बोला, 'पिताजी, हमारा स्कूल का बस्ता फट गया है, नया खरीदना है।' उस दिन महीने की 25 तारीख थी। शास्त्री जी ने बेटे से कहा, 'तनख्वाह मिलने दो, तुम्हारा नया बस्ता खरीद लेंगे।' बस्ते की कीमत केवल 10 रुपये थी, लेकिन शास्त्री जी देश के एक आम आदमी की तरह जीते थे। उसी प्रवास के दौरान राधाकृष्ण मिश्र ने देखा कि शास्त्री जी के परिवार के लोग सरकारी गाड़ी से कहीं चले गए। शास्त्री जी सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल कभी निजी उपयोग के लिए नहीं करते थे। जब उन्हें इस बात का पता चला तो उन्होंने ड्राइवर से कहा, 'जितने किमी गाड़ी चली है, लॉगबुक में मेरे व्यक्तिगत खाते में लिख दो ताकि तनख्वाह से पैसा कट जाए।' ऐसे थे लालबहादुर शास्त्री।

Subrata Dhar

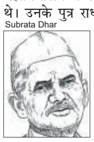

बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी के वादे अर्थशास्त्रियों की नींद उड़ा रहे हैं

मुफ़्त रेवड़ियों का नया रेकॉर्ड

बिहार एक बार फिर देश को राह दिखा रहा है। लेकिन यह राह जा किधर रही है? यह राह जा रही है वित्तीय अस्थिरता की ओर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य की 1.2 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपये नगद दे रहे हैं। यूं तो इसका मकसद उन महिलाओं को कारोबार शुरू करने में सहायता करना बताया गया है, लेकिन आरोप है कि नीतीश इसके जरिये अपना 'कारोबार' जमाए रखना चाहते हैं।

स्वामीनाथन एस अंकलेसरिया अय्यर

घोषणा और जवाबी घोषणा । 1.27 करोड़ महिलाओं को दस-दस हजार रुपये देने से 12,700 करोड़ रुपये का कुल खर्च आएगा। नीतीश ने यह भी कहा है कि इनमें जो बिजनेस कामयाब होंगे, उन्हें 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त मदद दी जाएगी। बेटी के लिए दहेज देने या पुराना कर्जा चुकाने जैसे कार्यों में इन पैसों का इस्तेमाल करने पर किसी तरह की सजा नहीं है। RJD नेता तेजस्वी यादव ने भी हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है।

पुराने क्लब में नई एंट्री । ये दोनों ही नेता विभिन्न राज्यों के नेताओं के उस जाने-माने क्लब में शामिल हो रहे हैं, जो जानते हैं कि वोटर के दिल तक पहुंचने का रास्ता बैंक अकाउंट से होकर जाता है। तमिलनाडु से शुरू हुई इस दौड़ में अब तक महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश शामिल हो चुके हैं।

बौद्धिक आवरण । अर्थशास्त्री इस आर्थिक प्रहसन को बौद्धिक आवरण देने में पूरी दिलचस्पी ले रहे हैं। हर दो-चार साल पर कोई न कोई यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI) यानी सरकार की ओर से निश्चित रकम देने की योजना का नया रूप लेकर सामने आ जाता है। मिल्टन फ्रीडमैन ने दशकों पहले सुझाया था कि सारी कल्याणकारी योजनाएं बंद करके लोगों को कैश देना शुरू कर दीजिए। वाम खेमे के प्रणब वर्धन जैसे अर्थशास्त्रियों के मुताबिक बेसिक इनकम राज्य और नागरिकों के बीच का नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट है।

वोट खरीदने की होड़

- तमिलनाडु से शुरू हुई इस दौड़ में सभी शामिल
- नेताओं के एहसान में वोटरों की कोई गरिमा नहीं
- वोटरों का दिल जीतने के लिए चाहिए एक नया नुस्खा

वफादारी का नया रूप । UBI का भारतीय स्वरूप नागरिकता या लोककल्याण को नहीं, वफादारी को पुनर्परिभाषित करता है। बिहार की ये स्कीमें किसी गहरे वैचारिक विमर्श का संकेत नहीं हैं। ये चुनावी चिंता को ही व्यक्त करती हैं। लगातार चार चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार को अब मतदाताओं का दिल जीतने के लिए कोई नया नुस्खा चाहिए।

मुफ्त रेवड़ियों का सिलसिला । केंद्र सरकार पहले से ही तमाम तरह की मुफ्त रेवड़ियां बांटती रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है करीब दो तिहाई परिवारों को मुफ्त अनाज देना। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में सही सवाल किया कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देते हुए सरकार गरीबी को लगभग खत्म करने का दावा कैसे कर सकती है? जवाब राजनीतिक भौतिकी में छुपा है जहां गुरुत्वाकर्षण का झुकाव लॉजिक की ओर नहीं चुनावों की ओर होता है। जहां तक राज्य और नागरिकों के बीच सबकी गरिमा सुनिश्चित करने वाले नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट के वाम स्वप्न की बात है तो इस सिद्धांत में कोई गरिमा नहीं हो सकती कि 'पैसा लो और याद रखो कि पैसा किसने दिया है।'

चुनाव जीतने का गणित । लोकतंत्र के गणित के सामने सारी वैचारिक भिन्नताएं घुल-मिल जाती हैं। दक्षिण कहता है, 'लोगों पर भरोसा करो, वे समझदारी से खर्च करते हैं।' वाम कहता है, 'ढंग से जीने में लोगों की मदद करो।' राजनेता कहता है, 'क्या मैं वोट खरीद लूं?' इस प्रकार फ्रीडमैन और वर्धन, मुक्त बाजार और लोक कल्याणकारी राज्य, सभी भारतीय बैलट बॉक्स के रूप में एक आम मकसद पा लेते हैं।

वित्तीय अनुशासन की बलि । नतीजा होता है आर्थिक सुधार के बजाय नैतिक असमंजस। हमें बताया जाता है कि यह सशक्तीकरण है, लेकिन देखा जाए तो यह नेताओं को सत्ता में बने रहने की ताकत देने की चाल भर है। इस बीच, अर्थशास्त्री चिंतित नजरों से वित्तीय अनुशासन को चुनावी गणित की वेदी पर बलि चढ़ते देखते रहते हैं। लेकिन हर पार्टी ऐसा करती है।

UBI की जगह UBF । भारतीय लोकतंत्र ने UBI के शानदार स्वप्न को UBF (यूनिवर्सल बेसिक फ्रीबीज) यानी सबके लिए मुफ्त रेविड़ियों में तब्दील कर दिया है। यह पक्षपातरहित है, डिजिटल है और सबकी समझदारी पर सवाल भी बहुत हलके से उठाता है। यह सबको सूट करता है। राजनेताओं की गद्दी सुरक्षित रहती है, वोटर जेबखर्च पा जाते हैं और अर्थशास्त्रियों का सिरदर्द बढ़ जाता है।

बड़ा सुख है दिवाली के बाज़ार में गुम हो जाना

खुशी केवल मंजिल तक पहुंचने में नहीं, उसके रास्ते में भी छिपी होती है। बीच के छोटे-छोटे पड़ाव बड़ी मुस्कान ले आते हैं और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दिवाली की खरीदारी। त्योहार से पहले त्योहार की तैयारी शुरुआत है उत्सव की, क्योंकि इसके साथ ही मन भर जाता है उमंग से।

दिवाली की खरीदारी केवल सामान लेना नहीं, एक अनुभव है, जिसमें उत्साह, रंग-बिरंगी रोशनी, मिठाइयों की खुशबू और लोगों की मुस्कान शामिल होती है। इस शॉपिंग में सबसे बड़ा आनंद तब है, जब कुछ तलाशते हुए हमें कुछ और मिल जाए। जब मिट्टी के दीये, खिलौने, खील-बताशे, प्लास्टिक की बंदूकें और चुटपुटिया ले जाएं पुरानी यादों में।

यह खरीदारी भरी है संतोष और समझदारी से। बाजार अपनी पूरी रौनक दिखाकर ललचाता है। हर दुकान नई नजर आती है और उसमें रखा हर सामान अनोखा। इस चमक-दमक से न मेगास्थनीज बच सका, न फाह्यान, न अल-बरूनी, इब्न बतूता या फिर बर्नियर। भारतीय बाजार की रंगीनियों ने मोह लिया था उनको। लेकिन, दिवाली के लिए जब थैला उठाकर निकलते हैं, तो सब कुछ देखते हुए भी बहुत कुछ नजरअंदाज करना पड़ता है। यहां परीक्षा होती है आत्मनियंत्रण की। केवल उतना ही लेना, जितना जरूरी है और वही लेना, जिसे ले सकते हैं। थोड़े में संतोष की आदत जीवन को भरती है आनंद से। भारतीय दर्शन भी कहता है कि जो व्यक्ति कम में ज्यादा प्रसन्न रहना सीख लेता है, वही जीवन की हर परिस्थिति में शांति पाता है। असली सुख सब पाने में नहीं, मन की तृप्ति में है।

AI Image

जीवन आनंद
शैलेंद्र पांडेय

दिवाली अपने साथ गुच्छों में पर्व-त्योहार लेकर आती है - नवरात्रि, दशहरा, करवा चौथ, धनतेरस, भैया दूज, छठ। बाजार भी इसी तरह भरा है विविधताओं से, जहां सभी के लिए कुछ न कुछ है।

दिवाली का बाजार है सादगी और सुंदरता का। घर सजाने की हजार चीजें मौजूद होती हैं इस बाजार में, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा अहमियत होती है मिट्टी के दीपों की। ये दीप याद दिलाते हैं कि जीवन का अर्थ उसकी उपयोगिता में है, प्रदर्शन में नहीं। रौंदकर, सूखकर, तपकर मिट्टी एक नया आकार लेती है - तेल-बाती के साथ मिलकर अंधेरी रात को रोशन करती है। और जब काम हो जाता है, तब वही मिट्टी फिर से मिल जाती है मिट्टी में - अगली बार की दिवाली के लिए, जब उसे फिर से कोई आकार दिया जाएगा।

शॉपिंग का तरीका और अनुभव बदल चुका है - अब ऑनलाइन डिलिवरी सर्विस है, मॉल्स हैं, लेकिन इनके बीच भी दिवाली का बाजार मौजूद है अपनी परंपराओं के साथ। उसकी भीड़भाड़ में खोकर त्योहार के लिए कुछ पाना खुद में एक त्योहार है।

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें
www.speakingtree.nbt.in

जीवन की ख़ुशियां छीन लेती है इच्छाओं की ग़ुलामी

संजय तेवतिया

मनुष्य का जीवन ईश्वर का अनमोल उपहार है, जिसमें विवेक, आत्मज्ञान और आत्मनियंत्रण जैसी दिव्य शक्तियां समाई हैं। लेकिन जब यह जीवन केवल इच्छाओं की पूर्ति में ही व्यतीत होने लगता है, तो यही उपहार एक बोझ में बदल जाता है। इच्छाएं स्वाभाविक हैं, परंतु जब वे हमें नियंत्रित करने लगती हैं, तब हम उनके गुलाम बन जाते हैं। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। पहले अच्छा घर चाहिए, फिर बड़ी गाड़ी, फिर प्रसिद्धि, और फिर अधिक धन। यह लालसाओं की अंतहीन श्रृंखला है। जैसे अग्नि में घी डालने से वह और भड़कती है, वैसे ही इच्छाओं की पूर्ति उन्हें शांत करने के बजाय और बढ़ा देती है।

आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो कामना और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होते हैं और यही आत्मा के पतन का कारण बनते हैं। जब किसी की कोई इच्छा अधूरी रह जाती है, तो मनुष्य दुखी, क्रोधित, और अस्थिर हो जाता है, और फिर गलत दिशा में भटकने लगता है। जो व्यक्ति केवल भौतिक सुख-सुविधाओं की पूर्ति में लगा रहता है, वह अपने आत्मिक उद्देश्य को भूल जाता है। जीवन का सार केवल धन, भोग या प्रतिष्ठा में नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति और भीतर की शांति में है। इच्छाओं के पीछे भागते-भागते मनुष्य न तो सच्चा सुख पा सकता है, न ही आत्मिक विश्रांति।

AI Image

जो व्यक्ति अपनी लालसाओं को नियंत्रित कर लेता है, वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। इच्छाएं ही दुख का मूल कारण हैं। जब तक मनुष्य उनसे ऊपर नहीं उठता, तब तक वह सच्चे आनंद और मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। इसके लिए जो कुछ हमारे पास है, उसमें संतुष्ट रहना सीखना चाहिए। अभिलाषाओं से मुक्त जीवन ही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र जीवन है। जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता है, वही सच्चा वीर कहलाता है।

इच्छाओं का होना गलत नहीं है, लेकिन उनका दास बन जाना आत्मिक पतन का मार्ग है। इसलिए हमें हमेशा इस बात के लिए सतर्क रहना चाहिए कि हम अपनी इच्छाओं के अधीन न होकर विवेक और आत्मनियंत्रण के स्वामी बनें।

कांटे की बात

> ऑपरेशन ब्लू स्टार गलती थी। इंदिरा गांधी ने उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकाई। लेकिन वह गलती सेना, पुलिस, खुफिया एजेंसियों और सिविल सेवा, सबके सामूहिक निर्णय का नतीजा थी।

पी चिदंबरम, पूर्व गृहमंत्री

डेटा Window

शांति समझौता होने से पहले ग़ाजा में कितनी तबाही हुई

इस्राइल की कैबिनेट ने बीते शुक्रवार को ट्रंप की गाजा में युद्धविराम और बंधकों की रिहाई की योजना को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही युद्धविराम लागू हो गया है। जानते हैं, इस संघर्ष में कितने लोगों की जान गई :

गाजा में नुकसान

कुल मृत्यु		कुल घायल
67,000+		169,000+
बच्चे	औरतें	बच्चे
13,300+	33,500+	84,500

इस्राइल में नुकसान

कुल मृत्यु	1,200
सिविलियन	815
बच्चे	36
कुल घायल	5,431

इन्फ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त

गाजा

भवन	स्कूल	सड़कें
60%+	80%	70%
खेत	अस्पताल	वृक्ष-फसलें नष्ट
68%	90%	97%

इस्राइल

2,200 रॉकेट्स से प्रभावित कुछ आवासीय भवन और सीमा इंफ्रास्ट्रक्चर

(सोर्स: WHO, OCHA, ABC News, NPR, Statista)

मीम बहार

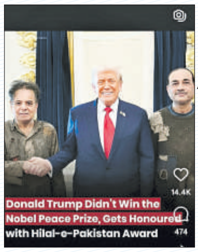

AI Image

डॉनल्ड ट्रंप ने कई बार नोबेल शांति पुरस्कार की चाहत का इजहार किया था, लेकिन उनकी यह तमन्ना पूरी नहीं हुई।

आज कई ख़तरे हैं, कैसी होगी आगे की दुनिया

मृत्युंजय राय

क्या आपने कभी सोचा है कि ऐतिहासिक प्राचीन सभ्यताएं कैसे खत्म हो गईं? यह कोई ऐसा सवाल नहीं है, जिसका पहले जवाब न दिया गया हो। जेरेड डायमंड की 'गन्स, जर्म्स और स्टील' नाम की किताब में ऐसी कुछ सभ्यताओं का जिक्र है। उसके कारण भी दिए गए हैं। 'Goliath curse' नाम की किताब भी हमें ऐसे ही एक दिलचस्प यात्रा पर ले जाती है। इसे लिखा है ल्यूक कैंप ने। वह कैंब्रिज यूनिवर्सिटी के रिसर्चर हैं। इस किताब में उन्होंने इजिप्ट, रोम, माया, चीन जैसी सभ्यताओं के साथ मॉडर्न वर्ल्ड के खतरों की भी बात की है। आज की दुनिया के बारे में वह लिखते हैं कि आर्थिक असमानता, बीमारी और जलवायु परिवर्तन बड़ी चुनौती है।

स्पेन की माइंस । प्राचीन सभ्यताओं की बात होती है तो वह स्पेन के इतिहास का जिक्र करते हैं। ल्यूक लिखते हैं कि वहां की चांदी की खानें इसकी गवाही देती हैं। प्राचीन काल में मुद्रा के रूप में सोना, चांदी, कॉपर जैसी धातुओं का इस्तेमाल होता था। इसलिए इनकी माइनिंग भी खूब होती थी। प्राचीन स्पेन में जब इसी काम के लिए भारी मात्रा में चांदी निकाली जा रही थी, तब लाखों टन पत्थर और सीसे (लेड) की धूल वातावरण में फैल गई। इसका सबूत ग्रीनलैंड की बर्फ में हजारों साल पुरानी सीसे की परतों के रूप में मिलता है। लेकिन जैसे ही कांस्य युग से लौह युग आया, यह सीसा बर्फ में दब गया।

औसत आयु गिरी । ल्यूक ने इस किताब में सभ्यताओं को लेकर पारंपरिक सोच बदलने की भी कोशिश की है। वह बताते हैं कि माना जाता है नई सभ्यता के स्थापित होने से समृद्धि आती है। लेकिन रिसर्च बताती है कि जब बड़े पैमाने पर इंसानों ने शिकार-संग्रह का जीवन छोड़ खेती शुरू की तो कुपोषण से उन्हें जूझना पड़ा। इस वजह से तब औसत आयु में भी गिरावट देखी गई।

बदलाव से आया सुधार । फिर, सभ्यता में सत्ता के शीर्ष पर कुछ लोगों का कब्जा होता था और वे अपनी सनक पूरी करने के लिए आम जनता पर जुल्म करते थे। ऐसे में कई बार जनता के विद्रोह की वजह से उन सभ्यताओं में बदलाव हुए। ल्यूक लिखते हैं कि कई बार इन बदलावों को संबंधित सभ्यता के पतन के रूप में देखा जाता है, लेकिन असल में यह बदलाव वहां की स्थिति में सुधार लाते हैं। ये बदलाव जरूरी भी होते हैं। वह किताब में बताते हैं कि कांस्य युग के पतन की कई वजहें थीं। इनमें सूखा, भुखमरी, बीमारी, युद्ध और अंदरूनी विद्रोह जैसी बातें शामिल थीं। इससे मायसीन, मिनोआन, बैबिलोनिया, हिताइट जैसी सभ्यताएं खत्म हुईं।

विचार विंडो

AI Image

अमीरों का नुकसान । ल्यूक इस सोच को भी चुनौती देते हैं कि सभ्यता के पतन का सभी लोगों पर बुरा असर होता है। अमीर और ताकतवर लोगों को भले इससे भारी नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन आम लोगों पर उतना बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। अक्सर ऐसे बदलाव की वजह से नए आइडियाज, नई टेक्नॉलजी और आम लोगों में जुड़ाव भी बढ़ता है।

इंसान आगे बढ़ेगा । वह लिखते हैं कि आज समाज नई-नई मुश्किलों से घिरा हुआ है। क्लाइमेट चेंज बड़ा खतरा बनता जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने कई युद्ध देखे हैं, जिनमें से कुछ अभी जारी हैं। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का डर भी बना हुआ है। ल्यूक यह भी दावा करते हैं कि 21वीं सदी के अंत तक मौजूदा सभ्यता के धराशायी होने की आशंका लगभग एक-तिहाई है। लेकिन वह यह भी बताते हैं कि इसके बाद भी इंसान आगे बढ़ेगा। वह नई सभ्यताएं बनाएगा।

रीडर्स मेल
www.edit.nbt.in

बिहार में दावे और वादे

बिहार की बहार को लूटने वाले आज फिर बिहार के विकास का दावा कर रहे हैं। बेरोजगारी की वजह से जिनके समय में सबसे अधिक पलायन हुआ, वही दल आज बिहार में नौकरियां देने का वादा कर रहे हैं। भ्रष्टाचार, मुफ्तखोरी, झूठे वादे, जातिवाद, घुसपैठिए जैसे मुद्दों को जनता ही महत्व नहीं देती। लोकतंत्र में जनता ही जज होती है, लेकिन जब जनता सही फैसला नहीं ले पाए, तो राजनीति में अपराधियों और भ्रष्टाचारियों का आना निश्चित है। चुनाव के समय जनता को सही फैसले लेकर लोकतंत्र को मजबूत बनाना चाहिए।

-सुधा चौबे, ईमेल से

readersmail.nbt@gmail.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

आर.एन.आई. पंजीयन नंबर 1613/1957 स्वत्वाधिकारी बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड के लिए आर. कृष्णमूर्ति द्वारा टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग, डॉ. डी. एन. रोड, फोर्ट, मुंबई 400001 से प्रकाशित और उनके द्वारा (1) टाइम्स ऑफ इंडिया सबर्बन प्रेस, आकुर्ली रोड, निकट वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, कांदिवली (पू.) मुंबई 400101 एवं (2) टाइम्स ऑफ इंडिया प्रिंट सिटी, प्लॉट नं. 4, टी.टी.सी. इंडस्ट्रियल एरिया, ठाणे बेलापुर रोड, ऐरोली, नवी मुंबई-400708. फोन नं. (022) 2760 9999 ; फैक्स: (022) 2760 5275। फोन मुंबई: (022) 66353535, 22733535 रेस्पांस: (022) 66353636, 22733636 फैक्स: (022) 22731889, 22731144, कांदिवली (022) 28872324 से मुद्रित। **स्थानीय संपादक (मुंबई) : सुंदर चंद ठाकुर** (पी. आर. बी. अधिनियम के अंतर्गत समाचारों के चयन के लिए उत्तरदायी) सर्वाधिकार सुरक्षित। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। सड़क व रेल परिवहन सेवा शुल्क: मुंबई, ठाणे व रायगड जिलों के बाहर 1.00 रुपया। विमान सेवा शुल्क: रायपुर, नागपुर, गोवा एवं वाया 2.00 रुपये, इंदौर, चेन्नै एवं वाया 3.00 रुपये, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोचीन, कोयम्बतूर, एरनाकुलम, हैदराबाद, कोझीकोड, मंगलूर, त्रिवेंद्रम, उदयपुर, वाइजग एवं वाया 4.00 रुपये, दिल्ली, कोलकाता, एवं वाया 5.00 रुपये।

विराम, शांति नहीं

डोनाल्ड ट्रंप को एक ईमानदार मध्यस्थ की भूमिका निभानी चाहिए, पक्षपातपूर्ण संरक्षक की नहीं। दो साल से लगातार

ए इज़राइली बमबारी के बाद, गाजा में फ़िलिस्तीनियों को आखिरकार राहत मिल रही है। संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं।

इस समझौते पर अमेरिका के हिस्से के रूप में हमास और इज़राइल ने हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20-सूत्रीय शांति योजना ने इज़राइल के हमलों पर विराम लगा दिया है। उम्मीद है कि हमास सोमवार को सभी जीवित बंधकों को और बाकी के शवों को अगले कुछ दिनों में रिहा कर देगा। इज़राइली सैनिकों ने दक्षिण में राफा से लेकर उत्तर में सीमा पर गाजा शहर तक, प्रारंभिक वापसी रेखा की ओर पीछे हटना शुरू कर दिया है, और लगभग 2,000 फ़िलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। श्री ट्रंप इस युद्धविराम के लिए श्रेय के पात्र हैं। हाल ही तक, इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जिन्होंने हमेशा "पूर्ण विजय" तक लड़ने की कसम खाई थी, युद्धविराम के सभी आह्वानों का विरोध करते रहे थे।

7 अक्टूबर, 2023 को हमास के हमले के बाद, जब इज़राइल ने गाजा पर युद्ध शुरू किया, तो उसने इस्लामी उग्रवादियों को "खत्म" करने का संकल्प लिया। दो वर्षों में, इज़राइल ने गाजा को मलबे में बदल दिया है और इसके 23 लाख लोगों में से अधिकांश को विस्थापित कर दिया है। फिलिस्तीनियों पर उसके क्रूर नरसंहार और भुखमरी के कारण उसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलगाव हो गया। फिर भी, हमास एक अनसुलझी समस्या बनी रही। श्री नेतन्याहू अंतरराष्ट्रीय जनमत की परवाह किए बिना लड़ाई जारी रखना चाहते थे। लेकिन अमेरिका, जो सैन्य और कूटनीतिक रूप से इज़राइल का समर्थन करता रहा है, ने अंततः श्री नेतन्याहू को बंधकों की रिहाई के बदले युद्धविराम स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया।

यद्यपि यह संघर्ष विराम फिलिस्तीनियों, बंधकों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि इससे गाजा में स्थायी शांति स्थापित हो जाए।

यह संघर्ष विराम ट्रम्प योजना का केवल प्रारंभिक चरण है, जिसमें हमास का विसैन्यीकरण, गाजा को एक अंतर्राष्ट्रीय शासन निकाय के अधीन रखना और सुरक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल की तैनाती का भी आह्वान किया गया है। ट्रम्प योजना के जवाब में, हमास बंधकों को रिहा करने पर सहमत हो गया, लेकिन अन्य शर्तों पर कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई। एक अन्य विवादास्पद मुद्दा गाजा में इज़राइली रक्षा बलों (आईडीएफ) की निरंतर उपस्थिति है - प्रारंभिक वापसी के बाद भी, आईडीएफ गाजा के लगभग 53% हिस्से पर नियंत्रण बनाए रखेगा। श्री।

ट्रम्प के सोमवार को गाजा पर एक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मिस्र जाने की उम्मीद है — फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भी मौजूद रहेंगे। फ़िलिस्तीन के मुद्दे पर नए सिरे से अंतरराष्ट्रीय ध्यान एक सकारात्मक घटनाक्रम है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये विचार-विमर्श इज़राइल और फ़िलिस्तीनी रुख़ों के बीच की दूरियों को पाट पाएँगे, जिससे स्थायी शांति स्थापित हो सके। हमास द्वारा ख़ुद को ख़त्म करने की माँग स्वीकार करने की संभावना कम है, ख़ासकर दो साल तक इज़राइली सेनाओं से लड़ने के बाद तो बिल्कुल नहीं। लेकिन उस पर गाजा में सत्ता छोड़कर अंतरराष्ट्रीय ताकतों द्वारा समर्थित एक फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण के लिए दबाव डाला जा सकता है, जबकि इज़राइल को वहाँ से निकलने के लिए राजी किया जाना चाहिए। श्री ट्रम्प के लिए,

ट्रम्प की स्थायी शांति की आशाओं को ध्यान में रखते हुए, उन्हें एक स्वतंत्र मध्यस्थ के रूप में कार्य करना चाहिए, न कि किसी एक देश के पक्षपातपूर्ण संरक्षक के रूप में, तथा इजरायल की सुरक्षा और आत्मनिर्णय के लिए फिलिस्तीनी प्रयास को मान्यता देनी चाहिए।

परिपक्व संबंध

भारत और यूनाइटेड किंगडम ने बिना किसी परेशानी के व्यापारिक संबंधों को गहरा किया है

ए ऐसे समय में जब सोशल मीडिया पर धमकियाँ, पारस्परिक कार्रवाइयाँ और तीखी बयानबाज़ी वैश्विक मानदंड बनती जा रही है, भारत-ब्रिटेन आर्थिक संबंधों का जिस तरह से विकास हो रहा है, वह एक ताज़ा बदलाव है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की पिछले हफ़्ते की दो दिवसीय भारत यात्रा ने आर्थिक संबंधों में मौजूदा मज़बूती को और मज़बूत किया और उन्हें और गहरा किया। अमेरिका के साथ भारत की वार्ताएँ तनावपूर्ण, अनिश्चित और नाटकीय रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी दिखाया है कि वह पहले से हुए समझौतों की रूपरेखा बदलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यूरोपीय संघ के साथ वार्ताएँ कम तनावपूर्ण और नाटकीय रही हैं, लेकिन नेताओं द्वारा दिए गए सकारात्मक आश्वासनों और वार्ताकारों द्वारा सौदे की प्रगति के बारे में निजी तौर पर कही गई बातों के बीच निश्चित रूप से एक अंतर प्रतीत होता है। इस पृष्ठभूमि में, सर स्टारमर ने 100 से ज़्यादा उद्यमियों, सांस्कृतिक प्रतिनिधियों और विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का एक प्रतिनिधिमंडल लाने का फ़ैसला किया और रक्षा, निवेश और फ़िल्म सौदों के साथ भारत से विदा ली, जिससे जुलाई में हस्ताक्षरित व्यापार समझौते को और मज़बूती मिली। व्यापारिक संबंधों को गहरा करने की उत्सुकता काफ़ी मायने रखती है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे बड़े बाज़ारों में से एक होने के बावजूद, भारत, ब्रिटेन के कुल व्यापारिक निर्यात में 2% से भी कम का योगदान देता है। भारत के निर्यात में ब्रिटेन का योगदान लगभग 3% है। व्यापार बढ़ने की भरपूर गुंजाइश है। भारत-ब्रिटिश व्यापार में वृद्धि, अमेरिका के दंडात्मक 50% शुल्क के प्रभाव को भी कम कर सकती है, अगर वे बने रहें।

भारत अपने पूंजीगत व्यय को धीमा कर रहा है, इसका एक अनकहा कारण यह है कि उसे अपने रक्षा अधिग्रहणों को निधि देने की आवश्यकता है। सर स्टारमर की यात्रा ने सुनिश्चित किया कि इनमें से कुछ अधिग्रहण - £ 350 मिलियन के मिसाइल आपूर्ति सौदे के रूप में - यूके के रास्ते में आए। यूके सरकार ने यह भी खुलासा किया कि 64 भारतीय कंपनियों ने अब तक यूके में £ 1.3 बिलियन का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। यह बिना कहे जा सकता है कि यूके की कंपनियों ने भारत में भी इसी तरह की निवेश प्रतिबद्धताएं की होंगी, लेकिन भारत सरकार ने अस्पष्ट रूप से इन्हें अभी तक सार्वजनिक नहीं किया है। फिर भी, रोल्स रॉयस जैसी कंपनियों के बयानों से पता चलता है कि वहां उत्साह है। यूके में भारतीय आबादी सबसे बड़ी जातीय अल्पसंख्यक है, और यह बात राजनीतिक नेतृत्व से भी छिपी नहीं है। मुंबई पहुंचने पर सर स्टारमर ने सबसे पहले यशराज फिल्म्स (YRF) का दौरा किया और भारतीय निर्माताओं से मुलाकात की।

इसका परिणाम यह हुआ कि वाईआरएफ ने ब्रिटेन में तीन फिल्मों की शूटिंग करने की प्रतिबद्धता जताई है। ब्रिटेन के दो विश्वविद्यालयों ने भी भारत में अपने परिसर खोलने की प्रतिबद्धता जताई है।

यह अंतर-क्षेत्रीय सहयोग ही है, जिसके तहत परिपक्व लोकतंत्रों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए - बिना किसी उपद्रव और अहंकार के, केवल व्यापार के लिए।

इज़राइल के अस्थिर आधिपत्य के संकेतक

मुहम्मद अयूब

वह मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी, अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रतिष्ठित प्रोफेसर एमेरिटस हैं और हाल ही में 'फ्रॉम रीजनल सिक्योरिटी टू' पुस्तक के लेखक हैं।

वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संबंध: एक बौद्धिक यात्रा' (2024)

टी इजरायल की हालिया विजयों ने यह धारणा छोड़ दी है कि इजरायल अब पश्चिम एशिया में सैन्य और राजनीतिक प्रभुत्वशाली है और वह इस क्षेत्र को अपनी इच्छानुसार ढाल सकता है - लेबनान में हिजबुल्लाह की सैन्य शाखा का लगभग विनाश; असद शासन को उखाड़ फेंकने से सीरियाई क्षेत्र पर इजरायल का नियंत्रण बढ़ गया; गाजा का पूर्ण विनाश और हमास की सैन्य क्षमताओं में भारी कमी, और सबसे बढ़कर, अमेरिकी मदद से ईरान की परमाणु हथियार क्षमता का लगभग पूर्ण विनाश।

पिछले हफ़्ते गाज़ा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लागू किया गया नाज़ुक युद्धविराम इस धारणा को और पुख्ता करता है, क्योंकि उनके साथ-साथ उनके कठोर बयानों ने हमास को सार्वजनिक रूप से चेतावनी दी है कि अगर वह उनकी योजना को अस्वीकार करता है तो उसे विनाशकारी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। जो लोग इस बारे में ज़्यादा नहीं जानते, उन्हें यह इज़राइल के पक्ष में और झुकाव का संकेत लग सकता है।

लेकिन श्री ट्रम्प की योजना हमास से कहीं ज़्यादा इज़राइल पर थोपने जैसी थी। असल में, इज़राइल को ही युद्ध विराम का आदेश दिया गया क्योंकि वह गोलीबारी और हत्याएँ कर रहा था और उसे अपनी सेना को आंशिक रूप से गाजा में नई जगहों पर वापस बुलाना पड़ा। इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को हमास को पूरी तरह से नष्ट करने और गाजा पर पूर्ण इज़राइली नियंत्रण फिर से स्थापित करने का अपना लक्ष्य छोड़ना पड़ा। हमास ने बस एक हज़ार से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले में इज़राइली बंधकों की रिहाई स्वीकार की। हमास ने अब तक श्री ट्रम्प की इस मांग को स्वीकार नहीं किया है कि वह निरस्त्र हो जाए और इज़राइल की पूरी वापसी के बाद गाजा पर शासन करने का अपना लक्ष्य छोड़ दे। क्या वह ऐसा कभी करेगा, यह एक खुला प्रश्न है।

यह एक द्विराष्ट्रीय राज्य है । हालाँकि इज़राइल के क्षेत्रीय प्रभुत्व की संभावनाएँ अल्पावधि में उज्ज्वल दिख सकती हैं, लेकिन ऐसा प्रभुत्व किसी भी समय तक टिकाऊ नहीं है। अपनी वर्तमान सैन्य रूप से निर्विवाद स्थिति के बावजूद, अंततः इज़राइल एक मिट्टी के पैरों वाला विशालकाय देश साबित होगा। कई संकेत इस ओर इशारा करते हैं।

पहला है इसका जनसांख्यिकीय आधार। 1967 की सीमाओं के भीतर इज़राइल की आबादी लगभग 90 लाख है, जिसमें फिलिस्तीनियों की संख्या 20% या लगभग 20 लाख है। पूर्वी यरुशलम और गाजा पट्टी सहित पश्चिमी तट पर 60 लाख से ज़्यादा फिलिस्तीनी रहते हैं। ग्रेटर इज़राइल, जो कि इज़राइली यहूदियों के एक बड़े हिस्से का सपना है, की आबादी यहूदियों और फिलिस्तीनियों के बीच लगभग बराबर-बराबर विभाजित होगी।

इसलिए, जनसांख्यिकी की दृष्टि से, यह स्पष्ट रूप से एक द्विराष्ट्रीय राज्य होगा। इससे इज़राइल के लिए अस्तित्व संबंधी दुविधा उत्पन्न होना स्वाभाविक है। अगर वह एक लोकतांत्रिक देश बना रहना चाहता है, तो उसे अपने सभी यहूदी और फ़िलिस्तीनी नागरिकों के समान अधिकारों वाले द्विराष्ट्रीय राज्य की राजनीतिक और जनसांख्यिकीय वास्तविकता को स्वीकार करना होगा। वैकल्पिक रूप से, उसे इस तथ्य को खुले तौर पर स्वीकार करना होगा कि वह एक

> अपनी सैन्य रूप से निर्विवाद स्थिति के बावजूद, तेल अवीव मिट्टी के पैरों वाला एक विशालकाय व्यक्ति साबित हो सकता है

रंगभेदी राज्य जिसमें एक जातीय समूह दूसरे पर शासन करता था, जैसे दक्षिण अफ्रीका में अफ्रिकन शासन के तहत।

पहला विकल्प पश्चिम एशिया के हृदय में यहूदी राज्य के ज़ायोनी स्वप्न को समाप्त कर देगा।

दूसरा, यह मौजूदा स्थिति को औपचारिक रूप तो देगा ही, साथ ही इज़राइल पर भारी अंतरराष्ट्रीय कलंक भी लाएगा, जिससे वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और भी अलग-थलग पड़ जाएगा और रंगभेदी शासन के तहत दक्षिण अफ्रीका की तरह एक बहिष्कृत राज्य जैसा व्यवहार किया जाएगा। दोनों ही विकल्पों में से कोई भी विकल्प इज़राइल को आंतरिक रूप से विभाजित या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग या दोनों ही स्थिति में छोड़ देगा। ऐसे राज्य के लिए लंबे समय तक इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व बनाए रखना बहुत कठिन काम होगा।

इजरायल की कार्रवाइयों का प्रभाव इजरायल के आधिपत्य के अस्थिर होने की दूसरी वजह यह है कि इसकी हालिया कार्रवाइयों ने कई अरब शासनों, विशेष रूप से खाड़ी के शेखों और सऊदी अरब को डरा दिया है, जो इस क्षेत्र में ईरान की कथित आधिपत्य की महत्वाकांक्षाओं के संभावित प्रतिकार के रूप में इजरायल को देखते थे। यह आकलन इजरायल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के बीच तथाकथित अब्राहम समझौते के पीछे प्रेरक शक्ति था, और बाद में मोरक्को और सूडान तक बढ़ा दिया गया। ये राज्य अब इजरायल को एक सत्ता के नशे में चूर अभिनेता के रूप में देखते हैं जो बेकाबू हो गया है। हालांकि उनमें से कुछ ने इजरायल द्वारा हिजबुल्लाह के सफाए की गुप्त रूप से सराहना की हो सकती है, लेकिन गाजा में इजरायल द्वारा किए गए अत्याचारों ने उन्हें बेचैन कर दिया है - जहां हजारों महिलाओं और बच्चों सहित 67,000 फिलिस्तीनियों को इजरायली बमों और गोलियों और घेरे हुए लोगों को भूखा रखने की इजरायल की नीति से मार दिया गया है। यद्यपि इन राज्यों में सत्तावादी शासन है, लेकिन उनके शासकों को यह एहसास है कि गाजा में नरसंहार पर जनता का गुस्सा उबलने के बिंदु पर पहुंच रहा है और यदि वे फिलीस्तीनियों को आत्मनिर्णय के उनके अधिकार से वंचित करने पर तुले हुए, हमेशा आक्रामक तेल अवीव के साथ घनिष्ठता बढ़ाते हुए देखे गए, तो उनके शासन की वैधता पर इसका हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है।

इसके अलावा, कतर में हमास के अधिकारियों पर हमला न करने के अपने वादे के विपरीत, सितंबर 2025 में दोहा पर बमबारी करके कतर में हमास के वार्ताकारों को मारने की इजरायल की निर्मम कोशिश ने खाड़ी देशों को यह विश्वास दिला दिया है कि वे इजरायल को एक भरोसेमंद दोस्त तो दूर, सहयोगी भी नहीं मान सकते। इसने तथाकथित अब्राहम समझौते को आगे बढ़ाने के इजरायली-अमेरिकी सपने को, और खासकर सऊदी अरब के साथ इजरायल के संबंधों को सामान्य बनाने के सपने को वर्षों पीछे धकेल दिया है। सहानुभूति रखने वाले अरब अभिजात वर्ग के बीच भी इजरायल की वैधता अपने निम्नतम स्तर पर पहुँच गई है।

अंत में, गाजा में इजरायल की कार्रवाई, जो सीमा पर है जातीय सफाए पर, अमेरिका में आम राय में भारी बदलाव आया है। यह बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि पश्चिम एशिया में आधिपत्य की इज़राइल की महत्वाकांक्षा इस धारणा पर टिकी है कि उसे वाशिंगटन का अटूट समर्थन प्राप्त होगा। हालाँकि यह बात शुरू में स्पष्ट नहीं हो सकती है।

इस दृष्टि से, अमेरिका में इज़राइल के प्रति जनसमर्थन में कमी निकट भविष्य में अमेरिकी नीति में परिलक्षित होगी। श्री ट्रम्प द्वारा गाजा में युद्ध समाप्त करने की अपनी योजना को स्वीकार करने के लिए श्री नेतन्याहू को मनाना, हालाँकि यह उनके लक्ष्यों को पूरा नहीं करता, भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत हो सकता है। इज़राइल की अमेरिका पर अत्यधिक निर्भरता श्री नेतन्याहू द्वारा, श्री ट्रम्प के आदेश पर, कतर के प्रधानमंत्री से दोहा पर हमले के लिए माफ़ी मांगने के आह्वान से उजागर हुई।

अमेरिकी जनमत इज़राइल के प्रति इतना शत्रुतापूर्ण पहले कभी नहीं रहा जितना कि अब है। हाल ही में हुए एक प्यू सर्वेक्षण में पाया गया कि लगभग 60% अमेरिकी इज़राइली सरकार के प्रति नकारात्मक विचार रखते हैं। यहाँ तक कि अमेरिकी यहूदियों का एक बड़ा हिस्सा भी इज़राइल के खिलाफ हो गया है। वाशिंगटन पोस्ट के एक अन्य हालिया सर्वेक्षण से पता चला है कि 61% अमेरिकी यहूदियों का मानना है कि इज़राइल ने गाज़ा में युद्ध अपराध किए हैं और 40% का मानना है कि इज़राइल ने नरसंहार किया था। अधिकांश नरसंहार विद्वानों सहित कई अमेरिकी शिक्षाविदों का मानना है कि गाज़ा में इज़राइल की नीतियाँ नरसंहार की कानूनी परिभाषा को पूरा करती हैं। यह अधिकांश मानवाधिकार संगठनों के लिए भी सच है। संक्षेप में, अमेरिकी जनमत अधिकांश यूरोपीय देशों में व्याप्त जनमत के साथ तालमेल बिठा रहा है, जिसने इज़राइल और अमेरिका की कड़ी आपत्तियों के बावजूद अपनी कई सरकारों को फ़िलिस्तीन राज्य को मान्यता देने के लिए मजबूर किया है। जनमत में यह बदलाव अंततः वाशिंगटन के निर्णयकर्ताओं को प्रभावित करेगा, खासकर जब से श्री ट्रम्प के MAGA ('अमेरिका को फिर से महान बनाएँ') समर्थकों का एक बड़ा हिस्सा भी इसका समर्थन करने लगा है।

वाशिंगटन में इज़राइल को अमेरिकी समर्थन की धारणा तेल अवीव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इज़राइल-फ़िलिस्तीन संघर्ष और सामान्यतः पश्चिम एशिया के प्रति वाशिंगटन के दृष्टिकोण में एक बड़ा बदलाव इज़राइल और उसके पड़ोसियों के बीच पूरे समीकरण को बदल सकता है। यह निष्कर्ष इस तथ्य से पुष्ट होता है कि पश्चिम एशिया में अमेरिका के प्रमुख सामरिक और आर्थिक हित हैं, जो अब तक इज़राइल के प्रति उसके निर्विवाद समर्थन के बाद गौण रहे हैं। श्री ट्रम्प के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रति उनके लेन-देन संबंधी दृष्टिकोण को देखते हुए, जहाँ सहयोगियों के हितों को अमेरिकी उद्देश्यों के मुकाबले गौण माना जाता है, इसमें आसानी से बदलाव आ सकता है।

इसके अलावा, ईरान की परमाणु और मिसाइल क्षमताएँ कमज़ोर होने और तेहरान के नेतृत्व वाली प्रतिरोध धुरी के बिखराव के साथ, वाशिंगटन के लिए इज़राइल का सामरिक महत्व कम हो गया है। दरअसल, इसे अमेरिका के व्यापक सामरिक और आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति में एक बाधा के रूप में देखा जाने लगा है। अमेरिका के बिना शर्त समर्थन के, इज़राइल का आकार छोटा हो जाएगा और क्षेत्रीय प्रभुत्व के उसके सपने पूरी तरह से चकनाचूर हो जाएँगे। यह एक ऐसा परिदृश्य है जो देर-सवेर, और संभवतः उससे भी पहले घटित हो सकता है।

ग्रेट निकोबार ने प्रकृति के कानूनी अधिकारों के मुद्दे को पुनर्जीवित किया

अनवर सादात

भारतीय पर्यावरण सोसायटी में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून पढ़ाते हैं

अंतरराष्ट्रीय कानून, नई दिल्ली

पारिस्थितिक दृष्टिकोण से, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को आसानी से दुनिया के सबसे प्रमुख जैविक विविधता हॉटस्पॉट में से एक माना जा सकता है, जो वैश्विक कार्बन भंडार और जलवायु नियामक के रूप में कार्य करता है।

दुर्भाग्य से, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का विकास पथ मुख्यतः भारत की मुख्य भूमि से प्रभावित रहा है, जो अक्सर द्वीपीय पारिस्थितिकी की ज़रूरतों से कोसों दूर रहा है। अब ध्यान का केंद्र ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के लिए भारत सरकार की करोड़ों रुपये की मेगा-योजना है - एक बिजली संयंत्र, टाउनशिप, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट और हवाई अड्डे का निर्माण, जो 13,000 हेक्टेयर प्राचीन वनों को भी प्रभावित करेगा।

वनों के परिवर्तन के मुद्दे से संबंधित एक ऐतिहासिक निर्णय, जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के बचाव में आ सकता है, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अनुसरण में नियमगिरि हिल्स मामले में दिया गया है ।

उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम पर्यावरण एवं वन मंत्रालय एवं अन्य मामले में अपने 2013 के फैसले में , भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने डोंगोरिया कोंध जनजाति की चिंताओं पर ध्यान दिया, जिन्होंने ओडिशा की पवित्र नियमगिरि पहाड़ियों में बॉक्साइट खनन की योजना का विरोध किया था । इस क्षेत्र की जनजातियों द्वारा खनन के खिलाफ किए गए विरोध प्रदर्शनों, जिससे उनकी संस्कृति, धर्म और पर्यावरण को खतरा था, के बाद न्यायालय ने प्रभावित ग्राम सभाओं में जनमत संग्रह का आदेश दिया, जिसने सर्वसम्मति से परियोजना के खिलाफ मतदान किया। न्यायालय ने समुदाय की परंपराओं, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों और विवाद समाधान के सामुदायिक तरीकों की रक्षा और संरक्षण हेतु ग्राम सभा की क्षमता को बरकरार रखा।

इस निर्णय के आलोक में, ग्रेट निकोबार द्वीप पर प्रस्तावित परियोजना के संबंध में प्रासंगिक प्रश्नों में यह शामिल है कि क्या लिटिल और ग्रेट निकोबार की जनजातीय परिषद को वन अधिकारों के निपटान को प्रमाणित करने में अपनी क्षमता का प्रयोग करने की अनुमति दी गई है

> कानूनी दुनिया में ऐसे उदाहरण हैं जो क्षेत्रों और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।
>
> संसाधन

वन भूमि को अन्यत्र स्थानांतरित करने के निर्णय से पहले वन अधिकार अधिनियम के तहत आदिवासियों के अधिकारों की पहचान की गई थी। इस दैनिक में प्रकाशित एक रिपोर्ट, "निकोबार परियोजना के लिए आदिवासियों के वन अधिकारों का निपटारा नहीं किया गया: परिषद" (23 अगस्त, 2025), ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि कैसे जनजातीय परिषद ने कहा था कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन ने केंद्र को यह दावा करके गलत जानकारी दी थी कि परियोजना के लिए आवश्यक वन भूमि को अन्यत्र स्थानांतरित करने से पहले वन अधिकार अधिनियम के तहत आदिवासियों के अधिकारों की पहचान की गई थी और उनका निपटारा किया गया था।

भारत में प्रकृति को अधिकार प्रदान करना ग्रेट निकोबार में जो कुछ देखने को मिल रहा है, वह नया नहीं है, बल्कि यह इस बात का एक और उदाहरण है कि कैसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाएँ योजनाबद्ध आपदाओं की ओर अग्रसर हैं। इसके कई उदाहरण हैं - उत्तर में टिहरी से लेकर पूर्व में कोयल कारो और पश्चिम में सरदार सरोवर तक। पारिस्थितिकी की रक्षा में पर्यावरण कानून की निरंतर विफलता के जवाब में, कई देशों (बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर और न्यूज़ीलैंड) ने 'पृथ्वी न्यायशास्त्र' या 'प्रकृति के अधिकार' नामक एक नया कानूनी दृष्टिकोण अपनाया है, जो गैर-मानव प्राकृतिक संस्थाओं (नदियाँ, जंगल, पहाड़ और विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र) को अधिकार प्रदान करता है, उन्हें अधिकार धारकों के विषय के रूप में मान्यता देता है।

यह दृष्टिकोण क्रिस्टोफर स्टोन द्वारा 1972 में लिखे गए एक प्रभावशाली लेख - 'क्या पेड़ों को खड़ा होना चाहिए? - प्राकृतिक वस्तुओं के कानूनी अधिकारों की ओर' - से प्रेरित था। उन्होंने तर्क दिया कि वर्तमान दृष्टिकोण पर्यावरण को होने वाले नुकसान पर विचार नहीं करता, बल्कि राहत प्रदान करते समय केवल पर्यावरण से संबंधित मनुष्यों को होने वाले नुकसान पर विचार करता है।

दूसरा, ऐसी राहत प्राकृतिक इकाई को नहीं, बल्कि केवल प्रभावित मनुष्यों को ही मिलती है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक इकाइयों को अधिकार धारक बनाकर, उन्हें न्यायालय में कानूनी दर्जा देकर और उन्हें कानूनी निवारण का प्रत्यक्ष लाभार्थी बनाकर, पर्यावरण में सुधार होगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या प्राकृतिक इकाइयों को, वयस्कों की तरह, कानूनी रूप से उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए और अनुबंध करके कानूनी अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए या क्या वे मुकदमा कर सकती हैं और उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है?

एक पीड़ित पक्ष। स्टोन ने एक संरक्षक निकाय के निर्माण का सुझाव दिया जो कानूनी कार्रवाई शुरू कर सके और इसकी स्थिति को संरक्षित और बहाल करने के लिए धन भी इकट्ठा कर सके।

भारत में प्राकृतिक संस्थाओं के अधिकारों को मान्यता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ 2017 में आया जब उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गंगा और यमुना नदियों के साथ-साथ गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियरों को कानूनी व्यक्तित्व प्रदान किया। मोहम्मद सलीम बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य मामले में दिए गए फैसले ने इन संस्थाओं को अधिकार और दायित्व प्रदान किए, लेकिन केवल एक निर्दिष्ट व्यक्ति के माध्यम से। हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी, लेकिन उच्च न्यायालय के फैसले के कुछ तत्व, विशेष रूप से उन प्राकृतिक संस्थाओं की ओर से संरक्षकता की ज़िम्मेदारियाँ प्रदान करने का विचार, कानूनी व्यक्तित्व की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक मार्गदर्शक हो सकता है।

कोलंबिया का मामला मार्गदर्शन के रूप में: वन अधिकार अधिनियम की सीमाओं को और आगे बढ़ाकर कानूनी व्यक्तित्व प्रदान करने के विचार को शामिल करना एक ऐसा ही विकल्प है। फिर भी, प्राकृतिक संस्थाओं को कानूनी व्यक्तित्व प्रदान करने के विचार के लिए विशिष्ट कानूनी अधिकारों और उन्हें बनाए रखने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की ज़िम्मेदारी पर अधिक स्पष्टता की आवश्यकता होगी। महत्वपूर्ण मानक प्रश्नों का गहन अध्ययन आवश्यक है, जैसे कि प्रकृति को अधिकार प्रदान करने वाले अधिकारों को कैसे परिभाषित किया जाए, किन अधिकारों को मान्यता दी जाए, प्रकृति के लिए कौन बोल सकता है, और क्या किसी को प्रकृति की रक्षा के लिए ज़िम्मेदार होना चाहिए।

इन मानक प्रश्नों के उत्तर खोजने में, कोलंबिया के अत्रातो नदी मामले (2016) से मार्गदर्शन मिलता है, जिसमें जैव-सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता दी गई थी - जो जातीय समुदायों के अपने क्षेत्रों के साथ-साथ अपने आवास का निर्माण करने वाले प्राकृतिक संसाधनों का स्वायत्त रूप से प्रशासन और संरक्षण करने के अधिकार का संदर्भ है। संरक्षक आयोग के गठन के लिए उन मूल निवासियों के प्रतिनिधियों को शामिल करना आवश्यक है जो अपने आवास के विनाश का सामना कर रहे हैं।

द टटर्सटूदएडिटर

श्रमिकों के अधिकार

मैं यह पत्र श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के उप निदेशक (मीडिया एवं संचार) के रूप में लिख रहा हूँ।

कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य कारखाना अधिनियम, 1948 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। इनका कार्यान्वयन संबंधित राज्य द्वारा किया जाता है।

सरकारें। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियां (ओएसएच और डब्ल्यूसी) संहिता, 2020 ने 13 केंद्रीय श्रम कानूनों के प्रावधानों को युक्तिसंगत और समामेलित किया है जिसमें कारखाना अधिनियम 1948 भी शामिल है। ओएसएच और डब्ल्यूसी संहिता ने स्पष्ट रूप से नियोक्ताओं पर स्वास्थ्य,

संहिता के प्रावधानों और केन्द्र सरकार द्वारा जारी मानकों के अनुसार कर्मचारियों की सुरक्षा और कार्य स्थितियों का ध्यान रखा जाएगा।

कार्यस्थल पर सुरक्षा और श्रमिकों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए ओएसएच और डब्ल्यूसी कोड में कई नए प्रावधान शामिल किए गए हैं। प्रत्येक कर्मचारी को नियुक्ति पत्र जारी करना अनिवार्य कर दिया गया है।

निरीक्षण प्रावधानों को बरकरार रखा गया है। खतरनाक प्रक्रियाओं से संबंधित नियोक्ताओं के कर्तव्यों के प्रावधानों का कोई भी उल्लंघन दो साल तक की कैद और ₹5 लाख तक के जुर्माने से दंडनीय है।

लेख में दावा किया गया है, "क्या श्रमिकों के अधिकारों का हनन हो रहा है?" (ऑनलाइन - 'द हिंदू एक्सप्लेन्स', 9 अक्टूबर, 2014)

2025) के अनुसार, श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा अधिकार कार्यकारी विवेकाधिकार बन जाएंगे, यह तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक है।

रिनी चौधरी, नई दिल्ली

भारत-अफगानिस्तान संबंध

ऐसे समय में जब चीन विभिन्न देशों, विशेषकर भारत के साथ घनिष्ठता बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है,

पड़ोसी देश और पाकिस्तान आक्रामक होते जा रहे हैं, इसलिए यह ज़रूरी है कि भारत अफ़ग़ानिस्तान को खुश रखे। हालाँकि, नई दिल्ली को निरंकुश शासन को एक निष्पक्ष अधिकार-आधारित व्यवस्था अपनाने के लिए राजी करना होगा।

आन्या सिंघल, नोएडा, उत्तर प्रदेश

letters@thehindu.co.in पर भेजे गए पत्रों में डाक पता अवश्य होना चाहिए।

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

राष्ट्रीय सहारा

पटना • सोमवार • 13 अक्टूबर • 2025

www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

जैसे अधिकतर लोग अपनी दुर्बलता को नहीं जानते वैसे ही अधिकतर लोग अपनी क्षमताओं को भी नहीं जानते

-जोनाथन स्विफ़्ट

स्वदेशी से सशक्त होगा भविष्य

देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वदेशी महामंत्र को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आगे बढ़ाया है। हाल ही में प्रदेशवासियों को स्वदेशी अपनाने का मंत्र देकर न केवल आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को जोर दिया है, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने की पहल भी की है। यह केवल एक नारा नहीं, बल्कि आर्थिक स्वावलंबन, स्थानीय उत्पादन और जनसहभागिता पर आधारित विकास का एक ठोस मॉडल है। आज वैश्वीकरण के दौर में जहां विदेशी वस्तुओं की चमक-दमक ने बाजार पर कब्जा कर रखा है, वहीं योगी सरकार का यह संदेश जनजागरण की तरह है कि जब तक हम अपनी मिट्टी से बने उत्पादों को प्राथमिकता नहीं देंगे, तब तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती। स्वदेशी का अर्थ केवल विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार नहीं, बल्कि अपने संसाधनों से अपनी जरूरतों को पूरा करना है। यही भाव वोकल फॉर लोकल का आधार है। इस कारण उन्होंने सभी से सबसे पहले स्वदेशी अपनाने का नारा बुलंद किया है। यह वह मंत्र है, जिसके जरिये विजन 2047 का असली मकसद पूरा होगा।

प्रदेश सरकार ने पहले ही वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट (ओडीओपी) योजना के माध्यम से स्थानीय उद्योगों को पुनर्जीवित करने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए स्वदेशी को जीवनशैली का हिस्सा बनाना प्रदेश के छोटे और मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को नई उड़ान देगा। जब लोग अपने जिले, अपने गांव के उत्पादों को अपनाएंगे, तब स्थानीय बाजारों में मांग बढ़ेगी, जिससे उद्योग स्वतः पनपेंगे। इसका असर यह होगा कि मैट्रो सिटी से उद्योग का बाजार तेजी के साथ छोटे शहरों की तरफ बढ़ेगा। स्वदेशी नीति का एक बड़ा लाभ यह भी होगा कि इससे प्रदेश में नए उद्योगों की स्थापना के अवसर बढ़ेंगे। औद्योगिक निवेश बढ़ेगा, जिससे रोजगार सृजन स्वाभाविक रूप से होगा। योगी सरकार पहले ही औद्योगिक गलियारों, एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर और स्मार्ट कनेक्टिविटी परियोजनाओं के माध्यम से निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर चुकी है। अब जब जनता भी स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देगी, तब यह प्रयास एक जनांदोलन का रूप ले लेगा। साथ ही, स्वदेशी के प्रति यह आह्वान पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक स्वाभिमान से भी जुड़ा है। जब हम अपने पारंपरिक हस्तशिल्प, कपड़ा, कृषि उत्पाद और घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देंगे, तब न केवल रोजगार मिलेगा बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान भी सुरक्षित रहेगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह संदेश वास्तव में आर्थिक आत्मनिर्भरता के साथ-साथ मानसिक स्वावलंबन का भी संदेश है। यह हमें यह याद दिलाता है कि हम अपनी क्षमता और प्रतिभा के बल पर भी विकास कर सकते है, हमें केवल अपने संसाधनों पर विश्वास करना होगा। यदि प्रदेश का हर नागरिक स्वदेशी अपनाओ, प्रदेश बढ़ाओ के मंत्र को जीवन में उतार ले, तो आने वाले वर्षो में प्रदेश न केवल देश का सबसे बड़ा राज्य रहेगा, बल्कि सबसे सशक्त आर्थिक इकाई के रूप में भी अपने को स्थापित करता नजर आएगा। स्वदेशी केवल आर्थिक नीति नहीं, बल्कि एक विचारधारा है। आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और आत्मगौरव से भरे समाज की नींव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह आह्वान उसी दिशा में एक निर्णायक कदम साबित हो सकता है, लेकिन इसमें लोगों की सहभागिता और जागरूकता के जरिये प्रदेश की आर्थिक नीति को बुलंदी प्रदान की जा सकती है।

अंदर की बात/सुधीश पचौरी

मर्दानगी बेचते फिल्म कलाकार

एक हीरोइन एक हीरो से चिपकी हुई चलती है। अगले सीन में हीरो कुछ पहलवानों को अपनी बनियान फाडने को दे देता है लेकिन वे कोशिश करके भी नहीं फाड पाते। हीरोइन हीरो से पूछती है तुम ये सब कैसे कर लेते हो... तो हीरा आंखे मारते हुए कहता है...ये अंदर की बात है! इन दिनों ऐसे कई ब्रांडरों के कच्छा-बनियान के विज्ञापन दिखते हैं जिनकी कैच लाइन द्विअर्थी होती है जैसे कि ये अंदर की बात है या फिट है बॉस!

इसी तरह एक मसलमेन हीरो एक अन्य बनियान को इस तरह बेचता हैः वह काफी उंचाई से कूदता है तो उसकी शर्ट एक तार पर अटक जाती है और उसकी कसी हुई बॉडी एक बनियान में नजर आती है। यही वो हीरो था जो शुरूआती फिल्मों सिपर्फ रोमांटिक भूमिकाएं निभाता था थोडी मार-पिटाई कर लेता था लेकिन वह कोई बॉडी बिल्डर या एक्शन हीरो नहीं था। लेकिन जब फिल्म वालों ने माचो यानी मर्दानगी को बेचने वाली फिल्में बनानी शुरू की तब से एक हीरो न अपने मसल बनाने शुरू किए। उसकी एक शुरूआती एक्शन फिल्म को देख एक महिला पत्रकार ने अंग्रेजी में लिखा था कि जब एक्शन सीन में उस हीरो की शर्ट फट जाती है और उसकी नंगा सीना और सिक्स पेक ऐब वाले मसल नजर आते है तो उसकी बॉडी स्त्रियों के लिए किसी दावत से कम नहीं होती।

आज लगभग सारे हीरो बाडी बिल्डर है। अधिकांश कच्छा बनियान बेचते है उनकी केच लाइन दो अर्थ वाली होती है जैसे कि ये अंदर की बात है या कि फिट है बॉस! आप इन दोनों मुहावरों को लें और इनमें निहित सेक्सी मानियों को पढें तो मालूम होगा कि जब से अपने यहां बालीवुड ने अपने ही मेन या सुपर मेन की कल्पना की है तब से बहुत से हीरो सिक्स पेक ऐब्स वाली बॉडी को दिखाते देखे गए है। उनमें से एक हीरो की कमीज उसकी पिक्चर के अंतिम एक्शन सीनों फटती ही है या कि जिसे वह फाड देता है और अपने सिक्स पेक एब्स को दिखाकर वह खलनायक को भी कूट देता है जबकि इन दिनों के खलनायक भी बॉडी बिल्डर जैसे नजर आते हैं।

जब से हिंदी में आने वाली एक्शन फिल्मों का चलन शुरू हुआ तब से हमें ऐसे बॉडी बिल्डर हीरो अधिक नजर आने लगे है। पहले दौर की रोमांटिक फिल्मों में कोई भी हीरो बॉडी बिल्डर नहीं होता था। न ही वह बनियान बेचता थ न कच्छा बेचता था। वह प्रेमी होता था और सिर्फ प्रेम बेचता था। हमें प्रेम करना सिखाता था। इसीलिए न दिलीप कुमार की बॉडी बिल्डर वाली बॉडी थी न देवानंद या राजकपूर की बॉडी थी बाद में आए रोमांटिक हीरो राजेश खन्ना की बॉडी किसी शहरी प्रेमी की सामान्य बॉडी की तरह की होती थी और तब की हीराइनें हीरो की बॉडी पर नही उसके दिल पर मरती थीं, उसकी भावनाओं पर मरती थी। इसीलिए पुरानी फिल्में आज की तरह की फिल्में नहीं थी। उनमें मारा मारी के लंबे सीन नहीं होते थे न वहां सीन न कोई मेल बॉडी को नंगा करता था सिवाय दारासिंह के जो सीधे एक्शन हीरो की तरह हर फिल्म में फ्री स्टाइल वाली कुश्ती लडते थे।

तब के हीरा हीरोइन प्रेम करते थे प्रेम के गीत गाते थे खलनायक विघ्न डालता था तो मजबूरी में फाइट करते थे... तब के हीरो की बॉडी जेंटलमेन बॉडी थी हीरोइन साडी में लिपटी भारतीय नारी थी... यह शायद सत्तर के दशक की बात होगी जब, अब तक प्रेमी की भूमिका निभानेवाले धर्मेंद्र फिल्म फूल और पत्थर 1966 में पत्थर दिल क्रिमिनल की भूमिका में टी शर्ट में दिखते है जिसमें उनकी बॉडी के मसल साफ दिखते है। इससे पहले टी शर्ट सिर्फ खलनायक पहनते थे लेकिन तब भी अंदर की बात करने वाले हीरो हीरोइन कच्छे बनियान नहीं बेचते थे... शायद सलमान खान ने बॉडी बिल्डर हीरो की शुरूआत दबंग से की! इससे पहले जिसने बॉडी बनाई थी वो शायद खलनायक बने पुनीत इस्सर थे जिनके साथ फाइट सीन करते हुए अमिताभ बच्चन घायल हो गए थे और जिस एक्शन सीन को कुली फिल्म में अलग से दिखाया गया था।

फिल्मों में ऐसे ही मैन्स की शुरूआत शायद सन 1990 के आसपास शुरू हुई क्योंकि तब तक टेलीविजन में अमरीकी फ्री स्टाइल कुश्ती वाले डब्लूडब्लूएफ दिखने लगी थी जहां एक से एक बॉडी बिल्डर पहलवान नकली फाइट दिखाते हुए अपनी मेल बॉडी की करामातों को अधिक दिखाते थे.. जब से अब तक आते आते अपनी बालीवुड के हीरो हीरोइनों की ड्रेस में बहुत कुछ बदल गया है। अब तो हीरो हीरोइन दोनों ही कच्छा बनियान में दिखते है। साडी या कुरते पाजामे तो शोक सभाओं में ही दिखते है। बहुत से पुराणपंथी पहले कच्छा बनियान को देखते ही अश्लील कह कंडम कर सकते थे, अब कोई नहीं करता!

बिहार में चुनाव का गणित

बिहार चुनाव

किशोर झा

वर्ष 2025 के 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बिहार में राजनीतिक दलों के बीच सरगर्मी तेज हो चुकी है। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में क्रमशः 6 नवंबर और 11 नवंबर को कराने की घोषणा की है और चनाव के नतीजे 14 नंवबर को आयेंगे। बिहार के चुनावी इतिहास में चालीस साल बाद ऐसा मौका आ रहा है जब चुनाव दो चरणों में होंगे। साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव तीन चरण में हुए थे। जबकि 2015 के विधानसभा चुनाव पांच चरण में हुए थे। उससे पहले 2010 के विधानसभा चुनाव छह चरणों में संपन्न हुए थे।

बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटे है। जिसमें 38 सीटें अनसूचित जाति और 2 अनूसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। यदि वर्ष 2020 के 17वीं विधानसभा का चुनावी विश्लेषण किया जाए तो इस चुनाव में कुल 6 राष्ट्रीय दल (National Parties) 11 राज्य दल (State Parties), और 197 गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दलों (Unrecognised Registered Parties) ने भाग लिया। वोट प्रतिशत के लिहाज से सर्वाधिक 42.56 प्रतिशत वोट भाजपा को प्राप्त हुए, जबकि राजद को 38.96 प्रतिशत वोट प्राप्त हुआ। सीपीआई (एम) को 37.58 प्रतिशत,सीपीआई को 33.28 प्रतिशत, कांग्रेस को 32.91 प्रतिशत, जदयू को 32.83 प्रतिशत और लोजपा को 10.26 प्रतिशत मत प्राप्त हुआ। सीटों के लिहाज से देखा जाए तो 75 सीटों के साथ राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी थी। जबकि 74 सीटों के साथ भाजपा दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन कर उभरी।

यद्यपि भाजपा की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने सरकार बनाने लायक बहुमत जुटा कर बिहार में जदयू के नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चला रही है। यद्यपि इस बात के लिए भाजपा की तारीफ बनती है की जदयू के 43 सीट के बावजूद भी नीतीश कुमार के नेतृत्व पर ही भाजपा ने भरोसा जताया और अपने दो उपमुख्यमंत्रियों के साथ बिहार के शासन में हिस्सेदार है। बिहार में चुनाव का जिक्र हो और जाति की चर्चा ना हो ऐसा हो नहीं सकता। प्रसिद्ध राजनीति विज्ञानी प्रोफेसर रजनी कोठारी का कथन कि आखिर जाति क्यों नहीं जाती? बिहार के संदर्भ में सटीक बैठता है। चुनाव आते ही सभी राजनीतिक दल व्यक्ति से ज्यादा जाति को महत्व देकर टिकट बांटते है, टिकट वितरण के पैमाने में जाति निर्णायक भूमिका अदा करती है।

ब्रह्म्ण, राजपूत, भूमिहार, कायस्थ, यादव, कोयरी, कुर्मी, पासी, धानुक, रविदास, पासवान, डोम व मल्लाह आदि जातियों से राजनीतिक दल चुनाव में उम्मीदवार खड़े करते है। यदि राजद की बात करें तो राजद का वोट बैंक माई (मुस्लिम और यादव) समीकरण कुछ उतार-

चढ़ाव के साथ राजद मे ही है, यद्दपि पिछले चुनाव में असद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम से पांच विधायक जीत कर आये तो यह चर्चा होने लगी की राजद का मुस्लिम वोट बैंक अब राजद से दूर जा रहा है, लेकिन राजद ने संतुलन साधते हुए ओवैसी के चार मुस्लिम विधायकों को अपने पाले में कर लिया। वहीं एनडीए में भाजपा का सवर्ण, जदयू का ईबीसी, चिराग पासवान का दलित, जीतनराम मांझी का महादलित वोट मिलकर एनडीए को बड़ी ताकत प्रदान करता है।

बहरहाल इस बार के चुनाव में जहां राजद और कांग्रेस की अगुवाई वाली इंडिया गठबंधन व भाजपा और जदयू की अगुवाई वाली एनडीए गठबंधन के साथ प्रशांत किशोर का जनसुराज भी चुनावी मैदान में है। तेजस्वी यादव जहां एंटी इनकंबेसी फैक्टर को भुनाने की कोशिश कर रहे है और अपने जनसंपर्क अभियान में राहुल गांधी के साथ वोट चोरी और चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण ( ) का मुद्दा उठा रहे है। वहीं नीतिश कुमार ने वोटरों को साधने की कोशिश में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार की एक करोड़ 21 लाख महिलाओं के खाते में दस हजार रुपये दिये है।बिहार सरकार की ओर से पहले ही चरणबद्ध तरीके से पैसों का वितरण करने के लिए तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। पहली किस्त 26 सितंबर को जारी हुई थी। 75 लाख महिलाओं के खाते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैसा भेजा था। फिर सीएम नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 3 अक्टूबर को दूसरी किस्त के तौर पर 25 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये भेजे थे। इसके बाद 6 अक्टूबर को 21 लाख महिलाओं को सीएम महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हजार रुपये मिले। इसके मूल में महिलाओं को उद्योग धंधे के लिए प्रोत्साहित कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। लेकिन विपक्षी दलों का आरोप है कि चुनाव के तुरंत पहले ये एक तरह से वोट खरीदने की चाल है। वहीं जनसुराज के प्रशांत किशोर द्वारा बिहार भाजपा के नेताओं के भ्रष्टाचार पर खुलासे हो रहे है और साथ ही उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की शैक्षणिक योग्यता पर भी सवाल उठाए गये है। प्रशांत किशोर का कहना है कि हमनें पद-यात्रा के माध्यम से जनता का मन टटोल लिया है और जनता अब परिवर्तन चाहती है। बिहार विधानसभा चुनाव राजनीतिक दलों के अपने-अपने दावे और वादे है, लेकिन लोकतंत्र में सैद्धांतिक ताकत जनता के पास है, चुनाव जनता की अदालत में होना है और आखिरी मुहर जनता ही लगाएगी।

(लेखक सिविल सेवा परीक्षा के मार्गदर्शक और स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटे हैं। जिसमें 38 सीटें अनुसूचित जाति और 2 अनूसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। यदि वर्ष 2020 के 17वीं विधानसभा का चुनावी विश्लेषण किया जाए तो इस चुनाव में कुल 6 राष्ट्रीय दल 11 राज्य दल, और 197 गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दलों ने भाग लिया। वोट प्रतिशत के लिहाज से सर्वाधिक 42.56 प्रतिशत वोट भाजपा को प्राप्त हुए, जबकि राजद को 38.96 प्रतिशत वोट प्राप्त हुआ। सीपीआई (एम) को 37.58 प्रतिशत, सीपीआई को 33.28 प्रतिशत, कांग्रेस को 32.91 प्रतिशत, जदयू को 32.83 प्रतिशत और लोजपा को 10.26 प्रतिशत मत प्राप्त हुआ। सीटों के लिहाज से देखा जाए तो 75 सीटों के साथ राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी थी। जबकि 74 सीटों के साथ भाजपा दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन कर उभरी।

बुग्यालों (मिडोज) में खिला पुष्प ब्रह्म कमल बना लोगों के आकर्षण का केंद्र

- अपनी खूबसूरती और पवित्रता के कारण इंसानों को ही नहीं, बल्कि देवी-देवताओं को भी प्रिय और उच्च हिमालयी क्षेत्रों विशेषकर उत्तराखंड में उगने वाले पुष्प ब्रह्म कमल का वानस्पतिक नाम साईसुसेरिया आवोबाल्टा है। यह भारत, दक्षिण चीन, नेपाल, पाकिस्तान के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है

- प्रायः 3700-4600 मीटर की ऊंचाई पर उगने वाले ब्रह्म कमल के पुंकेसर हिमालयी वन्य प्राणी कस्तूरी मृगों और मोनल पक्षी को खूब पसंद हैं। भाद्रपद में हिमालय की अधिष्ठात्री मां नंदादेवी और भगवान शिव का अभिषेक भी ब्रह्म कमल से होता है

(स्रोत : मीडिया इन्पुट्स)

बारिश कुदरती घटना है, पर पहाड़ों में जो कुदरती जल निकास के स्रोत थे, वे पिछले दशकों में लगातार अवरुद्ध किए गए। स्मार्ट नई तकनीकी से उनके नये विकल्प बनाने की जिम्मेदारी स्मार्ट सिटी बनाने वालों की ही बनती है।

मृणाल पांडे, पत्रकार
@MrinalPandey1

सिरप की मीठी खुराक, कड़वी हकीकत!

मुद्दा | सोनम लववंशी

यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते है कि जो दवा किसी मासूम को जीवन देने के लिए दी जाए, वही उसकी मौत का कारण बन जाए। दरअसल यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि हमारे देश की भयावह सच्चाई है। हाल ही में मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा और राजस्थान के कुछ ज़िलों से जो खबरें आई, उन्होंने पूरे देश को हिला दिया। सरकारी अस्पतालों में इलाज के दौरान खांसी की दवा पीने के बाद कई बच्चों ने दम तोड़ दिया। इन मासूमों को जो सिरप दिया गया था, उसका नाम था कोल्ड्रिफ़ और अब वही सिरप जांच के घेरे में है। मध्यप्रदेश में अब तक 9 बच्चों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि राजस्थान में भी कई बच्चों के बीमार पड़ने और मौत की घटनाएं दर्ज हुई है। प्रारंभिक जांच में इस सिरप में डायएथिलीन ग्लाइकोल जैसे घातक रसायन की मौजूदगी की आशंका जताई गई है। वही ज़हर, जिसने कुछ साल पहले गैबिया, उज़्बेकिस्तान और कैमरून में भारतीय कंपनियों की दवाओं से सैकड़ों बच्चों की जान ली थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उन मामलों में भारत को कड़ी चेतावनी दी थी। मगर अफसोस, इस देश के नियामक और निर्माता तब ही हरकत में आते है जब किसी की जान चली जाती है।

आंकड़े बताते है कि 2022 में गैबिया में मेडेन फार्मास्यूटिकल्स की खांसी की दवा से 66 मासूम बच्चों की जान चली गई थी। वहीं 2023 में उज़्बेकिस्तान में मैरियन बायोटेक के सिरप ने 65 बच्चों को निगल लिया। ये सिर्फ़ संख्याएँ नहीं है, ये उन नन्हे जीवनों की गवाही है जो किसी लालच, किसी लापरवाही और किसी व्यवस्था की चुप्पी की बलि चढ़ गए। यह महज़ एक औद्योगिक गलती नहीं, इंसानियत की सबसे बड़ी विफलता है। सोचिए, जिन शीशियों में जीवन का भरोसा बंद होना चाहिए था, उनमें ज़हर भर दिया गया। और यह सब उस उद्योग के भीतर हुआ जो खुद को दुनिया की फार्मेसी कहने पर गर्व करता है। बच्चों की मौतें किसी दूर देश की खबर भर हों। देश का नियामक तंत्र, जो जनता की सुरक्षा की आखि़री दीवार होना चाहिए था, वही अब सबसे कमज़ोर कड़ी बन गया है।

ऐसे में ये मौतें सिर्फ़ किसी सिरप की कहानी नहीं है, ये भरोसे की मौत की कहानी है। उस भरोसे की, जो हर माँ अपने बच्चे की पहली खुराक के साथ करती है। जब दवा ही ज़हर बन जाए, तो इलाज किससे माँगा जाए? और जब व्यवस्था ही दोषी हो, तो इंसाफ़ कौन देगा? आज जिन परिवारों ने अपने मासूमों को खोया है, उनके लिए कोई शब्द, कोई माफी, कोई मुआवज़ा पर्याप्त नहीं। उन्हें चाहिए सच्ची जवाबदेही, पारदर्शी जांच, और एक ऐसा सिस्टम जो अगली बार किसी बच्चे की जान लेने से पहले कांप उठे। अगर ये देश उस भरोसे को फिर से पाना चाहता है, तो उसे सिर्फ़ दवा की बोतलें नहीं, अपने ज़मीर को भी शुद्ध करना होगा। क्योंकि जब जीवन देने वाली दवा मौत का कारण बन जाए, तब यह समझ लेना चाहिए कि ज़हर सिर्फ़ बोतलों में नहीं, व्यवस्था में घुल चुका है। देश को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। लेकिन इस चमकदार पहचान के पीछे की सच्चाई अब डराने लगी है। हिमाचल प्रदेश, जहाँ यह दवा तैयार की गई, वही देश का प्रमुख फार्मा हब माना जाता है। वहाँ की 655 दवा निर्माण इकाइयों में से सिर्फ़ 122 ही गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के नियमों का पालन करती है। बाकी इकाइयाँ किस आधार पर काम कर रही है, कौन देख रहा है, और कौन जिम्मेदार है इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं।

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की 2024 की रिपोर्ट भी स्थिति का भयावह चित्र पेश करती है। अप्रैल से जून के बीच लिए गए 7,087 दवा-सैंपलों में से 353 असफल पाए गए यानी हर बीसवीं दवा गुणवत्ता की कसौटी पर खरे उतरने में नाकाम रही। सोचिए, जब यही दवाएँ सरकारी अस्पतालों या ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुँचती है, तो गरीब जनता के पास कौन-सा विकल्प बचता है? दरअसल यह कोई पहली बार नहीं हुआ। 2020, 2022 और 2023 में भी डायएथिलीन ग्लाइकोल युक्त भारतीय सिरप ने बच्चों की जान ली थी। हर बार जांच बैठी, रिपोर्ट आई, और फिर सब कुछ पहले जैसा हो गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, लेकिन देश के भीतर कोई सबक नहीं सीखा गया। जैसे मानो हर बार किसी मासूम की मौत ही इस तंत्र को जगाने का एकमात्र तरीका बन चुकी हो। इतना ही नहीं सच्चाई यह है कि डायएथिलीन ग्लाइकोल (डीईजी) कोई नया रसायन नहीं है। यह वही जहर है जो 1937 में अमेरिका में 100 से ज्यादा लोगों की मौत का कारण बना था, जिसके बाद वहाँ फ़ूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जैसी सशक्त संस्था बनी। यहाँ तो हर जांच प्रारंभिक रह जाती है, और हर अपराध दुर्भाग्यपूर्ण घटना बन जाता है।

यह सिलसिला बताता है कि यह सिर्फ़ एक कंपनी की गलती नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की नाकामी है। जब तक नियामक संस्थाएँ राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से काम नहीं करेंगी, और दवा निर्माण की जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक ऐसी त्रासदियाँ यूँ ही दोहराई जाएँगी। ज़रूरत सिर्फ़ बैच वापस लेने या किसी अधिकारी को निलंबित करने की नहीं है, ज़रूरत है आपराधिक मुकदमों की, कठोर सज़ाओं की, और सबसे बढ़कर उस मानसिकता को बदलने की जो मानव जीवन को महज़ आंकड़ों में बदल देती है। आज जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है, उनके लिए यह सब सरकारी बयान किसी सांत्वना से कम नहीं। वे बच्चे, जो कल तक हँसते हुए दवा पीते थे, अब अस्पताल की ठंडी रिपोर्टों में केस नंबर बन गए है। यह केवल एक सिरप की कहानी नहीं है, यह उस टूटते भरोसे की कहानी है, जहाँ जनता अब यह सोचने पर मजबूर है कि क्या इस देश में दवा ज़िंदगी देती है, या उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक मौत? ऐसे में जब लोकतंत्र में जनता का भरोसा ही दवा से उठ जाए, तब समझ लीजिए कि बीमारी सिर्फ़ शरीर की नहीं, व्यवस्था की है और उसका इलाज किसी प्रयोगशाला में नहीं, बल्कि जवाबदेही के भीतर छिपा है।

मन | ओशो

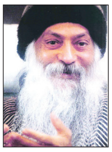

मन कभी-कभी निर्लिप्त सा मालूम देता है, लेकिन क्षण भर। और उस क्षण आनंद और प्रसन्नता का अनुभव होता है। थोड़ी कृपा और करो, ताकि मैं निर्लिप्त हो जाऊं; क्योंकि क्षण भर की निर्लिप्तता स्वप्नवत है। पहल बात, लोभ से न भरो। ध्यान में लोभ को मत लाओ, नहीं तो ध्यान खो जाएगा; जो क्षणभर मिल रहा है, वह भी खो जाएगा। अगर क्षण भर में मिल रहा है जो, उसे भी गंवाना हो, तो लोभ को ले आना। यह मैं यहां रोज देखता हूं। जब ध्यान की घटना शुरू होती है, स्वभावतः लोभ जगता है। लोभ तो पड़ा है भीतर। लोभ कोई धन का ही थोड़े होता है, ध्यान का भी होता है। लोभ तो लोभ है; किस चीज का इससे कोई संबंध नहीं है। लोभ का मतलब हैः और ज्यादा। धन हो, तो और ज्यादा। पद हो, तो और ज्यादा। प्रतिष्ठा हो, तो और ज्यादा। जो भी हो, वह और ज्यादा। यही लोभ पड़ा है तुम्हारी मटकी में। इस लोभ को बाहर विदा करो। अन्यथा जब ध्यान आएगा, यह लोभ कहेगा और ज्यादा। क्षणभर में क्या होगा! शाश्वत चाहिए। अब थोड़ा समझो। एक बार में एक ही क्षण तो मिलता है। दो क्षण तो साथ कभी मिलते नहीं। अगर एक क्षण में भी शांत होना आ गया, तो और क्या चाहिए! सारा जीवन शांत हो जाएगा। एक क्षण में शांत होना आ गया, तो तुम्हारे हाथ में कला आ गई। मगर यह लोभ कहेगा कि एक क्षण की शांति से क्या होता है! एक-एक कदम चल कर आदमी हजार मील की यात्रा पूरी कर लेता है। कोई हजारों कदम एक साथ तो चल भी नहीं सकता। दो कदम भी एक साथ नहीं चल सकते। चलते तो तब हो, जब एक कदम चलते हो। एक क्षण मिलता है एक बार में। जब एक चला जाता है हाथ से, तब दूसरा आता है। तुम्हें एक क्षण को ध्यान में रंगने की कला आ गई, धन्यभागी हो। अब लोभ को मत जगाओ, नहीं तो इस क्षण को भी नष्ट कर देगा। अब तुम कहते होः क्षण भर की निर्लिप्तता स्वप्नवत है। यह तुम्हारा लोभ कह रहा है। तुम्हारी मांग पैदा होने लगी। जब ध्यान की घटनी शुरू होती है, तो पहले तो क्षण में ही घटेगी; क्षण का ही द्वार खुलेगा। अब जब क्षण का झरोखा खुले, तो दो बातें संभव हैं। एक तो यह कि तुम धन्यवाद दो परमात्मा को कि हे प्रभु, मैं इतना भी योग्य न था, तूने क्षण भर को खिड़की खोली, इतना भी बहुत है। यह तेरे प्रसाद से ही हुआ होगा; यह तेरी अनुकंपा से हुआ होगा, क्योंकि तू रहीम है, रहमान है, इसलिए हुआ होगा।

रीडर्स मेल

जागरूकता अभियान चले

दिल्ली में चाइनीज मांझा की खरीद, बिक्री, निर्माण, भंडारण और पतंग उड़ाना एक दंडनीय अपराध है। दिल्ली पुलिस इस संदर्भ में विज्ञापन के माध्यम से जनता को जागरूक करती रही है और इस कार्य में लिप्त लोगों की धर-पकड़ भी करती है। प्रत्येक वर्ष चाइनीज मांझा की लपेट में आने से युवाओं की जान चली जाती है और बड़ी संख्या में लोग और पक्षी घायल होते हैं। कानूनी रूप से चाइनीज मांझे पर लगे प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले पर 5 साल की कैद और ₹100000 जुमनि का प्रावधान है। अकेले दिल्ली में ही 2017 से लेकर 2025 तक करीब 10 लोगों की जान जा चुकी है। स्वतंत्रता दिवस पर पतंगबाजी का जोश होता है। इसलिए जरूरी है कि दिल्ली के स्कूल, कॉलेज एवं आरडब्लूए को साथ जोड़कर दिल्ली सरकार जागरूकता अभियान चलाया जाए।

रामेन्द्र सिंह- ईमेल से

पहले बताते तो अच्छा होता

यह पत्र 'देर से जागे एयर चीफ' से संबंधित है। हालांकि 'ऑपरेशन सिंदूर' के बारे में काफी कुछ देशवासियों को मालूम है, लेकिन जो बातें एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने बताई उनमे से कुछ अभी तक लोगों के साथ साझा नहीं हुई थी। भारत ने जिस तरह से सतह से हवा में पाकिस्तानी लड़ाकू विमान को 300 किमी की दूरी से मार गिराया है वह निसंदेह उल्लेखनीय है और भारत की बढ़ती हुई सैन्य क्षमता के बारे में बताता है। जिस तरह से भारत और अमेरिका के रिश्ते में ट्रंप के रवैये के कारण खटास आई है उसके चलते हमारे एयर चीफ मार्शल ने अमेरिका द्वारा निर्मित एफ 16 को गिराए जाने की बात को छुपा लिया है। अगर यह सारी बातें सिंह पहले बता देते तो अच्छा होता, लेकिन अब विपक्ष और राहुल गांधी को अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। इसके साथ ही हमारी सरकार को सिंह के कुछ समय पहले दिए गए बयानों पर भी गौर करना चाहिए जहां उन्होंने सेना को देर से मिलने वाले लड़ाकू विमानों और हथियारों की उपलब्धता के विषय में गंभीर सवाल उठाए थे।

सुरेन्द्र भदौरिया, वाराणसी

मजबूत बने सामाजिक सुरक्षा तंत्र

देश में जन्म दर और कुल प्रजनन दर में लगातार गिरावट ने स्पष्ट किया है कि आने वाले वर्षों में भारत का सामाजिक-आर्थिक ढांचा बदलेगा। औसत महिला अब प्रतिस्थापन स्तर से कम बच्चे को जन्म दे रही है, जिससे कार्यशील आबादी घटेगी और वृद्धजन का अनुपात बढ़ेगा। आर्थिक दृष्टि से यह परिवर्तन गंभीर है। श्रम शक्ति घटने से उत्पादन और विकास पर दबाव आएगा। वृद्धजन की बढ़ती संख्या स्वास्थ्य और पेंशन व्यवस्था पर सरकारी व्यय भी बढ़ाएगी। समाधान के रूप में स्वचालन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से उत्पादकता बढ़ाई जाए और जेरियाट्रिक सेवाओं को सुदृढ़ किया जाए। राजनीतिक स्तर पर उत्तर भारत की उच्च प्रजनन दर और दक्षिण भारत की वृद्धावस्था स्थिति के बीच भारी असमानता है। भविष्य की रणनीति यह होनी चाहिए कि शिक्षा और कौशल नीति जीवन पर्यंत सीखने पर आधारित हो जिससे वृद्धजन भी योगदान दे सकें। जनसांख्यिकीय लाभांश समाप्त होने से पहले सामाजिक सुरक्षा तंत्र भी इतना मजबूत बने कि भारत संतुलित और समर्थ राष्ट्र के रूप में उभरे।

प्रियांशी, वैशाली

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा • राष्ट्रीयता • कर्तव्य • समर्पण

सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन द्वारा हिन्दुस्तान मीडिया वेन्चर्स लिमिटेड प्रेस, मौजा-दरियापुर, पुलिस स्टेशन-शाहपुर, दानापुर, पटना से मुद्रित तथा चतुर्थ तल, सहारा इण्डिया विहार, बोरिंग रोड क्रासिंग, पटना से प्रकाशित। । स्थानीय संपादक - संजय त्रिपाठी *।

पटना कार्यालय- 3911448/417/454/422, फैक्स : 2535935,2520760 विज्ञापन-3911455/434, प्रसार- 3911451/428

वर्ष - 20, अंक 6801

आर.एन.आई. सं. -बीआईएचएचआईएन/2006/18082 Postal Reg. No. : R-10/NP-50/06-07

*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु उत्तरदायी

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्
भगवान इस जग के कण-कण में विद्यमान हैं।

संस्थापक: शहीद शिरोमणि लाला जगतनारायण जी, अमर शहीद रमेश चन्द्र जी एवं कलम के योद्धा अश्विनी कुमार जी

आदित्य नारायण चोपड़ा
adityachopra@punjabkesari.com

डिजिटल युग और महिलाएं

डिजिटल की दुनिया में अब ऐसा कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं बचा है जहां महिलाएं अपने सम्मान पर डाका डालने वाले साइबर खतरों से बचकर रह सकें। आज के दौर में दुनिया भर में 60 प्रतिशत से अधिक युवतियां और महिलाएं सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर उत्पीड़न का सामना कर रही हैं। भारत इस समय युवाओं का देश है। यहां की युवा आबादी ऑनलाइन दुनिया में सबसे ज्यादा सक्रिय है। इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाली महिलाओं की बढ़ती संख्या एक सकारात्मक बदलाव है लेकिन इसने महिलाओं को वर्चुअल दुनिया में खतरों के जोखिम में डाल दिया है। भारत के प्रधान न्यायाधीश बी.आर. गवई ने डिजिटल युग में महिलाओं की सुरक्षा के खतरे को रेखांकित करते हुए कहा है कि डिजिटल दौर में बालिकाओं की सुरक्षा मुख्य प्राथमिकता होनी चाहिए। यह सुनिश्चित होना चाहिए कि तकनीकी प्रगति के साथ-साथ नैतिक सुरक्षा भी हो। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। लड़कियों को होने वाले खतरे सिर्फ भौतिक स्थानों तक सीमित नहीं हैं। अब यह डिजिटल दुनिया में विस्तार पा चुके हैं। ऑनलाइन उत्पीड़न, साइबर बुलिंग, डिजिटल स्टाकिंग, व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग और डीप फेक इमेजनरी तक चुनौतियां बढ़ी हैं।

हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने मुंबई में आयोजित 'साइबर सुरक्षा जागरूकता माह' के उद्घाटन समारोह में उनकी बेटी के साथ ऑनलाइन गेमिंग के दौरान हुई एक घटना का जिक्र किया। अभिनेता ने बताया कि ऑनलाइन गेम खेलते वक्त उनकी 13 साल की बेटी से न्यूड तस्वीरें मांगी गईं। उन्होंने आने वाली पीढ़ी को साइबर अपराध के बढ़ते खतरों से सुरक्षित रखने के लिए महाराष्ट्र सरकार से स्कूलों में साप्ताहिक साइबर पीरियड शुरू करने का आग्रह भी किया। यह घटना न केवल साइबर अपराध की गंभीरता को रेखांकित करती है, बल्कि हर माता-पिता के लिए सबक बन गई है। इसके अलावा अभिनेत्री रश्मिका मंदाना, ऐश्यर्वा राय और कई अभिनेता भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर डीप फेक तस्वीरों को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटा चुके हैं। आए दिन साइबर अपराधों से जुड़े मामले अदालतों में पहुंच रहे हैं।

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार वर्ष 2024 में महिलाओं द्वारा दर्ज कराए गए साइबर अपराधों की संख्या लगभग 48500 थी, जो वर्ष 2020 में दर्ज लगभग 22000 मामलों से दोगुनी है। अप्रैल 2025 में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, 50 प्रतिशत से अधिक महिला इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने किसी न किसी रूप में ऑनलाइन उत्पीड़न का अनुभव किया है। इनमें बदनाम करने के उद्देश्य से मॉर्फ की गई तस्वीरें वायरल करना, धमकी भरे संदेश भेजना और निजी जानकारी के आधार पर ब्लैकमेल करने जैसे अपराध शामिल हैं।

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार वर्ष 2024 में महिलाओं द्वारा दर्ज कराए गए साइबर अपराधों की संख्या लगभग 48500 थी, जो वर्ष 2020 में दर्ज लगभग 22000 मामलों से दोगुनी है। अप्रैल 2025 में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, 50 प्रतिशत से अधिक महिला इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने किसी न किसी रूप में ऑनलाइन उत्पीड़न का अनुभव किया है। इनमें बदनाम करने के उद्देश्य से मॉर्फ की गई तस्वीरें वायरल करना, धमकी भरे संदेश भेजना और निजी जानकारी के आधार पर ब्लैकमेल करने जैसे अपराध शामिल हैं। वर्ष 2025 में सामने आए कुछ प्रमुख मामले साइबर अपराधों की गंभीरता को उजागर करते हैं। पुणे में एक 64 वर्षीय महिला वैज्ञानिक को डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लगभग पौने दो करोड़ रुपए से अधिक की ठगी का शिकार बनाया गया। गुजरात में एक बड़े साइबर अपराध रैकेट का भंडाफोड़ हुआ, जहां महिलाओं को व्हाट्सएप कॉल्स के जरिए डराया और धमकाया गया। एक अन्य मामला पुणे की महिला का था जिसने ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग घोटाले में लगभग तेरह लाख रुपए गंवा दिए। इन अपराधों का न केवल वित्तीय, बल्कि मानसिक प्रभाव भी गंभीर होता है। ऐसे अनेकों मामले पूरे देश में देखने को मिले हैं, जिसमें विशेष तौर से महिलाओं को साइबर ठगों द्वारा शिकार बनाया गया है। महिलाएं अवसाद, तनाव और सामाजिक अलगाव का शिकार हो जाती हैं। दुर्भाग्यवश, समाज में साइबर पीड़ितों को दोषी ठहराने की प्रवृत्ति के कारण कई महिलाएं शिकायत दर्ज कराने से हिचकती हैं, जिससे अपराधी आसानी से बच निकलते हैं। हालांकि भारत सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन उनकी प्रभावशीलता पर सवाल उठते हैं।

वैसे तो देश में साइबर अपराध के लिए सूचना प्रौद्योगिकी नियम (आईटीएक्ट 2000) में हैकिंग, इंटरनेट पर अश्लील सामग्री का प्रसार, प्राइवेसी का उल्लंघन, धोखाधड़ी के उद्देश्य से प्रकाशन इत्यादि को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है लेकिन इसमें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विशिष्ट रूप से कोई उल्लेख नहीं है। लड़कियों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी ढांचे को मजबूत करना होगा और इसके लिए विशेष कानून बनाने होंगे। सीजेआई बी.आर. गवई ने भी लड़कियों के अधिकारों की रक्षा के लिए डिजिटल गवर्नेंस पर बल दिया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि हमें लड़कियों को शिक्षित करने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने का काम भी करना होगा। लड़कियों की रक्षा करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। अभिभावकों को भी चाहिए कि अपने बच्चों को पूरी जानकारी दें और उन्हें लगातार सतर्क करते रहें। स्कूलों में भी इस विषय को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, ताकि बच्चे खुद को बचाएं। आर्टिफिशियल इंटेलीजैंसी ने डिजिटल युग को और भी खतरनाक बना दिया है। हालांकि कई क्षेत्रों में एआई वरदान सिद्ध हो रही है। बेहतर यही होगा कि घर का वातावरण ऐसा बनाएं कि बच्चे अभिभावकों से डरने की बजाय ऑनलाइन खतरों के बारे में उनसे बात कर सकें। ई-मेल और व्हाट्सएप पर आने वाले किसी भी लिंक के जरिये गेम्स या अन्य सामग्री डाउनलोड करने से बचें और अनजान लोगों से चैटिंग न करें। अगर कोई उन्हें डराये, धमकाए या ब्लैकमेलिंग का प्रयास करे तो तुरन्त पुलिस के साइबर अपराध सेल में शिकायत करें। ऐसे मामलों को सतर्कता और संवेदनशीलता से ही सम्भाला जा सकता है। केन्द्र सरकार को भी नए कानून बनाकर डिजिटल वातावरण को सुरक्षित बनाना होगा।

आत्मनिर्भर किसान से बनेगा भारत महान

गीता पाढा

"अन्नदाता हमारे समाज की पहचान है,
उन्हीं के कारण तो उन्नत हमारा खाद्यान्न है,,
विकसित भारत की दिशा में अतुलनीय उनका योगदान है,
आत्मनिर्भर किसान से ही बनेगा यह भारत महान है...।।"

करोड़पति हैं अनेक भारतीय लेखक

डा. चन्द्र त्रिखा
chandertrikha@gmail.com

एक अच्छा लेखक जब 'रायल्टी' के आधार पर चर्चा में आता है तो लेखन की दुनिया का सम्मान बढ़ जाता है। प्रख्यात हिंदी कवि विनोद कुमार शुक्ल को हाल ही में उनकी एक कृति 'दीवार में एक खिड़की रहती थी' के लिए 30 लाख की 'रायल्टी' (मानदेय) मिली है। अब उनका नाम भारतीय पाठकों के लिए आकर्षण का बिन्दु बन गया है। वे पाठक जो अब तक उनकी काव्य-प्रतिभा के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, अब उनकी इस कृति को खरीद कर चाव से पढ़ने लगे हैं।

'रायल्टी' के बारे में चर्चाएं छिड़ी हैं तो अब चेतन भगत का नाम भी पहली कतार में उभर आया है। आज से छह वर्ष पूर्व 2019 में उनकी कुल 'रायल्टी' 28 करोड़ रुपए थी जबकि जासूसी उपन्यास लेखक को हर छमाही में 30 लाख रुपए रायल्टी के रूप में मिलने की चर्चा है। ऐसे नामों में इब्ने सफी, दत्तभारतीय आदि हैं।

करोड़ों की 'रायल्टी' पाने वाले भारतीय लेखकों में विक्रम सेठ भी हैं, जिनके बारे में यह भी चर्चा है कि उन्हें उनकी किसी भी आगामी कृति के लिए अग्रिम 'रायल्टी' मिल जाती है। इसी क्रम में अन्य चर्चित लेखकों के नाम हैं सलमान रश्दी, रस्किन बांड, झुम्पा लाहिड़ी, आरके नारायण, अनीता देसाई। इनके अलावा पुरानी पीढ़ी के करोड़ों की रायल्टी पाने वाले नामों से गुरुदेव टैगोर, मुंशी प्रेमचंद, खुशवंत सिंह, अमृता प्रीतम, श्रीलाल शुक्ल, यशपाल, विमल मित्र, कृष्णा सोबती, धर्मवीर भारती, महादेव वर्मा, निराला, वृंदावन लाल वर्मा, अज्ञेय आदि के नाम हैं। इनमें ऐसे नाम भी हैं जिन्हें फिल्म जगत से भी उनकी कृतियों के लिए करोड़ों की राशि मिली। एक केंद्रीय अधिसूचना के तहत गुरुदेव टैगोर की वृत्तियों से होने वाली आज शांति निकेतन को अदा होती है, मगर अपने जीवनकाल में इनमें से अनेक ऐसे लेखक थे, जिनकी जीवन यात्रा विपन्नता एवं तंगहाली में बीती।

ऐसे प्रतिष्ठित लेखकों में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी शामिल थे और अपने शुरूआती दौर में मुंशी प्रेमचंद भी शामिल थे। भारतीय उपमहाद्वीप के सर्वाधिक चर्चित लेखक मंटो को कुछ रुपयों के बदले में अपनी एक बहुचर्चित पुस्तक की पांडुलिपि के सर्वाधिकार भी बेचने पड़े थे। हबीब जालिब की पूरी जिंदगी तंगहाली में गुजरी। उनकी बेटी अब भी सस्ते अस्पतालों में अपनी बीमारियों का इलाज कराने की मोहताज है। वैसे साहिर लुधियानवी को भी अपने लोकप्रिय काक-संकलनों से नाममात्र के पैसे ही मिले थे। उन्हें जो भी मिला, फिल्मी-गीतों से मिला। साहिर बताते थे, उनके काव्य संकलन 'तलखियां' के पाकिस्तान में ही 16 संस्करण छपते थे, मगर उन्हें वहां के प्रकाशकों ने एक रुपया भी नहीं दिया। गैर-साहित्यिक रूमानी हिंदी लेखकों गुलशन नंदा, दत्त भारती, कुशवाहा कांत आदि शामिल थे।

हिंदी में निरंतर लेखन का कीर्तिमान आचार्य चतुरसेन शास्त्री व वैद्य गुरुदत्त ने स्थापित किया था। इधर, पौराणिक आख्यानों पर हिंदी व अंग्रेजी में लेखन की एक लहर चल निकली है। देवदत्त पटनायक, आशीष नंदी, आमित तिवारी आदि ने लेखन, प्रकाशन व 'रायल्टी' के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। ये लेखक हिंदी व अंग्रेजी में समान रूप से लोकप्रिय रहे हैं। भारतेन्दु-युग में एक विशेष उल्लेखनीय बात यह भी थी, लाखों पाठकों ने देवकीनंदन खत्री के उपन्यास पढ़ने के लिए ही हिंदी सीखी थी। पुराने लेखकों ने अपने लेखन, प्रकाशन व 'रायल्टी' के लिए आजीवन संघर्ष किया, मगर उनके वंशज अपने पूर्वजों के लेखन की आय से ही खूब मालामाल हो गए।

'रायल्टी' के मामले में कुछेक जासूसी लेखकों ने नए कीर्तिमान स्थापित किए। इस सूची में सुरेंद्र मोहन पाठक, वेद प्रकाश शर्मा, इब्ने सफी, व्योमकेश बख्शी, ओमप्रकाश शर्मा आदि शामिल हैं।

अब थोड़ा साहित्य के नोबेल-पुरस्कार विजेता के बारे में। कल नोबेल पुरस्कार विजेताओं में अमेरिकी वैज्ञानिक फ्रेड राम्सडेल का नाम घोषित हुआ, लेकिन राम्सडेल ग़ायब थे। नोबेल असेंबली ने घोषणा के तुरंत बाद उनसे संपर्क करने की कोशिश की, 15 फोन, कई ईमेल, यहां तक कि उनके परिवार और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के पुराने सहयोगियों के जरिए संदेश भेजे। सब बेकार। फिर पता लगा कि फ्रेड आइडाहो के सैल्मन रिवर माउंटेंस के जंगलों में 'ऑफ ग्रिड' हाइकिंग पर हैं। कोई मोबाइल सिग्नल, इंटरनेट- कुछ नहीं। बस वे और प्रकृति। पर्यावरण प्रेमी और पूर्व प्रोफेसर 62 वर्षीय राम्सडेल, गर्मियों से ही लैब छोड़कर इस 'डिस्कनेक्ट मोड' में हैं। उनके आखिरी ज्ञात इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, विज्ञान ने मुझे दुनिया दी, लेकिन जंगल ने शांति। मैं अपनी सबसे अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूं- बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। सोलर-पावर्ड टेंट और फिशिंग गियर के साथ वे जंगलों में डेरा डाले हैं, जहां नोबेल का संदेश अभी तक पहुंचा नहीं। यह घटना हमारी हाइपर-कनेक्टेड दुनिया पर एक तीखा तंज़ है। जहां हर सेकेंड नोटिफिकेशन की होड़ है, वहीं राम्सडेल का संदेश साफ है। कनेक्टेड रहने के लिए कभी कभी डिस्कनेक्टेड होना भी ज़रूरी है। हंगरी के मशहूर लेखक लास क्रास्नाहोर्काई को 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। नोबेल कमेटी ने उनकी रचनाओं को असाधारण और दूरदर्शी बताया। उनका लेखन गहरा, रहस्यमयी और मानव संघर्ष को दर्शाने वाला है, जो पाठकों को अपने जादुई संसार में खींच लेता है। 1954 में हंगरी के ग्युला में जन्मे क्रास्नाहोर्काई की पहली किताब सातानतांगो (1985) ने एक ढहते गांव की कहानी से सबका ध्यान खींचा। उनकी लंबे वाक्यों और दार्शनिक गहराई वाली शैली की तुलना दोस्तोव्स्की और गोगोल से होती है।

जल संकट की दस्तक: अब दिल्ली से दूर नहीं

विनीत नारायण
www.vineetnarain.net

इस वर्ष देशभर में हुई भारी बारिशों और जल प्रलय के बावजूद भारत के शहरी क्षेत्रों में जल संकट अब कोई दूर की आशंका नहीं, बल्कि एक कठोर सच्चाई बन चुका है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु जैसे महानगर, जो आर्थिक प्रगति और आधुनिक जीवनशैली के प्रतीक हैं, अब जल प्रबंधन की विफलता के गंभीर परिणाम झेल रहे हैं। हाल ही में दिल्ली के वसंत कुंज क्षेत्र में तीन बड़े मॉल और आसपास की कॉलोनियों में पानी की सप्लाई पूरी तरह ठप्प हो जाने से यह संकट फिर सुर्ख़ियों में आया। इन प्रतिष्ठानों को बंद करने की नौबत इसलिए आ गई है, क्योंकि टैंकरों से इनकी जल आपूर्ति रुक गई, जबकि भूजल दोहन (ग्राउंड वॉटर बोरिंग) पर पहले से ही एनजीटी ने प्रतिबंध लगा रखा है। यह स्थिति केवल अस्थायी तकनीकी समस्या नहीं, बल्कि एक गहरे प्रशासनिक और नीतिक संकट की ओर संकेत करती है। पिछले सात दशकों में खरबों रुपया जल प्रबंधन पर खर्च किए जाने के बावजूद ऐसा क्यों है?

दिल्ली जैसे शहर में जहां जनसंख्या 2 करोड़ से अधिक है, जल आपूर्ति व्यवस्था लंबे समय से दबाव में है। दिल्ली जल बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, शहर में प्रतिदिन करीब 1,000 मिलियन गैलन पानी की मांग है, जबकि उपलब्धता मुश्किल से 850 मिलियन गैलन तक पहुंच पाती है। वसंत कुंज जैसे पॉश इलाकों में भी पिछले कुछ वर्षों से पानी की टंकियों और निजी टैंकरों पर निर्भरता बढ़ी है, परंतु इस बार स्थिति पहले से कहीं अधिक भयावह हो गई, क्योंकि प्रशासन ने सुरक्षा और ट्रैफिक कारणों से टैंकरों की आवाजाही पर रोक लगा दी। इस निर्णय का सबसे बड़ा असर व्यापारिक केंद्रों जैसे मॉल्स, रेस्तरां और दुकानों पर पड़ा है। इन मॉल्स में हज़ारों कर्मचारी काम करते हैं और प्रतिदिन लाखों ग्राहक आते हैं; बिना पानी के ऐसी व्यवस्था एक दिन भी नहीं चल सकती। शौचालय, सफाई, भोजनालय, अग्निशमन प्रणाली, सबकुछ जल आपूर्ति पर निर्भर हैं। जब टैंकरों की आपूर्ति रुकी, तो केवल व्यापार ही नहीं, आसपास के आवासीय समाज भी संकट में पड़ गए।

दिल्ली सरकार ने कुछ वर्ष पहले भूजल दोहन पर सख्त प्रतिबंध लगाया था। उद्देश्य यह था कि गिरते जलस्तर को रोका जाए। यह पहल पर्यावरणीय दृष्टि से आवश्यक थी, क्योंकि लगातार बढ़ते दोहन ने दिल्ली के अधिकांश क्षेत्रों में भूजल को 300 फीट से भी अधिक नीचे पहुंचा दिया था, लेकिन सवाल यह है कि क्या वैकल्पिक व्यवस्था पर्याप्त रूप से विकसित की गई?

जब सरकार ने ग्राउंड वॉटर बोरिंग को गैरकानूनी घोषित किया, तब उसे समानांतर रूप से मजबूत टैंकर नेटवर्क, पुनर्चक्रण संयंत्र और रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम विकसित करने चाहिए थे। दुर्भाग्यवश, नीतियां बनीं पर उनका कार्यान्वयन अधूरा रह गया। परिणामस्वरूप, लोग न तो कानूनी तरीके से पानी निकाल सकते हैं, न सरकारी वितरण पर भरोसा कर सकते हैं। सोचने वाली बात ये है कि यदि जाड़ों में यह हाल है तो गर्मियों में क्या होगा?

दिल्ली ही नहीं, बल्कि पूरे देश में पानी की आपूर्ति से जुड़ा टैंकर कारोबार वर्षों से विवादों में रहा है। कई जगह यह सार्वजनिक सेवा से अधिक निजी व्यवसाय बन चुका है। अधिकारियों और टैंकर ठेकेदारों के बीच मिलीभगत के आरोप नए नहीं हैं। दिल्ली में जल आपूर्ति में आई यह हालिया बाधा भी ऐसे ही भ्रष्टाचार की परतें उजागर करती प्रतीत होती है। त्योहारों के मौसम में जब पानी की मांग बढ़ जाती है, घरों में सजावट, साफ-सफाई और उत्सव आयोजन अधिक होते हैं। ऐसे समय पर टैंकरों की आवाजाही पर प्रतिबंध या 'तकनीकी समस्या' का बहाना बना देना संदेह उत्पन्न करता है। कई स्थानीय निवासियों का कहना है कि कुछ जल एजेंसियों ने टैंकरों की उपलब्धता को कृत्रिम रूप से सीमित कर कीमतें बढ़ाने की कोशिश की है। इससे न केवल आम नागरिकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा, बल्कि मॉल्स और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद करने की स्थिति आ गई, अगर ये आरोप सही साबित होते हैं, तो यह सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि नैतिक दिवालियापन का उदाहरण होगा। जल जैसी बुनियादी संपदा के साथ ऐसा बर्ताव किसी नागरिक समाज में अक्षम्य अपराध है।

भारत में जल नीति के कई स्तर हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और नगरपालिका निकाय सब अपने ढंग से काम करते हैं, लेकिन इन सबमें तालमेल का अभाव है। राष्ट्रीय जल नीति (2012) यह कहती है कि हर नागरिक को पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण जल मिलेगा, पर छोटे शहरों को तो छोड़ें, दिल्ली जैसे शहरों में भी वास्तविकता इसके उलट है। नगर पालिकाएं रेन वॉटर हार्वेस्टिंग की अनिवार्यता घोषित तो करती हैं, पर अधिकांश इमारतों में यह प्रणाली केवल कागज़ों पर मौजूद है। जल पुनर्चक्रण संयंत्रों की क्षमता भी इस संकट का सामना करने के लिए अपर्याप्त है। यमुना का प्रदूषण भी दिल्ली की जल आपूर्ति पर सीधा असर डालता है। यदि यमुना से शुद्ध जल नहीं मिलेगा, तो शहर को बाहरी स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ेगा, जिससे राजनीतिक टकराव भी बढ़ते हैं। हालांकि नीति-निर्माण और कार्यान्वयन की बड़ी जिम्मेदारी सरकार पर है, नागरिक भी पूरी तरह निर्दोष नहीं हैं। शहरी समाज में जल का अनावश्यक उपयोग आम बात है। बागवानी में अत्यधिक पानी, कार धोने में व्यर्थ बहाव, और रिसाव की अनदेखी।

स्वच्छ भारत मिशन या हर घर जल जैसे अभियानों की सफलता तभी संभव है जब लोग खुद बदलाव का हिस्सा बनें। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग और ग्रे-वॉटर रीसाइक्लिंग जैसे उपाय व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर अपनाए जा सकते हैं। मॉल्स और हाउसिंग सोसाइटीज़ में यह व्यवस्था अनिवार्य की जानी चाहिए, ताकि टैंकरों पर निर्भरता घटे।

दिल्ली का वर्तमान संकट केवल एक चेतावनी है। आने वाले वर्षों में ऐसी घटनाएं और बढ़ सकती हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक़, यदि ठोस कदम नहीं उठाए गए तो 2030 तक देश के आधे बड़े शहर 'जल-विहीन' क्षेत्रों की श्रेणी में आ सकते हैं। इसलिए अब समय है कि सरकार और समाज दोनों मिलकर दीर्घकालिक रणनीति अपनाएं। गौरतलब है कि अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी पानी के अभाव के कारण मात्र 15 सालों में ही उजड़ गई थी। महानगरों में वर्षा जल संग्रहण प्रणाली को सख्ती से लागू करना। जल पुनर्चक्रण संयंत्रों की संख्या और क्षमता बढ़ाना। टैंकर संचालन को पारदर्शी और जीपीएस-नियंत्रित बनाना ताकि रिश्वतखोरी पर रोक लगे। यमुना जैसी नदियों की सफाई और पुनर्जीवन को प्राथमिकता देना। पानी की बर्बादी रोकने के लिए सख्त कानून और जनजागरूकता अभियान चलाना। इन कदमों के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जल प्रबंधन केवल संकट आने पर चर्चा का विषय न बने, बल्कि शहरी नियोजन की मूल नीति का हिस्सा हो। दिल्ली पर आई जल संकट की दस्तक यह याद दिलाती है कि पानी केवल संसाधन नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। जब-जब हम इसे समझने में चूक करते हैं, तो सभ्यता के अस्तित्व पर ही प्रश्नचिह्न लग जाता है, यदि सरकार और नागरिक समाज अब भी इस संकट को गंभीरता से नहीं लेते, तो 'जल युद्ध' भविष्य का नहीं, वर्तमान का शब्द बन जाएगा। जलसंकट का समाधान केवल योजनाओं से नहीं, ईमानदार नीयत और सामूहिक प्रयासों से ही संभव है।

एनएसई पर रोज होते हैं 17 करोड़ साइबर हमले

मुंबई, (पंजाब केसरी): नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) को प्रतिदिन लगभग 17 करोड़ साइबर हमलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में निर्बाध परिचालन सुनिश्चित करने को एक्सचेंज को चौबीसों घंटे काम करने के लिए 'साइबर योद्धाओं' की एक समर्पित टीम की आवश्यकता होती है। एनएसई को 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान एक दिन में सबसे अधिक 40 करोड़ साइबर हमलों का सामना करना पड़ा था। इसे डीडीओएस सिमुलेशन के रूप में डिजाइन किए गया था। हालांकि, साइबर हमलावर कर्मियों, मशीनों और उन्नत प्रौद्योगिकी के समन्वित प्रयासों के कारण कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए।

एनएसई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया, "एक्सचेंज पर हर दिन लाखों साइबर हमले होते हैं। लेकिन हमारी तकनीकी टीमें, उनकी प्रणाली और तकनीक विशेष सॉफ्टवेयर का उपयोग करके चौबीसों घंटे इन हमलों का मुकाबला करती हैं।" उन्होंने कहा कि साइबर हमलों की संख्या प्रतिदिन 15 करोड़ से 17 करोड़ के बीच है, जिससे टीमों और प्रणालियों के लिए यह कार्य बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाता है। दोनों साइबर सुरक्षा केंद्रों की तकनीकी टीमें लगातार सक्रिय रहती हैं और वित्तीय बाजार के बुनियादी ढांचे पर बड़े पैमाने पर होने वाले हमलों को बेअसर करने और उन्हें रोकने के लिए उन्नत सॉफ्टवेयर से लैस हैं। अधिकारी ने कहा, "तकनीकी रूप से दक्ष कर्मियों, मशीनों और तकनीक से युक्त मजबूत साइबर सुरक्षा संरचना, एनएसई के संचालन को सुरक्षित बनाती है।" एनएसई ने अपने संचालन के लिए मजबूत आंतरिक साइबर सुरक्षा उपाय लागू किए हैं और एनएसई अकादमी के माध्यम से एक साइबर सुरक्षा बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाया जाता है। अधिकारियों के अनुसार, ट्रेडिंग सदस्यों को नियमित रूप से साइबर सुरक्षा और साइबर-जुझारू क्षमता ऑडिट करवाना पड़ता है, जिसके परिणाम एक्सचेंज को प्रस्तुत किए जाते हैं। सुरक्षा व्यवस्था में ई-मेल, बाहरी डेटा, पेन ड्राइव और डिस्ट्रिब्यूटिड डिनायल ऑफ सर्विस (डीडीओएस) हमलों से सुरक्षा के लिए सख्त प्रोटोकॉल शामिल हैं। उन्होंने

आगे कहा कि इन माध्यमों से किसी भी संदिग्ध गतिविधि का पता चलने पर 'पॉप-अप' और 'अलर्ट' तुरंत जारी किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि डीडीओएस हमला सर्वर पर कई स्रोतों से आने वाले ट्रैफिक को बढ़ा देता है, जिससे वह क्रैश हो जाता है या वैध उपयोगकर्ताओं के लिए अनुपलब्ध हो जाता है। यह शेयर बाजार जैसे निर्बाध संचालन पर निर्भर उद्योगों के लिए एक गंभीर खतरा है। सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एनएसई ने अपनी प्रणाली की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए सभी ट्रेडिंग सदस्यों और कर्मचारियों के लिए भेद्यता मूल्यांकन और प्रवेश परीक्षण (वीएपीटी) अनिवार्य कर दिया है। जम्मू-कश्मीर के पत्रकारों के एक समूह ने शनिवार को एनएसई का दौरा किया और इसकी प्रबंधन सुविधाओं, साइबर सुरक्षा केंद्रों और बैकअप सेटअप का निरीक्षण किया। शीर्ष अधिकारियों ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान हुई एक घटना के बारे में जानकारी साझा की। अधिकारियों ने बताया कि उस अवधि के दौरान अत्यधिक सुरक्षा खतरे के जवाब में एनएसई ने एहतियाती उपाय के रूप में विदेशी उपयोगकर्ताओं के लिए अपनी वेबसाइट तक पहुंच को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित करने का एक सचेत निर्णय लिया। एनएसई नेतृत्व ने कहा कि किसी भी उल्लंघन की स्थिति में न केवल एक्सचेंज के सिस्टम, बल्कि 'हमसे जुड़ी हर चीज प्रभावित होगी। अधिकारियों ने आगे कहा कि बढ़ते वैश्विक अंतर्संबंध और प्रणाली की जटिलता ने बड़े पैमाने पर साइबर हमलों के जोखिम को और भी प्रासंगिक बना दिया है, जिससे वित्तीय बाजारों की स्थिरता को गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि वित्तीय बाजार के बुनियादी ढांचे पर बहुत कम लागत पर बड़े पैमाने पर साइबर हमलों की संभावना एक प्रमुख वैश्विक जोखिम बनी हुई है। एनएसई के पास एक टिकाऊ, स्व-सक्रिय बैकअप प्रणाली है जिसे औपचारिक डिजिटल प्रक्रिया और अनिवार्य अनुमोदन के माध्यम से चेन्नई स्थित अपने मुख्यालय से दूरस्थ रूप से संचालित किया जा सकता है। एक अधिकारी ने कहा, "ट्रेडिंग प्रणाली से लेकर बैकअप सेटअप तक, यह प्रणाली काफी हद तक अपना काम खुद करती है। यह न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ स्वचालित रूप से दोषों या त्रुटियों को ठीक कर सकती है। यदि यहां कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो आवश्यक प्रक्रियाओं के बाद चेन्नई में एक समानांतर बैकअप सेटअप चालू हो जाता है।" उन्होंने कहा कि ऐसा स्थिति अभी तक नहीं बनी है।

साल में 9 दिन ही खुलता है हसनंबा मंदिर

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): भारत के अलग-अलग राज्यों में कई ऐसे छोटे-बड़े मंदिर हैं, जो अपनी दिव्य मान्यताओं के लिए जाने जाते हैं। कर्नाटक में ऐसा ही एक मंदिर है, जो सिर्फ साल में 9 दिन ही खुलता है और यहां जाकर भक्त लिखित में अपनी मनोकामना रखते हैं। कर्नाटक के हासन जिले में हसनंबा मंदिर है, जिसकी मान्यता पूरे देश में है। इस मंदिर को भगवान शिव और मां पार्वती के कई रूपों से जोड़ा गया है। कहा जाता है कि राक्षस अंधकासुर को अदृश्य होने का वरदान था। असुर को ये वरदान ब्रह्मा जी की घोर तपस्या के बाद मिला था। अदृश्य होने की वजह से असुर ने उत्पाद मचाना शुरू कर दिया। उसने संतों और ब्राह्मणों को अपना निशाना बनाया। ऐसे में असुर का अंत करने के लिए भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से योगेश्वरी को बुलाया, जिन्होंने असुर का नाश किया।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83
पंजाब केसरी
दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com

स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रैस, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

प्रवाह
77 साल बेमिसाल
निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना : 18 अप्रैल 1948 • आगरा

स्वास्थ्य ही असली धन है, सोने-चांदी के टुकड़े नहीं।
-महात्मा गांधी

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की ऐतिहासिक भारत यात्रा में उन्हें जो तवज्जो मिल रही है, उसमें छिपे अर्थों को समझना जरूरी है। दक्षिण एशिया की भू-राजनीति के मद्देनजर इसे अगर भारत की कूटनीतिक जरूरत कहा जाए, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।

कूटनीतिक जरूरत

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की छह दिवसीय भारत यात्रा काबुल में तालिबान की दोबारा वापसी के बाद उनका इस स्तर पर नई दिल्ली का पहला ही दौरा है, जो सही मायनों में कई बदलावों का संकेत दे रहा है। भारत की विदेश नीति में भी इसे एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा सकता है, क्योंकि नई दिल्ली और तालिबान में बातचीत चल रही है, जबकि भारत ने अब तक तालिबान शासित अफगानिस्तान को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है। भले ही इसकी वजह बदलती भू-राजनीतिक स्थितियां और राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल हो, लेकिन तालिबान की मानवाधिकार और खासकर महिलाओं को लेकर प्रतिगामी नीतियों के चलते भारत के लिए यह राह आसान नहीं होने वाली। उल्लेखनीय है कि 2001 के अमेरिकी हमले के बाद से ही भारत अफगान सरकार को आर्थिक और सैन्य सहायता प्रदान कर तालिबान के खिलाफ मजबूती से खड़ा रहा। लेकिन, 2021 में तालिबान की वापसी के बाद भारत ने काबुल के साथ अपने राजनीतिक और कूटनीतिक रिश्ते खत्म कर दिए। फिर 2025 की शुरुआत में स्थितियों में फिर से बदलाव आया, जब भारतीय विदेश सचिव अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी से दुबई में मिले। अब उन्हीं मुत्ताकी की विदेश मंत्री एस जयशंकर से नई दिल्ली में मुलाकात से द्विपक्षीय रिश्ते परवान चढ़ते नजर आ रहे हैं। इस मुलाकात में भारतीय विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के प्रति भारत की पूर्ण प्रतिबद्धता जताई है, तो मुत्ताकी ने भी भारत को अपना घनिष्ठ मित्र बताते हुए यह आश्वासन दिया है कि अफगानी जमीन का उपयोग भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के लिए नहीं होगा। अफगानिस्तान के बगराम एयर बेस पर कब्जे की अमेरिकी मंशा के विरोध में भारत ने हाल ही में चीन, रूस और पाकिस्तान के साथ खड़े होकर तालिबान को अपना समर्थन दिखाया है। यह भी नहीं भूला जा सकता कि अफगानिस्तान उन देशों में है, जिन्होंने सबसे पहले पहलगाम आतंकी हमले की सार्वजनिक निंदा की थी। इधर मुत्ताकी भारतीय दौरे पर हैं, उधर अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमा पर संघर्ष छिड़ा हुआ है। इस संदर्भ में देखें, तो यह दौरा और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। पाकिस्तान के लिए भी यह किसी झटके से कम नहीं है, कि जिस तालिबान को कभी उसने सहारा दिया था, आज वही उसके प्रभाव से निकल कर स्वतंत्र निर्णय ले रहा है। पहलगाम आंतकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान जिस तरह से अमेरिका की गोद में बैठना चाह रहा है, और चीन अफगानिस्तान में अपना दखल बढ़ाता जा रहा है, ऐसे में तालिबानी शासन के साथ रिश्ते मजबूत करने को भारत के लिए एक रणनीतिक जरूरत के रूप में भी देखा जा सकता है।

आखिर ये सिरप बाजार में पहुंचते कैसे हैं

भारत के पास ऐसी त्रासदियों को रोकने की क्षमता है, लेकिन नीति-नियंताओं में इच्छाशक्ति का अभाव दिखता है। अगर भारतीय दवा उद्योग के व्यावसायिक हितों की रक्षा प्राथमिकता बनी रही, तो सार्थक सुधारों में रुकावटें आएंगी। यह मामला वैश्विक सुर्खियों में है, जो भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहा है।

पत्रलेखा चटर्जी
वरिष्ठ पत्रकार

छिंदवाड़ा, बैतुल और पंधुरना-ये तीनो मध्य प्रदेश के ग्रामीण जिले हैं, जहां ज्यादातर आदिवासी आबादी रहती है। इन तीनों जिलों में लगभग दो दर्जन बच्चों की मौत हो गई, जिनमें से अधिकतर पांच वर्ष से कम उम्र के थे, जिन्होंने डायथिलीन ग्लाइकॉल (डीईजी) से संदूषित कफ सिरप पिया था। डीईजी का सेवन विशेष रूप से बच्चों में किडनी फेल होने और मृत्यु का कारण बनता है। दवा के रूप में यह जहर मध्य प्रदेश के कई जिलों और राजस्थान में फैल गया, जिससे और भी जानें गईं।

इस मामले में अब तक तीन दूषित कफ सिरप की पहचान की गई है: कोल्ड्रिफ, रेस्पिफ्रेश टीआर और रीलाइफ। तमिलनाडु स्थित श्रीसन फार्मास्युटिकल्स, कोल्ड्रिफ का निर्माण करती थी। रेडनेक्स फार्मास्युटिकल्स और शेप फार्मा की भी दूषित सिरप बनाने वाली कंपनियां है। श्रीसन के मालिक को गिरफ्तार कर उसका विनिर्माण लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में बने डीईजी-दूषित सिरप के कारण दुनिया भर में कम से कम 150 बच्चों की मौत हो चुकी है।

हालिया त्रासदी एक भयावह शृंखला में शामिल हो गई है: 2022 में गांबिया, उसी वर्ष उज्बेकिस्तान, 2020 में जम्मू और कश्मीर, 1998 में गुड़गांव, 1986 में मुंबई। हर बार, यही क्रम दोहराया जाता है—दूषित सिरप, मृत बच्चे, जन आक्रोश, और फिर सन्नाटा। गिरफ्तारियां तो होती हैं, लेकिन भारत में दवाओं को दूषित करने के आरोप में किसी को जेल नहीं भेजा गया है।

तमिलनाडु औषधि नियंत्रण विभाग के निरीक्षण में पाया गया कि श्रीसन फार्मास्युटिकल्स ने 364 विनिर्माण नियमों का उल्लंघन किया है, जिनमें से 39 'बहुत गंभीर' और 325 'गंभीर' श्रेणी के हैं। खबरों के मुताबिक, रिपोर्ट में अयोग्य कर्मचारियों, घटिया पानी और उपकरणों, कीट नियंत्रण की कमी, उत्पादन निगरानी प्रक्रियाओं की कमी, और गुणवत्ता आश्वासन या डाटा संग्रह के अभाव का हवाला दिया गया है। सिरप में इस्तेमाल किया गया डीईजी कथित तौर पर बिना बिल के खरीदा गया था, जिससे अवैध स्रोत का संकेत मिलता है। पुलिस ने उस डॉक्टर को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिसने यह सिरप लिखा था, हालांकि चिकित्सा समूहों का तर्क है कि असली जिम्मेदारी नियामकों की है, न कि चिकित्सकों की। लेकिन सिर्फ गिरफ्तारी से व्यवस्था ठीक नहीं होगी।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने भारत की नियामक खामियों पर गहरी चिंता व्यक्त की है और चेतावनी दी है कि ऐसी दवाएं अनियमित माध्यमों से दूसरे देशों तक पहुंच सकती हैं। भारत का कहना है कि इनमें से किसी भी सिरप का निर्यात नहीं किया गया, लेकिन अतीत को मिटाया नहीं जा सकता। भारत में डीईजी त्रासदियों में मौतों का भूगोल चिंताजनक रूप से एक जैसा है। पीड़ित लगभग हमेशा गरीब, ग्रामीण और बेजुबान होते हैं। ये सिरप सस्ते होने के कारण गरीब लोग खरीदते हैं। निर्माता अक्सर छोटी कंपनियां होती हैं, जिन पर बहुत कम निगरानी होती है, और ये ढीले खरीद मानकों वाले राज्यों में अपना उत्पाद बेचते हैं।

आखिर ये सिरप शहरी भारत के संपन्न इलाकों में क्यों नहीं पहुंचते? जाने-माने जन स्वास्थ्य कार्यकर्ता और *'द ट्रुथ पिल: द मिथ ऑफ ड्रग रेगुलेशन इन इंडिया'* के सह-लेखक दिनेश ठाकुर कहते हैं: 'संपन्न लोग शायद इन उत्पादों को उन दुकानों से खरीदते हैं, जहां छोटी और मध्यम दवा कंपनियों द्वारा बनाए गए कफ सिरप नहीं होते। बड़े शहरों की दवा दुकानों में बड़ी दवा कंपनियों द्वारा बनाए गए कफ सिरप मिलते हैं, जो एक हद तक औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की अनुसूची एम का पालन करती हैं।'

अनुसूची एम भारत में दवा उत्पादों के लिए उत्तम विनिर्माण प्रथाओं (जीएमपी) की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। दिसंबर 2023 में अधिसूचित विनिर्माण नियमों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने और गुणवत्ता नियंत्रण को मजबूत करने के लिए हाल ही में संशोधित करके अद्यतन किया गया है। एक निश्चित आय स्तर से ऊपर के शहरी भारतीय अपनी दवाइयां बेहतर स्टॉक वाली फार्मेसियों से खरीदते हैं, ब्रांडेड विकल्पों की मांग करते हैं, तथा ऐसे स्थानों पर रहते हैं, जहां मीडिया की जांच और नियामक दृश्यता अधिक होती है। संक्षेप में, जो सिरप छिंदवाड़ा में लोगों की जान लेता है, वह दिल्ली के पॉश डिफेंस कॉलोनी या मुंबई के बांद्रा वेस्ट में कभी नहीं पहुंच पाएगा।

इसलिए जहां नियामकीय विफलता स्पष्ट रूप से ऐसी घटिया और खतरनाक दवाओं को बाजार में आने देने के लिए जिम्मेदार है, वहीं यह भारत की दो-स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का भी स्पष्ट संकेत है। एक ओर, भारत में अच्छी गुणवत्ता वाली दवाएं (जिनमें जेनेरिक भी शामिल हैं) जिंदगी बचाती हैं। दूसरी ओर, सस्ते और खतरनाक सिरप बच्चों की जान ले लेते हैं। सुरक्षा अब अधिकार नहीं, विशेषाधिकार बन गया है।

भारत में डीईजी-दूषित सिरप की हालिया त्रासदी में एक प्रमुख नियामकीय खामी केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) और राज्य औषधि नियंत्रण प्राधिकरणों के बीच एक-दूसरे पर दोष मढ़ने और जवाबदेही की कमी है। यह औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के दोहरे नियामक ढांचे से उपजा है, जहां सीडीएससीओ राष्ट्रीय नीति, लाइसेंसिंग और निर्यात को संभालता है, जबकि राज्य प्रवर्तन, निरीक्षण और स्थानीय लाइसेंसिंग का प्रबंधन करते हैं, जिसके चलते असंगत निरीक्षण, विलंबित प्रतिक्रियाएं और एक-दूसरे पर दोष मढ़ा जाता है, जिससे रोकथाम में बाधा आती है।

जैसा कि वैश्विक स्वास्थ्य नीति और जैव नैतिकता विशेषज्ञ डॉ. अनंत भान कहते हैं: 'सभी भारतीय फार्मा कंपनियों को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन नियामक ढांचे में लगातार खामियों का मतलब है कि दवाओं की गुणवत्ता, प्रभावकारिता और सुरक्षा के लिए कठोर परीक्षण और निगरानी नहीं हो रही है। इसके अलावा दवाओं के अतार्किक संयोजनों को भी खत्म करने की जरूरत है।

भारत के पास ऐसी त्रासदियों को रोकने की क्षमता है, लेकिन राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव है। अगर भारतीय दवा उद्योग के व्यावसायिक हितों की रक्षा प्राथमिकता बनी रही, तो सार्थक सुधारों में रुकावटें आएंगी। इस रक्षात्मक रुख ने व्यवस्थागत खामियों को जारी रहने दिया है। विडंबना यह है कि, गांबिया, उज्बेकिस्तान और अब मध्य प्रदेश जैसी त्रासदियों के कारण यह मामला वैश्विक सुर्खियों में है, जो अब भारत की फार्मा प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहा है।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

सुसान आर. वुल्फ

जो हम सोचते और महसूस करते हैं, उससे कहीं ज्यादा हमारे कार्यों से जीवन में अर्थ आता है। हमें अपने जुनून को पहचानना होगा, उसे मूल्यवान कार्यों से जोड़ना होगा, और फिर उसे जीना होगा।

कुछ ऐसा रचें, जो दूसरों के लिए भी मायने रखे

जीवन में अर्थ की खोज हर व्यक्ति की यात्रा का एक केंद्रीय हिस्सा है। हम सभी अपने जीवन में उद्देश्य, संतुष्टि और गहराई की तलाश करते हैं। जब यह अर्थ अनुपस्थित होता है, तो जीवन में ऊब, नीरसता, अलगाव और उदासीनता जैसे भाव हावी हो जाते हैं। लेकिन जीवन में अर्थ क्या है? क्या यह एक विशिष्ट अवधारणा है, या इसे अन्य लक्ष्यों और विचारों में समाहित किया जा सकता है? जीवन में अर्थ तब उत्पन्न होता है, जब व्यक्ति की व्यक्तिगत रुचि किसी ऐसी चीज से मिलती है, जो वस्तुनिष्ठ रूप से मूल्यवान है। अर्थ तब उत्पन्न होता है जब व्यक्तिपरक आकर्षण वस्तुनिष्ठ आकर्षण से जुड़ता है। अर्थ उन वस्तुओं से प्यार करने से उत्पन्न होता है, जो प्यार के योग्य हैं और उन्हें सकारात्मक तरीके से जोड़ने से। लोग कभी-कभी दूसरों को असाधारण रूप से अर्थपूर्ण जीवन जीते हुए देखते हैं, या उनके जीवन को व्यर्थ मानते हैं, जिसमें अर्थ की कमी है। तीन महत्वपूर्ण तत्व हैं, व्यक्तिपरक आकर्षण, वस्तुनिष्ठ मूल्य, और उत्पादक जुड़ाव। मानव जीवन की गहरी चाहत पूर्णता की ओर होती है। जीवन का अर्थ केवल व्यक्तिगत संतुष्टि या केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि उस संतुलन में है, जहां हमारी व्यक्तिगत रुचियां और जुनून किसी ऐसी चीज से मिलते हैं, जो व्यापक रूप से मूल्यवान हो। केवल यह कहना कि जीवन तब अर्थपूर्ण होता है, जब वह किसी बड़े उद्देश्य में योगदान देता है, अपूर्ण है; क्योंकि यह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की उपेक्षा करता है, जैसे कि व्यक्तिगत संतुष्टि, रिश्तों की गहराई, और छोटे-छोटे दैनिक सुख, जो जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं। अर्थपूर्ण जीवन के लिए जुनून और कार्य का सामंजस्य महत्वपूर्ण है, जहां दोनों मिलकर कुछ ऐसा रचें, जो आपके लिए और दूसरों के लिए भी मायने रखे। यह विचार व्यक्तिगत और सामूहिक कल्याण के बीच एक सेतु बनाता है। जो हम सोचते और महसूस करते हैं, उससे कहीं ज्यादा हमारे कार्यों से जीवन में अर्थ आता है। हमें अपने जुनून को पहचानना होगा, उसे मूल्यवान कार्यों से जोड़ना होगा, और फिर उसे जीना होगा। हमारा दिल, हमारा दिमाग, और हमारा कार्य, तीनों में तालमेल हो, तो एक ऐसा जीवन बनता है, जिसमें आप अपने दिल की सुनते हैं, अपने दिमाग का उपयोग करते हैं, और उन योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं, जिससे गहरी संतुष्टि और सार्थकता मिलती है। हम अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी मूल्यवान बनाएं। जीवन का असली आनंद तब मिलता है, जब हम अपने कार्यों के माध्यम से दुनिया में कुछ सकारात्मक जोड़ते हैं। एक सार्थक जीवन के लिए व्यक्तिपरक अनुभव (सकारात्मक भावनाएं) और वस्तुनिष्ठ मूल्य (जैसे दूसरों की मदद करना), दोनों महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जब आपको व्यक्तिगत खुशी व्यक्तिपरक लक्ष्यों से मिलती है, जो वस्तुनिष्ठ रूप से मूल्यवान हैं, तो जीवन वास्तव में सार्थक बन जाता है। यह तब होता है, जब आप अपने जुनून, मूल्यों और विश्वासों के अनुसार एक उद्देश्यपूर्ण और पूर्ण जीवन जीते हैं।

कार्य से प्रेम करना सीखें

सूत्र

हम सबके पास एक ही जीवन है, इसलिए स्वयं को ऐसे कार्यों में समर्पित करें, जो स्वयं के लिए तो बेहतर हों ही, दूसरों के लिए भी मददगार हों। स्वयं के जुनून को पहचानें और उसे ऐसे कार्य में लगाएं, जो आपको आनंद प्रदान करे। कार्य से प्रेम करना सीखें। जीवन का असली आनंद तब मिलता है, जब हम अपने कार्यों के माध्यम से दुनिया में कुछ सकारात्मक जोड़ते हैं।

दूसरा पहलू

आखिर ये अक्ल दाढ़ क्यों आती हैं? इसका जवाब सुदूर अतीत से लेकर कुछ हद तक वर्तमान से जुड़ा है।

किस काम आती है अक्ल दाढ़

एरिडेन लेट्रा

आपको शायद मालूम होगा कि हर किसी के चारों अक्ल दाढ़ नहीं आतीं। अधिकांश लोग अपनी अक्ल दाढ़ निकलवा देते हैं।

ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफारेन्सिस नामक एक प्रजाति के जबड़े व दांत अभी के इन्सानों की तुलना में काफी बड़े और मोटे होते थे। प्रारंभिक मानव पूर्वजों को सख्त खाना चबाने के लिए मजबूत जबड़े व दांतों की जरुरत थी।

अक्ल दाढ़ (विजडम टीथ) हमारे मुंह के सबसे पीछे स्थित दाढ़ों का तीसरा समूह होता है। यह पहली और दूसरी दाढ़ों की तरह दिखती है, लेकिन कभी-कभी थोड़ी छोटी हो सकती है। इसे आम तौर पर अक्ल दाढ़ कहते हैं, क्योंकि यह 32 स्थायी दांतों में से आखिरी होती है, जो 17 से 25 साल की उम्र के बीच निकलती है, जब हम बड़े और समझदार हो जाते हैं। आपको शायद मालूम होगा कि हर किसी के चारों अक्ल दाढ़ नहीं आतीं। अधिकांश लोग अपनी अक्ल दाढ़ निकलवा देते हैं। आखिर ये अक्ल दाढ़ क्यों आती हैं? इसका जवाब सुदूर अतीत से लेकर कुछ हद तक वर्तमान से जुड़ा है। जिस तरह आपके और आपके रिश्तेदारों के बीच कई चीजें मेल खाती हैं, उसी प्रकार मानव जाति भी अपने विस्तृत परिवार यानी बंदर, गोरिल्ला और चिंपैंजी जैसे प्राइमेट्स से कई समनाताएं साझा करते हैं। इन सभी के पास अक्ल दाढ़ होती हैं। कुछ लाख वर्ष पहले, प्रारंभिक मानव पूर्वजों के जबड़े और दांत आज के इन्सानों से बड़े थे।

उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफारेन्सिस नामक एक प्रजाति के जबड़े व दांत अभी के इन्सानों की तुलना में काफी बड़े और मोटे होते थे। वैज्ञानिकों का मानना है प्रारंभिक मानव पूर्वजों को कच्चा मांस और पौधे जैसे सख्त खाना चबाने के लिए मजबूत जबड़े और दांतों की जरूरत थी।

आज का खाना तब के मुकाबले बहुत नरम है। खेती, खाना पकाने और खाने को संग्रहीत करने की तकनीकों की वजह से अब हमें सख्त चीजें चबाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस वजह से, लाखों वर्षों में इन्सानों के जबड़े छोटे व चेहरे सपाट होत गए। वर्षों के सतत बदलाव के बाद हमारे लिए पहले की तरह अब अक्ल दाढ़ महत्वपूर्ण नहीं रही। आजकल करीब 25 प्रतिशत लोगों के अक्ल दाढ़ नहीं आती। वैज्ञानिकों को स्पष्ट रूप से नहीं मालूम कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन इसका संबंध माता-पिता से मिलने वाली जीन से हो सकता है। कुछ वैज्ञानिकों का तर्क है कि आजकल, छोटे जबड़े वाले इन्सानों के लिए अक्ल दाढ़ का न होना फायदेमंद है। कभी-कभी, जगह की कमी के कारण, अक्ल दाढ़ जबड़े की हड्डी के अंदर फंस जाती है। कुछ मामलों में अक्ल दाढ़ आंशिक रूप से ही उभरी होती है। उनमें कभी-कभी दर्द, दांतों में सड़न या मसूड़ों में सूजन हो जाती है, जिससे उन्हें चिकित्सक से निकलवाना पड़ता है। यदि अक्ल दाढ़ मुंह में सही स्थिति में और स्वस्थ हों, तो उन्हें निकलने की आवश्यकता नहीं होती। दिन में कम से कम दो बार ब्रश करने और मुंह की नियमित सफाई करने से आपके दांत स्वस्थ रहेंगे। - साथ में सेठ एम. वेनबर्ग (द कन्वर्सेशन से)

आंकड़े

मानसिक स्वास्थ्य

अब लोग मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को स्वीकार कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से ऑस्ट्रेलिया के लोग पीड़ित हैं।

ऑस्ट्रेलिया	43%
अमेरिका	41%
ब्रिटेन	38%
कनाडा	37%
जर्मनी	32%

भारत में मानसिक स्वास्थ्य समस्या के आंकड़े 23 प्रतिशत हैं। | स्रोत : Statista

सुखिया फलवाली का एक भी फल नहीं बिका व घर में अनाज भी नहीं था। निःस्वार्थ दान और कान्हा द्वारा दिए गए गेहूं के केवल चार दानों ने उसकी तकदीर बदल दी।

उदारता का फल मीठा होता है

अंतर्यात्रा
संकलित

नन्हा कान्हा माखन-मिश्री के साथ रसीले फलों का शौकीन था। सुखिया फलवाली रोज गोकुल की गलियों में फल बेचती थी। एक दिन वह थकी-हारी कान्हा के दरवाजे पर बैठ गई। उसने उदास होकर कहा, 'सुबह से शाम हो गई, पर एक भी फल नहीं बिका। घर में अनाज भी नहीं है। हे भगवान, मेरी मदद करो!'

कान्हा वहीं पास में खेल रहे थे, सुखिया के पास आए और बोले, 'मैया, मुझे ये मीठे फल खिलाओ, भूख लगी है।' सुखिया ने कहा, 'फल दूंगी, पर तुम्हें इनकी कीमत चुकानी होगी, तुम्हें इन फलों के बदले में मुझे कुछ देना होगा।' कान्हा ने हंसकर कहा, 'हां-हां, अभी लाता हूं!' वह घर गए और अपनी छोटी-छोटी मुट्ठियों में गेहूं के दाने भरकर लौटे। उनकी छोटी मुट्ठी से गेहूं के दाने गिरकर रास्ते में ही बिखर गए और सुखिया तक पहुंचते-पहुंचते केवल चार दाने बचे। कान्हा ने कहा, 'मैया, ये लो कीमत!' सुखिया बोली, 'अरे, बस चार दाने?' कान्हा ने जवाब दिया, 'मैं तो मुट्ठी भर लाया था, पर रास्ते में गिर गए।' सुखिया ने मुस्कराकर कहा, 'कोई बात नहीं, ये सारे फल ले लो।' सुखिया ने कान्हा की भूख मिटाने के लिए सारे फल दे दिए। घर पहुंचकर सुखिया ने देखा कि उसकी टोकरी हीरे-मोतियों से भरी थी। उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया और बोली निःस्वार्थ भाव से किया गया कार्य अप्रत्याशित फल देता है। सुखिया की उदारता ने उसे अपार सुख और समृद्धि दी।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 13 अक्तूबर, 1953

फ्रांसीसी किसानों का पेरिस की ओर मार्च

फ्रांसीसी किसानों का पेरिस की ओर मार्च
मंदी के विरुद्ध उग्र प्रदर्शन

फ्रांस में मंदी का भारी दौर चल रहा है, जिसके फलस्वरूप किसानों में बेचैनी छाई हुई है। मध्य फ्रांस में लाखों किसानों ने सरकार के विरुद्ध उग्र प्रदर्शन के लिए पेरिस की ओर मार्च किया।

सूचना अधिकार के बीस साल

भारत में आरटीआई कानून लागू हुए दो दशक पूरे हुए हैं, इसलिए इसके प्रभाव और क्रियान्वयन की चुनौतियों पर गौर करना होगा।

मुहम्मद खालिद जीलानी

मुद्दा

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को बीते बारह अक्तूबर को बीस बरस पूरे हो गए। सूचना के अधिकार को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा तथा आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय संधि में मानवाधिकार के रूप में देखा गया है।

भारत में लोक प्रशासन में पारदर्शिता, शुचिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्ट (सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम), 2002 बना, हालांकि इसे कभी अधिसूचित नहीं किया गया। यह लागू भी नहीं हुआ और इसके कमजोर प्रावधानों की आलोचना भी हुई।

वर्ष 2005 में एक व्यापक सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 बना, जो लागू भी हुआ। भारत के संविधान के अनुच्छेद-19 (1) (ए) के अंतर्गत जो वाक्-स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों को दिया गया है, उसमें सूचना प्राप्त करने का अधिकार अंतर्निहित है। सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है। ये कानून नागरिकों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने, सरकारी गतिविधियों, नीतियों और निर्णयों के बारे में जानकारी लेने, लोक प्राधिकारियों के नियंत्रण में उपलब्ध सूचनाओं तक पहुंच हासिल करने और जन-सामान्य के प्रति नौकरशाही की जवाबदेही, शुचिता व पारदर्शिता का अधिकार देता है।

भारत में आरटीआई कानून को लागू हुए दो दशक पूरे हुए हैं, इसलिए इसके प्रभाव और क्रियान्वयन की चुनौतियों पर गौर करना जरूरी होगा। यहां उल्लेखनीय है कि विश्व के 132 देशों ने सूचना के अधिकार को सांविधानिक गारंटी के तौर पर अपनाया या आरटीआई कानून बनाए। इन्हें लागू करने के लिए कानूनी ढांचों की मजबूती पर आधारित सेंटर फॉर लॉ एंड डेमोक्रेसी (सीएलडी) की ग्लोबल आरटीआई रेटिंग में वर्ष 2011 में भारत दूसरे स्थान पर था, लेकिन लगातार गिरावट के बाद 2024 में यह खिसक कर नौवें पायदान पर आ गया। इस गिरावट का कारण भारत के आरटीआई कानून की दूसरी अनुसूची में व्यापक अपवाद होना है, जो सुरक्षा, खुफिया और अन्य निकायों से सूचना तक पहुंच को प्रतिबंधित करते हैं। यह छूट इसलिए दी गई है, ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यक्तिगत गोपनीयता या अन्य महत्वपूर्ण हितों को सुरक्षित रखा जा सके। हालांकि, इन छूटों की व्याख्या करने की गुंजाइश काफी होती है, जिसका उपयोग अक्सर जन सूचना अधिकारियों द्वारा सूचना देने से बचने के लिए किया जाता है। सरकारों की राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव का ही नतीजा है कि इस कानून के अस्तित्व में आने के दो दशक बाद भी सरकारी कार्यालयों में आसानी से सूचना देने की प्रवृत्ति विकसित नहीं हो पाई है, कहीं बड़ी संख्या में आवेदन लंबित हैं, तो कहीं आधी-अधूरी, अपूर्ण और भ्रामक सूचनाएं दी जाती हैं। राज्य सूचना आयोगों में अपीलों की तादाद लगातार बढ़ती रहती है, न तो सूचना देने में तीस दिन की समय-सीमा का पालन किया जाता है और न ही सूचना देने और अपीलों के निस्तारण में देरी का कारण ही बताया जाता है। सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 के जरिये केंद्र और राज्य स्तर पर सूचना आयुक्तों की सेवा शर्तों में संशोधन हुआ, इन संशोधनों से सूचना आयुक्तों की स्वतंत्र कार्यप्रणाली प्रभावित हुई है। इसी तरह वर्ष 2023 में आरटीआई एक्ट की धारा-8 (1)(जे) के संशोधन में सभी व्यक्तिगत जानकारी को प्रकटीकरण से छूट दी गई। ऐसे में, आम लोगों का हथियार बन चुके इस कानून के मूल स्वरूप को बचाए रखना और लोगों में इस कानून के इस्तेमाल की बेहतर समझ बनाना एक बड़ी चुनौती जैसा है।

सूचना के अधिकार कानून के अमल में अगर ऐसी ही उदासीनता जारी रही, तो यह कानून निष्प्रभावी हो जाएगा और अभी घपलों-घोटालों, लोक सेवकों के भ्रष्टाचार से सबंधित जो भी जानकारियां छनकर ही सही, मिल रही हैं, वे भी नहीं मिलेंगी। सरकार को द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें लागू करनी चाहिए, जिनमें आरटीआई अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए गठित राष्ट्रीय समन्वय समिति का राष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य, आरटीआई राष्ट्रीय पोर्टल के कार्यों की निगरानी और अधिनियम के प्रभाव का मूल्यांकन, राज्य स्तर पर विश्वसनीय गैर-लाभकारी संगठनों को शामिल किया जाना, लोक प्राधिकरणों में सूचना अधिकार के उचित कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त कर्मचारियों की नियुक्ति, दस्तावेजी रिकॉर्ड का उचित रख-रखाव, सूचना मांगने वालों की जीवन सुरक्षा, सरकारी अधिकारियों का व्यापक प्रशिक्षण और रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण इत्यादि शामिल हैं।

सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिक से अधिक लोग इस कानून के जरिये प्रशासनिक पारदर्शिता का लाभ उठा सकें। लिहाजा सूचना देने में हीला-हवाली करने पर सख्त दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर सरकार की मंशा साफ है, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाने में उसे गुरेज नहीं होना चाहिए।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

देश-विदेश में नोबेल

परस्पर संवाद और यात्रा के बिना ज्ञान में वृद्धि नहीं होती है। नोबेल विजेताओं पर जब हम नजर डालते हैं, तो यह बात स्पष्टता से सामने आती है कि ज्ञान के लिए अपना घर, देश छोड़ना पड़ता है। कम से कम 30 प्रतिशत ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं, जो अपने जन्म के देश में नहीं, बल्कि अपने अध्ययन-अनुसंधान के देश में आकर कामयाब हुए हैं। नेचर की एक विशेष रिपोर्ट के मुताबिक, इस सदी में भौतिकी, रसायन विज्ञान और चिकित्सा क्षेत्र में 202 नोबेल विजेताओं में से 70 प्रतिशत से कम अपने देश में रहते सम्मानित हुए हैं। इस सदी में 63 पुरस्कार विजेता ऐसे हैं, जिन्होंने नोबेल जीतने से पहले अपने जन्मस्थान को छोड़ दिया। इनमें से अनेक वैज्ञानिकों ने एकाधिक बार अपना देश बदला और तब कामयाबी तक पहुंचे हैं। इस बार के विजेताओं को भी अगर देखें, तो उनमें से कम ही वैज्ञानिकों का जन्म अमेरिका में हुआ है।

रसायन विज्ञान क्षेत्र के विजेताओं को अगर देखें, तो रिचर्ड रॉबसन का जन्म यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, पर अब वह ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। इसके अलावा, उमर याघी, जो अब अमेरिका निवासी हैं, विज्ञान में जॉर्डन में जन्मे पहले नोबेल विजेता बने हैं। 2025 के लिए भौतिकी के तीन विजेताओं में से दो अप्रवासी हैं : मिशेल डेवोरेट का जन्म फ्रांस में और जॉन क्लार्क का जन्म यूनाइटेड किंगडम में हुआ है, पर दोनों अब अमेरिका निवासी हैं। नोबेल के मामले में प्रवासी वैज्ञानिकों की कामयाबी देखने लायक है। अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे प्रख्यात वैज्ञानिक जर्मनी में जन्मे, पर बाद में स्विट्जरलैंड और फिर अमेरिका जा बसे। ठीक इसी तरह से विख्यात मैरी क्यूरी, पोलैंड में जन्म लेने के बाद फ्रांस आकर कामयाब हुईं। बेशक, इन वैज्ञानिकों को वहां जाकर लाभ हुआ, जहां प्रशिक्षण, प्रयोगशाला व उपकरणों की सुविधा थी। अमेरिका इस मामले में कामयाब है। अमेरिका में रहने वाले वैज्ञानिकों को ज्यादा नोबेल मिलता है, पर नोबेल विजेता सर्वाधिक वैज्ञानिकों का जन्म इंग्लैंड में होता है। मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट विश्वविद्यालय की अर्थशास्त्री इना गांगुली बताती हैं कि प्रतिभाएं कहीं भी पैदा हो सकती हैं, पर अवसर हर जगह नहीं पैदा होते। भारत को देखें, तो यहां अवसर की कमी है। यहां जन्मे और यहीं रहते हुए केवल तीन भारतीयों को नोबेल मिला है - टैगोर, सी वी रमन और कैलाश सत्यार्थी। दो अन्य मदर टेरेसा और दलाई लामा को भारत में रहते नोबेल मिला है। बाकी पांच भारत में जन्म लेने वाले वैज्ञानिक और अर्थशास्त्री विदेश जाकर ही नोबेल विजेता हुए हैं। भारत के पास अकेले सी वी रमन ऐसे वैज्ञानिक हैं, जो यहीं रहते हुए नोबेल विजेता हुए थे। अन्य भारतीय वैज्ञानिकों को विदेश जाकर नोबेल प्राप्त हुआ।

डोनाल्ड ट्रंप की वर्तमान नीति अगर जारी रही, तो अमेरिका में अध्ययन करने वाले विदेशी वैज्ञानिकों-विद्वानों की संख्या धीरे-धीरे घटती चली जाएगी।

यहां चिंता की बात यह है कि नोबेल के मामले में अमेरिकी वर्चस्व टूटने वाला है, क्योंकि उसकी नीतियां विदेशियों के लिए प्रतिकूल होती जा रही हैं। ट्रंप की वर्तमान नीति अगर जारी रही, तो अमेरिका में अध्ययन करने वाले विदेशी वैज्ञानिकों-विद्वानों की संख्या धीरे-धीरे घटती चली जाएगी। चूंकि अमेरिकी प्रशासन विज्ञान के बजट को घटा रहा है, इसलिए भारतीय मूल के नोबेल विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी अमेरिका छोड़कर जा रहे हैं। सख्त आव्रजन नीतियों की वजह से अमेरिका से प्रतिभा पलायन का खतरा मंडराने लगा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, संयुक्त राज्य अमेरिका विज्ञान का एक वैश्विक केंद्र बन गया था। ज्ञान-विज्ञान के प्रति उसकी उदारता उदाहरण थी, लेकिन अब अमेरिका की अनुदारता उसे महंगी पड़ने वाली है।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 13 अक्तूबर, 1950

युद्ध वर्जन घोषणा

भारत के प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री लियाकत अली खां के सामने बहुत समय पूर्व एक सीधा-सादा सुझाव रखा था। सुझाव यह था कि भारत और पाकिस्तान दोनों एक संयुक्त घोषणापत्र प्रकाशित करें कि वे अपने आपसी झगड़ों को निपटाने के लिए किसी भी अवस्था में युद्ध का आश्रय नहीं लेंगे। अपने तमाम झगड़ों को आपसी बातचीत द्वारा, मध्यस्थ की मदद से या पंच फैसले द्वारा हल करने की कोशिश करेंगे। बहुत समय से भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों में इस विषय में पत्र-व्यवहार हो रहा है, किन्तु दोनों अभी तक एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके हैं। इस प्रकार की घोषणा का लाभ स्पष्ट है। आज भारत और पाकिस्तान एक-दूसरे को भय की दृष्टि से देखते हैं। एक को दूसरे के प्रति आशंका है कि कहीं वह हमला न कर दे। हमले के खतरे का मुकाबला करने के लिए दोनों देशों को अपनी शक्ति से कहीं अधिक रुपया सेना पर व्यय करना पड़ रहा है। युद्ध वर्जन की घोषणा से दोनों देशों का आपसी तनाव कम हो जायेगा, वे एक-दूसरे के प्रति निश्चित हो सकेंगे और सैनिक तैयारियों पर होने वाला काफी खर्च बच जायेगा। यह रुपया जनता की भलाई के कार्यों पर व्यय किया जा सकेगा।

भारत सरकार जहां तक संभव हो, अपने झगड़े शान्तिपूर्ण तरीकों से निपटाने के पक्ष में है। पड़ोसी देशों के प्रति उसकी आक्रामक नीति नहीं है। जबतक उस पर कोई देश चढ़ न दौड़े, वह तलवार का सहारा नहीं लेना चाहती। इसीलिए, उसने आगे होकर पाकिस्तान के सामने युद्ध वर्जन की घोषणा करने का प्रस्ताव रखा था। किन्तु पाकिस्तान को यह सीधा-सादा सुझाव मान लेने में भी अड़चन महसूस हो रही है। उसका कहना है कि इस सीधी-सादी घोषणा से काम नहीं चल सकता। ऐसी घोषणा करने से पहले झगड़ों को निपटाने के निश्चित तरीके के बारे में भी दोनों देशों को सहमत हो जाना चाहिए। पाकिस्तान ने सुझाव दिया है कि किसी भी झगड़ को निपटाने के लिए यह तरीका काम में लाया जायेगा। दो महीने तक दोनों देश आपसी बातचीत करें। उसके बाद दो महीने तक किसी मध्यस्थ की मदद से झगड़ को हल करने की कोशिश की जाये। अगर दोनों उपाय निष्फल सिद्ध हों, तो झगड़ को मान्य पंचों के सिपुर्द कर दिया जाये और पंचों का फैसला दोनों देश स्वीकार कर लें।

प्रवासी अपने घर-देश भेजते रहें पैसा

आलोक जोशी | वरिष्ठ पत्रकार

यहां स्कैन करें

दुनिया के किसी देश की प्रवासी बिरादरी इतनी रकम अपने मुल्क नहीं भेज रही, जितनी प्रवासी भारतीय भेज रहे हैं। साल 2024 में भारतीय प्रवासियों ने कुल 129.4 अरब डॉलर भेजे।

भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार और मजबूती पर पिछले कुछ वर्षों में काफी कुछ कहा-सुना और लिखा जा चुका है, लेकिन इस बात को कम ही लोगों ने तवज्जो दी है कि कैसे एक विदेशी हाथ भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। यह हाथ विदेशी जरूर है, मगर किसी विदेशी ताकत का हाथ नहीं, बल्कि विदेश में जाकर काम कर रहे या फिर वहां बस गए भारतीयों या भारतवंशियों का है, जिन्हें प्रवासी भारतीय, यानी एनआरआई या फिर पीआईओ या भारतीय मूल के लोग कहा जाता है।

हर महीने या साल में अपनी कमाई से जो हिस्सा ये भारत भेजते हैं, वह कुल मिलाकर इतनी बड़ी रकम बन चुकी है कि अब यह एक नया विश्व रिकॉर्ड है। दुनिया के किसी भी देश की प्रवासी बिरादरी इतनी रकम अपने देश नहीं भेज रही, जितनी दुनिया भर में बसे प्रवासी भारतीय भेज रहे हैं। पिछले साल, यानी 2024 में भारतीय प्रवासियों ने कुल 129.4 अरब डॉलर, यानी करीब 110 लाख करोड़ रुपये की रकम अपने देश भेजी है। यह पैसा वे किसी को दान में या भारत सरकार के खजाने में जमा करने के लिए नहीं, बल्कि अपने या अपने परिवार के इस्तेमाल या बचत के लिए भेज रहे हैं। मगर इससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी होती है और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा व्यापार में भारत की स्थिति मजबूत होती है।

पिछले साल के आखिरी तीन महीनों में ही 36 अरब डॉलर की रकम इस रास्ते से भारत आई। और वित्त-वर्ष 2024-25 का हिसाब लगा लें, तो इस साल प्रवासियों द्वारा घर भेजी हुई रकम कुल मिलाकर 135.46 अरब डॉलर हो चुकी है। यह रकम हमारी जीडीपी का लगभग 3.5 प्रतिशत हिस्सा के बराबर है। इससे भी बड़ी बात यह है कि पिछले कई वर्षों से भारत में 'रेमिटेन्स' के रूप में आने वाली रकम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यानी एफडीआई के रूप में आने वाली रकम से कहीं ज्यादा है। यही नहीं, भारत को वस्तुओं के आयात-निर्यात में जो घाटा होता है, उसकी आधी रकम की भरपायी इसी रेमिटेन्स से हो रही है। शायद यही वजह है कि विदेशी मुद्रा बाजार में भी इससे भारत को काफी सहारा मिलता है।

भारतीय प्रवासियों की बिरादरी इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी प्रवासी बिरादरी है। 'विवेकानंद फाउंडेशन' के एक अध्ययन के अनुसार, साल 2024 की शुरुआत में करीब साढ़े तीन करोड़ लोग इसमें शामिल थे। इनमें से 1.58 करोड़ प्रवासी भारतीय या एनआरआई और 1.96 करोड़ पीआईओ, यानी भारतीय मूल के लोग हैं। फर्क यह है कि प्रवासी भारतीय कहीं भी रहते हों, वे अब भी भारतीय नागरिक हैं। और 'परसन ऑफ इंडियन ओरिजिन' या पीआईओ वे लोग हैं, जो दूसरे देशों की नागरिकता ले चुके हैं, मगर अपनी भारतीय पहचान बनाए रखने के लिए पंजीकरण करवा चुके हैं।

बेहतर कमाई के मौके तलाशने वाले भारतीय काफी लंबे समय से विदेश जाते रहे हैं। खासकर खाड़ी के देशों में मजदूरी या बढ़ई, लोहार, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, ड्राइवर, मैकेनिक या दूसरे किस्म के कारीगर बड़ी संख्या में भारत से गए हैं। आईआईटी, आईआईएम या अच्छे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़कर या फिर विदेश से डिग्री लेकर वहीं बसने वाले लोग अधिकतर अमेरिका और यूरोप जाते रहे हैं, लेकिन उनकी गिनती अरब देशों में जाने वालों के मुकाबले काफी कम रहती थी। आज भी भारत की प्रवासी बिरादरी में करीब-करीब आधे लोग अरब देशों में ही रह रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से इनकी तरफ से आने वाली रकम में एक बड़ा बदलाव दिख रहा है। अब इसमें अमेरिका, इंग्लैंड की हिस्सेदारी अरब देशों के मुकाबले तेजी से बढ़ रही है।

पिछले साल जिन देशों से भारतीयों ने सबसे ज्यादा रकम भारत भेजी, उनमें अमेरिका अव्वल नंबर पर है। हालांकि, यह बात सिर्फ भारतीयों पर लागू नहीं होती। अमेरिका से दुनिया भर को जाने वाली ऐसी रकम में कोविड के बाद तेज बढ़ोतरी हुई है। मगर भारत की नजर से देखें, तो अब प्रवासियों द्वारा भेजी जाने वाली रकम का आधे से ज्यादा हिस्सा अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, यानी विकसित देशों से आ रहा है। यह जानकारी रिजर्व बैंक के 'रेमिटेन्स सर्वे' में दी गई है। इसका अर्थ यह है कि अब मेहनत मजदूरी करने के लिए विदेश जाने वालों के मुकाबले ज्यादा कमाई करने वाले टेक्नोलॉजी या हुनरमंद कामों में लगे लोग ज्यादा पैसे घर भेज रहे हैं। यहां यह ध्यान देने वाली बात है कि मजदूर लोग अपनी कमाई का करीब-करीब आधा हिस्सा घर भेज देते हैं, जबकि ऊंची कमाई वाले लोग अपनी आय का एक छोटा हिस्सा ही भेजते हैं।

पिछले कुछ महीनों में अमेरिका से बड़ी रकम भेजे जाने की एक वजह यह भी रही कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल में रेमिटेन्स पर पांच प्रतिशत तक टैक्स लगाने का प्रस्ताव शामिल था। हालांकि, बाद में इसे घटाकर एक फीसदी कर दिया गया और मुमकिन है कि व्यापार समझौते के बाद यह पूरी तरह खत्म ही हो जाए। लेकिन किसी भी टैक्स की आशंका में लोगों ने सोचा कि टैक्स लगने से पहले ही बड़ी रकम ट्रांसफर कर दी जाए और झंझट खत्म किया जाए। देखने वाली बात यह है कि सारी अनिश्चितता खत्म होने के बाद अमेरिका व दूसरे विकसित देशों से इस रकम का प्रवाह कैसा रहता है?

इसमें यह जोखिम है कि अगर अमेरिका या दूसरे देशों ने रेमिटेन्स पर टैक्स लगाने जैसे फैसले लागू किए, तो फिर लोग बैंकिंग माध्यम से पैसा भेजने के बजाय हवाला जैसा कोई रास्ता ढूंढ़ सकते हैं, जिसके बाद यह हिसाब लगाना मुश्किल हो जाएगा कि इस रास्ते कितना पैसा आया और आया भी या नहीं? फिर सबसे बड़ी चिंता जो इस वक्त दिख रही है, वह है रोजगार का संकट। अगर विकसित देश अपने रोजगार और आप्रवासन नियमों को कड़े करते गए, तो फिर भारत के पढ़े-लिखे हुनरमंद लोगों का रोजगार बाजार अचानक गंभीर संकट में आ सकता है। ऐसे में, घर भेजना तो दूर घर चलाना भी मुश्किल हो सकता है।

ऐसे में, इस वक्त शायद सबसे जरूरी यही है कि भारत सरकार तमाम देशों के साथ इस तरह के व्यापार समझौते करे, जिनसे न सिर्फ दोनों देशों के बीच व्यापार, बल्कि यहां से वहां जाकर काम करने वाले भारतीयों के हितों को सुरक्षित रखने का इंतजाम भी सुनिश्चित किया जा सके।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

आंतरिक प्रकाश के महोत्सव पर हावी न हो जाए प्रदूषण

प्रणव पंड्या | कुलाधिपति, देव संस्कृति विश्वविद्यालय

यहां स्कैन करें

दीपावली के मौके पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति देने के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मगर इस पूरे विवाद ने कई नागरिकों को, खासकर प्रदूषण के कारण सांस संबंधी कष्ट उठा रहे लोगों के मन में कुछ सवाल पैदा कर दिए हैं कि क्या इस त्योहार से पटाखों का वाकई कोई ठोस पौराणिक संबंध भी है? क्या हजारों-लाखों बुजुर्गों-बच्चों के लिए कष्टकारी स्थितियां पैदा करना किसी त्योहार का अभीष्ट हो सकता है? दीपावली का संदेश क्या है?

भारतवर्ष का इतिहास असंख्य पर्वों और परंपराओं की अमर गाथा है, परंतु इन सबमें जो पर्व भारतीय जीवन-दर्शन की आत्मा को सर्वाधिक स्पंदित करता है, वह है दीपावली। यह केवल उत्सव नहीं, बल्कि उस अनादि यात्रा का प्रतीक है, जिसमें मनुष्य युगों से अंधकार पर विजय पाकर प्रकाश की ओर बढ़ता आया है। यह पर्व हमें स्मरण कराता है कि जीवन के तम में भी एक ज्योति छिपी है, जिसे जलाकर हम न केवल अपना मार्ग, बल्कि संपूर्ण सृष्टि का पथ आलोकित कर सकते हैं। दीपावली का यह पर्व-पुंज (उत्सव-समूह) भारतीय संस्कृति की उस सात्विक निरंतरता का द्योतक है, जिसमें प्रकाश केवल दीयों से नहीं, भावों से जलता है। यह उत्सव शारदीय फसल के परिपक्व होने का उल्लास भी है और मानव की आत्मा में बसने वाली ज्योति के प्रति कृतज्ञता का भी। सनातन परंपरा के जीवंत इतिहास में इसी दिन भगवान श्रीराम लंका-विजय के उपरांत अयोध्या लौटे और नगर दीपों से जगमगा उठा; इसी विशिष्ट दिन पर भगवान विष्णु द्वारा नरकासुर वध के रूप में धर्म की पुनःस्थापना का स्मरण निहित है।

क्या हजारों-लाखों लोगों के लिए कष्टकारी स्थितियां पैदा करना किसी उत्सव का अभीष्ट हो सकता है? दीपावली का संदेश क्या है?

मगर आज जब संसार बाहरी चकाचौंध, शोर-शराबे में लिप्त होता जा रहा है, तब दीपावली का यह संदेश और भी गुंजायमान है- सच्चा प्रकाश अंतःकरण से आता है, न कि बाहर की आभा से। माया की चमक और आडंबर की गरज के बीच दीपावली सही अर्थों में हमें यह भी स्मरण कराती है कि जीवन में हर अंधकार का समाधान केवल एक दीपक है- एक सद्कर्म, एक शुभ विचार, एक सच्चा प्रयास। एक दीप अनेक दीपों को जला सकता है, और जब हर हृदय एक दीप बन जाए, तब संपूर्ण समाज से अमावस्या का भय मिट जाता है। यही कारण है कि ऋषियों ने इस पर्व को प्रकाशोत्सव कहा- केवल लौकिक प्रकाश का नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दीप्ति का प्रकाशोत्सव।

पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने इसी भाव को अपने जीवन में जीते हुए कहा था- *दीप हूं जलता रहूंगा, मैं प्रलय की आंधियों से अंत तक लड़ता रहूंगा।*

ये पंक्तियां केवल काव्य नहीं हैं, एक आध्यात्मिक प्रतिज्ञा हैं, उस साधक की, जो संसार के अंधकार में भी अपने अंतःदीप को बुझने नहीं देता। दीपावली के संदर्भ में यह संदेश और भी प्रासंगिक है, क्योंकि यह हमें सिखाता है कि सच्चा दीप वह नहीं, जो तेल और बत्ती से जलता है, बल्कि वह है, जो श्रद्धा और संकल्प से प्रकाशित होता है। अंधकार चाहे समय का हो, समाज का हो या स्वयं के मन का, एक जाग्रत आत्मा, प्रज्ज्वलित दीप उसकी सीमाओं को भेद सकता है।

यह समय केवल उत्सव का नहीं, आत्ममंथन का भी है कि हम जिस दीपक को जलाते हैं, उसकी ज्योति केवल दीपदान तक सीमित न रह जाए, बल्कि हमारे आचरण में भी दिखे। जब हम किसी निराश व्यक्ति के जीवन में आशा जगाते हैं, जब हम किसी भूखे को अन्न देते हैं, जब हम किसी गलती को क्षमा कर देते हैं, तभी हम दीपावली के सच्चे दीये जलाते हैं। इसलिए इस पावन अवसर पर आइए, हम सब अपने भीतर का दीप खोजें- वह दीप जो विवेक का है, जो संयम का है, जो प्रेम का है। यदि हर मनुष्य अपने भीतर एक दीप जला सके, तो समाज के अंधकार मिटते देर नहीं लगती। यह उत्सव हमें बार-बार याद दिलाता है- अंधकार का नाश केवल प्रकाश से ही संभव है, शोर-शराबे से नहीं और वह प्रकाश बाहर नहीं, हमारे भीतर जन्म लेता है।

इस दीपावली पर केवल घर नहीं, हृदय जगमगाएं। केवल दीपक नहीं, संकल्प भी प्रज्ज्वलित हों। और यह संकल्प हो कि हम जीवन के हर क्षेत्र में प्रकाश का विस्तार करेंगे। ज्योतिर्मय बनेंगे और उसी ज्योति से जग को आलोकित करेंगे।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

शर्तों पर खुशी नहीं मिलती

सुख के पीछे लोग भागते रहते हैं, लेकिन सुख उनसे भी आगे दौड़ता है, कभी हाथ नहीं आता। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? कभी-कभी ज्ञानी पुरुषों से सलाह लेना अच्छा होता है, उनसे एक नई सोच मिलती है। ताओ के महान संत लाओत्से का सूत्र है, 'अगर आप जो हैं, उसे स्वीकार कर लेते हैं, तो आपके दुखी होने की कोई आशंका नहीं रहती।'

यह बड़ी अजीब बात मालूम होती है। ऐसा लगेगा, जैसे मन को मारकर जीना पड़ेगा, उदासी छा जाएगी। लेकिन बात इतनी सी नहीं है, कहीं गहरी है। ओशो कहते हैं कि मुझे ऐसे लोग नहीं दिखते, जो सचमुच खुश रहना चाहते हों। ऐसा लगता है कि किसी को भी खुश रहने में रस नहीं है, क्योंकि लोग किसी क्षुद्र सी बात के लिए खुशी त्यागने को तैयार हैं : ईर्ष्या के लिए, अधिकार जमाने की भावना के लिए, क्रोध के लिए, नफरत के लिए। मगर वे खुशी की खातिर क्रोध और ईर्ष्या को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं।

यह वाकई सोचने की बात है, लोगों को एक-दूसरे से बदला लेने में, झगड़े को लंबा खींचने में ज्यादा मजा आता है। यह उनकी जिंदगी में जायका लाता है। असली बात यह है कि दूसरे को दुखी देखने में सबकी दिलचस्पी होती है। किसी का नुकसान हुआ, फजीहत हुई, कोई असफल हुआ, तो ज्यादातर लोगों को बड़ा आनंद आता है। यह जो रुग्ण खुशी है, इसके कारण लोग स्वस्थ, निर्मल खुशी का अनुभव नहीं ले पाते।

गौर कीजिए, लोग बातें तो करते हैं सुख की, लेकिन उनकी पूरी जीवन शैली से दुख ही पैदा होता है। फिर कैसा आश्चर्य कि आदमी को छोड़कर इस दुनिया में कोई दुखी नहीं है, जबकि दुख को बड़ी मेहनत से पैदा करना पड़ता है, वह अपने आप नहीं होता। आदमी बड़ा कलाकार है, जिसने इस असंभव को संभव कर दिखाया है। खुशी एक सहज घटना है, इसे करने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। बस वहां मौजूद रहना और खुश रहना जरूरी है। खुशी, यानी जो है, उसे स्वीकार करना। लेकिन आप अपनी शर्तों और अपने नियमों पर खुशी चाहते हैं। दरअसल, आपको खुशी में कोई दिलचस्पी नहीं है, वरना आप उस पर शर्तें नहीं थोपते? आप ऐसी असंभव शर्तें रखते हैं कि वे पूरी नहीं हो सकतीं।

किसी को भी खुश रहने में रस नहीं है, क्योंकि लोग किसी क्षुद्र सी बात के लिए खुशी त्यागने को तैयार हैं : ईर्ष्या के लिए, अधिकार जमाने की भावना के लिए, क्रोध के लिए, नफरत के लिए।

आप एक प्रेमिका हैं या प्रेमी हैं, आप अभी खुश हो सकते हैं। लेकिन आपकी एक शर्त है कि प्रेमी पहले वादा करे कि वह आपसे हमेशा-हमेशा प्यार करेगा। इसे बीच में क्यों लाया जाए? कोई वादा कैसे कर सकता है कि वह सिर्फ आपसे प्रेम करे, किसी और से नहीं? प्रेम पर ऐसे बंधन कैसे लगा सकते हैं? देखें किस तरह आप दुख के बीज बो रहे हैं। इसीलिए जो है, उसे स्वीकार करें और खुश रहें।

अमृत साधना

पोप लियो XIV | ईसाई धर्मगुरु

पत्रकार के काम को अपराध नहीं माना जा सकता, बल्कि यह उसका अधिकार है, जिसकी रक्षा की जानी चाहिए। स्वतंत्र एवं निःशुल्क सूचना हमारे समाज का स्तंभ है, इसलिए इसकी रक्षा की गारंटी देना हमारा कर्तव्य है।

अनुलोम-विलोम

राजनीति में वंशवाद

विकल्प की बात करने वालों ने निराश किया

बिहार विधानसभा चुनाव के आते ही एक मुद्दा फिर से बहस के केंद्र में आ गया है- राजनीति में वंशवाद। देश का कोई सूबा या कोई दल ऐसा नहीं है, जो इसका शिकार न हो। भारतीय राजनीति की विडंबना यही है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री चुने जाने का विरोध करने वाली मुख्य विपक्षी पार्टियों के दिग्गज खुद इसके शिकार हो गए और उन्होंने अपने बचाव में यह दलील गढ़ी कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, वकील की संतान वकील और प्रोफेसर-इंजीनियर की औलादें प्रोफेसर-इंजीनियर बन सकती हैं, तो नेता के बच्चे नेतागिरी क्यों नहीं कर सकते? निस्संदेह, यह तर्क अपनी जगह है, मगर वकील, डॉक्टर, इंजीनियर-प्रोफेसर को अपनी औलादों के लिए प्रक्रिया को प्रभावित करने की हैसियत नहीं हासिल। उन्हें अपने पिता की जमीन का लाभ नहीं मिल सकता। उनको संबंधित पेशे की परीक्षाएं पास करनी होंगी। पास करने के बाद एक नियत समय तक पढ़ाई करनी पड़ेंगी, फिर उनकी आंतरिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के बाद ही वह डिग्री के हकदार होंगे। नेता संतानों के पास सीधे चुनाव में उतरने और हारने की सूरत में राज्यसभा या विधान परिषद पहुंचने का विकल्प होता है और इसके बहुतेरे उदाहरण हैं।

इसीलिए जब अरविंद केजरीवाल और प्रशांत किशोर जैसे लोगों ने कहा कि देश में चंद परिवार समूचे भारतीय लोकतंत्र पर हावी होने लगे हैं, तो मतदाताओं को ताजा हवा के झोंके सा महसूस हुआ। इन दोनों ने दावे किए कि हम अपने लोकतंत्र को जीवंत बनाने के लिए इन गढ़ों को ढहाएंगे। मगर आम आदमी पार्टी की पंजाब की सूची उठाकर देख लीजिए या राज्यसभा में पहुंचे उनके प्रतिनिधियों की योग्यता परख लीजिए, घनघोर निराश करने वाली है। इसी तरह, अब बिहार में जन सुराज पार्टी की पहली सूची देखकर लग रहा है कि कथनी और करनी में कितना फर्क होता है! इस सूची में कर्पूरी ठाकुर की पोती, आरसीपी सिंह की बेटी का भी नाम है। अभी तो 243 में से सिर्फ 51 उम्मीदवारों की सूची सामने आई है। अगले 192 में और कितने नेता-संतानें होंगी। इस पर सबकी नजर रहेगी।

साफ है, जो लोगों में नई उम्मीद जगाते हैं, वे बहुत जल्दी अपना असली रंग भी दिखा देते हैं। ऐसे में, मतदाता ठगा हुआ महसूस करता है। अगर वही सब करना है, जो पुरानी पार्टियां करती रही हैं, तो आप पर क्या भरोसा करें? जब आप करीब आठ करोड़ मतदाताओं वाले बिहार में 243 नए प्रतिबद्ध चेहरे नहीं तलाश सकते, तो भाई-भतीजावाद से खाक लड़ेंगे।

रमेश सिंह तोमर, टिप्पणीकार

ऐसे आरोप योग्य संतानों को रोक नहीं सकते

तय था, यह विषय फिर उठेगा। दरअसल, हर छोटे-बड़े चुनाव में यह मसला बौद्धिक जुगाली के लिए उठाया जाता है। हर बार खूब स्यापा होता है और फिर वही ढाक के तीन पात। समझ में नहीं आता कि बार-बार जनता की अदालत से खारिज होने के बाद भी लोग इसको छोड़ क्यों नहीं देते?

ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में नेताओं के परिजन राजनीति में अपना करियर बनाते हैं। दुनिया के सबसे सफल लोकतंत्रों में से एक अमेरिका में निकट भविष्य में हमनें जॉर्ज डब्ल्यू बुश पिता-पुत्र को राष्ट्रपति चुने जाते देखा है। राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की पत्नी हिलेरी भी राष्ट्रपति की रेस में उतर चुकी हैं, हालांकि वह कामयाब नहीं हुईं, मगर उन्होंने बराक ओबामा के कार्यकाल में बतौर विदेश मंत्री काम किया। उनके विदेश मंत्री काल में ही दुर्दांत आतंकी ओसामा बिन लादेन का सफाया हुआ था। ट्रंप के मौजूदा कार्यकाल में स्वास्थ्य मंत्री रॉबर्ट केनेडी पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी के भतीजे हैं। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के दादा भी इस पद पर रह चुके थे।

भारतीय उप-महाद्वीप में तो ऐसे नेताओं की एक लंबी सूची है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार तमाम जगहों पर ऐसे लोग प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन चुके हैं। इसलिए इस मुद्दे पर शोर मचाने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। बेहतर होगा कि ऐसे नेताओं के खिलाफ अगर उनसे सुयोग्य कोई प्रत्याशी हो, तो उसकी जीत सुनिश्चित करने के लिए काम किया जाए। वैसे भी, नैसर्गिक न्याय यही कहता है कि हर व्यक्ति अपने कृत्यों का जिम्मेदार है। हत्यारे के पुत्र को क्या हत्यारा कहा जा सकता है? रावण के खानदान में विभीषण था। हिरण्यकश्यप के आधार पर यदि प्रह्लाद का मूल्यांकन किया गया, तब तो नाइंसाफी होगी।

लोकतंत्र में व्यक्ति से महत्वपूर्ण दल होना चाहिए और उसकी नीतियों के आधार पर ही जन-प्रतिनिधियों का चुनाव होना चाहिए। निस्संदेह, कई नेताओं की संतानें नाकारा होती हैं और जनता की उपेक्षा करती हैं, मगर यह भी कटु सत्य है कि बहुत से राजनीतिक परिवारों का अब कोई सदस्य सियासत में नहीं है। प्रिवी पर्स खत्म होने के बाद कई राजा संसद का चुनाव लड़े। कुछ जीते, तो कुछ को शिकस्त भी मिली। बाद में चंद रह गए। असली ताकत जनता के हाथों में है। वह जिसे चाहे नवाज दे, जिसको चाहे उतार दे। इसलिए अच्छा होगा कि लोकतंत्र में आस्था रखी जाए और उसे मजबूत करने के लिए प्रतिरोध को सशक्त किया जाए। राजनीति में वंशवाद की लकीर पीटने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि संविधान हर नागरिक को समान अधिकार देता है।

ममता राय, टिप्पणीकार

संपादकीय जागरण

(8) सोमवार, 13 अक्टूबर, 2025 : कार्तिक कृष्ण - 7 वि. 2082

मोह से मुक्ति पाए बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं

ममता की संवेदनहीनता

पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक मेडिकल कालेज की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जिस तरह पीड़ित छात्रा को ही कठघरे में खड़ा कर दिया, वह आश्चर्यचकित करने के साथ ही उनकी संवेदनहीनता को भी रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि वह लड़की रात को साढ़े बारह बजे मेडिकल कालेज परिसर से बाहर कैसे आ गई? क्या ऐसा करना अनुचित-अपराध है अथवा इसके कारण अपराधियों को कुछ भी करने की छूट मिल जाती है? ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि लड़कियों को रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए। ऐसे बयान देकर तो वे अपराधी तत्वों के दुस्साहस को बढ़ाने का ही काम कर रही हैं। यह शर्मनाक है कि जब उन्हें पीड़ित छात्रा और उसके स्वजन के पक्ष में खड़ा दिखना चाहिए, तब वे उन्हें ही कठघरे में खड़ा कर रही हैं। यह पहली बार नहीं है जब ममता ने बंगाल में कानून एवं व्यवस्था को चुनौती देने वाली किसी घटना पर गैर-जिम्मेदाराना बयान दिया हो। वे ऐसे बयान देने के लिए ही जानी जाती हैं। कोलकाता के चर्चित पार्क स्ट्रीट सामूहिक दुष्कर्म की घटना पर उन्होंने उसे मनगढ़ंत बताते हुए यह भी जोड़ा था कि इस वारदात के जरिये राज्य सरकार को बदनाम करने का इरादा था। यह भी किसी से छिपा नहीं कि पिछले वर्ष कोलकाता के ही आरजी कर मेडिकल कालेज में एक डाक्टर से दुष्कर्म और हत्या की देश को झकझोर देने वाली घटना पर पुलिस और प्रशासन ने किस तरह लीपापोती वाला रवैया अपनाया था। इसके चलते ही देश भर में आक्रोश उपजा और इस मामले की जांच सीबीआइ को सौंपनी पड़ी। बंगाल अपनी गिरती हुई कानून एवं व्यवस्था के लिए पहले ही कुख्यात है। चिंताजनक यह है कि बंगाल के शिक्षण संस्थानों में भी दुष्कर्म की घटनाएं घट रही हैं। आरजी कर मेडिकल कालेज की घटना के बाद ला कालेज की एक छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया था और फिर इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट के परिसर में भी। इन घटनाओं से बंगाल में महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े होना स्वाभाविक हैं। विडंबना यह है कि जब मुख्यमंत्री को इन घटनाओं पर कठोर रवैये का परिचय देना चाहिए, तब वे अगंभीरता दिखा रही हैं। यदि वे कमजोर होती कानून एवं व्यवस्था पर लीपापोती दिखाएंगी तो इससे स्थितियां और खराब ही होंगी। इसकी भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि ममता मुख्यमंत्री होने के साथ-साथ गृहमंत्री का भी दायित्व संभाले हुए हैं। इस नाते उन्हें और अधिक सजगता का परिचय देना चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक महिला होने के बाद भी वे महिलाओं के साथ होने वाले जघन्य अपराधों पर अपने पुरातनपंथी सोच का परिचय दे रही हैं। आज के युग में ऐसे सोच के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता।

जरूरी है कड़ाई

आसन्न विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। गश्ती के साथ वाहन जांच अभियान भी चलाया जा रहा है। मकसद, शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराना है। यह तैयारी चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पहले से ही शुरू हो गई थी। शस्त्र सत्यापन, हिस्ट्रीशीटर व तड़ीपार अपराधियों को जिलाबदर का आदेश जारी हो चुका है। इस बीच शराब के धंधेबाजों पर भी खास नजर रखी जा रही है। सीमाओं पर चेकपोस्ट से इस पर खास निगरानी की जा रही है। ट्रेनों में भी सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। दरअसल, चुनाव में धनबल के साथ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग सक्रिय हो जाते हैं, वहीं मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए शराब-पैसे भी बांटने की आशंका रहती है। ऐसे में सतर्कता जरूरी हो जाती है। चुनाव आयोग द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई व्यक्ति कितनी अधिकतम नकदी लेकर चल सकता है। हाल में गया में कालका मेल से दो किलो सोना जब्त किया गया था। राजधानी पटना में दो दिन पूर्व ही भारी मात्रा में हथियार व गोलियों के साथ पांच बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। इधर, मुंगेर में दियारा में मिनी गन फैक्ट्री का राजफाश किया गया और दो आरोपितों को भी दबोचा गया है। चुनाव को लेकर सतर्कता बहुत जरूरी है। आमजन को भी यदि अपने आसपास कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई देती है तो डायल 112 पर सूचित किया जा सकता है। चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है। यह जितना भयमुक्त होगा, लोकतंत्र उतना मजबूत होगा।

चुनाव के दौरान प्रशासन को पूरी सख्ती बरतनी चाहिए, ताकि आपराधिक तत्वों पर नकेल कसी जा सके।

कह के रहेंगे — माधव जोशी

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या अमेरिकी राष्ट्रपति का यह कहना सही है कि चीन दुनिया को बंधक बनाने की कोशिश में है?

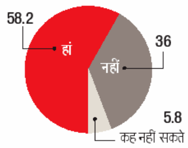

आज का सवाल

क्या महिलाओं की आवाजाही सीमित करने से जुड़ा ममता बनर्जी का बयान बंगाल में कानून व्यवस्था की लचर स्थिति को दर्शाता है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

गाजा में शांति पर संदेह का साया

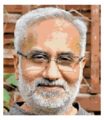

शिवकांत शर्मा

नेतन्याहू और हमास के पास ट्रंप की शांति योजना पर सहमति के सिवा और कोई विकल्प नहीं था, लेकिन क्या गाजा में वास्तव में शांति स्थापित हो सकेगी?

राष्ट्रपति ट्रंप की बीस सूत्री शांति योजना पर इजरायली कैबिनेट की मंजूरी के बाद गाजा में युद्धविराम लागू हो गया है। इससे जुड़ी शांति योजना के तीन चरण हैं। जिस पहले चरण पर हमास और इजरायल सहमत हुए हैं, उसमें सबसे पहले इजरायली हमले रुकना और इजरायली सेना को गाजा के 47 प्रतिशत क्षेत्र से पीछे हटना था। साथ ही, इजरायल आतंकी हमलों और दूसरे अपराधों के आरोपों में सजा काट रहे करीब 250 फलस्तीनी कैदियों को और गाजा के उन 1700 लोगों को रिहा करेगा जो हिरासत में हैं। हमास 28 इजरायली बंधकों की पार्थिव देह सौंपेगा और इजरायल अपनी हिरासत में मरे गाजा के 15 लोगों के पार्थिव शरीर हमास को सौंपेगा।

इजरायल, हमास, अरब देश और ट्रंप सभी एक-दूसरे की पीठ थपथपा रहे हैं। ट्रंप अपनी योजना को पश्चिम एशिया में स्थायी शांति का कदम बताकर नोबेल शांति पुरस्कार की आस लगाए बैठे थे। वह तो पूरी नहीं हो सकी, पर क्या वे टूटी आस की कड़वाहट को पीकर शांति योजना को सफल बनाने में पूरी शक्ति लगाएंगे? क्योंकि उनकी योजना के पहले चरण का क्रियान्वयन तो अपेक्षाकृत आसान था। हालांकि इसमें भी हमास की मांग पर रिहा होने वाले कैदियों के नामों और संख्या को लेकर रुकावटें खड़ी हो सकती हैं। इसके पूरा होने के बाद दूसरे और तीसरे चरणों की सौदेबाजी शुरू होगी।

योजना के अनुसार गाजा पट्टी का पूरी तरह विसैन्यीकरण होना है। यानी हर तरह के सैनिक, आतंकी और आक्रामक ढांचे को ढहाया जाएगा, जिसमें उन सुरंगों का जाल भी शामिल है जिनका प्रयोग हमास के आतंकी अपने राकेट, गन और गोला बारूद रखने के लिए करते थे। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के आकलन के अनुसार हमास ने युद्ध के दौरान करीब 15 हजार नए लड़ाकों की भर्ती भी की थी। इजरायल चाहता है कि ये सभी सदस्य हथियार डालें और भविष्य में लड़ाई न करने का प्रण लें। हालांकि हमास की शर्त रही है कि वह स्वतंत्र फलस्तीन राष्ट्र की स्थापना होने के बाद ही हथियार डालेगा।

शांति योजना के अनुसार गाजा का प्रशासन एक शांति बोर्ड की देखरेख में फलस्तीनी विशेषज्ञों की अस्थायी समिति संभालेगी। शांति बोर्ड की अध्यक्षता खुद ट्रंप करेंगे। पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर की भी इसमें प्रमुख भूमिका होगी। फलस्तीनी प्राधिकरण में सुधार करने के बाद गाजा का प्रशासन उसे सौंप दिया जाएगा, परंतु उसमें हमास की प्रत्यक्ष या परोक्ष कोई भूमिका नहीं होगी। हमास के जो सदस्य इजरायल के शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को स्वीकार करेंगे, उन्हें अभयदान देकर दूसरे देशों में भेज दिया जाएगा। हालांकि अभी तक हमास इजरायल के अस्तित्व को स्वीकार करने से इन्कार करता रहा है। दूसरी ओर, नेतन्याहू ने ट्रंप की शांति योजना को पूरी तरह स्वीकार भले कर लिया हो, पर वे गाजा का प्रशासन फलस्तीनी प्राधिकरण को नहीं देना चाहते।

अवधेश राजपूत

गाजा के युद्धविराम को ट्रंप पश्चिम एशिया में स्थायी शांति का पहला कदम बताते हैं, परंतु इतना वे भी जानते हैं कि फलस्तीनियों को उनका देश मिले बिना यहां कोई शांति स्थायी नहीं हो सकती। पिछली सदी के अंत तक यह संभव लगता था। इजरायल में भी काफी बड़ा जनमत इसके पक्ष में था, लेकिन जब से नेतन्याहू ने सत्ता संभाली है, अलग फलस्तीनी राष्ट्र की संभावना को सपने में बदल दिया है। फलस्तीनी चाहते हैं कि पश्चिमी किनारे और गाजा में उनका देश बने, जिसकी राजधानी पूर्वी यरूशलम हो। कहने को पश्चिमी किनारे पर फलस्तीनी प्राधिकरण का शासन है, परंतु इजरायल ने धीरे-धीरे वहां यहूदी बस्तियों का जाल बिछा दिया है, जिनमें लगभग सात लाख यहूदी बसते हैं। उन बस्तियों पर इजरायली शासन है।

पश्चिमी किनारे की मात्र 18 प्रतिशत भूमि पर ही फलस्तीनी प्राधिकरण का शासन है। 22 प्रतिशत भूमि पर इजरायल और फलस्तीनी प्राधिकरण का संयुक्त शासन है और जार्डन और इजरायल से लगती शेष 60 प्रतिशत भूमि पर इजरायली शासन। यदि मानचित्र पर देखें तो पश्चिमी किनारे के शहर इजरायली भूमि पर फलस्तीनी द्वीपों जैसे लगते हैं। यह सुनियोजित रणनीति के तहत किया गया लगता है ताकि फलस्तीनी शहर इजरायल के विरुद्ध एकजुट न हो सकें। सीमावर्ती जमीन को भी इजरायल ने इसलिए अपने पास रखा ताकि पड़ोसी देशों में खुलने वाली सुरंगों का जाल न बिछाया जा सके, जो गाजा में हुआ है। शायद इसीलिए नेतन्याहू पश्चिमी किनारे और गाजा में एक फलस्तीनी सरकार नहीं बनने देना चाहते।

इस समय नेतन्याहू और हमास के पास ट्रंप की शांति योजना के लिए सहमत होने के सिवा और कोई विकल्प नहीं बचा था। नेतन्याहू शांति के नोबेल की आस लगाए बैठे ट्रंप को नाराज नहीं कर सकते थे। हमास के पास भी न तो निरंतर बढ़ती आ रही इजरायली सेना से बंधकों को छिपाए रखने की जगह बची थी और न ही दुनिया से और अधिक सहानुभूति बटोरने की गुंजाइश। अब शांति कायम हो जाने और गाजा में पुनर्निर्माण शुरू होने के साथ ही दोनों को अस्तित्व की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। नेतन्याहू के समक्ष अपनी सरकार बचाने, हमास के हमले को रोकने में हुई सुरक्षा चूक की जांच से और भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जाने से बचने की चुनौतियां हैं। हमास के समक्ष सत्ता से बाहर रहते हुए अपना प्रभाव बनाए रखने की चुनौती है। इजरायली हमलों में मारे गए 67 हजार से अधिक लोगों के परिवारों का इजरायल विरोधी रोष उन्हें उसे बनाए रखने और संगठन खड़ा करने की आधारभूमि देगा।

इजरायली बड़ी शान से कहा करते थे कि उनकी लड़ाइयां सैनिक अकादमियों में पढ़ाई जाया करेंगी, लेकिन गाजा की लड़ाई उन्हें बहुत मायूस करेगी। ऐसा इसलिए, क्योंकि इजरायल ने भले ही हमास के साथ-साथ हिजबुल्ला के फनों को भी कुचल दिया हो, परंतु उनके उद्देश्य के लिए बढ़ती सहानुभूति की लहर को नहीं थाम पाया है। साख की लड़ाई में तो वह बुरी तरह हार गया है। संयुक्त राष्ट्र के जांच आयोग ने उस पर जनसंहार का आरोप लगाया है और ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा जैसे पारंपरिक मित्र देशों ने उसकी मर्जी के खिलाफ फलस्तीन को मान्यता दे दी है।

(लेखक बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक हैं)
response@jagran.com

संबंधों को पटरी पर लाने की चुनौती

मनिष वगाडे

चीनी आक्रामकता एवं वैश्विक अस्थिरता के इस दौर में भारत-अमेरिका के बीच साझेदारी ही स्थिरता की गारंटी है

अमेरिका के नवनियुक्त राजदूत और दक्षिण एवं मध्य एशियाई मामलों के विशेष दूत सर्जियो गोर ने पहले ही दिन भारत के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश सचिव विक्रम मिस्री से उनकी बैठकें संकेत हैं कि वाशिंगटन भारत के साथ अपने रिश्ते को नई गति देने के मूड में है। इस सौहार्दपूर्ण शुरुआत के पीछे गोर के लिए चुनौतियों का एक जटिल जाल बिछा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मित्रता ने जहां संबंधों में नई ऊर्जा डाली है, वहीं दोनों देशों के बीच व्यापारिक मतभेद, तकनीकी साझेदारी की जटिलताएं और दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को लेकर चिंताएं अब भी बनी हुई हैं। गोर के लिए सबसे बड़ी कसौटी यह होगी कि वे व्यक्तिगत निकटता को नीति में बदलें और इन विरोधाभासों को समेटते हुए संबंधों को नई दिशा दें।

गोर का भारत में राजदूत के साथ-साथ दक्षिण एवं मध्य एशियाई मामलों का विशेष दूत भी होना एक राजनीतिक संकेत है कि अमेरिका भारत और उसके पड़ोसी क्षेत्र को अब सीधे राष्ट्रपति की प्राथमिकता के रूप में देख रहा है, परंतु यह दोहरी भूमिका भारत के लिए दुविधा का विषय भी है। नई दिल्ली लंबे समय से यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसे दक्षिण एशिया के पारंपरिक 'भारत-पाकिस्तान' ढांचे में न बांधा जाए। गोर के लिए यह चुनौती होगी कि वे भारत की वैश्विक भूमिका को बनाए रखते हुए अपने क्षेत्रीय दायित्वों का निर्वाह करें। उनकी सबसे कठिन परीक्षा आर्थिक मोर्चे पर होगी। ट्रंप प्रशासन की 'अमेरिका फर्स्ट' नीति के तहत भारत पर लगाए गए ऊंचे टैरिफ ने दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ा दिया है। अमेरिका का दावा है कि भारत के ऊंचे आयात शुल्क और रूस से तेल खरीद जैसी नीतियां 'असंतुलित' हैं। इसके जवाब में भारत ने अपने हितों की रक्षा पर जोर दिया है। संभावित व्यापार समझौता महीनों से ठप पड़ा है। ऐसे में गोर को इस प्रक्रिया को पुनर्जीवित करना होगा, वह भी बिना किसी घरेलू राजनीतिक विवाद के।

नई उम्मीदों के साथ आए नए राजदूत सर्जियो गोर ● प्रेट्र

प्रौद्योगिकी साझेदारी भी उनके एजेंडे का एक संवेदनशील बिंदु है। भारत रक्षा और नवाचार क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण चाहता है, जबकि अमेरिका अपनी बौद्धिक संपदा और सुरक्षा चिंताओं को लेकर सतर्क है। सेमीकंडक्टर, एआइ और डाटा सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग के अवसर तो हैं, पर नीतिगत स्पष्टता की कमी दोनों पक्षों को सतर्क रखती है। गोर का कार्य यह साबित करना होगा कि वाशिंगटन की तकनीकी नीति चीन को लेकर है, भारत को लेकर नहीं। रक्षा सहयोग के क्षेत्र में गोर को एक सकारात्मक आधार मिला है। दोनों देशों के बीच हुए कोमकासा और बीईसीए जैसे समझौते सामरिक साझेदारी के नए युग की नींव बन चुके हैं। फिर भी भारत अमेरिका से अधिक तकनीकी हस्तांतरण और स्थानीय उत्पादन चाहता है, जबकि वाशिंगटन रूस से भारत के सैन्य संबंधों पर दबाव डालता है। गोर को इस संतुलन को साधना होगा, ताकि भारत की रक्षा स्वायत्तता प्रभावित न हो और अमेरिका की रणनीतिक अपेक्षाएं भी पूरी हों।

दक्षिण एशिया के परिप्रेक्ष्य में चुनौती और गहरी है। ट्रंप के पाकिस्तान के प्रति हालिया रुझान-इस्लामाबाद के नेतृत्व से मुलाकात और उसके ऊर्जा क्षेत्र में अमेरिकी निवेश के संकेत दिल्ली के लिए असहज हैं। भारत को यह आशंका है कि कहीं वाशिंगटन पुनः 'री-हाइफनेशन' यानी भारत-पाकिस्तान समानांतर नीति की ओर न लौट जाए। गोर की दोहरी जिम्मेदारी-दिल्ली और इस्लामाबाद, दोनों से संपर्क इस चिंता को और गहरा करती है। उन्हें भारत को यह विश्वास दिलाना होगा कि ट्रंप का पाकिस्तान प्रेम रणनीतिक गणित का हिस्सा है, न कि नीति परिवर्तन का। महत्वपूर्ण खनिजों पर गोर और मोदी के बीच चर्चा यह दिखाती है कि अमेरिका इस क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाना चाहता है। दोनों देश चीन पर निर्भरता कम करने और 'फ्रेंड-शोरिंग' के माध्यम से वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखला बनाने के पक्षधर हैं, पर भारत की खनन नीतियां अभी भी जटिल हैं। यदि गोर यहां ठोस निवेश या संयुक्त परियोजनाएं आगे बढ़ा पाते हैं तो यह उनके कार्यकाल की एक उल्लेखनीय उपलब्धि होगी। आव्रजन नीति और एच-1बी वीजा व्यवस्था पर भी उन्हें सावधानी से चलना होगा। भारतीय पेशेवरों के लिए अमेरिका की कड़ी वीजा नीति चिंता का विषय रही है। गोर को इन घरेलू राजनीतिक बाधाओं को समझाते हुए भी भरोसे का माहौल बनाना होगा।

गोर के पास एक बड़ा लाभ यह है कि वे सीधे राष्ट्रपति तक पहुंच रखते हैं, पर यही उनकी सबसे बड़ी चुनौती भी है। यदि वे ट्रंप की व्यक्तिगत सद्भावना को ठोस नीतिगत परिणामों में बदलने में सफल रहते हैं तो न केवल संबंधों को पुनर्जीवित करेंगे, बल्कि उन्हें नई ऊंचाई भी देंगे। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में भारत और अमेरिका का सहयोग अनिवार्य है। चीन की आक्रामकता, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और आपूर्ति श्रृंखला के पुनर्संतुलन के युग में दोनों देशों की साझेदारी ही स्थिरता की गारंटी है। गोर के आगमन से यह उम्मीद बंधती है कि संवाद की रफ्तार फिर से बढ़ेगी, रक्षा-प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्रों में प्रगति होगी और असहमतियों के बावजूद सहयोग का दायरा विस्तृत होगा।

(लेखक द इंडियन फ्यूचर्स थिंक टैंक के संस्थापक और जेएनयू में एसोसिएट प्रोफेसर हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

मधुर वाणी

वाणी का प्रभाव गहरा होता है। मधुर वाणी के प्रयोग से संबंधों में प्रेम, सहृदयता और आत्मीयता का संचार होता है। जबकि कटु और कर्कश वचन संबंधों में दरार डालते हैं, जिससे झगड़े, मारपीट और दंगों जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। कटु वचन का घाव कभी नहीं भरता, जबकि शारीरिक चोटें औषधि से ठीक हो जाती हैं। कटु वाणी का जख्म जीवनभर टीसता रहता है और व्यक्ति बदले की भावना से ग्रस्त हो जाता है। धनुष से निकले तीर की तरह मुख से निकली कटु वाणी भी अत्यंत शक्तिशाली और खतरनाक होती है।

अधिकतर मूर्ख और उद्दंड व्यक्ति वाणी का दुरुपयोग करते हैं। वे अपशब्द, कटु और व्यंग्यात्मक वचन बोलकर न केवल अपने जीवन को, बल्कि दूसरों के जीवन को भी दुखी करते हैं। ज्ञानी व्यक्ति सोच-समझकर बोलते हैं। वे कम बोलते हैं, लेकिन उनके शब्दों में गहराई होती है। इसलिए मितभाषी होना जीवन के कल्याण का एक महत्वपूर्ण सबक है। वाणी का दुरुपयोग पाप की वृद्धि करता है। कटु वाणी से किसी को कष्ट पहुंचाना अपराध है। मनुष्य का जीवन इस संसार में सीमित है और कब यह समाप्त हो जाए, कोई नहीं जानता। इसलिए हमें मधुर वार्तालाप करके प्रेम और मित्रता का संचार करना चाहिए। मधुर वचन एक प्रकार का वशीकरण मंत्र है।

द्रौपदी के कटु वचन ने दुर्योधन को दुखी किया, जिसके परिणामस्वरूप महाभारत का युद्ध हुआ। इसी प्रकार माता कैकेयी के कठोर वचन राजा दशरथ की मृत्यु का कारण बने और प्रभु श्रीराम को वनवास जाना पड़ा। इस प्रकार वाणी का अत्यधिक महत्व है। हमें अपने शब्दों का चयन सोच-समझकर करना चाहिए। मधुर वाणी से न केवल संबंधों में मिठास बढ़ती है, बल्कि यह समाज में शांति और सद्भाव का भी निर्माण करती है। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक और मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए, ताकि हम अपने और दूसरों के जीवन को सुखद बना सकें।

मुकेश ऋषि

पाठकनामा

pathaknama@pat.jagran.com

अनुचित हैं लोकलुभावन वादे

'लोकलुभावन वादों पर टिकी राजनीति' शीर्षक से लिखे लेख में संजय गुप्त ने स्पष्ट किया है कि अगर जाति की राजनीति और लोकलुभावन घोषणाओं के माध्यम से चुनाव लड़े जाएंगे तो बिहार पिछड़े राज्यों की श्रेणी से बाहर नहीं निकल पाएगा। प्रश्न यह उठता है कि हमारी राजनीति ऐसी बुनियाद क्यों नहीं रख पा रही है, जिससे जाति की राजनीति और लोकलुभावन घोषणाओं को खारिज किया जा सके। यह जानते हुए भी कि इस एक सुधार से विकास के सभी दरवाजे खुल सकते हैं। जाति की राजनीति अधिकांश राज्यों में प्रचलित है, लेकिन बिहार में इसका प्रभाव कुछ अधिक है। इसका मुख्य कारण यह है कि यहां जाति वर्चस्व वाली छोटी-छोटी पार्टियों की भरमार है। बड़ी पार्टियों ने समावेशी राजनीति के तहत सभी जातियों को समायोजित करने में असफलता दिखाई है। दूसरी ओर, मतदाता भी किसी न किसी जाति या धर्म से जुड़े होते हैं। ऐसे में सभी को अपने नेता की तलाश बड़ी पार्टियों के भीतर करनी चाहिए। बिहार की राजनीति में एक नई दिशा की आवश्यकता है, जहां जाति और धर्म से ऊपर उठकर विकास की बात की जाए। यह तभी संभव है जब सभी राजनीतिक दल एकजुट होकर समावेशी राजनीति को अपनाएं और मतदाता भी अपने सोच में बदलाव लाएं। केवल तभी बिहार अपने विकास की नई ऊंचाइयों को छू सकेगा।

मुकेश कुमार मनन, पटना

संयम ही लोकतंत्र की ताकत

लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें हर नागरिक को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है। लोग सरकार, न्यायपालिका या किसी भी संस्था के निर्णय पर अपनी असहमति प्रकट कर सकते हैं, किंतु यह स्वतंत्रता तभी सार्थक है जब इसका प्रयोग संविधान और शालीनता की मर्यादाओं के भीतर किया जाए। हाल ही में धार्मिक टिप्पणी के बाद किसी व्यक्ति द्वारा मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने की कोशिश की घटना ने इस मर्यादा पर गंभीर प्रश्न खड़ा किया है। जूता फेंकना या किसी भी प्रकार का हिंसात्मक प्रदर्शन लोकतांत्रिक आचरण नहीं है। यह आवेग, असहनशीलता और विधिक अज्ञानता का प्रतीक है। यदि किसी टिप्पणी से किसी वर्ग या समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं तो न्यायिक या संवैधानिक माध्यमों से उसका प्रतिकार संभव है। न्यायालय, जन आंदोलन, याचिकाएं या शांतिपूर्ण विरोध। ये सब लोकतंत्र में असहमति व्यक्त करने के वैध रास्ते हैं। असंयमित कार्य न केवल कानून के विरुद्ध हैं, बल्कि देश की अंतरराष्ट्रीय छवि को भी धूमिल करते हैं। जब किसी लोकतांत्रिक राष्ट्र में असहमति हिंसात्मक प्रतीकों के रूप में सामने आती है तो यह उसकी परिपक्वता और सहिष्णुता पर प्रश्नचिह्न लगाता है। यह आवश्यक है कि हम असहमति को संवाद, तर्क और संयम के माध्यम से व्यक्त करना सीखें। लोकतंत्र की असली शक्ति हिंसा में नहीं बल्कि विचारों के आदान-प्रदान और संवैधानिक मर्यादा के पालन में निहित है। यही किसी राष्ट्र की परिपक्व लोकतांत्रिक पहचान होती है।

प्रभात कुमार भारती, झंझारपुर

जाति-धर्म से ऊपर उठकर करें मतदान

संजय गुप्त द्वारा लिखित आलेख 'लोकलुभावन वादों पर टिकी राजनीति' पढ़ा। बिहार विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। यह चुनावी मुकाबला मुख्य रूप से सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और महागठबंधन के बीच होने की संभावना है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की पार्टी एवं मुस्लिम नेता असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के मैदान में उतरने से चुनाव का रोमांच बढ़ गया है। किसी भी नेता की असली परीक्षा चुनावी मैदान में होती है, इसलिए यह चुनाव प्रशांत किशोर के लिए एक कठिन परीक्षा है। सभी राजनीतिक दलों द्वारा लोकलुभावन वादों की झड़ी लगा दी गई है। इन वादों की वजह से राज्य सरकार की आर्थिक अर्थव्यवस्था दयनीय हो जाती है। लोकलुभावन वादा वोट प्राप्त करने का एक आसान जरिया बन चुका है, इसलिए कोई भी दल इस रेवड़ी संस्कृति में पीछे नहीं रहना चाहता है। बिहार में जातीय राजनीति का बोलबाला है। सभी गठबंधन जातीय समीकरण का हिसाब-किताब बैठाने में लगे हैं, जो बिहार के पिछड़ेपन की मुख्य वजह बन चुकी है। लोकतंत्र के आंगन में परिवारवाद, धनबल और बाहुबल की राजनीति फल-फूल रही है। प्रत्याशी की योग्यता को नजरअंदाज कर उसकी जाति को अहमियत दी जाती है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए जाति-धर्म से ऊपर उठकर मतदान करना चाहिए।

इं. हिमांशु शेखर, केसपा, गयाजी

पोस्ट

अफगान विदेश मंत्री की भारत यात्रा पर पाकिस्तान ने जैसी विस्तृत प्रतिक्रिया व्यक्त की है, वह दर्शाता है कि इस दौरे से पाकिस्तान में कितनी बेचैनी है।
कंवल सिब्बल@KanwalSibal

नैतिकता के तकाजे के साथ कोई देश कभी महाशक्ति नहीं बन सकता। अपने हितों की पूर्ति की दिशा में निर्ममता के साथ आगे बढ़ने पर ही महाशक्ति बनने की आकांक्षा पूरी होती है। अमेरिका इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कुशल मेहरा@kushal_mehra

सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौता पाकिस्तान को अफगानिस्तान से नहीं बचा पाया। अफगानिस्तान तो पाकिस्तान की सामरिक शक्ति का 10 प्रतिशत भी नहीं है। इसके बावजूद कुछ लोग सऊदी से समझौते के बाद दिन में ही सपने देखने लगे थे कि भारत के विरुद्ध यह करार पाकिस्तान के लिए मददगार होगा।
मोनिका वर्मा@TrulyMonica

ममता बनर्जी कह रही हैं कि लड़कियों को रात में बाहर नहीं जाने देना चाहिए। अगर यही शब्द किसी भाजपा नेता या मंत्री ने बोला होता तो अब तक देश में बवाल खड़ा हो जाता। सुरेश सिंह@sureshsinghj

जनपथ

चिदंबरम के बोल से फंसती है कांग्रेस,
आखिर क्यों पहुंचा रहे राहुल जी को ठेस।
राहुल जी को ठेस बनेंगे यदि वह अय्यर,
पक्का मानो आप कटेंगे उनके भी पर।
कांग्रेस में सेफ वही जो बोलेगा कम,
क्यों भविष्य के साथ खेलते हैं चिदंबरम!
- ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व.पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त
जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प. बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073
E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर. बी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 26 अंक 180

****

कल्पमेधा

जो सुरक्षा के लिए आजादी का त्याग कर देता है, वह दोनों में से किसी के भी लायक नहीं है।
– बेंजामिन फ्रैंकलिन

दुराग्रहों की सीमा

भारत में महिला सशक्तीकरण की तस्वीर को सिर्फ इतने से समझा जा सकता है कि आज यहां महिलाएं अमूमन हर क्षेत्र में पुरुषों के समकक्ष खड़ी हैं। वे किसी भी जिम्मेदारी या दायित्व के मामले में बेहतरीन नतीजे दे सकती हैं। मगर चाहे-अनचाहे कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, जिसमें महिलाओं के खिलाफ दुराग्रह आम दिखते हैं। गौरतलब है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने अपने भारत दौरे के क्रम में नई दिल्ली में शुक्रवार को जो संवाददाता सम्मेलन किया, उससे महिला पत्रकारों को बाहर रखा गया। जिस दौर में भारत की बहुत सारी महिला पत्रकार देश-दुनिया की मुख्यधारा की पत्रकारिता में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कर रही हैं, वैसे समय में किसी देश के विदेश मंत्री से सवाल करने वालों के बीच उन्हें जगह नहीं दी जाए, तो यह न केवल सामान्य औपचारिकता के खिलाफ है, बल्कि पत्रकारिता के मोर्चे पर बेहद सक्षम रही महिलाओं को कमजोर मानने की तरह है।

यह संभव है कि किसी देश के दूतावास के परिसर के संदर्भ में जो नियम-कायदे लागू होते हैं, उसके मुताबिक मेजबान देश के दखल की एक सीमा होगी। मगर यह विचित्र है कि संवाददाता सम्मेलन से महिला पत्रकारों को बाहर रखने के मसले पर सरकार की ओर से कोई औपचारिक विरोध दर्ज नहीं किया गया। इस मुद्दे के तूल पकड़ने के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने एक स्पष्टीकरण जरूर जारी किया कि इस संवाददाता सम्मेलन में उसकी कोई भूमिका नहीं थी! सवालों से घिरने के बाद रविवार को मुत्ताकी के एक और संवाददाता सम्मेलन में महिला पत्रकारों को भी बुलाया गया। इसे सिर्फ गलती में सुधार की कोशिश ही कहा जा सकता है! इससे पहले के संवाददाता सम्मेलन में महिलाओं को बाहर रखने के पीछे की मानसिकता सवालों से परे नहीं हो जाती। दुनिया भर में भू-राजनीतिक तकाजों के मुताबिक रणनीतिक रूप से किसी अन्य देश के साथ संवाद और संबंध के ऐसे प्रारूप तय किए जा सकते हैं, जिससे अपने देश के हित सुनिश्चित किए जा सकें। आतंकवाद के मोर्चे पर अफगानिस्तान के साथ संवाद कायम करना भारत के हित में हो सकता है, लेकिन इस क्रम में तालिबान के वैचारिक मानदंडों या मानसिकता को जगह देना कितना सही माना जा सकता है।

अफगानिस्तान में वर्ष 2021 में सत्ता में आने के बाद तालिबान की सरकार की राजनीतिक विचारधारा और सामाजिक सोच से जुड़े पूर्वाग्रह छिपे नहीं रहे हैं। खासतौर पर महिलाओं के जीवन को लेकर उसकी संकीर्णता जगजाहिर रही है। अफगानिस्तान की महिलाओं और उनके मानव अधिकारों पर चोट करने वाली तालिबान की मानसिकता पर भारत में एक ठोस विरोध रहा है। मगर तमाम प्रगतिशील मूल्यों और अपेक्षाओं को दरकिनार करके तालिबान ने अफगानिस्तान की महिलाओं की शिक्षा और नौकरी से लेकर सार्वजनिक गतिविधियों तक को नियम-कायदे बना कर नियंत्रित किया। सवाल है कि अफगानिस्तान में अपनी वैचारिक राजनीति को मनचाहे तरीके से लागू करने वाले तालिबान को भारत में वैसा कर पाने की सुविधा कैसे मिली। कायदे से संवाददाता सम्मेलन से महिलाओं को बाहर रखे जाने के मुद्दे पर सरकार से लेकर वहां गए पत्रकारों की ओर से भी आपत्ति उठनी चाहिए थी। महिलाओं के अधिकारों और उनके सशक्तीकरण के सवाल पर प्रगतिशील मूल्यों का वाहक रहे भारत में महिलाओं को दोयम समझने वाले किसी संकीर्ण मानदंडों की जगह नहीं होनी चाहिए।

साइबर फर्जीवाड़ा

डिजिटल प्रौद्योगिकी हमारे जीवन को आसान और कुशल बनाती है। इससे संचार, शिक्षा, बैंकिंग और स्वास्थ्य सहित कई सेवाएं बेहतर हो जाती हैं। निस्संदेह यह तकनीक आज के समय की जरूरत बन गई है। मगर निजी और व्यावसायिक स्तर पर इसका जितना महत्त्व है, बिना व्यापक जानकारी के इसका इस्तेमाल उतना ही खतरनाक साबित हो सकता है। इस आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल अब आपराधिक गतिविधियों में भी धड़ल्ले से होने लगा है। इसी तरह के एक मामले में महाराष्ट्र के अमरावती में उपभोक्ता अदालत से सेवानिवृत्त न्यायाधीश को साइबर जालसाजों ने 'डिजिटल अरेस्ट' कर उनसे इकतीस लाख रुपए ठग लिए। हालांकि, इस तरह की यह कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी ऐसे कई मामले देश भर में सामने आ चुके हैं। मगर सवाल है कि इन घटनाओं से शासन-प्रशासन और डिजिटल तकनीक से जुड़े लोग क्या सबक ले रहे हैं? क्या इस तरह के अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए विभिन्न स्तरों पर कोई ठोस उपाय किए गए हैं?

दरअसल, 'डिजिटल अरेस्ट' का मतलब है कि जब साइबर जालसाज किसी व्यक्ति को आनलाइन माध्यम से डराते-धमकाते हैं और उसे तब तक एक स्थान पर ही रहने को मजबूर कर देते हैं, जब तक कि वह मुंह मांगी रकम नहीं दे देता। ऐसे में सबसे पहले यह जरूरी है कि डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल करने वाले लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूक हों। ताजा आंकड़ों के मुताबिक, देश में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या सौ करोड़ तक पहुंच गई है। मगर, सवाल है कि इनमें से कितने लोग ऐसे होंगे, जो डिजिटल तकनीक की जटिलताओं और इसके संभावित खतरों को जानते-समझते हैं? आए दिन सामने आ रहे साइबर अपराधों की तस्वीर से साफ है कि ऐसे लोगों की संख्या बेहद कम है। अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अगर शिक्षित एवं उच्च पदों पर रहे लोग भी साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं, तो डिजिटल तकनीक के मामले में आम लोगों के साथ क्या स्थिति होगी। सरकार की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि किसी नई तकनीक को लेकर जनता के बीच व्यापक जागरूकता लाई जाए। साथ ही, तकनीक के दुरुपयोग को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।

रोगों से बचाव के ज्ञान का सम्मान

अध्ययन बताते हैं कि हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र और उसकी प्रतिक्रिया कैसे नियंत्रित होती है। साथ ही, यह ज्ञात हुआ है कि कहां यह प्रणाली गड़बड़ हो जाती है और अपने मूल प्रतिरक्षा तंत्र तक कैसे पहुंचा जा सकता है।

सुरेश सेठ

अपने भीतर रोगों से बचाव की क्षमता बढ़ाने की चाह कौन नहीं करता? जहां तक भारत का सवाल है, तो यहां देश के कोने-कोने में लोगों को असाध्य रोगों से बचाने के लिए क्षमता विकसित करने के ऐसे प्रयास किए गए कि वह स्वास्थ्य के एक ढांचे के रूप में वास्तविक हितकारी साबित होने के बजाय नेताओं के लिए प्रचार पाने के ही काम आए। फिर भी चिकित्सा के क्षेत्र में हमारा देश किसी से कम नहीं है, लेकिन यह भी तथ्य है कि देश के निर्धन लोगों के लिए बीमार हो जाने पर उनका जीना मुहाल हो जाता है। सरकार ने केंद्रीय और राज्य स्तर पर बहुत-सी मुफ्त उपचार बीमा योजनाएं भी शुरू कर रखी हैं। वृद्धों को भी उनकी बीमारियों की स्थिति में संरक्षण दिया जा रहा है। वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की जा चुकी है। इससे इतर, पंजाब सरकार ने भी ऐसी चिकित्सा बीमा योजना राज्य के हर परिवार के लिए घोषित कर रखी है। हालांकि देश में जहां वरिष्ठ नागरिकों के लिए योजना के तहत पांच लाख रुपए की राशि तय की गई है, वहीं पंजाब में इसे दस लाख रुपए तक रखा गया है।

जब इस तरह की योजनाएं घोषित होने के बाद लागू होती हैं, तो आम आदमी खुश हो जाता है। उसे लगता है कि निजी क्षेत्र में चलाए जाने वाले बड़े अस्पतालों के भारी-भरकम बिल से उसे छुटकारा मिल जाएगा। वह अपने आप को ऐसा भाग्यवान नागरिक मान सकता है, जिसे कभी कोई रोग लग जाए, तो उसके निदान और उपचार का दायित्व सरकार के ऊपर रहेगा। संबंधित स्वास्थ्य कार्ड दिखाते ही मुफ्त इलाज हो जाएगा। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ अलग है। अब भी सार्वजनिक क्षेत्र में चलने वाले सरकारी अस्पताल या पंजाब में चलाए गए मोहल्ला क्लीनिक बेहतर उपचार का वचन तो देते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसे वचन पूरे होते नजर नहीं आते। दरअसल, निजी अस्पतालों का कहना है कि जब वे स्वास्थ्य कार्ड वाले मरीजों का उपचार करते हैं, तो सरकार की ओर से तुरंत भुगतान नहीं किया जाता। इसलिए कई बार निजी अस्पताल मरीजों को दाखिल करने से इनकार कर देते हैं।

कभी तपेदिक यानी टीबी से लोग बहुत डरते थे। इसे जानलेवा समझकर किसी आरोग्य आश्रम में रहने लगते थे। अब यह रोग नियंत्रित हो गया है। बिल्कुल यही हाल डेंगू बुखार का भी हो गया है। कोरोना ने दो साल तक मानव जाति को जिस प्रकार आर्थिक और सामाजिक संकट में डाला, उसे भी कोई भूल नहीं सकता। इस संदर्भ में देखें तो किसी भी नए मौलिक या उपयोगी काम के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल सम्मान को माना जाता है। पिछले कुछ वर्षों से जो नोबेल सम्मान घोषित हो रहे हैं, उनमें इस समय मानव जाति के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाला चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार है। इस बार अमेरिका और जापान के वैज्ञानिकों के नाम 'मेडिसिन' के लिए इस सम्मान की घोषणा हुई। उनके नाम हैं मैरी ई ब्रांको, फ्रैड रैंच डेल और शिमोन साकागुची। इन विद्वान वैज्ञानिकों ने न केवल इंसान के 'इम्यून सिस्टम' यानी रोग प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाने के मामले में शोध किया है, बल्कि मनुष्य के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र से जूझने वाली शत्रु कोशिकाओं को

भी बेअसर किया और बाहर से इंसान के प्रतिरक्षा तंत्र पर कोई हमला न कर दे, इसके लिए 'मास्टर स्विच' भी खोजा है।

इन तीनों वैज्ञानिकों का मुख्य शोध या अध्ययन कैंसर और मधुमेह में रहा और वे इसमें नए शोध को सामने लाने का प्रयास भी कर रहे हैं। इस

> **कभी तपेदिक यानी टीबी से बहुत लोग डरते थे। इसे जानलेवा समझकर किसी आरोग्य आश्रम में रहने लगते थे। अब यह रोग नियंत्रित हो गया है। बिल्कुल यही हाल डेंगू बुखार का भी हो गया है। कोरोना ने दो साल तक मानव जाति को जिस प्रकार आर्थिक और सामाजिक संकट में डाला, उसे भी कोई भूल नहीं सकता। इस संदर्भ में देखें तो किसी भी नए मौलिक या उपयोगी काम के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल सम्मान को माना जाता है। पिछले कुछ वर्षों से जो नोबेल सम्मान घोषित हो रहे हैं, उनमें इस समय एक बड़ा और मानव जाति के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाला चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार है।**

युगांतकारी विश्लेषण को आसान शब्दों में समझने के लिए हम कह सकते हैं कि खास तरह की कोशिका प्रतिरक्षा तंत्र को इंसानी शरीर को अपने अंदर तलाश करना होता है और अगर गलती से कोई कोशिका इस तंत्र की ताकत को समझ न पाने के कारण उस पर हमला कर दे, तो वे उसे रोक सकते हैं। यानी ये खोज बताती है कि हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र और उसकी प्रतिक्रिया कैसे नियंत्रित होती है। साथ ही, कहां यह प्रणाली गड़बड़ हो जाती है और अपने मूल प्रतिरक्षा तंत्र तक कैसे पहुंचा जा सकता है।

यानी यह इलाज का एक नया तरीका है। इसे एक क्रांतिकारी बदलाव भी कह सकते हैं। यह रोग प्रतिरक्षा प्रणाली हमारे शरीर में हजारों किस्म के जीवाणुओं को घुसने से रोकती है। ये जीवाणु मानव कोशिकाओं जैसे होते हैं और यह समझना मुश्किल हो जाता है कि शरीर में हजारों कोशिकाओं में से कौन शरीर का बचाव करेगा और कौन शरीर का दुश्मन बन जाएगा। यों यह प्रतिरक्षा तंत्र को बड़ी सुरक्षा है, जो बाहर से आने वाले रोगों, विषाणु या जीवाणु को रोकता है, मारता है। लेकिन गड़बड़ यह है कि कई बार ये 'सुरक्षा सेना' अपने ही शरीर के छिपे विषाणुओं को पहचान नहीं पाती।

अब पुरस्कार प्राप्त तीनों वैज्ञानिकों की भूमिका पर गौर किया जाए, तो सन् 1995 में शिमोन साकागुची ने शरीर में मौजूद 'शांति रक्षक सैनिक' यानी सुरक्षा कोशिकाओं की तलाश की। इन कोशिकाओं का ताल्लुक लड़ाई शुरू करना नहीं, बल्कि अन्य हमलावर कोशिकाओं को रोकना है। यह भी देखना है कि ये कोशिकाएं रास्ता भटककर अपने ही शरीर की हानि न पहुंचा दें। यह एक स्थापित ज्ञान को चुनौती थी, क्योंकि प्रायः उपचार विशेषज्ञ यह समझते थे कि जो प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर में है, वह हमेशा लाभदायक होता है और उससे संक्रमण का कोई डर नहीं है, बल्कि यह बाहर से होने वाले संक्रमण से बचाता है। इसका अर्थ यह है कि इन तीनों वैज्ञानिकों ने और विशेषकर शिमोन साकागुची ने यह बताया कि हर शरीर में एक सहन करने वाली ताकत भी बन जाती है। यह केंद्रीय सहन करने वाली ताकत है।

यह खोज बहुत समय से हो रही थी। वर्ष 2001 में इसके लिए एक 'मास्टर कवच' खोजा गया, जिसने पाया कि प्रतिरक्षा प्रणाली अगर बेकाबू हो जाए तो अपने ही शरीर को नुकसान पहुंचाने लगती है। अगर यह अनियंत्रित रहे तो इंसानी शरीर में 'आइपैक्स सिंड्रोम' भी पैदा हो सकता है। इन तीनों वैज्ञानिकों का शोध बहुत मूल्यवान है, क्योंकि इसके जरिए बड़ी तेजी से बीमारियों की जड़ तक पहुंचा जा सकता है और इलाज के नए तरीके भी विकसित किए जा सकते हैं।

इस समय इन 'टी सेल' के दो सौ चिकित्सीय परीक्षण चल रहे हैं। इसके निष्कर्ष आने में अभी वक्त है, लेकिन ये परीक्षण निश्चित रूप से इस प्रतिरक्षा प्रणाली की उपादेयता के हक में होंगे। मगर कैंसर की कोशिकाएं जैसी कुछ असाध्य बीमारियां, जो आजकल आदमी को मौत का संदेश लगती हैं, उन्हें 'रेगुलेटरी टी सेल' पहचानने और खत्म करने में भूमिका निभा सकते हैं। एक और बड़ी चुनौती तब आती है, जब अंग प्रत्यारोपण करना पड़ता है। जैसे घुटनों को बदलना या गुर्दा और यकृत के दानकर्ताओं से दान लेकर रोगी व्यक्ति को लगाना। चिंता की बात यह है कि प्रत्यारोपित गुर्दा या यकृत कई बार नए शरीर को स्वीकारने से इनकार कर देता है। अब अगला कदम इन चिकित्सा विशेषज्ञों का यह है कि अगर ऐसे अंगों का प्रत्यारोपण होता है, तो वह शरीर के साथ पूरी तरह सहज हो जाए। इस तरह, खून या अंगों के न मिलने को विज्ञान की यह प्रगति सहज और सुलभ बना सकती है।

भरोसे की दुनिया

मनीष कुमार चौधरी

एक कार्यशील समाज के लिए विश्वास आवश्यक है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें मूल रूप से उन लोगों पर भरोसा करने में सक्षम होना चाहिए, जिन्हें हम प्यार करते हैं। अपने दोस्तों और परिवार पर..। साथ ही अपने पड़ोसियों, सहकर्मियों और यहां तक कि उन लोगों पर भी, जिन्हें हम अच्छी तरह से नहीं जानते। मसलन, हमारे किराना दुकानदार और हमें दूध पहुंचाने वाले। शोधकर्ताओं ने दुनिया भर के सभी उम्र के ढाई लाख से अधिक प्रतिभागियों को शामिल करते हुए लगभग पांच सौ अध्ययनों के परिणामों का विश्लेषण किया, ताकि यह देखा जा सके कि भरोसा करने में सक्षम होने से उनके जीवन की संतुष्टि और खुशी पर क्या प्रभाव पड़ा। उन्होंने पाया कि विश्वास और कल्याण एक साथ चलते हैं। दूसरों पर भरोसा करने से खुशहाली बढ़ी और बेहतर खुशहाली का एहसास किसी और पर ज्यादा भरोसा करने में मदद करता है। शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि जैसे-जैसे हम जीवन के विभिन्न चरणों से गुजरते हैं, भरोसा और उसका महत्त्व बदलता जाता है। बच्चों, किशोरों और बुजुर्गों के लिए भरोसा युवा या मध्यम आयु वर्ग के वयस्कों की तुलना में थोड़ा ज्यादा जरूरी है।

विश्वास का विकास शिशु उम्र से ही शुरू हो जाता है। स्नेहपूर्वक, ध्यानपूर्ण और संवेदनशील देखभाल पाकर शिशु सीखते हैं कि वे अपने आसपास के लोगों पर भरोसा कर सकते हैं और उनकी दुनिया एक सुरक्षित और दयालु जगह है। दूसरी ओर, अगर उन्हें कठोर, अनियमित या उपेक्षापूर्ण देखभाल मिलती है, तो वे इसके विपरीत सीखेंगे, जिससे उन्हें बाद में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं, वे अनुभव से सीखना शुरू करते हैं कि हर कोई भरोसेमंद नहीं होता। शोध बताते हैं कि पांच साल की उम्र के बच्चे भी उस वयस्क को पहचान लेते हैं जो उन्हें धोखा देने की कोशिश कर रहा है, और उस व्यक्ति के सच बोलने पर भरोसा नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि बच्चों को भरोसा दिलाने के लिए हमें खुद भी भरोसेमंद होना चाहिए। जैसे-जैसे बच्चे किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, दूसरों पर भरोसा करना उनके लिए आवश्यक सहकर्मी संबंधों को विकसित करने के लिए महत्त्वपूर्ण बना रहता है। इस दौरान ऐसे मित्रों और मार्गदर्शकों की आवश्यकता होगी जिन पर वे भरोसा कर सकें। भले ही किशोर खुद को माता-पिता से अलग करना सीख जाते हैं और अधिक दूर या सहकर्मी-केंद्रित लग सकते हैं, माता-पिता उनके विकास के लिए महत्त्वपूर्ण बने रहते हैं, भले ही इस प्रक्रिया से विश्वास कम हो जाए।

हालांकि दूसरों पर भरोसा करना सीखने की शुरुआत बचपन में ही हो सकती है, लेकिन दूसरों पर भरोसा करने की क्षमता और जरूरत, खासकर पारस्परिक संबंधों में, जीवन भर बढ़ती रहती है। चूंकि मधुर, घनिष्ठ संबंध हमारी भलाई के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण हैं और विश्वास मजबूत संबंध बनाने में मदद करता है, इसलिए यह समझ में आता है कि अधिक भरोसेमंद और विश्वसनीय होने से हमारी सकारात्मक भावनाएं और जीवन संतुष्टि बढ़ेगी। अपने व्यापक समुदाय से जुड़े रहना, इसके लिए थोड़ा अधिक संवेदनशील होना और दूसरों की सामान्य अच्छाई पर भरोसा करना आवश्यक हो सकता है। हालांकि पूर्वाग्रह हमें उन लोगों पर भरोसा करने से रोक सकते हैं, जो हमसे अलग दिखते, सोचते या कार्य करते हैं। अध्ययनों में पाया गया है कि जिन नागरिकों का अपनी सरकार और अपनी संस्थाओं पर अधिक भरोसा होता है, वे भी अधिक खुश रहते हैं।

वृद्धावस्था में विश्वास और भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है। जहां कई बुजुर्गों के लिए अपने परिवार और दोस्तों में से करीबियों पर भरोसा करना सबसे जरूरी है, वहीं दूसरे भरोसेमंद रिश्ते भी मायने रखते हैं। बुजुर्ग लोग अक्सर उम्र बढ़ने के साथ अपने पड़ोसियों और यहां तक कि अजनबियों पर भी ज्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि कमजोर रिश्ते शारीरिक या संज्ञानात्मक गिरावट के दौर में (खासकर अगर उनके करीबी रिश्तेदार चले जाएं या उनका निधन हो जाए) सांत्वना और सहायता का स्रोत बन सकते हैं। बेशक, बुजुर्गों को दूसरों पर अंधाधुंध भरोसा नहीं करना चाहिए, फिर भी उन्हें दूसरों पर अपना समग्र विश्वास खोने की जरूरत नहीं है। बशर्ते वे किसी पर भरोसा करने से पहले उसकी विश्वसनीयता की जांच कर सकें।

यों तो हर व्यक्ति, चाहे उसकी उम्र या लिंग कुछ भी हो, भरोसेमंद और विश्वसनीय होने से लाभान्वित हो सकता है, लेकिन अविश्वास को बढ़ावा देने वाले समाज में यह बहुत कठिन हो सकता है। अगर हम किसी तानाशाही शासन में रह रहे हैं या जहां राजनीतिक भ्रष्टाचार, हिंसक अपराध या नागरिकों पर अवैध निगरानी का बोलबाला है, तो हमारे लिए दूसरों पर भरोसा करना मुश्किल या खतरनाक भी हो सकता है। फिर भी, भरोसा न करना हमारे स्वभाव में नहीं है। मनुष्य होने के नाते हम जीवित रहने के लिए एक-दूसरे की सद्भावना पर निर्भर हैं। अपने परिवारों, सामाजिक दायरे, आस-पड़ोस और संस्थाओं में विश्वास को जीवित रखकर हम सभी के लिए एक ज्यादा भरोसेमंद और खुशहाल समाज बनाने में मदद कर सकते हैं।

दुनिया मेरे आगे

> **मधुर, घनिष्ठ संबंध हमारी भलाई के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण हैं और विश्वास मजबूत संबंध बनाने में मदद करता है, इसलिए यह समझ में आता है कि अधिक भरोसेमंद और विश्वसनीय होने से हमारी सकारात्मक भावनाएं और जीवन संतुष्टि बढ़ेगी।**

चौपाल

उत्पीड़न का दायरा

'कानून के घर में' एवं 'संवेदनहीनता की हद' (संपादकीय 8 अक्तूबर) विचारणीय हैं। पिछले कई वर्षों से अनेक क्षेत्रों में कमजोर तबकों और अल्पसंख्यकों को सामाजिक और मानसिक प्रताड़ना के साथ हिंसा का शिकार होना पड़ रहा है। देश में हर तरफ छाया सन्नाटा हमें सोचने के लिए विवश करता है। किसी समय हमारे राजनेता ऐसी घटनाओं पर दलितों से माफी मांगते थे। मगर अब ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक दलित की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि ने आवाज नहीं उठाई। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संविधान का अनुसरण करने वाले हमारे देश का वर्तमान परिदृश्य नेताओं की ही देन है। यह उनकी नहीं, बल्कि जनता की गलती है, जिसने ऐसे प्रतिनिधियों का चयन किया है। संविधान आज भी हमारे मार्गदर्शन के लिए उपस्थित है, लेकिन हम आंखें मूंदे हुए हैं। यह संवेदनहीनता किस हद तक जाएगी यह तो नहीं मालूम, पर इतना अवश्य है कि संविधान के होते हुए उसकी अनदेखी कोई सुखद परिणाम नहीं दे सकता। पक्की सड़क और सुविधाजनक रास्ता होते हुए भी ऊबड़-खाबड़ पगडंडियों पर चलना कोई समझदारी नहीं है।

– इशरत अली कादरी, भोपाल

तनाव की परतें

देश के युवाओं में तनाव और अवसाद तेजी से बढ़ रहा है। भविष्य की चिंता और करिअर को लेकर उनमें तनाव तो है ही, वहीं आर्थिक चुनौतियां भी हैं। इससे उनकी पढ़ाई में बाधा आती है। एक अध्ययन के अनुसार बड़ी संख्या में छात्र करिअर, प्रतियोगी परीक्षाओं और बेहतर प्रदर्शन के दबाव में मानसिक रूप से दबाव में हैं। अत्यधिक प्रतिस्पर्धा के साथ पारिवार की अपेक्षाएं भी उन्हें भावनात्मक रूप से कमजोर कर रही हैं। परिणामस्वरूप कई छात्र अवसाद में आ जाते हैं और आत्मघाती कदम तक उठा लेते हैं, जिससे उनके परिवार को सदा के लिए गहरी क्षति होती है। शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों की समय-समय पर काउंसलिंग की जानी चाहिए। उन्हें यह समझाया जाना चाहिए कि परीक्षा जीवन का केवल एक पड़ाव है। हर युवा की अलग-अलग योग्यता और दिशा होती है। युवाओं को अवसाद से बचाना राष्ट्र की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि वही हमारे देश का भविष्य हैं।

– अरविंद जैन 'बीमा' फ्रीगंज, उज्जैन

दरकते पहाड़

पिछले दिनों हिमाचल के बिलासपुर में सवारियों से भरी बस पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। अगर प्रशासन ने समय रहते इस पहाड़ की जांच की होती और वहां वाहनों की आवाजाही बंद कर दी होती, तो शायद यह हादसा न होता। अब देखना यह है कि हादसे से सबक लेते हुए राज्य के उन पहाड़ों की जांच होती है कि नहीं, जहां से सड़कें गुजरती हैं। इस बार ज्यादा बरसात हुई है और अभी भी हो रही है। हो सकता है कि इस कारण पहाड़ कमजोर पड़ गए हों। हिमाचल प्रदेश के ही नहीं, बल्कि दूसरे पहाड़ी राज्यों में भी इस बार भारी बारिश हुई है, वहां की सरकारों को भी इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। देश के पहाड़ी इलाकों में कई सड़कें ऐसी हैं जो बड़े-बड़े पहाड़ों के नीचे से गुजरती हैं। इनमें से कुछ तो बहुत ही पुरानी हैं। समय के साथ-साथ पहाड़ कमजोर हो रहे हैं। यह चिंता की बात है और उन्हें बचाने की जरूरत है।

– राजेश कुमार चौहान, जलंधर

युद्ध के समांतर

दो वर्ष तक युद्धोन्माद में डूबे रहने के बाद मध्यपूर्व का एक क्षेत्र शांत होता दिखाई दे रहा है। कितने दिनों तक ऐसा रह पाएगा, कहना मुश्किल है। इजराइल ने युद्धविराम की मंजूरी दे दी है। कोई भी युद्ध शुरू होता है, तो उसका अंत भी होता है। भारी तबाही के बाद दोनों पक्षों को लगता है कि बस अब बहुत हो गया। दुनिया भर के लोग यह कह रहे हैं कि हमास और इजराइल के बीच इस युद्धविराम में अमेरिका के राष्ट्रपति का योगदान है। लेकिन सच यह है कि इजराइल अमेरिका के लिए कठपुतली से अधिक कुछ नहीं है। दो वर्ष से अधिक गाजा में जनसंहार चला। अगर आज अमेरिका सिर्फ एक महीने के लिए इजराइल को हथियारों की आपूर्ति बंद कर दे, तो वह चुप बैठ जाएगा। अगर ट्रंप ईमानदार हैं, तो उन्हें अब फिलिस्तीनियों को न्याय दिलाने के लिए साहस दिखाना चाहिए।

– जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

{ संपादकीय }

नई दिल्ली, सोमवार 13 अक्टूबर 2025
संस्थापक-सम्पादक : स्व. मायाराम सुरजन

जातिवाद का जहर और दलित उत्पीड़न

हरियाणा में आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार का अंतिम संस्कार इन पंक्तियों के लिखे जाने तक नहीं हो पाया है, वहीं हरियाणा सरकार के दो मंत्री, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव जैसे बड़े अधिकारी पूरन कुमार के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें अंतिम संस्कार और पोस्टमार्टम के लिए मनाने में जुटे हुए हैं। इस मामले में हरियाणा सरकार ने रोहतक के पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजारनिया को हटा दिया है। आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की पत्नी ने उन पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था।

बता दें कि पूरन कुमार का शव 7 अक्टूबर मंगलवार को उनके घर पर मिला था। पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया। अपनी मौत से पहले दिवंगत अधिकारी ने एक नोट छोड़ा है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जातिगत प्रताड़ना और अपमान के आरोप उन्होंने लगाए। पूरन कुमार ने लिखा कि 2020 में तत्कालीन डीजीपी मनोज यादव ने मेरा उत्पीड़न शुरू किया, हरियाणा कैडर के अन्य अधिकारी आज भी प्रताड़ित कर रहे, तत्कालीन एसीएस गृह राजीव अरोड़ा ने मुझे छुट्टियां नहीं दी। मैं अपने बीमार पिता से मिलने तक नहीं जा सका। वर्षों तक मुझे मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ा। मेरे खिलाफ छद्म नामों से दुर्भावनापूर्ण शिकायतें की गईं। सार्वजनिक रूप से मुझे अपमानित और शर्मिंदा किया गया। अपने उत्पीड़न की एक लंबी फेरहिस्त देते हुए पूरन कुमार ने लिखा कि- मैं और अधिक प्रताड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने सब कुछ खत्म करने का निर्णय लिया है।

यकीन करना मुश्किल है कि 21 वीं का चौथाई हिस्सा निकल गया है और भारत में दलित उत्पीड़न खत्म ही नहीं हो रहा है। कहा जाता है कि कमजोर वर्गों को शिक्षा की शक्ति से लैस किया जाए, तो उनकी स्थिति में सुधार आएगा। लेकिन यहां ये तर्क भी नाकाम दिख रहा है। रायबरेली में गरीब हरिओम वाल्मिकी को पीट-पीट कर मारना, देश के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई पर जूता फेंकना और फिर सोशल मीडिया पर उसे सही ठहराया जाना और एक पुलिस सेवा के एक वरिष्ठ लेकिन दलित अधिकारी का उत्पीड़न के कारण आत्महत्या करना या उससे पहले वैज्ञानिक बनने की चाह रखने वाले छात्र रोहित वेमुला का आत्महत्या करना, तमाम मामले इस बात की गवाही चीख-चीख कर दे रहे हैं कि दलितों की स्थिति में तब तक सुधार नहीं आ सकता, जब तक इस देश से मनुवादी सोच का पूरी तरह खात्मा नहीं हो जाता। लेकिन अभी तो हाल ये है कि मनुस्मृति को ही धर्म बताकर संघ और भाजपा के समर्थकों का बड़ा हिस्सा उसे संविधान में तब्दील करने की तैयारी में है। राहुल गांधी ने इस बारे में संसद से ही देश को चेतावनी दे दी थी कि भाजपा मनुस्मृति को लागू करना चाहती है, संविधान को नहीं।

लेकिन उनकी बात को राजनीति कहकर टालने की कोशिश सरकार कर रही है। हालांकि देश देख रहा है कि राहुल गांधी एक बार फिर सही साबित हो रहे हैं। पूरन कुमार की आत्महत्या मामले में आरोपियों को बचाने की कोशिशें हुईं, लेकिन उनकी पत्नी अमनीत पी. कुमार जो कि खुद 2003 बैच की आईएएस अधिकारी हैं, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि, 'पुलिस की एफआईआर में नाम हटाए गए और एससी एसटी एक्ट के सेक्शन कमजोर किए गये।' अमनीत कुमार खुद प्रशासन और कानून की बारीकियों से वाकिफ हैं, इसलिए वे समझ गईं कि आरोपियों को बचाने की कैसी चालाकी चल रही है। अगर उनकी जगह आईपीएस अधिकारी की पत्नी साधारण पृष्ठभूमि की होतीं या इस बात को नहीं समझ पाती तो शायद इस मामले में पीड़ित को ही दोषी बताकर मामला दबा दिया जाता।

अब तो विपक्ष ने भी इस पर पुरजोर आवाज़ उठाई है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ लिखा, वहीं सोनिया गांधी ने एक कदम आगे बढ़कर अमनीत कुमार को ही चिट्ठी लिखी और इस संघर्ष में उनके साथ खड़े होने का यकीन दिलाया। आम आदमी पार्टी ने भी इस पर सवाल उठाए हैं कि कैसे आज भी दलितों को मध्ययुगीन प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है। विपक्ष अपना दायित्व निभा रहा है, लेकिन राज्य और केंद्र में सत्तारुढ़ भाजपा को इसमें राजनीति नजर आ रही है। क्या भाजपा यह नहीं जानती कि विपक्ष का काम उसकी गलतियों और कमजोरियों पर ध्यान दिलाना है, बाकी जी हुजूरी का सारा काम मीडिया तो कर ही रहा है, विपक्ष के दल भी अगर ऐसे ही सरकार की चापलूसी करने लगें तो फिर लोकतंत्र को पूरी तरह खत्म हो जाएगा। क्या भाजपा यही चाहती है कि इस देश में लोकतंत्र और संविधान न रहे।

वैसे भी एनसीआरबी का डेटा बताता है- 2013-2023 के बीच दलितों पर अत्याचार 46 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति पर 91प्रतिशत तक बढ़ा है। 2023 में 57,789 दलित उत्पीड़न के मामले दर्ज हुए हैं। जिनमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 15,368 मामले फिर मध्यप्रदेश, राजस्थान, बिहार जैसे भाजपा शासित राज्य है, इसे महज संयोग माना जाए या फिर मनुवादी सोच पर आधारित सरकार और प्रशासन का परिणाम। अपराधी बेखौफ हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहां आज भी ब्राह्मण के आगे देवता लगाकर बात करना समाज को अजीब नहीं लगता। बाबा साहेब अंबेडकर से पहले, उनके काल में और आज तक दलितों की स्थिति समाज में जस की तस है। समस्या शिक्षा की कमी नहीं, नसों में जातिवाद के फैले जहर की है, जो दलितों के लिए उच्च स्थान कतई बर्दाश्त नहीं कर पाता है।

नफरत ही खाना, नफरत ही पीना, नफरत रोज बढ़ाना: जय भाजपा!

दलितों के खिलाफ मन में इतना जहर! उन्हें नीचा दिखाने के लिए वे जिन्हें अपना सबसे बड़े नेता मानते हैं उन डॉ. अम्बेडकर को रैलियां निकाल कर अंग्रेजों का गुलाम कहा जा रहा है।

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थिति विस्फोटक हो गई है। यहां दिल्ली की तरह एक सामान्य वकील नहीं बल्कि ग्वालियर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे अनिल मिश्रा लगातार डॉ. अम्बेडकर को गालियां दे रहे हैं। उनके खिलाफ पुलिस में एफआईआर भी दर्ज की गई है मगर इसके बावजूद वे न केवल अम्बेडकर के खिलाफ बोल रहे हैं बल्कि उनके समर्थन में बड़ी तादाद में आ गए उनकी विचारधारा के वकील और राजनीतिक लोग भी अब इसे बढ़ाकर संविधान निर्माता के तौर पर उनका नाम हटाकर वी एन राव का नाम लिखने की मांग कर रहे हैं। साथ ही आरक्षण खत्म करने की।

देश में नफरत और विभाजन को कहां तक ले आया गया है यह ग्वालियर में अम्बेडकर के खिलाफ दिए जा रहे बयानों से मालूम पड़ता है। जिन वकीलों ने अम्बेडकर के खिलाफ मुहिम शुरू की है वे अब खुलेआम पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं कि अम्बेडकर के खिलाफ बोलने वाले वकील अनिल मिश्रा को गिरफ्तार करके दिखाओ!

राज्य सरकार की हिम्मत नहीं पड़ रही है। प्रशासन ने केवल अभी धारा 144 लगाकर जुलूस प्रदर्शनों पर रोक का इंतजाम किया है। अम्बेडकर देश में हमेशा से दक्षिणपंथियों के निशाने पर रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा प्रतिमाएं अम्बेडकर की तोड़ी गई हैं। कारण स्पष्ट है अम्बेडकर ने मनुवाद को सीधे चैलेंज किया था। सौ साल होने वाले हैं जब उन्होंने मनुस्मृति को जलाया था। 1927 में। और इसके बाद संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने संविधान में एससी एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी।

बीजेपी आरएसएस जो कभी सामाजिक समानता के सिद्धांत को स्वीकार नहीं कर पाई वह दलित पिछड़े आदिवासियों में पैठ बनाने के लिए तो अम्बेडकर की बात करती है मगर मन से कभी उन्हें स्वीकार नहीं कर पाती। इसलिए संघ ने उस समय संविधान का विरोध किया था। उस समय संघ के मुखपत्र आर्गनाइजर ने लिखा था: 'हम संविधान को कभी स्वीकार नहीं कर सकते। क्योंकि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। मनुस्मृति ही दुनिया में प्रशंसित है। 1949 में।'

यहां इस विरोधाभास को रेखांकित करना भी जरूरी है कि आज उसी प्रतिक्रियावादी सोच के लोग दावा कर रहे हैं कि संविधान अम्बेडकर ने नहीं वीएन राव ने लिखा था। तो अगर राव ने लिखा था जिसे वे ब्राह्मण होने के कारण स्वीकृति और सम्मान दे रहे हैं तो फिर संघ ने इसका विरोध क्यों किया था ?

शकील अख्तर

अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री की दिल्ली में हुई प्रेस कान्फ्रेंस में केवल पुरुष पत्रकार जाएंगे इस पर मोदी सरकार को कोई आपत्ति नहीं हुई। उल्टा जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसमें महिला पत्रकारों को नहीं जाने दिए जाने का सवाल उठाया तो विदेश मंत्री एस जयशंकर गोदी मीडिया और भक्तों, ट्रोलों वाला यह बचकाना तर्क देने लगे कि अपने दूतावास में वे किसे बुलाएं किसे नहीं यह उनका अधिकार है।

मूल समस्या अम्बेडकर के दलित होने से है। बीजेपी आरएसएस के लोग यह मानने को तैयार ही नहीं हैं कि कोई दलित इतना विद्वान हो सकता है कि वह संविधान लिखे। आज भी जो सारा आन्दोलन आरक्षण के खिलाफ होता है उसमें यही कहा जाता है कि इसके द्वारा आए हुए लोग अयोग्य होते हैं।

यह झूठ नफरती विचार फैलाए तो हमेशा से जा रहे हैं मगर पहले इसका असर उतना होता नहीं था। मगर अब जब से इनकी सरकार आई है नफरत का असर दिखने लगा है। और अब तो इतना विस्फोटक हो गया है कि अपनी काबिलियत मेहनत से चीफ जस्टिस आफ इंडिया बने बीआर गवई का अपमान करने के लिए उन पर जूता फेंका जाता है। और कोई पछतावा नहीं, माफी नहीं बल्कि उसे उचित ठहराया जाता है। जूते फेंकने वाले के इंटरव्यू धड़ाधड़ हो रहे हैं। मीडिया उन्हें हीरो की तरह पेश कर रहा है। उत्साहित भक्त ट्रोल और धमकियां दे रहे हैं कि दूसरे जजों के साथ ऐसा होगा। सड़क पर होगा।

डर का माहौल है। सुप्रीम कोर्ट के किसी जज, किसी हाई कोर्ट की हिम्मत नहीं पड़ रही कि जूता मारने वाले के खिलाफ कुछ बोल सके। और आप पक्का मानिए अगर वह कोर्ट में चला गया कि बार कौंसिल ने उसके वकालत करने पर कैसे रोक लगाई है या बार एसोसिएशन ने उसे कैसे निष्कासित किया है तो उसे तुरंत राहत मिल जाएगी। हो सकता है कोई कोर्ट जस्टिस गवई पर ही टिप्पणी करने की गलती उनकी थी।

कुछ भी हो सकता है। जो चाहते थे वह माहौल बना लिया। पहले मुस्लिम के खिलाफ बनाया। मुस्लिम होना ही गुनाह हो गया। उससे जुड़ी हर चीज पर सवाल खड़े कर दिए। खुद प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री स्तर पर। इसके बाद क्या बचता है ?

मगर विरोध केवल भारत के मुस्लिम का। भारत के बाहर के मुस्लिम का नहीं। अभी आपने तालिबान सरकार का प्रकरण देखा। इस तालिबान के खिलाफ देश में कितना प्रोपेगंडा चलाया गया। भाजपा से लेकर गोदी मीडिया तक सबने।

उद्देश्य उनका विरोध नहीं था। असली मकसद था उनके बहाने भारत के मुसलमानों को बदनाम करना। किसी भी दाढ़ी वाले को देखते ही खासतौर से नौजवान को उसे तालिबानी कहने लगते थे। मगर अब जब तालिबानी आए तो उन्हें गार्ड आफ आनर दिया गया।

अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री की दिल्ली में हुई प्रेस कान्फ्रेंस में केवल पुरुष पत्रकार जाएंगे इस पर मोदी सरकार को कोई आपत्ति नहीं हुई। उल्टा जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसमें महिला पत्रकारों को नहीं जाने दिए जाने का सवाल उठाया तो विदेश मंत्री एस जयशंकर गोदी मीडिया और भक्तों, ट्रोलों वाला यह बचकाना तर्क देने लगे कि अपने दूतावास में वे किसे बुलाएं किसे नहीं यह उनका अधिकार है। एकदम गलत।

भारत में भारत के किसी से भेदभाव नहीं होगा का कानून लागू होगा। कल शनिवार को हमने इसके बहुत सारे उदाहरण दिए हैं ट्वीटर फेसबुक पर उन्हें नहीं दोहराएंगे। एक नया उदाहरण। ज्यादातर देशों में जाति का कान्सेप्ट नहीं है तो जातिगत आधार पर भेदभाव का सवाल ही नहीं। लेकिन हमारे यहां एससी एसटी (अत्याचार निवारण) कानून है। अब अगर किसी विदेशी दूतावास के अंदर किसी के साथ जातिगत भेदभाव होता है तो दूतावास इस आधार पर नहीं बच सकता कि यह तो हमारे यहां अंदर हुआ है। करने वाला और पीड़ित दोनों भारतीय होंगे तो करने वाला भारतीय उस देश की आड़ में बच नहीं पाएगा।

बड़ा कानून, प्रिंसिपल लॉ हर जगह लागू होता है। महिला के साथ भारत में कोई भी कहीं भी भेदभाव नहीं कर सकता। और साफ कर दें। क्योंकि खुद उन विदेश मंत्री ने कहा है जो भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) के हैं। सर्वोच्च पद विदेश सचिव रह चुके हैं। सारे कानून मालूम हैं। यह भी कि कोई भी विदेशी जब भारत में है तो उस पर क्रिमिनल और सिविल सभी मामलों में भारतीय कानून लागू होंगे।

एक अनपढ़ दौर आया है कुछ भी बोल दो। नेता बोलते हैं तो वह विदेश मंत्री जयशंकर भी विदेश सेवा से आए हैं, कुछ भी बोल देते हैं। उद्देश्य एक ही है तालिबान को खुश करना। आखिर एकमात्र दोस्त है। कभी ऐसा पाकिस्तान के साथ होता था। भारत से युद्ध में उसके साथ केवल एक ही देश खड़ा होता था। अमेरिका। आज मोदी जी ने हमारी वह हालत कर दी है कि हमारे साथ अभी पाकिस्तान के साथ संघर्ष में केवल एक ही देश था। यही अफगानिस्तान की तालिबान सरकार।

देश हर मोर्चे पर पीछे जा रहा है। बस केवल नफरत में बढ़ रहा है। मुस्लिम से दलित, दलित से पिछड़ा आदिवासी और उसके बाद बचे कितने ? जो बचे हैं सब एक दूसरे के खिलाफ।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार है)

इतिहास की पुनरावृत्ति, तालिबान से मित्रता

■ **तुहिन**

अटल बिहारी वाजपेयी के शासन काल में 26 साल पहले कंधार में भारत के तत्कालीन विदेशमंत्री जसवंत सिंह ने तालिबान के विदेश मंत्री मुट्ठावकिल से समझौता किया था। उद्देश्य था- आईसी-415 एयर इंडिया फ्लाइट (जिसे पाक और तालिबान समर्थित आतंकवादियों ने अगवा किया था), के मुद्दे को सुलझाना। इस समझौते के आधार पर जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को रिहा किया गया और पाकिस्तान भेजा गया।

उस समय भी भाजपा की सरकार थी। 26 साल बाद इसी भाजपा की सरकार ने तालिबान को औपचारिक मान्यता दी है और हाल ही में दिल्ली में तालिबान के वर्तमान विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी के साथ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बैठक की और समझौता हुआ।

अफगानिस्तान में प्रगतिशील सरकार और अफगानिस्तान की प्रगतिशील ताकतों को खत्म करने के लिए अस्सी के दशक में अमेरिकी साम्राज्यवाद ने पाकिस्तान के सहयोग से इस्लामिक कट्टरपंथियों को हथियारबंद करके और भलीभांति प्रशिक्षित कर तालिबान को तैयार किया। तालिबान ने वामपंथी सरकार के पतन के बाद गृह युद्ध में नॉर्दर्न एलायंस को हराकर काबुल में प्रवेश किया।

ये तालिबान कौन है ?: अफगानिस्तान में प्रगतिशील सरकार और अफगानिस्तान की प्रगतिशील ताकतों को खत्म करने के लिए अस्सी के दशक में अमेरिकी साम्राज्यवाद ने पाकिस्तान के सहयोग से इस्लामिक कट्टरपंथियों को हथियारबंद करके और भलीभांति प्रशिक्षित कर तालिबान को तैयार किया। तालिबान ने वामपंथी सरकार के पतन के बाद गृह युद्ध में नॉर्दर्न एलायंस को हराकर काबुल में प्रवेश किया। इसके लिए तालिबान ने नॉर्दर्न एलायंस के नेता 'पंजशीर का शेर' अहमद शाह मसूद सहित कई मुजाहिदीन नेताओं की निर्मम हत्या की। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद सबसे पहले उन्होंने पांचवे अफगान राष्ट्रपति मोहम्मद नजीबुल्लाह और उनके सलाहकारों को काबुल में संयुक्त राष्ट्र संघ के दूतावास से जबरन निकालकर कुत्ते की तरह मारकर लैंप पोस्ट में लटका दिया। उन्होंने देश में मौजूद संग्रहालयों, अन्य धर्मों से संबंधित तमाम स्मारक मूर्तियों को जिनमें विश्व विख्यात बामियान की बुद्ध मूर्ति (जो यूनेस्को की विश्व विरासत थी), भी शामिल थी, को ध्वस्त कर दिया। तालिबान ने अपने पहले कार्यकाल में (जब तक तालिबान भस्मासुर नहीं बन गया और उनके जन्मदाता अमरीकी साम्राज्यवाद उनसे नाराज नहीं हो गए) 15 अगस्त 2021 में अमेरिका द्वारा उनको काबुल का शासन सौंपने के बाद दूसरे कार्यकाल में घोर प्रगति विरोधी, मध्य युगीन प्रतिक्रियाशील रूढ़िवादी धार्मिक कानूनों और घोर महिला विरोधी कानूनों को लागू किया। तालिबान ने बहुत क्रूर मध्ययुगीन तरीके से अपने विरोधियों, बड़ी संख्या में महिलाओं, बच्चों को मार डाला और इस तरह से एक प्रगतिशील शिक्षित अफगानिस्तान को पिछड़ेपन ज़हालत और बर्बादी में धकेल दिया। जब तक पाकिस्तान के धार्मिक सैन्य केंद्र से इसकी गलबहियां चलती रही तब तक सब ठीक था। अब अफगान तालिबान द्वारा पैदा किए गए तहरीक-ए-तालिबान, जो पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी गतिविधियां कर रहा है उससे पाकिस्तान को परेशानी हो रही है। इसलिए अब पाकिस्तान के हुक्मरान और अफगानिस्तान के तालिबानी शासकों के संबंधों में खटास आ गई है। दूसरी ओर, चूंकि भारत की मोदी सरकार विदेश नीति के मामले में न केवल अपने पड़ोसी देशों से बल्कि दुनिया के अधिकांश देशों से अलग-थलग पड़ गया है। इसीलिए उसे पाकिस्तान को पटखनी देने के लिए एक सहयोगी की जरूरत है। भले ही वह घोर धार्मिक कट्टरपंथी प्रगति-विरोधी तालिबान शासक ही क्यों न हो।

तालिबान को आतंकवादी जियोनवादी इजरायल और उसके संरक्षक अमेरिकी साम्राज्यवाद द्वारा गज़ा को श्मशान बनाने में या मध्य पूर्व के अन्य देशों में और दुनिया भर में उसके आका अमेरिकी शासकों द्वारा इस्लामोफोबिया के नाम पर शोषण, लूट या दमन से कुछ लेना-देना नहीं है। इसलिए उसको भारत के घोर जन-विरोधी और मुस्लिम-विरोधी संघ परिवार या उसके मार्गदर्शन में संचालित भाजपा सरकार से हाथ मिलाने में तो खुशी ही होगी और दूसरी ओर देखिए दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने फासीवादी संगठन ऋस्स को भी कोई समस्या नहीं है। इस्लाम का झंडा फहराकर देश को मध्य युग में ले जाने वाले तालिबान से मित्रता करने में। कारण यह है कि चाहे अफगानिस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाकर बर्बाद करने वाले आतंकवादी तालिबान हो या मनुस्मृति आधारित हिंदुराष्ट्र के नाम पर देश को लूटने वाला संघ परिवार हो दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों कॉरपोरेट पूंजीवादी और दुनिया की जनता के दुश्मन नंबर एक अमेरिकी साम्राज्यवाद के अनुगत हैं और घोर प्रगति-विरोधी, समाज-विरोधी और मानवता विरोधी हैं।

ललित सुरजन की कलम से

विकलांग चेतना का दौर

'सब जानते हैं शास्त्रीजी की मृत्यु ताशकंद में हुई थी। यह भी कोई छुपी बात नहीं है कि शास्त्रीजी को दिल की बीमारी थी। ताशकंद की जनवरी की हाड़ जमा देने वाली ठंड का उनकी सेहत पर क्या असर हुआ होगा यह सिर्फ अनुमान का विषय है, लेकिन जिस सोवियत संघ ने ताशकंद में सुलह वार्ता के लिए लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान दोनों को आमंत्रित किया था, उसकी कोई दिलचस्पी शास्त्रीजी की मृत्यु में होगी, यह कैसे और क्यों माना जाए ? अपनी धरती पर किसी मेहमान की मृत्यु सोवियत सरकार के लिए अप्रत्याशित और दुखद घटना ही रही होगी। दूसरी तरफ शास्त्रीजी की मृत्यु से भारत में किसको लाभ होता, यह भी एक नाहक प्रश्न है। याद रखना चाहिए कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार में मोरारजी देसाई वरिष्ठतम नेता थे तथा नेहरूजी व शास्त्रीजी दोनों की मृत्यु के बाद वे प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे। इस तथ्य को ध्यान में रखेंगे तो अनर्गल आरोप का उत्तर अपने आप मिल जाएगा।'

(देशबन्धु में 15 अक्टूबर 2015 को प्रकाशित)

https://lalitsurjan.blogspot.com/2015/10/blog-

गुरवाणी विचार

सांस सांस सिमरो गोविंद

माटी को पुतरा कैसे नचत है,
देखै देखै सुनै बोलै दउरिओ फिरत है (रहाओ)
जब कछ पावै तब गरब करत है
माया गई तब रोवन लगत है
मन बच करम रस कसहि लुभाना
बिनस गया जाये कहुं समाना
कह रविदास बाजी जग भाई,
बाजीगर सओ मोहि प्रीति बन आई।।

गुरवाणी की ये पंक्तियां गुरुग्रंथ साहिब में 487 अंग पर सुशोभित है। इन पंक्तियों द्वारा भक्त रविदासजी मानव के आदतों का बयां कर रहे हैं कि हर इंसान जब कुछ धन दौलत की प्राप्ति कर लेता है तब वह उछल-कूद करने लगता है और उसे घमंड आ जाता है कि उसने अपने बलबूते पर इतना कुछ बना लिया। धन दौलत, जमीन-जायदाद सब उसने उसकी मेहनत से कमाया है। अधिक धन होने पर उसे कई तरह की लत लग जाती है। सारांश यह है कि अलग-अलग तरह से धन प्राप्ति पर नाचने-कूदने लगता है। वह यह सब भूल जाता है कि ये जो कुछ भी उसने प्राप्त किया है वह प्रभु की उस पर असीम कृपा से प्राप्त हुआ है। मेहनत तो एक मजदूर भी उससे ज्यादा करता है, पर उस पर उतनी प्रभु की कृपा न हो पाने पर ही उसे ज्यादा कुछ नहीं मिल पाता।

याद रहे कि हमें अपने मन की ताल पर कभी नाचना नहीं है। प्रभु परमात्मा की ताल पर गुरमुख बनकर सत संतोख से अपना जीवनयापन करना है। हमारा एक सूत्रीय कार्यक्रम होना चाहिए कि प्रभु परमात्मा की सिमरन बंदगी में मन रमाकर रखना है। मानुस जनम पाकर इस संसार में आने का हमारा केवल यही मकसद होना चाहिए कि हम हर वक्त हाथ-पांव से अपना और अपने परिवार का उदरपोषण कर, अपनी कमाई का दसबंध निकालकर जरूरतमंदों की मदद में खर्च करना है। हर काम करते वक्त हमारा मन हमेशा उस निरंकार से जुड़े रहना चाहिए। याद रहे कि हमारे पूर्व जनमों के किसी पुण्य कर्मों के फल के कारण यह जीवन मिला है,प्रभु परमात्मा की हम पर विशेष कृपा दृष्टि होने के कारण हमें मानव जीवन की प्राप्ति हुई है-

भई परापति मानुख देहुरिया,
गोविंद मिलन के ऐहो तेरी बरिया
अवर काज तेरो किते न काम,
मिल साध संगति अज केवल नाम।।

पता नहीं हमें मानुख देही कब मिलेगी, मिलेगी भी या नहीं। अतएव हमें प्रभु सिमरन बंदगी मन लगाकर प्रभु परमात्मा की कृपा दृष्टि प्राप्त कर लेनी है। प्रभु परमात्मा की हम पर कृपा दृष्टि हो जाने पर फिर हमें किसी बात की कमी नहीं रहेगी। अगर हमने मानव जीवन योंहि व्यर्थ गंवा दिया, सांसारिक मोह माया में फंसे रहे तो बाद में पछताना पड़ेगा।

जिस तरह किसी दीवार के किनारे सीढ़ी लगाकर छत पर चढ़ने का प्रयास कर रहे हों और आखिरी सीढ़ी से हमारा पैर फिसल जाए तो सीधे जमीन पर आ गिरेंगे। ठीक उसी तरह अगर हमने मानव जीवन पाकर भी इसका भरपूर लाभ नहीं उठाया। अर्थात प्रभु भक्ति में मन नहीं लगाया तो हमें बहुत ही ज्यादा पछताना पड़ेगा। और फिर चौरासी जनमों के चक्कर में किसी भी निकृष्ट योनि में जनम लेना पड़ सकता है, अत: अभी से इस वक्त से समय रहते प्रभु सिमरन में मन रमाना चाहिए। रविदास जी भी इन शब्दों द्वारा यही समझा रहे हैं कि पूरा जीवन मानव कठपुतली की तरह नाचता है, लक्ष्य को पाने के लिए इधर-उधर दौड़ता है, कुछ पाने पर अहंकार और खोने पर विलाप करता है। जब वह उसका इस संसार से विदा होने का समय आता है तब ना जाने कहां चला जाता है। रविदास जी कह रहे हैं कि हमें उस बाजीगर प्रभु से प्रीत लगानी चाहिए-

सांस सांस सिमरो गोविंद।
मन अंतस की उतरे चिंद।।

इंदर सिंह आहूजा

आपके पत्र

अमेरिका परस्ती का शिकार हुआ नोबेल शांति पुरस्कार

शायद यह पहला मौका था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नोबेल शांति पुरस्कार के लिए तड़फते दिखे। जिनको दुनिया के बहुसंख्यक देश युद्ध रोपने और उस देश को बर्बाद कर लूटने वाले देश के नाम से जानते हैं। ये जानकर लोगों को खुशी हुई कि वे इस महत्वपूर्ण पुरुस्कार के काबिल नहीं पाए गए। यह पुरस्कार जिन महोदया को दिया गया और उन्हें लोकतंत्र के उद्धारक के रूप में पेश किया गया है। सरसरी तौर पर उनकी जो जीवन गाथा सामने आई उसे पढ़कर लोग अगले साल के लिए राहुल गांधी के संघर्ष और कामयाबी के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की उम्मीद कर बैठे। जबकि इन मोहतरमा के बारे में जानकारों की जो ख़बर आई वह चिंताजनक है और ऐसे हालात सामने आ रहे हैं कि लोग अब इस महत्वपूर्ण पुरुस्कार को भी संदेहास्पद मान रहे हैं।

मारिया मचाडो की राजनीति हिंसा में डूबी हुई हैं। उन्होंने सदैव विदेशी हस्तक्षेप की मांग की है, यहां तक कि गाजा के विनाश के सूत्रधार, इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से सीधे अपील की है कि वे 'आज़ादी' के नाम पर बमों से वेनेजुएला को 'आज़ाद' कराने में मदद करें। उन्होंने प्रतिबंधों की मांग की है, युद्ध का वह मौन रूप जिसके प्रभावों ने—जैसा कि द लैंसेट और अन्य पत्रिकाओं में प्रकाशित अध्ययनों से पता चला है—युद्ध से ज़्यादा लोगों की जान ली है, और पूरी आबादी के लिए दवा, भोजन और ऊर्जा की आपूर्ति ठप कर दी है।

ये वही मारिया माचाडो हैं जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने स्वतंत्रता और लोकतंत्र की योद्धा कहा है। और मुफ्त में नहीं कहा है। ये वही मारिया माचाडो हैं जिन्होंने कैरिबिया में अमेरिकी युद्धपोतों की तैनाती के ट्रंप के ऐलान का बाहें फैलाकर स्वागत किया। ये वही मारिया माचाडो हैं जिन्होंने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए वेनेजुएला की संप्रभुता प्लेट में सजाकर अमेरिका के सामने रख दी। ये वही मारिया माचाडो हैं जिन्होंने कहा अमेरिका को हमारे देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगा देना चाहिए। और तो और अमेरिका की शह पर उन्होंने अवैध तरीके से एक अंतरिम सरकार तक की स्थापना कर डाली जिसकी राष्ट्रपति वो खुद बन बैठीं।

अमेरिका और नेतन्याहू की नीतियों पर फिदा मारिया माचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार देकर नोबेल समिति पर अब संदेह और पक्षधरता का आरोप लग रहा है। सच बात ये है कि इससे खुद वेनेजुएला के लोग अवाक हैं। मारिया माचाडो को वेनेजुएला में अमेरिका की घोषित पिट्ठू माना जाता है इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप इज़राइल समर्थक मारिया माचाडो को नोबल शांति पुरस्कार दिए जाने पर जश्न मना रहे हैं। अप्रत्यक्षत: यह पुरस्कार अमेरिकी नीतियों को समर्पित नज़र आ रहा है।

ये वही मारिया माचाडो हैं जो चाहती हैं कि वेनेजुएला के प्राकृतिक संसाधनों को अमेरिका समर्थित बड़े कॉरपोरेट्स के हवाले कर देना चाहिए। छोटे कारोबारियों से नफ़रत करने वाली मारिया माचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार मिलना एक ऐसी घटना है जिसपर खुद वेनेजुएला के लोग स्तब्ध हैं। इसीलिए मिशेल एलनर कह रहे हैं कि जब मारिया कोरिना मचाडो जैसे दक्षिणपंथी नोबेल पुरस्कार जीतते हैं, तो 'शांति' का कोई मतलब नहीं रह जाता। वेनेजुएला के ग़रीब, साधारण और लोकतंत्र पसंद लोगों की नजरों में मारिया माचाडो अमेरिका की दलाल हैं। नोबेल कमेटी ने उन्हें शांति का पुरस्कार देकर डोनाल्ड ट्रंप को खुश कर दिया है। वो सिर्फ नाटक कर रहे हैं नाराजगी का। यहां ट्रम्प की खुशी मायने नहीं रखती है। यक़ीनन दुनिया के इस सबसे बड़ा पुरस्कार ने अपनी गरिमा चकनाचूर कर दी है।

-सुसंस्कृति परिहार

प्रकाशक, मुद्रक : राजीव रंजन श्रीवास्तव द्वारा पत्रकार प्रकाशन प्रा. लि. के लिए 506, आई.एन.एस. बिल्डिंग, 9, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित एवं बीएफएल इंफोटेक लि., सी 9, सेक्टर-3, नोएडा से मुद्रित। सम्पादक : राजीव रंजन श्रीवास्तव, (पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार)। आर.एन.आई. नं. DELHIN/2008/24216. दिल्ली कार्यालय :फोन: 011-23718195,23357784, फैक्स: 011-43581404, नोएडा कार्यालय: फोन: 0120-4114404 फैक्स: 0120-4273770
ई-मेल: deshbandhudelhi@gmail.com वेब: www.deshbandhu.co.in

चिंतन

चीन-अमेरिका में फिर शुरू होगी आर्थिक जंग

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर 'आर्थिक जंग' को भड़काते हुए चीन पर 100% अतिरिक्त शुल्क लगा दिया। इससे दोनों देशों के बीच 'ट्रेड वार' और तेज होगी। दोनों देशों के बीच अधिकांश व्यापार ठप होने की आशंका है। दूसरी तरफ, ट्रंप का कहना है कि यह कदम चीन द्वारा दुर्लभ धातुओं के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों के जवाब में उठाया है। वहीं, चीन ने भी इसका कड़ा विरोध किया और कहा कि वह टकराव नहीं चाहता, लेकिन उकसाए जाने पर जवाबी कार्रवाई करेगा। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि वे टैरिफ युद्ध से डरते नहीं हैं और अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे। बता दें कि रेयर अर्थ मिनरल्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल स्मार्टफोन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक कार, सेमीकंडक्टर या चिप से जुड़े उद्योगों, पानी से चलने वाले टरबाइन और जेट इंजन जैसे उत्पादों में किया जाता है। इस टकराव का असर पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर पड़ेगा। चीन का दुनिया की 70% रेयर अर्थ सप्लाई और 90% प्रोसेसिंग पर नियंत्रण है। ऐसे में अमेरिका या यूरोप के किसी देश के लिए इन खनिजों के बिना तकनीकी उत्पादन जारी रखना असंभव है। इस कदम से टेक कंपनियों, ऑटोमेकर्स और डिफेंस सेक्टर की लागत कई गुना बढ़ेगी। शुक्रवार को ट्रंप ने चीन पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की। नया टैरिफ 1 नवंबर से प्रभावी होगा। चीन से अमेरिका में आने वाले सामानों पर पहले से 30% टैरिफ है। ऐसे में चीन पर कुल 130% टैरिफ लगेगा। इससे पहले ट्रंप ने चीन पर 145% टैरिफ लगाया था, तब चीन ने यूएस पर 125% टैक्स लगाया था। बातचीत के बाद अमेरिका ने टैरिफ 30% और चीन ने 10% किया था। कुछ समय की शांति के बाद अब दोनों देश फिर ट्रेड वॉर की कगार पर खड़े हैं। इस फैसले से इसी माह होने वाली अमेरिका और चीन के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात भी अधर में लटक सकती है। भारत के संदर्भ में इसे देखें तो अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध के बीच रूस से जारी तेल खरीद पर नाराजगी के चलते भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, जिसका भारत ने कड़ा विरोध करते हुए उसे पूरी तरह से अनुचित और अविवेकपूर्ण बताया है। हालांकि चीन-अमेरिका के बीच ट्रेड वार में भारतीय निर्यातकों को फायदा हो सकता है। चीन से जाने वाला सामान अमेरिका में महंगा होगा। इससे अब अमेरिकी बाजार में चीन की जगह भारत ले सकता है। इससे कपड़ा, खिलौना और इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे सेक्टरों में निर्यात बढ़ेगा। इससे पहले चीन ने रेयर-अर्थ एलिमेंट्स और संबंधित वस्तुओं पर निर्यात नियंत्रण उपाय जारी किए थे। चीन के पास दुनिया के 17 प्रमुख रेयर अर्थ खनिज हैं। पहले वह इनमें से 7 पर नियंत्रण रखता था, उसने 5 और पर निर्यात प्रतिबंध लगा दिए। अब चीन का नियंत्रण 12 पर हो गया। अब कोई विदेशी कंपनी अगर इन खनिजों का इस्तेमाल करेगी, तो उसे चीनी सरकार से लाइसेंस लेना होगा। तकनीक के रथ पर सवार 21वीं शताब्दी का उभार बहुत हद तक रेयर अर्थ मिनरल्स पर टिका है। लेकिन इसमें महारत रखने वाले चीन ने जैसे ही निर्यात नियमों पर सख्ती लागू की तो अमेरिका ने भी ड्रैगन के सभी उत्पादों पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। इससे दुनिया के दो बड़े देशों के बीच 'आर्थिक जंग' गहराने का खतरा बढ़ गया है। यदि यह जंग और बढ़ती है तो सभी देशों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

स्वास्थ्य

मुनीष भाटिया

त्योहारों की मिठास में घुल रहा मिलावट का ज़हर

भारत त्योहारों का देश है, जहाँ हर पर्व खुशियों, रिश्तों और मिठास का प्रतीक माना जाता है। दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन या होली, हर उत्सव में मिठाइयाँ हमारे भावनात्मक जुड़ाव का हिस्सा बन जाती हैं। कोई रिश्ता बिना मिठाई के अधूरा लगता है, क्योंकि यही मिठाई हमारी संस्कृति की पहचान है। दुखद सच्चाई यह है कि आज यही मिठाई धीरे-धीरे ज़हर में बदलती जा रही है। हर त्योहारी सीजन में मिलावटी मिठाइयों और नकली मावे का कारोबार चरम पर पहुँच जाता है, जिससे न केवल त्योहारों की पवित्रता प्रभावित होती है बल्कि आम लोगों का स्वास्थ्य भी गंभीर खतरे में पड़ जाता है। त्योहारों के समय मिठाइयों की मांग अचानक कई गुना बढ़ जाती है। बढ़ती मांग के बीच कुछ व्यापारी लालच के चलते शुद्धता की जगह सस्ते और हानिकारक विकल्पों का सहारा ले लेते हैं। असली दूध या खोये की जगह सिंथेटिक मावा बनाया जाता है, जिसमें यूरिया, डिटर्जेंट, तेल और स्टार्च जैसी चीजें मिलाई जाती हैं। यह दिखने में भले ही असली लगे, पर शरीर के लिए जहर साबित होता है। विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसे पदार्थ लिवर, किडनी और दिल पर सीधा असर डालते हैं और लंबे समय में कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बन सकते हैं। त्योहारों से पहले देश के अलग-अलग राज्यों में खाद्य विभाग और पुलिस द्वारा भारी मात्रा में नकली मावा और दूध की खेप पकड़ी जाती हैं। पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली-एनसीआर, आगरा, मथुरा, कानपुर, झांसी, ग्वालियर और भोपाल में लाखों लीटर मिलावटी दूध और सैकड़ों किलो नकली मावा पकड़ा गया है। कई बार ये खेपें राज्यों की सीमाओं के पार से ट्रक भरकर लाई जाती हैं, ताकि त्योहारों के समय अचानक बढ़ी हुई मांग को पूरा किया जा सके। यह स्पष्ट होता है कि त्योहारों की भीड़-भाड़ और बढ़ते उपयोग ने मिलावटखोरों के लिए एक बड़ा और संगठित बाजार तैयार कर दिया है, जहाँ लालच के आगे न तो सेहत की चिंता बची है और न ही नैतिकता की परवाह। आज मिठाइयों की चमक जितनी बढ़ी है, उतनी ही उसमें खतरे की परतें भी चढ़ी हैं। बाजारों में बिकने वाली चमकीली बर्फी और रंगीन मिठाइयाँ आकर्षक ज़रूर लगती हैं, लेकिन अक्सर इनमें कृत्रिम रंगों और रसायनों का प्रयोग किया जाता है। ये रंग खाद्य उपयोग के लिए प्रमाणित नहीं होते। इन्हें वस्त्र या पेंट उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है, पर सस्ते दामों में आसानी से मिलने के कारण कई व्यापारी इन्हें मिठाइयों में मिला देते हैं। ये रंग शरीर में एलर्जी, पेट के संक्रमण, त्वचा संबंधी रोग और दीर्घकाल में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां उत्पन्न कर सकते हैं। भारतीय मिठाइयों की पहचान कही जाने वाली 'चांदी का वर्क' भी अब शुद्धता की गारंटी नहीं रह गया है। परंपरागत रूप से यह वर्क असली चांदी से बनाया जाता था, जो शरीर के लिए हानिकारक नहीं है। परंतु अब कई जगहों पर एल्यूमिनियम से बने नकली वर्क का उपयोग हो रहा है, जो सस्ता होता है लेकिन स्वास्थ्य के लिए बेहद घातक है। यह एल्यूमिनियम शरीर के तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाता है और लंबे समय तक सेवन करने पर याददाश्त कमजोर होने, सिरदर्द और न्यूरोलॉजिकल विकारों का कारण बन सकता है। कई बार मिठाई बनाने वाली इकाइयों पर छापेमारी भी होती है और मिलावटी मावा या रंगीन पदार्थ जब्त किए जाते हैं। परंतु सच्चाई यह है कि ये कार्रवाइयाँ अक्सर सीमित और दिखावटी रह जाती हैं। कई बार पकड़े गए व्यापारी मामूली जुर्माना भरकर फिर वही कारोबार शुरू कर देते हैं। स्थायी सुधार तब तक संभव नहीं, जब तक खाद्य सुरक्षा कानूनों को सख्ती से लागू न किया जाए और दोषियों को कठोर दंड न मिले। मिलावटी मिठाइयां सिर्फ स्वाद की धोखाधड़ी नहीं, बल्कि जीवन के साथ खिलवाड़ हैं। बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह और भी खतरनाक साबित होता है। त्योहारों के मौसम में खाद्य सुरक्षा विभाग को राज्य स्तर पर विशेष अभियान चलाने चाहिए। प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ाई जानी चाहिए ताकि नमूनों की जांच तेज़ी से हो सके। दोषियों पर सख्त दंड और सार्वजनिक नामांकन का प्रावधान होना चाहिए। साथ ही, ग्रामीण और शहरी इलाकों में जनजागरूकता कार्यक्रम चलाकर लोगों को बताया जाए कि असली और नकली मावे में अंतर कैसे पहचाना जाए। यदि हम मिलावटी मिठाइयों के मोह में स्वास्थ्य खो दें, तो त्योहारों की खुशी का अर्थ ही समाप्त हो जाएगा। कुछ पल की नकली मिठास का असर वर्षों तक शरीर पर भारी पड़ता है। आज आवश्यकता है सामूहिक प्रयास की, सरकार, व्यापारी और उपभोक्ता तीनों की साझा जिम्मेदारी ही इस संकट का स्थायी समाधान बन सकती है। शुद्धता से भरा एक छोटा टुकड़ा मिठाई, नकली चमक से भरे किलो भर ज़हर से कहीं बेहतर है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

संदेश
राजीव खंडेलवाल

वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाना विश्व के सभी लोकतांत्रिक (तथाकथित) तानाशाहों के लिए स्पष्ट संदेश है। जो भी व्यक्ति लोकतंत्र को बचाने और उसे सशक्त बनाने के लिए कदम उठाएगा, विश्व उसके शांतिपूर्ण प्रयासों को नमन करेगा, चाहे वह सत्ता के विरुद्ध ही क्यों न खड़ा हो। वास्तव में नोबेल शांति पुरस्कार का उद्देश्य भी यही है-शांति को बढ़ावा देना, मानवाधिकारों की रक्षा करना और संघर्षों के समाधान में योगदान देना। इस बार नोबेल समिति ने न केवल एक सच्चे लोकतंत्र सेवी को सम्मानित किया, बल्कि स्वयं "नोबेल" की गरिमा और प्रतिष्ठा भी अक्षत रखी।

नोबेल पुरस्कार ने अपनी इज्जत बचाई

नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने 10 अक्टूबर को ओस्लो में वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार देने की घोषणा की है। यह सम्मान उन्हें वेनेजुएला के नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा और तानाशाही से लोकतंत्र की ओर शांतिपूर्ण संक्रमण के लिए किए गए उनके अथक प्रयासों के कारण दिया गया। वस्तुतः मारिया को यह पुरस्कार दिया जाना विश्व के सभी लोकतांत्रिक (तथाकथित) तानाशाहों के लिए स्पष्ट संदेश है। जो भी व्यक्ति लोकतंत्र को बचाने और उसे सशक्त बनाने के लिए कदम उठाएगा, विश्व उसके शांतिपूर्ण प्रयासों को नमन करेगा, चाहे वह सत्ता के विरुद्ध ही क्यों न खड़ा हो। वास्तव में नोबेल शांति पुरस्कार का उद्देश्य भी यही है-शांति को बढ़ावा देना, मानवाधिकारों की रक्षा करना और संघर्षों के समाधान में योगदान देना। नोबेल पुरस्कार में एक मिलियन अमेरिकन डॉलर अर्थात 8.30 करोड़ रुपये की राशि भी मिलेगी। अंततः नोबेल पुरस्कार की जीत हुई।

जब से डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ष 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार पाने की "हुंकार" लगाते हुए स्वयंभू दावेदारी भरी थी, तभी से ट्रम्प की दादागिरी, सनक व ''टैरिफ वार'' के ''हथियार'' का उपयोग कर विश्व में ट्रम्प के बढ़ते दबाव के कारण "नोबेल पुरस्कार" बहुत डरा हुआ ''असहज'' हो गया था। एक वजह यह भी थी कि "नोबेल" किसी "कसाई के खूंटे से बंधने" के लिए तैयार नहीं था और न ही घुटने टेकने के लिए तैयार था। क्योंकि "नोबेल" तो "शांति का प्रतीक" है, जिसे कोई "शांति दूत" ही प्राप्त करने का अधिकारी हो सकता है। जबकि विश्व के विभिन्न हिस्सों में चल रहे अधिकांश युद्धों में विश्व का "दादा" बनने की चाह में ट्रंप की भूमिका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रही है। ट्रम्प पहले युद्ध को भड़काने और बढ़ाने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं, और फिर "चौधरी" बनकर ''चौधराहट'' कर सैन्य शक्ति और बमबारी के दम पर शांति स्थापित करने की नौटकीं कर "नरेटिव" बनाने की कोशिश करते हैं। ट्रंप की यह तथाकथित "शांति स्थापना" असल में 24 कैरेट की नहीं, बल्कि 5 माइक्रॉन गोल्ड-पॉलिश वाली थी। दिखने में चमकदार, पर असली नहीं। सच तो यह है कि अगर अमेरिका अपने सैन्य उद्योगों व सामानों के लिए बाजार के लिए युद्ध न भड़काए, तो विश्व में स्वयंमेव शांति बनी रह सकती है। आखिर "जिसका धंधा ही कफन और ताबूत का हो, वह शांति कैसे चाहेगा!" यही कारण है कि इस बार वास्तव में शांति और लोकतंत्र दोनों की जीत हुई है। पिछले छह महीनों से डोनाल्ड ट्रंप हर मंच पर जबरदस्त लॉबिंग कर प्रयासरत थे कि उन्हें 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मिल जाए। ट्रम्प ने दूसरे देशों पर भी जबरदस्ती दबाव बनाया। इतने अति आत्मविश्वास में थे कि उन्होंने वाईट हाउस में नोबेल पुरस्कार मिलने की आशा में स्वागत कार्यक्रम की तैयारी भी चालू कर दी थी। उनका तर्क था कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान के बीच युद्धविराम से लेकर विश्व के कई हिस्सों में "शांति स्थापित करने" के सफल प्रयास किए हैं। अमेरिका के प्रतिष्ठित समाचार पत्र "द गार्जियन" के अनुसार, ट्रंप नोबेल पुरस्कार पाने की दृष्टि से इतने मोहग्रस्त हो गए थे कि उन्होंने अपनी विदेश नीति ही इस उद्देश्य से गढ़ ली थी। परंतु ट्रंप यह भूल गए कि "नोबेल"

पाने के लिए सिर्फ युद्धविराम नहीं, बल्कि मन और मंशा दोनों की शांति जरूरी है। अतः ''ट्रंप कार्ड'' (तुरूप का एक्का) नहीं चला। ट्रंप ने "नई टैरिफ नीति" लाकर "टैरिफ वॉर" छेड़ दी। यानी तथाकथित शांति की बात करते-करते नई ''अशांति'' पैदा कर दी। नोबेल के लिए जिस शांति की आवश्यकता है, वह सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि प्रत्येक राजनैतिक, संवैधानिक, व्यापारिक, सामाजिक, धार्मिक समस्त क्षेत्रों में। सच तो यह है कि "कच्चे घड़े में पानी भरने के प्रयास में घड़ा बिखर जाता है"। हुआ यही। आज चर्चा इस बात की नहीं कि नोबेल पुरस्कार किसे मिला, बल्कि इस बात की ज्यादा है कि ट्रंप को नहीं मिला! यही असल में "नोबेल पुरस्कार" की जीत है, जिसने ट्रंप के बनाये "नरेटिव" को पूरी तरह ध्वस्त कर अपनी सर्वकालीन प्रतिष्ठा बनाये रखी। वैसे विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्ष प्रेसिडेंट ट्रंप द्वारा नोबेल पुरस्कार की ''गंभीर दावेदारी करने'' नोबेल पुरस्कार की महत्ता व प्रतिष्ठा पर मोहर लगी। "नोबेल पुरस्कार" डोनाल्ड ट्रंप जैसे व्यक्ति के पास न जाकर सचमुच में उसने अपनी इज्जत बचा ली। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि "चक्की में से साबुत निकल आने वाले" ट्रंप ने भारत में अपने संपर्कों के माध्यम से किस तरह का दबाव बनाने की कोशिश की थी। परंतु अंततः वे औंधे मुंह ही गिर पड़े। "ऑपरेशन सिंदूर" के बाद भारत-पाक युद्ध विराम का श्रेय लेने के लिए उन्होंने लगभग 50 बार दावा किया। यद्यपि भारत ने अधिकतम रूप से इससे इंकार किया। परन्तु प्रधानमंत्री मोदी ने उनका नाम लेकर कभी सीधा खंडन नहीं किया। ट्रंप के "पालित जमूरे" पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ परस्पर घोर विरोधी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ट्रंप को नोबेल पुरस्कार दिए जाने के लिए नामजद किया। इसी प्रकार अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव सहित पांच देशों ने भी उसी तर्ज पर उनका समर्थन किया। अहा! "सूप बोले तो चलनी भी बोले, जिसमें बहत्तर छेद"! ''विश्व का सबसे पुराना'' लोकतंत्र वाला देश अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने "विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र" देश ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के विरुद्ध की गई सैन्य करवाई से टैरिफ वार की धमकी द्वारा "बातचीत की टेबल" पर लाने का दावा कर अपने लिए "नोबेल" का रास्ता खोला। परंतु सच यह है कि "कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय के मद में चूर" ट्रंप ने खुद को "पीस प्रेसिडेंट" बताते हुए नौ महीने के कार्यकाल में "आठ युद्धों को समाप्त करने" का झूठा दावा किया। लोकतंत्र का सीधा संबंध शांति से होता है। यही कारण है कि तानाशाही शासक वाला देश वेनेजुएला में लोकतंत्र की रक्षा हेतु 30 वर्षों से संघर्षरत मारिया को यह पुरस्कार मिला।

आज जब हम चारों ओर नजर दौड़ाते हैं, तो पाते हैं कि लोकतांत्रिक देशों में भी "प्राकृतिक शांति" नहीं, बल्कि "दादागिरी की शांति" हावी है। लोकतंत्र भी आजकल निर्वाचित निरंकुश में बदल गया। ट्रंप अपनी "दादागिरी" स्थापित करने के लिए कभी युद्ध करवाते हैं, कभी रुक जाते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार पाने के लिए आपको "शांति दूत" बनना पड़ता है, न कि ''शांति का व्यापारी''। लेकिन आज की विश्व व्यापी राजनीति में भी ''परसेप्शन और ब्रांडिंग'' का बोलबाला है। इसलिए ट्रंप पहले युद्ध के मैदान ''सजाते'' हैं, दो देशों के बीच तनाव को बढ़ाते हुए युद्ध के दुष्चक्र में झोंक देते हैं, फिर कैमरे के सामने शांति के ''मसीहा'' बनने का असफल प्रयास करते हैं। इस बार नोबेल समिति ने न केवल एक सच्चे लोकतंत्र सेवी को सम्मानित किया, बल्कि स्वयं "नोबेल" की गरिमा और प्रतिष्ठा भी अक्षत रखी। इसलिए कहा जा सकता है। "नोबेल जीता नहीं, बल्कि इस बार सचमुच 'शांति' ने जीता है।"

(लेखक पूर्व बैतूल नगर सुधार न्यास अध्यक्ष हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया **haribhoomi@gmail.com** पर दे सकते हैं।

हमारा वास्तविक स्वभाव क्या है?

संकलित

दर्शन

जीवन क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? ये प्रश्न जितने सरल लगते हैं, उतने ही रहस्यमय भी हैं। इन्हें जितना समझने की कोशिश करते हैं, वे उतने ही उलझते जाते हैं। दरअसल, जानना हृदय का विषय नहीं है, जीना हृदय का विषय है। रहस्य समझने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए हैं। जीवन के रहस्य को जीना ही आनंद है। ज्ञान प्राप्त होने से पहले लगता है कि हममें अज्ञान नहीं है। लेकिन जैसे-जैसे ज्ञान बढ़ता है, तो लगता है हममें काफी अज्ञान है। एक कहावत है, आत्मज्ञान होने से पहले लकड़ी काटो और पानी भर कर लाओ। आत्मज्ञान के बाद भी, लकड़ी काटो और पानी भर कर लाओ। अंतर इतना है कि पहले हम दुखी रहकर काम करते थे। लेकिन आत्मज्ञान के बाद वही कार्य आनंद से करते हैं। हमारा जीवन कितना उत्तम है, यह हमारे मन की अवस्था पर निर्भर करता है। हम वही सुनना पसंद करते हैं, जिसमें हमारी रुचि होती है। जब हमारा जीवन प्रेम में केंद्रित होता है, तो हम प्रेम के बारे में जानना चाहते हैं। जब जीवन बच्चों के इर्द-गिर्द घूमता है, तो हम बच्चों के बारे में ही सुनना चाहते हैं। जो हमारी इच्छा हो, हमें वही सुनना पसंद है और हमारी इच्छाओं का कभी अंत ही नहीं होता।

मृत्यु अटल है, जो समझते हैं, वे प्रसन्न रहेंगे

संकलित

प्रेरणा

एक प्रवचन के बाद एक व्यक्ति तुकाराम के पास आया और बोला कि आप इतने आनंद में और शांत कैसे रहते हैं? तुकाराम जी ने उस व्यक्ति की बातें ध्यान से सुनीं और अचानक बोले कि भाई सात दिनों के बाद तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। ये बात सुनते ही तुरंत ही उस व्यक्ति की हालत खराब हो गई। क्योंकि वह मानता था कि तुकाराम जी बहुत सिद्ध संत हैं, इनकी बात गलत नहीं हो सकती है। उसने तय किया कि जीवन के सात दिन बचे हैं तो अब आनंद के साथ ही जीना चाहिए। उस व्यक्ति ने अपनी जीवन शैली ही बदल दी। सभी के साथ प्रेम से रहने लगा। उसने जो गलतियां की थीं, उनमें सुधार किया। जिन लोगों को उसकी वजह से नुकसान हुआ था, उनसे क्षमा मांगी। हर पर प्रसन्न रहने लगा। इसी तरह सातवां दिन आ गया। उनसे सोचा कि अंतिम दिन अपने गुरु से भी मिल लेना चाहिए। वह तुरंत ही तुकाराम जी के पास पहुंच गया। उसने कहा कि जैसा आपने कहा था कि मेरी सात दिन बात मृत्यु होगी। आज सातवां दिन है। अंतिम दिन मैं आपसे मिलने आया हूं। तुकाराम जी ने उसकी बात सुनी और कहा कि जुग-जुग जियो। ये बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा कि गुरु जी मैं अगले दिन तो मैं मर जाऊंगा तो आप ऐसा आशीर्वाद क्यों दे रहे हैं? तुकाराम जी ने कहा कि मैंने तो तुम्हें तुम्हारे ही सवाल का जवाब दिया था, तुमने मेरे प्रसन्न रहने का रहस्य पूछा था।

अंतर्मन

आज की पाती

न्यूनतम पेंशन में की जाए वृद्धि

केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कर्मचारी पेंशन योजना के तहत प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन में वृद्धि कर सकती है। अभी यह न्यूनतम पेंशन लगभग 1000 रुपए है। अगर सरकार इस पेंशन को लगभग 7500 रुपए कर देती है तो इससे करोड़ों लोगों को खुशी होगी और इससे इनकी बुढ़ापे में अपने खर्चे की टेंशन कुछ कम होगी। देश के हर कर्मचारी, चाहे वो सरकारी नौकरी का हो या निजी किसानों-संस्थान का, को पेंशन महंगाई के हिसाब से मिलनी चाहिए। 60 वर्ष के बाद तो किसी भी व्यक्ति में इतनी एनर्जी नहीं रह जाती कि वो अपने खर्चे पूरे करने के लिए और कोई नौकरी कर ले या काम धंधा कर ले। इसलिए उचित पेंशन जरूरी है। *- विकास जोशी, बिलासपुर*

करंट अफेयर

फिलीपीन के जहाज को चीनी तटरक्षत बल ने मारी टक्कर

चीनी तट रक्षक के एक जहाज ने रविवार को विवादित दक्षिण चीन सागर में फिलीपीनी निवासियों के एक द्वीप के पास लंगर डाले फिलीपीन सरकार के एक जहाज पर पहले तो जोरदार पानी की बौछार की और फिर उसे टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। फिलीपीन के तट रक्षक बल ने यह जानकारी दी। हालांकि इस घटना में फिलीपीन के मछुआरों को सहायता प्रदान करने वाले मत्स्य बेड़े का हिस्सा रहे 'बीआरपी दातु पगबुया' जहाज के फिलीपीनी चालक दल के सदस्यों में से किसी को भी चोट नहीं आई। मनीला, बीजिंग और चार अन्य देशों के बीच लंबे समय से जारी क्षेत्रीय विवादों के बीच ताजा घटना में चीन के तट रक्षक बल ने फिलीपीन के कब्जे वाले थिटू द्वीप के पास पगबुया को निशाना बनाया। चीन ने इस घटना पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। फिलीपीन तटरक्षक बल के प्रवक्ता कमोडोर जे टैरिएला ने एक बयान में कहा कि इस तरह की आक्रामकता फिलीपीन को ''किसी भी विदेशी ताकत को अपनी जमीन का एक इंच भी सौंपने'' के लिए मजबूर नहीं करेगी।

ऑफ बीट

विटामिन बी3 सप्लीमेंट से त्वचा कैंसर के खतरे कम

त्वचा कैंसर दुनिया का सबसे आम प्रकार का कैंसर है। इस कैंसर का कारण लगातार धूप में रहने, गोरी त्वचा और उम्र बढ़ने से जुड़ा है। रोकथाम की मौजूदा रणनीतियां पराबैंगनी (यूवी) किरणों से बचाव और 'सनस्क्रीन लोशन' के इस्तेमाल पर केंद्रित हैं। यह भी देखने में आया है कि एक बार त्वचा कैंसर का पता चलने पर कई बार रोगियों को इसकी पुनरावृत्ति का सामना करना पड़ता है। निकोटिनामाइड एक सस्ता और व्यापक रूप से उपलब्ध सप्लीमेंट है, जिसका इस्तेमाल त्वचा कैंसर से बचाव के लिए किया जा सकता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि विटामिन बी3 का यह रूप पराबैंगनी किरणों से होने वाली क्षति के बाद त्वचा की प्राकृतिक मरम्मत प्रणालियों को मजबूत करता है, सूजन कम करता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को असामान्य कोशिकाओं का पता लगाने तथा उन्हें हटाने में मदद करता है। नये अध्ययन में 12,000 से अधिक रोगियों, जिन्होंने एक महीने से अधिक समय तक प्रतिदिन दो बार 500 मिलीग्राम निकोटिनामाइड लेना शुरू किया, की तुलना 21,000 से अधिक रोगियों से की गई, जिन्होंने इसे नहीं लिया। निकोटिनामाइड लेने वालों में फिर से त्वचा कैंसर के विकास का जोखिम 14 प्रतिशत कम देखा गया।

ट्रेंड

आपातकाल के कष्ट

आज की युवा पीढ़ी शायद नहीं जानती कि आपातकाल के समय हमने क्या-क्या कष्ट झेले थे। घुटनों और कोहनियों पर डंडे मारे गए, गालियाँ दी गईं, किसी को बिजली के करंट के झटके दिए गए, किसी को बर्फ की सिल्ली पर सुला दिया गया
-शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री

आत्मनिर्भर भारत

दिल्ली के बाजारों, दिवाली मेलों और मिलन समारोहों में इस बार उत्साह का नया रंग है। हर आयोजन में आत्मनिर्भर भारत का संदेश है। आयोजक सभी नागरिकों को स्वदेशी उत्पादों के प्रति जागरूक कर रहे हैं और व्यापार को नई दिशा मिली है।
- रेखा गुप्ता, सीएम, नई दिल्ली

महिलाओं का उत्पीड़न

उत्तर प्रदेश समेत देश के विभिन्न राज्यों में महिलाओं के उत्पीड़न, दुष्कर्म और हत्या की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रहीं। सरकार को इसकी रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने की सख्त जरूरत है।
- मायावती, पूर्व सीएम, उप्र

लैंगिक समानता जरूरी

लैंगिक समानता सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रगति की आधारशिला है। हमें हर बालिका के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने होंगे, उन्हें बदलाव की अग्रिम पंक्ति में रखकर, उनकी आकांक्षाओं पर प्रतिक्रिया देकर और उन्हें निर्णय लेने के क्षेत्र में शामिल करके।
- मल्लिकार्जुन खड़गे, अध्यक्ष, कांग्रेस

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से **hbcgpati@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

दैनिक जागरण

मोह से मुक्ति पाए बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं

ममता की संवेदनहीनता

पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक मेडिकल कालेज की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जिस तरह पीड़ित छात्रा को ही कठघरे में खड़ा कर दिया, वह आश्चर्यचकित करने के साथ ही उनकी संवेदनहीनता को भी रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि वह लड़की रात को साढ़े बारह बजे मेडिकल कालेज परिसर से बाहर कैसे आ गई? क्या ऐसा करना अनुचित-अपराध है अथवा इसके कारण अपराधियों को कुछ भी करने की छूट मिल जाती है? ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि लड़कियों को रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए। ऐसे बयान देकर तो वे अपराधी तत्वों के दुस्साहस को बढ़ाने का ही काम कर रही हैं। यह शर्मनाक है कि जब उन्हें पीड़ित छात्रा और उसके स्वजन के पक्ष में खड़ा दिखना चाहिए, तब वे उन्हें ही कठघरे में खड़ा कर रही हैं। यह पहली बार नहीं है जब ममता ने बंगाल में कानून एवं व्यवस्था को चुनौती देने वाली किसी घटना पर गैर-जिम्मेदाराना बयान दिया हो। वे ऐसे बयान देने के लिए ही जानी जाती हैं। कोलकाता के चर्चित पार्क स्ट्रीट सामूहिक दुष्कर्म की घटना पर उन्होंने उसे मनगढ़ंत बताते हुए यह भी जोड़ा था कि इस वारदात के जरिये राज्य सरकार को बदनाम करने का इरादा था। यह भी किसी से छिपा नहीं कि पिछले वर्ष कोलकाता के ही आरजी कर मेडिकल कालेज में एक डाक्टर से दुष्कर्म और हत्या की देश को झकझोर देने वाली घटना पर पुलिस और प्रशासन ने किस तरह लीपापोती वाला रवैया अपनाया था। इसके चलते ही देश भर में आक्रोश उपजा और इस मामले की जांच सीबीआइ को सौंपनी पड़ी।

बंगाल अपनी गिरती हुई कानून एवं व्यवस्था के लिए पहले ही कुख्यात है। चिंताजनक यह है कि बंगाल के शिक्षण संस्थानों में भी दुष्कर्म की घटनाएं घट रही हैं। आरजी कर मेडिकल कालेज की घटना के बाद ला कालेज की एक छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया था और फिर इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट के परिसर में भी। इन घटनाओं से बंगाल में महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े होना स्वाभाविक हैं। विडंबना यह है कि जब मुख्यमंत्री को इन घटनाओं पर कठोर रवैये का परिचय देना चाहिए, तब वे अगंभीरता दिखा रही हैं। यदि वे कमजोर होती कानून एवं व्यवस्था पर लीपापोती दिखाएंगी तो इससे स्थितियां और खराब ही होंगी। इसकी भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि ममता मुख्यमंत्री होने के साथ-साथ गृहमंत्री का भी दायित्व संभाले हुए हैं। इस नाते उन्हें और अधिक सजगता का परिचय देना चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक महिला होने के बाद भी वे महिलाओं के साथ होने वाले जघन्य अपराधों पर अपने पुरातनपंथी सोच का परिचय दे रही हैं। आज के युग में ऐसे सोच के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता।

बस अड्डों का कायाकल्प

किसी प्रदेश की छवि वहां की राजधानी में उपलब्ध विभिन्न संरचनाओं से भी बनती है। सड़कें, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट तथा बस अड्डों की सुंदरता, साफ सफाई और वहां उपलब्ध नागरिक सुविधाओं से उस प्रदेश की अच्छी छवि बनती है। झारखंड सरकार ने इसे ध्यान में रखकर राजधानी रांची के तीन बस अड्डों के कायाकल्प का निर्णय लिया है, जो एक अच्छी पहल है। रांची के खादगढ़ा तथा आइटीआइ बस अड्डों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करते हुए राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित किए जाने की योजना को स्वीकृत मिल गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जर्जर हो चुके सरकारी बस डिपो का भी पुनर्निमाण होगा। बड़ी संख्या में लोग इन बस अड्डों से अपने गंतव्य के लिए बस पकड़ते हैं। निश्चित रूप से इसका लाभ उन्हें मिलेगा और उनकी यात्रा सुखद होगी। इन बस अड्डों पर ड्राइवर कैंटीन, मेंटेनेंस शेड, गार्ड रूम, स्लाइडिंग प्रवेश द्वार, प्रतीक्षालय, कार, आटो और ई-रिक्शा पार्किंग होने से सभी स्टेक होल्डर्स को सहुलियत होगी। आवश्यकता इस बात की है कि इन योजनाओं पर तेजी से काम हो। टेंडर प्रक्रिया पूरी करने की बात हो या इनके निर्माण की, सभी प्रक्रियाओं के लिए समय सीमा तय कर देने से योजना सही रूप से धरातल पर उतर सकेगी। योजना के क्रियान्वयन के लिए वैसी एजेंसी का चयन किया जाए जिसके पास ऐसे कार्यों का पर्याप्त अनुभव हो। इन योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान आम लोगों एवं संबंधित अन्य लोगों को कोई परेशानी न हो, इसे भी ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी।

सड़कें, रेलवे स्टेशन तथा बस अड्डों पर उपलब्ध नागरिक सुविधाओं से प्रदेश की अच्छी छवि बनती है

गाजा में शांति पर संदेह का साया

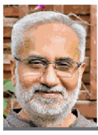

शिवकांत शर्मा

नेतन्याहू और हमास के पास ट्रंप की शांति योजना पर सहमति के सिवा और कोई विकल्प नहीं था, लेकिन क्या गाजा में वास्तव में शांति स्थापित हो सकेगी?

अवधेश राजपूत

राष्ट्रपति ट्रंप की बीस सूत्री शांति योजना पर इजरायली कैबिनेट की मंजूरी के बाद गाजा में युद्धविराम लागू हो गया है। इससे जुड़ी शांति योजना के तीन चरण हैं। जिस पहले चरण पर हमास और इजरायल सहमत हुए हैं, उसमें सबसे पहले इजरायली हमले रुकना और इजरायली सेना को गाजा के 47 प्रतिशत क्षेत्र से पीछे हटना था। साथ ही, इजरायल आतंकी हमलों और दूसरे अपराधों के आरोपों में सजा काट रहे करीब 250 फलस्तीनी कैदियों को और गाजा के उन 1700 लोगों को रिहा करेगा जो हिरासत में हैं। हमास 28 इजरायली बंधकों की पार्थिव देह सौंपेगा और इजरायल अपनी हिरासत में मरे गाजा के 15 लोगों के पार्थिव शरीर हमास को सौंपेगा।

इजरायल, हमास, अरब देश और ट्रंप सभी एक-दूसरे की पीठ थपथपा रहे हैं। ट्रंप अपनी योजना को पश्चिम एशिया में स्थायी शांति का कदम बताकर नोबेल शांति पुरस्कार की आस लगाए बैठे थे। वह तो पूरी नहीं हो सकी, पर क्या वे टूटी आस की कड़वाहट को पीकर शांति योजना को सफल बनाने में पूरी शक्ति लगाएंगे? क्योंकि उनकी योजना के पहले चरण का क्रियान्वयन तो आसान था। हालांकि इसमें भी हमास की मांग पर रिहा होने वाले कैदियों के नामों और संख्या को लेकर रुकावटें खड़ी हो सकती हैं। इसके पूरा होने के बाद दूसरे और तीसरे चरणों की सौदेबाजी शुरू होगी।

योजना के अनुसार गाजा पट्टी का पूरी तरह विसैन्यीकरण होना है। यानी हर तरह के सैनिक, आतंकी और आक्रामक ढांचे को ढहाया जाएगा, जिसमें उन सुरंगों का जाल भी शामिल है जिनका प्रयोग हमास के आतंकी अपने राकेट, गन और गोला बारूद रखने के लिए करते थे। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के आकलन के अनुसार हमास ने युद्ध के दौरान करीब 15 हजार नए लड़ाकों की भर्ती भी की थी। इजरायल चाहता है कि ये सभी सदस्य हथियार डालें और भविष्य में लड़ाई न करने का प्रण लें। हालांकि हमास की शर्त रही है कि वह स्वतंत्र फलस्तीन राष्ट्र की स्थापना होने के बाद ही हथियार डालेगा।

शांति योजना के अनुसार गाजा का प्रशासन एक शांति बोर्ड की देखरेख में फलस्तीनी विशेषज्ञों की अस्थायी समिति संभालेगी। शांति बोर्ड की अध्यक्षता खुद ट्रंप करेंगे। पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर की भी इसमें प्रमुख भूमिका होगी। फलस्तीनी प्राधिकरण में सुधार करने के बाद गाजा का प्रशासन उसे सौंप दिया जाएगा, परंतु उसमें हमास की प्रत्यक्ष या परोक्ष कोई भूमिका नहीं होगी। हमास के जो सदस्य इजरायल के शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को स्वीकार करेंगे, उन्हें अभयदान देकर दूसरे देशों में भेज दिया जाएगा। हालांकि अभी तक हमास इजरायल के अस्तित्व को स्वीकार करने से इन्कार करता रहा है। दूसरी ओर, नेतन्याहू ने ट्रंप की शांति योजना को पूरी तरह स्वीकार भले कर लिया हो, पर वे गाजा का प्रशासन फलस्तीनी प्राधिकरण को नहीं देना चाहते।

गाजा के युद्धविराम को ट्रंप पश्चिम एशिया में स्थायी शांति का पहला कदम बताते हैं, परंतु इतना वे भी जानते हैं कि फलस्तीनियों को उनका देश मिले बिना यहां कोई शांति स्थायी नहीं हो सकती। पिछली सदी के अंत तक यह संभव लगता था। इजरायल में भी काफी बड़ा जनमत इसके पक्ष में था, लेकिन जब से नेतन्याहू ने सत्ता संभाली है, अलग फलस्तीनी राष्ट्र की संभावना को सपने में बदल दिया है। फलस्तीनी चाहते हैं कि पश्चिमी किनारे और गाजा में उनका देश बने, जिसकी राजधानी पूर्वी यरूशलम हो। कहने को पश्चिमी किनारे पर फलस्तीनी प्राधिकरण का शासन है, परंतु इजरायल ने धीरे-धीरे वहां यहूदी बस्तियों का जाल बिछा दिया है, जिनमें लगभग सात लाख यहूदी बसते हैं। उन बस्तियों पर इजरायली शासन है।

पश्चिमी किनारे की मात्र 18 प्रतिशत भूमि पर ही फलस्तीनी प्राधिकरण का शासन है। 22 प्रतिशत भूमि पर इजरायल और फलस्तीनी प्राधिकरण का संयुक्त शासन है और जार्डन और इजरायल से लगती शेष 60 प्रतिशत भूमि पर इजरायली शासन। यदि मानचित्र पर देखें तो पश्चिमी किनारे के शहर इजरायली भूमि पर फलस्तीनी द्वीपों जैसे लगते हैं। यह सुनियोजित रणनीति के तहत किया गया लगता है ताकि फलस्तीनी शहर इजरायल के विरुद्ध एकजुट न हो सकें। सीमावर्ती जमीन को भी इजरायल ने इसलिए अपने पास रखा ताकि पड़ोसी देशों में खुलने वाली सुरंगों का जाल न बिछाया जा सके, जो गाजा में हुआ है।

इस समय नेतन्याहू और हमास के पास ट्रंप की शांति योजना के लिए सहमत होने के सिवा और कोई विकल्प नहीं बचा था। नेतन्याहू शांति के नोबेल की आस लगाए बैठे ट्रंप को नाराज नहीं कर सकते थे। हमास के पास भी न तो निरंतर बढ़ती आ रही इजरायली सेना से बंधकों को छिपाए रखने की जगह बची थी और न ही दुनिया से और अधिक सहानुभूति बटोरने की गुंजाइश। अब शांति कायम हो जाने और गाजा में पुनर्निर्माण शुरू होने के साथ ही दोनों को अस्तित्व की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। नेतन्याहू के समक्ष अपनी सरकार बचाने, हमास के हमले को रोकने में हुई सुरक्षा चूक की जांच से और भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जाने से बचने की चुनौतियां हैं। हमास के समक्ष सत्ता से बाहर रहते हुए अपना प्रभाव बनाए रखने की चुनौती है। इजरायली हमलों में मारे गए 67 हजार से अधिक लोगों के परिवारों का इजरायल विरोधी रोष उन्हें उसे बनाए रखने और संगठन खड़ा करने की आधारभूमि देगा।

इजरायली बड़ी शान से कहा करते थे कि उनकी लड़ाइयां सैनिक अकादमियों में पढ़ाई जाया करेंगी, लेकिन गाजा की लड़ाई उन्हें बहुत मायूस करेगी। ऐसा इसलिए, क्योंकि इजरायल ने भले ही हमास के साथ-साथ हिजबुल्ला के फनों को भी कुचल दिया हो, परंतु उनके उद्देश्य के लिए बढ़ती सहानुभूति की लहर को नहीं थाम पाया है। साख की लड़ाई में तो वह बुरी तरह हार गया है। संयुक्त राष्ट्र के जांच आयोग ने उस पर जनसंहार का आरोप लगाया है और ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा जैसे पारंपरिक मित्र देशों ने उसकी मर्जी के खिलाफ फलस्तीन को मान्यता दे दी है।

(लेखक बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक हैं)
response@jagran.com

संबंधों को पटरी पर लाने की चुनौती

मनिष दाभाडे

चीनी आक्रामकता एवं वैश्विक अस्थिरता के इस दौर में भारत-अमेरिका के बीच साझेदारी ही स्थिरता की गारंटी है

अमेरिका के नवनियुक्त राजदूत और दक्षिण एवं मध्य एशियाई मामलों के विशेष दूत सर्जियो गोर ने पहले ही दिन भारत के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश सचिव विक्रम मिस्री से उनकी बैठकें संकेत हैं कि वाशिंगटन भारत के साथ अपने रिश्ते को नई गति देने के मूड में है। इस सौहार्दपूर्ण शुरुआत के पीछे गोर के लिए चुनौतियों का एक जटिल जाल बिछा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मित्रता ने जहां संबंधों में नई ऊर्जा डाली है, वहीं दोनों देशों के बीच व्यापारिक मतभेद, तकनीकी साझेदारी की जटिलताएं और दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को लेकर चिंताएं अब भी बनी हुई हैं। गोर के लिए सबसे बड़ी कसौटी यह होगी कि वे व्यक्तिगत निकटता को नीति में बदलें और इन विरोधाभासों को समेटते हुए संबंधों को नई दिशा दें।

गोर का भारत में राजदूत के साथ-साथ दक्षिण एवं मध्य एशियाई मामलों का विशेष दूत भी होना एक राजनीतिक संकेत है कि अमेरिका भारत और उसके पड़ोसी क्षेत्र को अब सीधे राष्ट्रपति की प्राथमिकता के रूप में देख रहा है, परंतु यह दोहरी भूमिका भारत के लिए दुविधा का विषय भी है। नई दिल्ली लंबे समय से यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसे दक्षिण एशिया के पारंपरिक 'भारत-पाकिस्तान' ढांचे में न बांधा जाए। गोर के लिए यह चुनौती होगी कि वे भारत की वैश्विक भूमिका को बनाए रखते हुए अपने क्षेत्रीय दायित्वों का निर्वाह करें। उनकी सबसे कठिन परीक्षा आर्थिक मोर्चे पर होगी। ट्रंप प्रशासन की 'अमेरिका फर्स्ट' नीति के तहत भारत पर लगाए गए ऊंचे टैरिफ ने दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ा दिया है। अमेरिका का दावा है कि भारत के ऊंचे आयात शुल्क और रूस से तेल खरीद जैसी नीतियां 'असंतुलित' हैं। इसके जवाब में भारत ने अपने हितों की रक्षा पर जोर दिया है। संभावित व्यापार समझौता महीनों से ठप पड़ा है। ऐसे में गोर को इस प्रक्रिया को पुनर्जीवित करना होगा, वह भी बिना किसी घरेलू राजनीतिक विवाद के।

प्रौद्योगिकी साझेदारी भी उनके एजेंडे का एक संवेदनशील बिंदु है। भारत रक्षा और नवाचार क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण चाहता है, जबकि अमेरिका अपनी बौद्धिक संपदा और सुरक्षा चिंताओं को लेकर सतर्क है। सेमीकंडक्टर, एआइ और डाटा सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग के अवसर तो हैं, पर नीतिगत स्पष्टता की कमी दोनों पक्षों को सतर्क रखती है। गोर का कार्य यह साबित करना होगा कि वाशिंगटन की तकनीकी नीति चीन को लेकर है, भारत को लेकर नहीं। रक्षा सहयोग के क्षेत्र में गोर को एक सकारात्मक आधार मिला है। दोनों देशों के बीच हुए कोमकासा और बीईसीए जैसे समझौते सामरिक साझेदारी के नए युग की नींव बन चुके हैं। फिर भी भारत अमेरिका से अधिक तकनीकी हस्तांतरण और स्थानीय उत्पादन चाहता है, जबकि वाशिंगटन रूस से भारत के सैन्य संबंधों पर दबाव डालता है। गोर को इस संतुलन को साधना होगा, ताकि भारत की रक्षा स्वायत्तता प्रभावित न हो और अमेरिका की रणनीतिक अपेक्षाएं भी पूरी हों।

नई उम्मीदों के साथ आए नए राजदूत सर्जियो गोर। प्रेट्र

दक्षिण एशिया के परिप्रेक्ष्य में चुनौती और गहरी है। ट्रंप के पाकिस्तान के प्रति हालिया रुझान-इस्लामाबाद के नेतृत्व से मुलाकात और उसके ऊर्जा क्षेत्र में अमेरिकी निवेश के संकेत दिल्ली के लिए असहज हैं। भारत को यह आशंका है कि कहीं वाशिंगटन पुनः 'री-हाइफनेशन' यानी भारत-पाकिस्तान समानांतर नीति की ओर न लौट जाए। गोर की दोहरी जिम्मेदारी-दिल्ली और इस्लामाबाद, दोनों से संपर्क इस चिंता को और गहरा करती है। उन्हें भारत को यह विश्वास दिलाना होगा कि ट्रंप का पाकिस्तान प्रेम रणनीतिक गणित का हिस्सा है, न कि नीति परिवर्तन का। महत्वपूर्ण खनिजों पर गोर और मोदी के बीच चर्चा यह दिखाती है कि अमेरिका इस क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाना चाहता है। दोनों देश चीन पर निर्भरता कम करने और 'फ्रेंड-शोरिंग' के माध्यम से वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखला बनाने के पक्षधर हैं, पर भारत की खनन नीतियां अभी भी जटिल हैं। यदि गोर यहां ठोस निवेश या संयुक्त परियोजनाएं आगे बढ़ा पाते हैं तो यह उनके कार्यकाल की एक उल्लेखनीय उपलब्धि होगी। आव्रजन नीति और एच-1बी वीजा व्यवस्था पर भी उन्हें सावधानी से चलना होगा। भारतीय पेशेवरों के लिए अमेरिका की कड़ी वीजा नीति चिंता का विषय रही है। गोर को इन घरेलू राजनीतिक बाधाओं को समझाते हुए भी भरोसे का माहौल बनाना होगा।

गोर के पास एक बड़ा लाभ यह है कि वे सीधे राष्ट्रपति तक पहुंच रखते हैं, पर यही उनकी सबसे बड़ी चुनौती भी है। यदि वे ट्रंप की व्यक्तिगत सद्भावना को ठोस नीतिगत परिणामों में बदलने में सफल रहते हैं तो न केवल संबंधों को पुनर्जीवित करेंगे, बल्कि उन्हें नई ऊंचाई भी देंगे। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में भारत और अमेरिका का सहयोग अनिवार्य है। चीन की आक्रामकता, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और आपूर्ति श्रृंखला के पुनर्संतुलन के युग में दोनों देशों की साझेदारी ही स्थिरता की गारंटी है। गोर के आगमन से यह उम्मीद बंधती है कि संवाद की रफ्तार फिर से बढ़ेगी, रक्षा-प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्रों में प्रगति होगी और असहमतियों के बावजूद सहयोग का दायरा विस्तृत होगा।

(लेखक द इंडियन फ्यूचर्स थिंक टैंक के संस्थापक और जेएनयू में एसोसिएट प्रोफेसर हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

मधुर वाणी

वाणी का प्रभाव गहरा होता है। मधुर वाणी के प्रयोग से संबंधों में प्रेम, सहृदयता और आत्मीयता का संचार होता है। जबकि कटु और कर्कश वचन संबंधों में दरार डालते हैं, जिससे झगड़े, मारपीट और दंगों जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। कटु वचन का घाव कभी नहीं भरता, जबकि शारीरिक चोटें औषधि से ठीक हो जाती हैं। कटु वाणी का जख्म जीवनभर टीसता रहता है और व्यक्ति बदले की भावना से ग्रस्त हो जाता है। धनुष से निकले तीर की तरह मुख से निकली कटु वाणी भी अत्यंत शक्तिशाली और खतरनाक होती है।

उद्दंड व्यक्ति वाणी का दुरुपयोग करते हैं। वे अपशब्द, कटु वचन बोलकर न केवल अपने जीवन को, बल्कि दूसरों के जीवन को भी दुखी करते हैं। ज्ञानी व्यक्ति सोच-समझकर बोलते हैं। वे कम बोलते हैं, लेकिन उनके शब्दों में गहराई होती है। इसलिए मितभाषी होना जीवन के कल्याण का एक महत्वपूर्ण सबक है। वाणी का दुरुपयोग पाप की वृद्धि करता है। कटु वाणी से किसी को कष्ट पहुंचाना अपराध है। मनुष्य का जीवन इस संसार में सीमित है और कब यह समाप्त हो जाए, कोई नहीं जानता। इसलिए हमें मधुर वार्तालाप करके प्रेम और मित्रता का संचार करना चाहिए। मधुर वचन एक प्रकार का वशीकरण मंत्र है।

द्रौपदी के कटु वचन ने दुर्योधन को दुखी किया, जिसके परिणामस्वरूप महाभारत का युद्ध हुआ। इसी प्रकार माता कैकेयी के कठोर वचन राजा दशरथ की मृत्यु का कारण बने और प्रभु श्रीराम को वनवास जाना पड़ा। हमें अपने शब्दों का चयन सोच-समझकर करना चाहिए। मधुर वाणी से न केवल संबंधों में मिठास बढ़ती है, बल्कि यह समाज में शांति और सद्भाव का भी निर्माण करती है। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक और मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए, ताकि हम अपने और दूसरों के जीवन को सुखद बना सकें।

मुकेश ऋषि

इलेक्ट्रिक वाहनों में ध्वनि चेतावनी की अनिवार्यता

अली खान

इलेक्ट्रिक वाहन से शोर कम होता है, किंतु यह मौन संचालन पैदल यात्रियों के लिए खतरा भी उत्पन्न करता है

इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती लोकप्रियता और उनकी तकनीकी विशेषताओं ने जहां एक ओर स्वच्छ परिवहन का रास्ता खोला है, वहीं दूसरी ओर सड़क सुरक्षा से संबंधित एक नई चुनौती भी पेश की है। दरअसल इलेक्ट्रिक वाहन पारंपरिक इंजनों की तरह ध्वनि उत्पन्न नहीं करते। यह विशेषता कई मायनों में लाभकारी है, क्योंकि इससे शोर प्रदूषण कम होता है, किंतु यह मौन संचालन पैदल यात्रियों और विशेषकर दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करता है। सड़क पर चलते समय अधिकांश लोग आने वाले वाहन की उपस्थिति का अनुमान उसके इंजन की आवाज से ही लगाते हैं। जब वाहन बिना आवाज के आ जाए तो सड़क पार करने वाले व्यक्ति को इसकी भनक तक नहीं लग पाती और दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है।

इसी परिप्रेक्ष्य में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने हाल में एक प्रस्ताव रखा है कि एक अक्टूबर 2027 से देश की सभी इलेक्ट्रिक कारों, बसों और ट्रकों में ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली यानी 'अवार' को अनिवार्य रूप से लगाना होगा। हालांकि नए माडल के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए यह नियम एक वर्ष पहले ही अर्थात एक अक्टूबर 2026 से लागू हो जाएगा। ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली एक ऐसी तकनीक है जिसमें वाहन की गति और दिशा के अनुसार ध्वनि की तीव्रता और स्वर बदलते रहते हैं। यदि वाहन धीरे चल रहा है तो आवाज भी हल्की होगी और यदि गति अधिक है तो ध्वनि का स्तर बढ़ जाएगा। यह प्रणाली सामान्यतः 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति पर सक्रिय रहती है, क्योंकि इस सीमा के ऊपर वाहन के टायर और हवा की घर्षण ध्वनि स्वयं ही श्रव्य हो जाती है। प्रणाली से उत्पन्न ध्वनि का स्तर न तो बहुत अधिक होता है कि वह शोर प्रदूषण पैदा करे और न ही इतना कम कि सुनाई न दे। आमतौर पर यह आवाज 56 से 75 डेसिबल के बीच रखी जाती है, जो मानवीय कान के लिए सुरक्षित है।

दुनिया में कई देश इस तकनीक को पहले ही अपना चुके हैं। अमेरिका में 2018 से यह नियम लागू है। वहां सभी नए इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों में कृत्रिम ध्वनि प्रणाली लगाना अनिवार्य है। यूरोपीय संघ ने 2019 और जापान ने 2010 में ही इसे लागू कर दिया था। हालांकि इस तकनीक को अपनाने में कुछ चुनौतियां भी हैं। पहला, इससे वाहन की कीमतों में थोड़ी वृद्धि होगी, क्योंकि कंपनियों को अतिरिक्त उपकरण लगाने होंगे। दूसरा, यदि अलग-अलग कंपनियां अलग ध्वनियों का प्रयोग करेंगी तो इससे भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। तीसरा, ध्वनि प्रदूषण की समस्या भी एक हद तक सामने आ सकती है यदि आवाज का स्तर अनुचित ढंग से निर्धारित किया गया। इन सबके बावजूद, लाभ और सुरक्षा की दृष्टि से यह पहल कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।

(लेखक शिक्षक हैं)

मेलबाक्स

अनुचित हैं लोकलुभावन वादे

'लोकलुभावन वादों पर टिकी राजनीति' शीर्षक से लिखे लेख में संजय गुप्त ने स्पष्ट किया है कि अगर जाति की राजनीति और लोकलुभावन घोषणाओं के माध्यम से चुनाव लड़े जाएंगे तो बिहार पिछड़े राज्यों की श्रेणी से बाहर नहीं निकल पाएगा। प्रश्न यह उठता है कि हमारी राजनीति ऐसी बुनियाद क्यों नहीं रख पा रही है, जिससे जाति की राजनीति और लोकलुभावन घोषणाओं को खारिज किया जा सके। यह जानते हुए भी कि इस एक सुधार से विकास के सभी दरवाजे खुल सकते हैं। जाति की राजनीति अधिकांश राज्यों में प्रचलित है, लेकिन बिहार में इसका प्रभाव कुछ अधिक है। इसका मुख्य कारण यह है कि यहां जाति वर्चस्व वाली छोटी-छोटी पार्टियों की भरमार है। बड़ी पार्टियों ने समावेशी राजनीति के तहत सभी जातियों को समायोजित करने में असफलता दिखाई है। दूसरी ओर, मतदाता भी किसी न किसी जाति या धर्म से जुड़े होते हैं। ऐसे में सभी को अपने नेता की तलाश बड़ी पार्टियों के भीतर करनी चाहिए। बिहार की राजनीति में एक नई दिशा की आवश्यकता है, जहां जाति और धर्म से ऊपर उठकर विकास की बात की जाए। यह तभी संभव है जब सभी राजनीतिक दल एकजुट होकर समावेशी राजनीति को अपनाएं और मतदाता भी अपने सोच में बदलाव लाएं। केवल तभी बिहार अपने विकास की नई ऊंचाइयों को छू सकेगा।

मुकेश कुमार मनन, पटना

भारत के सधे कदम

अगस्त 2021 जब अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन हुआ तब यह आशंका थी कि वहां की तालिबान सरकार पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के लिए समस्यां पैदा कर सकती है, लेकिन भारत ने धैर्यपूर्ण और लचीलापन दिखाते हुए अपना संयत व्यवहार बनाए रखा तथा संकट के समय उसका भरपूर साथ भी दिया। वहां के तालिबान शासन ने भी समझदारी दिखाते हुए व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया तथा भारत के महत्व को समझा दोनों देशों के संबंध आर्थिक एवं सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। अफगानियों के लिए भारत में अनुकूल व्यावसायिक वातावरण है। इसका प्रमाण है कि चालू वित्तीय वर्ष में अफगानिस्तान और भारत के बीच व्यापार 763 मिलियन डालर तक पहुंच गया है, जिसमें अफगानिस्तान का निर्यात 541 मिलियन डालर और भारत से आयात 222 मिलियन डालर है। पिछले कई दशकों से अशांत रहे अफगानिस्तान के लिए यह बहुत बड़ा आर्थिक एवं व्यावसायिक संबल है। वहीं अफगानिस्तान में लिथियम, नियोडिमियम, लैंथेनम और सेरियम जैसी दुलर्भ धातुओं के अलावा लौह अयस्क, तांबा और एल्यूमीनियम के भी प्रचुर भंडार हैं। भारत की इसी व्यावहारिकता एवं लचीलेपन के कारण अफगानिस्तान ने भारतीय कंपनियों को अपने खनन क्षेत्र में निवेश के लिए आमंत्रित किया है।

विमलेश पगारिया, बदनावर, मप्र

ज्ञान की सार्थकता

ज्ञान केवल तथ्य और जानकारी का संग्रह नहीं है बल्कि यह जीवन को समझने, देखने और अनुभव करने का माध्यम है। किसी भी व्यक्ति के लिए ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह उसे केवल याद न रखे, बल्कि उसका प्रयोग अपने जीवन और समाज के उत्थान के लिए कर सके। बिना प्रयोग और समझ के ज्ञान, चाहे कितनी भी विशाल मात्रा में हो, एक खाली वस्तु के समान है। सार्थक ज्ञान हमें न केवल सही और गलत में अंतर बताता है बल्कि यह हमें निर्णय लेने, समस्याओं का समाधान खोजने और चुनौतियों का सामना करने में भी सक्षम बनाता है। उदाहरण स्वरूप, विज्ञानियों ने जो ज्ञान अर्जित किया, वह केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं रहा। उसने समाज में नई तकनीक, दवाई और विकास के रूप में रूप लिया। इसी प्रकार, शिक्षित समाज ही प्रगतिशील और सशक्त बन सकता है। ज्ञान की सार्थकता का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह व्यक्ति को विवेकशील बनाता है। विवेक के बिना ज्ञान अक्सर अहंकार, भ्रम और गुमराह करने वाला हो सकता है। वास्तविक ज्ञान हमें अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेने की शक्ति देता है।

अमन सिंह गौर, वाराणसी

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

https://t.me/AllNewsPapersPaid1